

[2014] 12 एस. सी. आर. 875

तमिलनाडु राज्य

बी.

केरल राज्य और ए. एन. आर.

(2006 का मूल सूट नंबर 3) 07 मई, 2014

[आर. एम. लोधा, सीजेआई, एच. एल. दत्तू, चंद्रमौली केआर। प्रसाद, मदन बी. लोकुर और एम. वाई. एक्बाल, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 131- अंतर-राज्यीय जलविवाद-मुल्लापेरियार बांध, एक चिनाई बांध, का निर्माण 29 तारीख के पट्टा समझौते के अनुसार पेरियार नदी के पार 10-1886 महाराजा की सरकार के बीच निष्पादित त्रावणकोर और भारत के राज्य सचिव-आने पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से प्रभावी राज्य त्रावणकोर-कोच्चि का गठन किया गया था और केरल राज्य इसका है।

परिषद में राज्यपाल, भारत के राज्य सचिव के हित में तमिलनाडु राज्य उत्तराधिकारी है। - बांध केरल के थेक्कडी जिले में स्थित है, लेकिन तमिलनाडु सरकार के स्वामित्व और संचालन में है-मुकदमेबाजी के पहले दौर में, 27-2-2006 के फैसले के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट अदालत ने मुल्लापेरियार बांध में जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाने की अनुमति दी और केरल राज्य पर भी रोक लगा दी इसके अधिकारियों को इसमें कोई बाधा डालने से-हालाँकि, 2006 के संशोधन अधिनियम के बाद के अधिनियमन द्वारा बांध तय और 136 फीट तक सीमित-तमिल राज्य द्वारा दायर मुकदमा नाडू यू/आर्ट। 131 केरल राज्य के खिलाफ संविधान के यू/के तहत मुकदमे की रखरखाव। कला. 131 - वैधता और बाध्यकारी

1886 एल की प्रकृति; आसान समझौता और 1970 के पूरक समझौतों का प्रभाव- आयोजित: तमिल राज्य द्वारा दायर मुकदमा नाडू रखरखाव योग्य यू/आर्ट था। 131 संविधान का-मुकदमा दिनांकित पट्टा विलेख के तहत दावा किए गए कानूनी अधिकार पर आधारित था 29-10-1886-केरल राज्य (प्रथम प्रतिवादी) को हटा दिया गया

याचिका दायर करने से कि पट्टा विलेख दिनांक 29-10-1886 था 875 876 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.: दिनांकित 28-05 पूरक समझौतों को ध्यान में रखते हुए समाप्त हो गया 1970 केरल राज्य और तमिलनाडु राज्य के बीच दिनांकित पट्टा विलेख 29-10-1886 पहले पर वैध और बाध्यकारी है। प्रतिवादी (केरल राज्य) और इसके

खिलाफ प्रवर्तनीय-केरल सिंचाई और जल संरक्षण अधिनियम, 2003-केरलसिंचाई और जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 131 - अंतर-राज्य जल विवाद-मुल्लापेरियार बांध, एक चिनाई बांध, का निर्माणपेरियार नदी के पार-में थेक्कडी जिले में स्थित बांध केरल लेकिन तमिलनाडु सरकार द्वारा स्वामित्व और संचालित-मुकदमेबाजी के पहले दौर में, दिनांकित निर्णय के माध्यम से 27-2-2006, उच्चतम न्यायालय ने जल स्तर की अनुमति दी

मुल्लापेरियार बांध को 142 फीट तक बढ़ाया जाएगा और केरल राज्य और उसके अधिकारियों को किसी भी तरह के नुकसान से रोका जाएगा। हालाँकि, केरल राज्य विधानमंडल द्वारा 2006 के संशोधन अधिनियम के बाद के अधिनियमन के माध्यम से, पूर्ण बांध का जलाशय स्तर (एफ. आर. एल.) निर्धारित और 136 फीट तक सीमित है।

तमिलनाडु राज्य यू/आर्ट द्वारा दायर मुकदमा। 131 केरल राज्य के खिलाफ संविधान-क्या 2006 का संशोधन अधिनियम

मुल्लई पेरियार बांध पर इसके अनुप्रयोग और प्रभाव में असंवैधानिक और अति अधिकार और क्या 27 का निर्णय 2-2006 प्रथम प्रतिवादी (केरल राज्य) द्वारा स्थापित सभी या किसी भी बचाव पक्ष के संबंध में न्यायपालिका के रूप में संचालित-आयोजित:

2006 संशोधन अधिनियम असंवैधानिक था और सत्ता के बाहर था। मुल्लापेरियार बांध पर इसका अनुप्रयोग और प्रभाव-अधिकार तमिलनाडु का, दिनांक 27-2-2006 के निर्णय में स्पष्टीकृत केरल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा रद्द नहीं किया जा सका राज्य विधानमंडल-27-2-2006 पर दिए गए पहले के फैसले को मुल्लापेरियार की सुरक्षा के मुद्दे पर रेस जुडिकाटा के रूप में संचालित किया गया था जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाने के लिए बांध। - केरल ने वर्तमान मुकदमे में मुद्दों को उठाने या फिर से आंदोलन करने से इनकार कर दिया-केरल

मुल्लापेरियार बांध की ऊंचाई 142 फीट है। और दिनांक 27-2-2006-केरल सिंचाई के निर्णय के अनुसार मरम्मत कार्यों को पूरा करने से और जल संरक्षण अधिनियम, 2003-केरल सिंचाई और जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006-तमिलनाडु के सिद्धांत/राज्य v.

केरल राज्य 877

सिद्धांत-न्याय और रचनात्मक न्याय का सिद्धांत

न्यायपालिका-की प्रयोज्यता।

भारत का संविधान, 1950-- Art.131-अंतर-राज्यीय जल

विवाद-मुल्लापेरियार बांध, एक चिनाई बांध, का निर्माण

नाडू मुकदमे के पहले दौर में, दिनांकित निर्णय के माध्यम से 27-2-2006 , उच्चतम न्यायालय ने जल स्तर की अनुमति दी

मुल्लापेरियार बांध को 142 फीट तक बढ़ाया जाएगा और इसे नियंत्रित भी किया जाएगा केरल राज्य और उसके अधिकारियों को किसी भी कारण से।

इसमें बाधा-हालाँकि, बाद के अधिनियम के अनुसार

केरल राज्य विधानमंडल द्वारा 2006 का संशोधन अधिनियम, पूर्ण

बांध का जलाशय स्तर (एफ. आर. एल.) निश्चित और 136 फीट तक सीमित है।

—

तमिलनाडु राज्य यू/आर्ट द्वारा दायर मुकदमा। 131 संविधान का

केरल राज्य के खिलाफ-क्या पहला प्रतिवादी (राज्य)

केरल का) यह तर्क देने से अलग हो गया कि पेरियार नदी नहीं है

एक अंतर-राज्यीय नदी-आयोजित: यह सच है कि तमिल का कथन

इस शिकायत में कि दो राज्य-केरल और तमिल

नाडू-तटवर्ती राज्य हैं जो पूरी तरह से सही नहीं हैं क्योंकि

तमिलनाडु एक नदी तटीय राज्य नहीं है, बल्कि पेरियार का दर्जा है।

अंतर-राज्यीय नदी के रूप में नदी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है-यह खुली नहीं है केरल को एक पूरी तरह से असंगत याचिका लेने और नए सिरे से शुरू करने के लिए

पेरियार नदी की स्थिति के बारे में विवाद इस आधार पर कि

पहले की याचिका कुछ गलत आधार पर आधारित थी -

केरल को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि पेरियार नदी एक नदी है।

अंतर-राज्यीय नदी नहीं बल्कि अंतर-राज्यीय नदी-केरल सिंचाई

और जल संरक्षण अधिनियम, 2003-केरल सिंचाई और

जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006-सिद्धांत /

सिद्धांत-अवरोध का नियम।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 131 - अंतर-राज्यीय जल

विवाद-मुल्लापेरियार बांध, एक चिनाई बांध, का निर्माण

पेरियार नदी के पार-में थेक्कडी जिले में स्थित बांध केरल लेकिन तमिल सरकार के
स्वामित्व और संचालन में है

नाडु-मुकदमे के पहले दौर में, दिनांकित निर्णय के माध्यम से

27-2-2006 , उच्चतम न्यायालय ने 878 में जल स्तर की अनुमति दी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

मुल्लापेरियार बांध को 142 फीट तक बढ़ाया जाएगा और केरल राज्य और उसके अधिकारियों
को किसी भी तरह के नुकसान से रोका जाएगा।

इसमें बाधा-हालांकि, केरल राज्य विधानमंडल, फुली द्वारा 2006 के संशोधन अधिनियम के
बाद के अधिनियम के माध्यम से

बांध का जलाशय स्तर (एफ. आर. एल.) निर्धारित और 136 फीट तक सीमित है।

तमिलनाडु राज्य यू/आर्ट द्वारा दायर मुकदमा। 131 संविधान का

मुल्लई पेरियार बांध के निचले क्षेत्र में पेरियार नदी न्याय के उद्देश्यों और वादी की
आवश्यकताओं को पूरा करेगी - आयोजित किया गया: नए बांध के निर्माण के लिए
समझौता होना चाहिए

दोनों पक्षों का-केरल द्वारा दिए गए प्रस्ताव को खारिज नहीं किया जा सकता है।

तमिलनाडु पर-हालांकि, पक्षों को आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई

न्यायालय में यदि वे कुछ सौहार्दपूर्ण स्थिति में पहुँचने में सक्षम हैं

समाधान-केरल सिंचाई और जल संरक्षण अधिनियम, 2003 केरल सिंचाई और जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम,

■ ■

2006 .

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 131 - अंतर-राज्य जल विवाद-मुल्लापेरियार बांध, एक चिनाई बांध, का निर्माण

पेरियार नदी के पार-में थेक्कडी जिले में स्थित बांध

केरल लेकिन तमिलनाडु सरकार द्वारा स्वामित्व और संचालित-मुकदमेबाजी के पहले दौर में, दिनांकित निर्णय के माध्यम से 27-2-2006 , उच्चतम न्यायालय ने जल स्तर की अनुमति दी

मुल्लापेरियार बांध को 142 फीट तक बढ़ाया जाएगा और केरल राज्य और उसके अधिकारियों को किसी भी तरह के नुकसान से रोका जाएगा। उसमें बाधा-हालाँकि, केरल राज्य विधानमंडल द्वारा 2006 के संशोधन अधिनियम के बाद के अधिनियमन के माध्यम से,

बांध का जलाशय स्तर (एफ. आर. एल.) निश्चित और 136 फीट तक सीमित है।

तमिलनाडु राज्य यू/आर्ट द्वारा दायर मुकदमा 131 केरल राज्य के विरुद्ध संविधान-क्या वादी एक के लिए हकदार है

पहले प्रतिवादी को रोकने वाला स्थायी निषेधाज्ञा (राज्य

केरल) 2006 के संशोधन को लागू करने और लागू करने से

मुल्लई पेरियार बांध के संदर्भ में अधिनियम-आयोजित: तथ्यों पर, तमिलनाडु अपने अधिकारों पर उस आक्रमण को स्थापित करने में सक्षम था पर्याप्त-तमिलनाडु अनुदान के लिए एक मामला बनाने में सक्षम है

केरल राज्य तमिलनाडु बनाम द्वारा पारित निषेधाज्ञा-2006 संशोधन अधिनियम।

केरल राज्य 879

मुल्लापेरियार बांध पर अपने अनुप्रयोग और प्रभाव में विधायिका असंवैधानिक-प्रथम प्रतिवादी (केरल राज्य) को स्थायी निषेधाज्ञा के डिक्री द्वारा लागू करने से रोक दिया गया

और विवादित कानून को लागू करना या किसी भी तरह से तमिलनाडु राज्य में हस्तक्षेप करना या उसमें बाधा डालना।

जल स्तर को बढ़ाकर 142 फीट किया जाए। और निष्पादित करने से

तारीख 27-2-2006 के फैसले के अनुसार मरम्मत कार्य-समाधान के लिए

मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा को लेकर केरल की आशंकाएँ एफ. आर. एल. को बहाल करके इसे 142 फुट करने पर।, एक 3-सदस्य पर्यवेक्षी समिति गठित समिति जिसमें एक हो

केंद्रीय जल आयोग के प्रतिनिधि और एक तमिलनाडु के दोनों राज्यों से प्रत्येक प्रतिनिधि और

केरल-केरल सिंचाई और जल संरक्षण अधिनियम, 2003-केरल सिंचाई और जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम,

2006- सूट-निषेधाज्ञा के लिए सूट।

मुकदमे का फैसला सुनाते हुए, अदालत ने

पकड़ना: 1.1 . 1886 के पट्टा समझौते की प्रकृति

इस न्यायालय द्वारा 2006 के फैसले (मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण मंच) में पहले ही राजनीतिक नहीं होने का निष्कर्ष निकाला जा चुका है।

इस न्यायालय ने इसमें अभिनिर्धारित किया है-और कोई न्यायोचित नहीं है

एक अलग दृष्टिकोण लेने का कारण है कि 1886 लीज

समझौता एक साधारण समझौता है जो एक पट्टा समझौता है और यह पूरी तरह से गैर-राजनीतिक प्रकृति का है। वहाँ

केरल का कि 1886 का पट्टा समझौता समाप्त हो गया भारतीय स्वतंत्रता की धारा 7 (1) (बी) का मुख्य प्रावधान

अधिनियम, 1947 जो केवल राजनीतिक संधियों और समझौतों से संबंधित है। अभिव्यक्ति "के शासक द्वारा निंदा की गई भारतीय राज्य "धारा 7 से जुड़े परंतुक में स्पष्ट, स्पष्ट और स्पष्ट रूप से संदर्भित करता है।

निंदा। केरल ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि वहाँ स्पष्ट था त्रावणकोर के शासक द्वारा उस प्रकृति की निंदा

जहाँ तक 1886 के पट्टा समझौते का संबंध है। यह नहीं हो सकता।

कहा जा सकता है कि 18.07.1947 पर जारी किया गया बुलेटिन स्पष्ट रूप से या 880

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

अंततः 1886 के पट्टा समझौते की निंदा की गई। इसके अलावा, की एक वैध और प्रभावी निंदा होने के लिए

शासक और महामहिम के बीच ऐसा समझौता

1947 के अधिनियम के लागू होने के बाद निंदा की जानी चाहिए। मान लीजिए, त्रावणकोर शासक द्वारा 1886 के पट्टा समझौते की कोई निंदा नहीं की गई है।

15.08.1947 . [पैरा 47 से 51] [941-ई-एच;, 915-ए-एफ]

1.2 . डोमिनियन में भारतीय राज्यों का विलय

भारत ने उन राज्यों को संस्थाओं के रूप में समाप्त नहीं किया। वे. केवल घटक के रूप में भारत डोमिनियन का हिस्सा बन गया

पूर्ववर्ती ब्रिटिश भारत के प्रांतों के साथ राज्य।

यह नहीं माना जा सकता है कि भारत अधिराज्य में शामिल होने वाले राज्यों की संस्थाओं का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया था।

तथ्य यह है कि 24.05.1949 पर त्रावणकोर और कोच्चि राज्यों का एक साथ विलय हो गया। यह भी स्थापित करता है कि भारतीय

डोमिनियन में शामिल होने वाले राज्य जारी रहे

इकाइयाँ। उपरोक्त के आलोक में, यह नहीं कहा जा सकता है कि मद्रास 15.08.1947 पर पट्टेदार नहीं रहा। यह प्रासंगिक है

यह देखने के लिए कि केरल ने 1970 में तमिलनाडु के साथ पूरक समझौते किए थे। इनमें पूरक समझौते, 1886 के पट्टे की निरंतरता

लीज समझौते का संचालन बंद हो गया 15.08.1947 , केरल में प्रवेश करने का कोई अवसर नहीं था।

1970 में तमिलनाडु के साथ पूरक समझौते। [पारस

62 , 63] [926 - ए-ई]

1.3 . 1886 से पट्टा समझौता एक सामान्य समझौता है।

समझौता और प्रकृति में राजनीतिक नहीं है, का प्रतिबंध

अनुच्छेद 363 और अनुच्छेद 131 का प्रावधान लागू नहीं होता है। संविधान का अनुच्छेद 131 इस न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। विषय के अधीन

संविधान के प्रावधानों के अनुसार, इस न्यायालय के पास किसी भी विवाद में मूल अधिकार क्षेत्र है, अन्य बातों के साथ-साथ

भारत सरकार और एक तरफ कोई भी राज्य या राज्य और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक अन्य राज्य यदि और जहां तक तमिलनाडु राज्य का संबंध है।

केरल राज्य 881

क्योंकि विवाद में कोई प्रश्न शामिल है (चाहे वह कानून का हो या

तथ्य) जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता है। वहाँ

क्या अनुच्छेद 363 और परंतुक में प्रावधान की समानता है

अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 में निहित मुख्य प्रावधान द्वारा इस न्यायालय को प्रदत्त मूल अधिकार क्षेत्र को राजनीतिक मामलों में परंतुक के आधार पर छोड़ दिया गया है।

बस्तियाँ। अनुच्छेद 363 जैसे प्रावधान करके

और अनुच्छेद 131 के प्रावधान के अनुसार, राजनीतिक समझौतों को न्यायिक घोषणाओं के दायरे से बाहर कर दिया गया है। एक सामान्य समझौते से उत्पन्न विवाद के संबंध में इस न्यायालय की अधिकारिता को नहीं हटाया जाता है। द.

परंतुक में संदर्भित और वर्णित उपकरण केवल हैं

जो राजनीतिक प्रकृति के होते हैं। गैर-राजनीतिक

उपकरण परंतु क द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं। [पैरा 65.2, 68 और 69] [930-बी; 931-एफ; 932-ए, बी, डी-जी]

1.4 . तमिलनाडु राज्य द्वारा दायर किया गया मुकदमा है

संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत बनाए रखने योग्य। द.

महाराजा की सरकार के बीच निष्पादित पट्टा विलेख के तहत दावा किए गए कानूनी अधिकार के आधार पर मुकदमा

त्रावणकोर और परिषद में भारत के राज्य सचिव 29.10.1886 पर संविधान के अनुच्छेद 131 के प्रावधान द्वारा वर्जित नहीं है। केरल राज्य (प्रथम प्रतिवादी)

पूरक को देखते हुए दिनांकित 29.10.1886 समाप्त हो गया है दिनांकित समझौते 28.05.1970। निष्पादित पट्टा विलेख

और 29.10.1886 पर परिषद में भारत के राज्य सचिव पहले प्रतिवादी पर वैध और बाध्यकारी है और यह है

प्रथम प्रतिवादी के विरुद्ध वादी द्वारा प्रवर्तनीय। [पैरा 74] [935 - एच; 936-ए-डी]

2.1 . यह बहुत स्पष्ट है कि एक ओर इस न्यायालय द्वारा सुनवाई पर निर्धारित तथ्य का निष्कर्ष है

प्रस्तुत साक्ष्य/सामग्री के आधार पर पक्षकार

मुल्लापेरियार में इस न्यायालय के फैसले में दर्ज पर्यावरण संरक्षण मंच, [2006 (2) एससीआर 740] और [2014] 12 एससीआर।

882 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दूसरी ओर 2006 (संशोधन) अधिनियम, केरल में

विधायिका ने बांध को लुप्तप्राय घोषित कर दिया है।

केरल राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित एक साथ खड़ा नहीं हो सकता है और वे अपरिवर्तनीय और असंगत हैं। आक्षेपित कानून एक के शून्यीकरण का एक उत्कृष्ट मामला है

निर्णय सरलता से, जैसा कि इस न्यायालय के निर्णय में बांध की सुरक्षा का प्रश्न इस आधार पर निर्धारित किया गया था

इसके समक्ष रखी गई सामग्री और किसी भी मौजूदा कानून की व्याख्या पर नहीं और इसके लिए कोई अवसर नहीं था

आधार में परिवर्तन करके कानून में संशोधन करने के लिए विधायिका

जिसकी आधारशिला निर्णय पर रखी गई थी। जब उलझन होती है

कानून एक सत्यापन कानून नहीं है, विधायिका द्वारा दोष को हटाने का कोई सवाल ही नहीं है, जैसा कि न्यायालय ने नहीं किया है।

मौजूदा कानून में कोई बुराई पाई गई और इस तरह के कानून को खराब घोषित किया। [पैरा 151] [998-ई-एच; 999-ए-बी]

2.2 . एक और पहलू यह है कि संघीय विवादों में,

विधायिका (संसद और राज्य विधानसभाएँ) ऐसा नहीं कर सकतीं।

किसी भी विवाद के मामले में स्वयं न्यायाधीश बनें

दूसरे राज्य के साथ। कानून का शासन जो हमारे संविधान की मूल विशेषता है, संघ और राज्यों को कानून द्वारा, दो राज्यों के बीच विवाद का निर्णय लेने से मना करता है।

दो राज्यों के बीच विवाद पर इस न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है, जिससे निपटने का उसे अधिकार है। किसी एक पक्ष द्वारा अधिनियमित कोई एकतरफा कानून जो

क्योंकि यह रेस जुडिकाटा के सिद्धांतों से प्रभावित है, लेकिन क्योंकि यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। और कानून का शासन, इस तरह के कानून द्वारा, विधायिका स्पष्ट रूप से है

न्यायिक शक्ति को हड़प लिया। [पैरा 152,154] [999-सी, डी; 1000-एफ-जी]

2.3 . रेस जुडिकाटा का नियम केवल तकनीकी नहीं है।

नियम लेकिन यह उच्च सार्वजनिक नीति पर आधारित है।

तमिलनाडु राज्य का नियम v. केरल राज्य 883

सार्वजनिक नीति के एक सिद्धांत को मूर्त रूप देता है, जो बदले में एक है

कानून के शासन का अनिवार्य हिस्सा। रेस जुडिकाटा का नियम

जो सार्वजनिक नीति पर आधारित है, न केवल एक

बाद के मुकदमे में नया निर्णय लेकिन यह भी रोकता है नया शोध। रेस के नियम की प्रयोज्यता के लिए

न्याय, महत्वपूर्ण बात जो देखी जानी चाहिए वह यह है कि

मामला प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक मुद्दे में था

पिछली कार्यवाही और एक निर्णय दिया गया है

उस मुद्दे पर न्यायालय। रेस जुडिकाटा के सिद्धांत हैं -

वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से आकर्षित। मुद्दे पर निर्णय

वास्तव में पिछली कार्यवाही में-ऐसी कार्यवाही

मुकदमा की प्रकृति में नहीं हो सकता है-न्यायपालिका का गठन करता है बाद के सूट में। केरल का दावा पहले

आगे बढ़ते हुए कि जल स्तर को इससे नहीं बढ़ाया जा सकता है 136 फीट का वर्तमान स्तर। स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया था और

केरल द्वारा जल स्तर तक बाधा

मुल्लापेरियार बांध को 142 फीट तक बढ़ाया जा रहा है। जमीन पर

सुरक्षा असमर्थनीय पाई गई। फैसला दिनांकित 27.2.2006 इस न्यायालय का, इस प्रकार, न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है

बांध की सुरक्षा के मुद्दे का सम्मान बढ़ाना इसका जल स्तर 136 फीट है। 142 फीट तक। 2006 का फैसला

अंतिम और बाध्यकारी होने के बाद, मुद्दों में निर्णय लिया गया

उक्त कार्यवाहियाँ निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करती हैं।
 संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर किया गया मुकदमा। [पारस
 156 , 162 , 163 , 164 और 170] [1001-सी; 1003-ए, ई; 1004-बी;
 1007 - सी, डी]

2.5 . इसके अलावा, इस न्यायालय ने ई. सी. को आश्वस्त करने के लिए नियुक्त किया। स्वयं

मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा के बारे में। के निष्कर्ष
 जांच की रिपोर्टों के विस्तृत विश्लेषण के साथ निर्वाचन आयोग,
 परीक्षण और अध्ययन एक ही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं।
 कि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है
 पर पहले की खोज से प्रस्थान की आवश्यकता
 2006 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा
 निर्णय। वास्तव में, इसमें कोई बदलाव नहीं है
 परिस्थितियों में किसी भी भारी परिवर्तन से बहुत कम
 884 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. को उचित ठहराने वाली
 परिस्थितियाँ या आकस्मिक स्थिति।

मुल्लापेरियार बांध के सुरक्षा पहलू को फिर से खोलना जो इस न्यायालय द्वारा पहले के फैसले में निर्धारित किया गया है।

[पैरा 198] [1023-बी-डी]

2.6 . केरल सिंचाई और जल संरक्षण

(संशोधन) अधिनियम, 2006 असंवैधानिक और अधिकार से बाहर है।

मुल्लापेरियार बांध पर इसके अनुप्रयोग और प्रभाव में। तमिलनाडु के अधिकार,
डब्ल्यू. पी. में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 27.2.2006 के निर्णय में स्पष्ट किए गए हैं।
(C) No.386 /

2001 द्वारा बनाए गए कानून द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है

केरल राज्य विधानमंडल। इससे पहले का फैसला

27.2.2006 पर दिया गया न्यायालय पानी बढ़ाने के लिए मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा के
मुद्दे पर न्यायिक कार्य करता है

स्तर 142 फीट तक। और अंत में 152 फीट तक। पूरा होने के बाद

मुल्लापेरियार पर और अधिक मजबूत करने के उपाय

दाम। केरल द्वारा दिनांकित पट्टा विलेख 29.10.1886 और मुल्लापेरियार की संरचनात्मक
सुरक्षा के संबंध में दायर याचिका

बांध को अंततः इस न्यायालय के दिनांक 27.2.2006 के फैसले द्वारा तय किया गया है और
केरल को केरल से अलग कर दिया गया है।

वर्तमान वाद में इन मुद्दों को उठाना या फिर से आंदोलन करना। केरल तमिलनाडु को वृद्धि करने
से नहीं रोक सकता है।

मुल्लापेरियार बांध का जल स्तर 142 फीट तक पहुंच गया है। और दिनांक 27.2.2006 के
निर्णय के अनुसार मरम्मत कार्यों को पूरा करने से। [पैरा 199] [1023-एफ-एच; 1024-ए-डी]

3.1 . पेरियार नदी-बेसिन का स्थलाकृतिक मानचित्र

यह दर्शाता है कि पेरियार बेसिन का हिस्सा (लगभग 114 वर्ग कि. मी.)

और प्रबंधन, कझिकोड, केरल। हालांकि तमिलनाडु में पड़ने वाला पेरियार बेसिन क्षेत्र बहुत
छोटा है, लेकिन इसकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतर-राज्यीय नदी के रूप में
पेरियार नदी का संबंध है। तथ्य यह है कि

बात यह है कि 114 वर्ग कि. मी. किमी. पेरियार बेसिन क्षेत्र का झरना

तमिलनाडु में। यह अग्रिम रिपोर्ट द्वारा भी मजबूत किया जाता है। लोक निर्माण
विभाग, केरल सरकार। [पैरा

206] [1026 - बी-डी] तमिलनाडु राज्य बनाम। केरल राज्य 885

3.2 . केरल के गवाह एम. के. परमेश्वरन नायर ने

स्वीकार किया कि अध्याय एल. एक्स. आई. आई. में शीर्षक के तहत " लोक निर्माण विभाग, सरकार द्वारा प्रकाशित "केरल के जल संसाधन" से अंतरराज्यीय जल "

केरल में 1958 में पेरियार का उल्लेख एक अंतरराज्यीय नदी के रूप में किया गया है। यह गवाह यह भी स्वीकार करता है कि जल एटलस केरल में पेरियार बेसिन का विवरण दिखाया गया है।

बेसिन का वह हिस्सा पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में पड़ता है। [पैरा 207] [1026-ई-एफ]

3.3 . चूंकि केरल ने यह दलील दी है कि पेरियार नदी

यह एक अंतर-राज्यीय नदी है, जाहिर है, इसका बोझ केरल पर है

इस तथ्य को सिद्ध करें। केरल, इस दावे को छोड़कर कि पेरियार नदी

केवल केरल के क्षेत्र में उगता है और गुजरता है।

अरब सागर में प्रवेश करने से पहले और भूमि का कोई हिस्सा नहीं

यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत कि पेरियार नदी एक इंद्रा नदी है राज्य नदी। केरल ने अदालत की संतुष्टि के अनुसार अपना बोझ नहीं उठाया है। [पैरा 208] [1026-जी, एच]

3.4 . यह सच है कि शिकायत में तमिलनाडु का कथन

कि दो राज्य-केरल और तमिलनाडु-नदी तटीय हैं।

राज्य पूरी तरह से सही नहीं हैं क्योंकि तमिलनाडु

एक नदी तटीय राज्य नहीं बल्कि पेरियार नदी की स्थिति अंतर-नदी राज्य के रूप में

राज्य की नदी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह केरल के लिए खुला नहीं है। एक पूरी तरह से असंगत याचिका लेने और नए सिरे से शुरू करने के लिए

गलत आधार। केरल को अनुमति नहीं दी जा सकती है तर्क है कि पेरियार नदी एक अंतर-राज्यीय नदी नहीं है। यह है।

यह माना गया कि केरल को उस नदी का विरोध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है पेरियार एक राज्य के भीतर बहने वाली नदी है। [पैरा 209,210] [1027-ए-सी]

4. वर्तमान विवाद का कोई भी सौहार्दपूर्ण समाधान

दोनों राज्यों के बीच वास्तव में अच्छा होता

इन राज्यों के लोग लेकिन यह संभव नहीं हुआ है

क्योंकि दोनों राज्यों में 886 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. विषय पर तीखा संघर्ष है।

पदार्थ और उनका रुख कठोर, 'अनम्य और कठोर' होता है। केरल ने नए बांध के निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया है। तमिलनाडु द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। नए बांध के निर्माण के लिए समझौता होना चाहिए

दोनों पक्ष। केरल द्वारा दिए गए प्रस्ताव को तमिलनाडु पर थोपा नहीं जा सकता है। हालाँकि, पक्षों को अदालत में आवेदन करने की स्वतंत्रता दी जाती है यदि वे सक्षम हैं

निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाए गए दो विकल्पों में से किसी एक पर कुछ सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त करें। [पैरा 212,213 और 215] [1029 - बी, सी, ई; 1032-सी]

5.1 . जहाँ तक 1979 से पहले की अवधि में पानी की निकासी का संबंध है और

1979 के बाद की अवधि का संबंध है, तमिल का एकमात्र गवाह

नाडु ने स्वीकार किया है कि 1979 के बाद की अवधि में 21,434 एम. सी. एफ. टी. पानी खींचा गया था। और औसत पानी पहले से खींचा गया 1979 अवधि 19,277 एम. सी. एफ. टी. थी। इसी तरह, उन्होंने स्वीकार किया है

सिंचाई 1979 से पहले 1,71,307 एकड़ से 1992-93 में 2,31,412 एकड़ तक बढ़ी, लेकिन, जैसा कि चुनाव आयोग ने देखा है, यह

यह 1954 में वैगई बांध के निर्माण और 1974 के बाद संबंधित नहर वितरण प्रणाली के कारण हुआ है। उन पाँचों

पेरियार परियोजना द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले रामनाथनपुरम सूखे की चपेट में हैं। इन पाँच क्षेत्रों में लगभग 2 लाख एकड़ भूमि आती है। जिन जिलों की सिंचाई की आवश्यकता है। अपर्याप्त

इन जिलों की आबादी को सिंचाई और पीने के उद्देश्यों के लिए समय पर पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

उनके जीवन के साथ-साथ आजीविका भी। सिंचाई में वृद्धि

और 1979 के बाद पानी की अधिक निकासी अभी भी प्रतीत होती है

इन जिलों में 80 लाख से अधिक लोगों की आबादी की कमी है। इन तथ्यों में, इसलिए, यह सुरक्षित रूप से हो सकता है कहा जा सकता है कि तमिलनाडु यह स्थापित करने में सक्षम रहा है कि उसके अधिकारों पर आक्रमण पर्याप्त है। तमिलनाडु निषेधाज्ञा देने के लिए एक मामला बनाने में सक्षम रहा है। [पैरा 219,

220] [1034 - ए-ई]

5.2 . यह घोषित किया जाता है कि केरल सिंचाई और जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 तमिलनाडु राज्य द्वारा पारित किया गया v:

केरल राज्य 887

केरल विधानमंडल अपने आवेदन में असंवैधानिक है

तमिलनाडु राज्य में जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाने में बाधा डालना। , और मरम्मत करने से इस न्यायालय के दिनांक 27.2.2006 के निर्णय के अनुसार कार्य करता है

डब्ल्यू. पी. में (ग) न. 386/2001 संबंधित मामलों के साथ। [पैरा 221] [1034-जी, एच; 1035-ए]

5.3 . हालांकि, केरल की आशंकाओं को दूर करने के लिए

हालांकि कोई मौजूद नहीं है-मुल्लापेरियार की सुरक्षा के बारे में

एफ. आर. एल. के पुनर्स्थापन पर बांध को 142 फीट तक पहुँचाया गया।, 3 सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का गठन किया जाता है। समिति ने केंद्रीय जल से एक प्रतिनिधि होगा

राज्य-तमिलनाडु और केरल। के प्रतिनिधि केंद्रीय जल आयोग इस समिति का अध्यक्ष होगा। [पैरा 222] [1035-बी-डी]

डॉ. बाबू राम सक्सेना बनाम राज्य आकाशवाणी 1950 एस. सी. 155: 1950

एस. सी. आर. 573; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ और अन्य। (2011) 13 एससीसी 344: 2011 (11) एस. सी. आर. 527; ठाकुर जगन्नाथ बख्श सिंह बनाम। संयुक्त प्रांत [73 IA 123] और

महाराज उमेग सिंह और अन्य। वी. बॉम्बे राज्य और ओआरएस। (1955) 2 एससीआर 164-प्रतिष्ठित।

रूपा अशोक हुरा बनाम। अशोक हुरा और अन्र। (2002) 4 एससीसी 388: 2002 (2) एस. सी. आर. 1006 लागू नहीं होता।

मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण मंच बनाम। संघ

भारत और ओआरएस। (2006) 3 एससीसी 643: 2006 (2) एस. सी. आर. 740; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2013) 5

एस. सी. सी. 68; विरेन्द्र सिंह और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश राज्य

(1955) 1 एस. सी. आर. 415; श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड और अन्र। वी.

बरोच बरो नगरपालिका और ओआरएस। (1969) 2 एससीसी 283: 1970 (1) एस. सी. आर. 388; इंदर साहनी बनाम।

भारत संघ और 888 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2014]

12 एस सी आर।

अन्य (2000) 1 एस. सी. सी. 168: 1999 (5) पूरक। एससीआर 229; मदन

मोहन पाठक और अन्र। वी. भारत संघ और अन्य (1978) 2 एस. सी. सी. 50: 1978 (3) एस. सी. आर. 334; पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल

लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और एएनआर। ; (2003) 4 एससीसी 399: 2003 (2) एस. सी. आर. 1136; नगर निगम

अहमदाबाद और अन्र का शहर। वी. न्यू श्रॉक एस. पी. जी. और डब्ल्यूवीजी। कं. लिमिटेड (1970) 2 एस. सी. सी. 280: 1971 (1) एस. सी. आर. 288; जनपद सभा छिंदवाड़ा बनाम। सेंद्रल प्रोविंस सिंडिकेट लिमिटेड और

एन. आर. (1970) 1 एससीसी 509: 1970 (3) एस. सी. आर. 745; कावेरी जल

पूरक। एस. सी. आर. 497; भारत संघ बनाम। एल्फिंस्टन स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। (2001) 4 एससीसी 139: 2001 (1) एससीआर 221 ; संजीव कोक मैनुफैक्चरिंग कंपनी। एम/एस। भारत कोकिंग

कोल लिमिटेड और ए. एन. आर. (1983) 1 एससीसी 147: 1983 (1) एससीआर 1000; एम/एस। डॉयपैक सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड वी. भारत संघ और ओआरएस।

(1988) 2 एससीसी 299: 1988 (2) एस. सी. आर. 962; महल चंद सेठिया

वी. पश्चिम बंगाल राज्य 1969 (2) यूजे 616 एससी; पटेल गोरधनदास हरगोविंदास बनाम। नगर निगम आयुक्त,

अहमदाबाद (1964) 2 एससीआर 608; एम. पी. बनाम राज्य

समामेलित कोलफील्ड्स लिमिटेड और ए. एन. आर. (1970) 1 एससीसी 509: 1970 (3) एस. सी. आर. 745; पी. संबमूर्ति और अन्य। वी. एपी का राज्य

और एन. आर. (1987) 1 एससीसी 362: 1987 (1) एस. सी. आर. 879; संघ

भारत बनाम. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड एन. आर. (2002)

एससीसी 225: 1973 पूरक। एस. सी. आर. 1; श्रीमती. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण और अन्र। 1975 (सप.) एससीसी 1: 1976 एससीआर 347 ; बिहार और अन्र राज्य। वी. बाल मुकुंद साह और अन्य (2000) 4 एससीसी 640: 2000 (2) एससीआर 299; आई. आर. कोएल्हो (मृत)

एलआर द्वारा। वी. टी. एन. राज्य (2007) 2 एस. सी. सी. 1: 2007 (1) एससीआर 706; आई. एन. सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1976) 4 एससीसी 750:

1976 (3) एस. सी. आर. 237; हरि सिंह और अन्य। वी. सैन्य संपदा अधिकारी और ए.
एन. आर. (1972) 2 एससीसी 239: 1973 (1) एस. सी. आर. 515;

हिंदुस्तान गम एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और

अन्य (1985) 4 एस. सी. सी. 124: 1985 (2) पूरक। एससीआर 630; विजय

मिल्स कम्पनी लिमिटेड और अन्य बनाम।

गुजरात राज्य और तमिलनाडु राज्य बनाम। केरल राज्य 889

ओआरएस। (1993) 1 एससीसी 345: 1992 (3) पूरक। एससीआर 324; पी।

कन्नदासन और अन्य बनाम। टी. एन. और अन्य राज्य (1996) 5

एससीसी 670: 1996 (4) पूरक। एस. सी. आर. 92; भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी और
अन्य बनाम। केरल राज्य और अन्य; (1996) 7

एससीसी 637: 1996 (2) एससीआर 23; राज्य टी. एन. वी. अरुन शक्कर

लिमिटेड (1997) 1 एससीसी 326: 1996 (8) पूरक। एस. सी. आर. 193; धरम दत्त और
अन्य। वी. भारत संघ और ओआरएस। (2004) 1 एससीसी 712:

2003 (6) पूरक। एस. सी. आर. 151; श्री श्री के. सी. गजपति नारायण

देव वी. उड़ीसा राज्य ए. आई. आर 1953 एस. सी. 375: 1954 एस. सी. आर 1; बोर्ड
आयुर्वेदिक और यूनानी टिबिया महाविद्यालय, दिल्ली बनाम।

एससी 458: 1962 पूरक। एस. सी. आर. 156; विरेन्द्र सिंह हुड्डा (द्वितीय)
और ओआरएस। वी. हरियाणा राज्य और एक अन्य (2004) 12 एस. सी. सी. 588: 2004
(5) पूरक। एस. सी. आर. 720; विरेन्द्र सिंह हुड्डा (आई) और अन्य।

वी. हरियाणा राज्य और एक अन्य (1999) 3 एस. सी. सी. 696; संदीप

सिंह बनाम। हरियाणा और अन्र राज्य। (2002) 10 एससीसी 549; तीरथ

राम राजिंदर नाथ, लखनऊ बनाम। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य। (1973) 3 एस.
सी. सी. 585; एस. एस. बोला और अन्य। वी. बी. डी. सरदाना और अन्य।

(1997) 8 एससीसी 522: 1997 (2) पूरक। एस. सी. आर. 507; श्योपरसन सिंह बनाम। रामनंदन प्रसाद नारायण सिंह ए. आई. आर 1916 पी. सी

78 ; दरियाव और ओआरएस। वी. यू. पी. और अन्य राज्य। ए. आई. आर. 1961 एससी

1457 : 1962 एससीआर 574; पंडित एम. एस. एम. शर्मा बनाम डॉ. श्री

कृष्ण सिन्हा और ओआरएस। ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1186; गुलाब चंद

भारत संघ बनाम। नानक सिंह (1968) 2 एससीआर 887: आकाशवाणी 1968 एससी 1370; पंजाब राज्य बनाम। बुआ दास कौशल (1970) 3 एससीसी

656 ; एन. डी. जयाल और अनुर। वी. भारत संघ और ओआरएस। (2004) 9 एससीसी 362: 2003 (3) पूरक। एससीआर 152; उड़ीसा राज्य बनाम ए. पी. राज्य (2006) 9 एस. सी. सी. 591; आर. नायक बनाम. ए. आर. अंतुले (1984)

2 एससीसी 183: 1984 (2) एस. सी. आर. 495 और इसाबेला जॉनसन (श्रीमती)

‘ वी. एल. आर. एस. द्वारा एम. ए. सुसाई (मृत)। (1991) 1 एससीसी 494: 1990 (2) पूरक। एस. सी. आर. 212-संदर्भित।

डॉन जॉन फ्रांसिस डगलस लियानेज एंड ओआरएस। वी. रानी।

(1966) 1 सभी ई. आर. 650; आर्थर एम. मैनिगॉल्ट बनाम अल्फ्रेड ए।

स्प्रिंग्स एट अल (1905) 199 यू. एस. 473; ब्रदरहुड ऑफ लोकोमोटिव

फायरमैन और इंजनमैन आदि। वी.

शिकागो, रॉक आइलैंड एंड पैसिफिक 890 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

रेल-रोड कंपनी और अन्य (1968) 393 यू. एस. 129; रेमंड मोटर

परिवहन, इंक. आदि। वी. जेल एस. राइस और अन्य (1978) 434 यूएस

429 ; अमेरिकन ट्रकिंग एसोसिएशन, इंक. बनाम। थॉमस डी. लार्सन (1982) 683 एफ. 2 डी 787; फाइजर एनिमल हेल्थ एसए बनाम। यूरोपीय संघ की परिषद (2002) ईसीआर II-03305;

पेन्सिलवेनिया राज्य बनाम। द व्हीलिंग एंड बेलमोंट ब्रिज

(1870) 77 यूएस 454; होजेस एट अल। वी. स्नाइडर एट अल। (1923) 261
यूएस 600; चार्ल्स बी. मिलर, अधीक्षक, पेंडलटन

सुधार सुविधा आदि। वी. रिचर्ड ए. फ्रेंच और अन्य। (2000)

530 यू. एस. 327; निकोलस बनाम। रानी (1998) 193 सी. एल. आर. 173;
प्लॉट एट अल। वी. स्पेंडथ्रिफ्ट फार्म, इंक., आदि। (1995) 514 अमेरिका.

211 ; रेजिना वी। उप औद्योगिक चोट आयुक्त, पूर्व

पार्ट जोन्स (1962) 2 क्यू. बी. 677 और डचेस ऑफ किंगस्टन 2 स्मिथ लीड कैस 13 एड। -
संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ:

संदर्भित किया गया है

पैरा 1

2006 (2) एससीआर 740

(2013) 5 एससीसी 68

संदर्भित किया गया है

पैरा 38

पैरा 57

1950 एससीआर 573

प्रतिष्ठित

पैरा 57

प्रतिष्ठित

2011 (11) एससीआर 527

(1955) 1 एससीआर 415।

संदर्भित किया गया है

पैरा 65।

संदर्भित किया गया है

पैरा 77

1970 (1) एससीआर-388

(1966) 1 सभी ई. आर. 650

संदर्भित किया गया है

पैरा 77

1999 (5) पूरक। एस. सी. आर. 229 संदर्भित

पैरा 82

पैरा 83

संदर्भित किया गया है

1978 (3) एससीआर 334

संदर्भित किया गया है

2003 (2) एससीआर 1136

पैरा 83

संदर्भित किया गया है

1971 (1) एससीआर 288

पैरा 83

संदर्भित किया गया है

पैरा 83

1970 (3) एससीआर 745 बी.

केरल राज्य 8

संदर्भित किया गया है

पैरा 84

प्रतिष्ठित

पैरा 86

प्रतिष्ठित

पैरा 86

संदर्भित किया गया है

पैरा 86

संदर्भित किया गया है

पैरा 87

संदर्भित किया गया है

पैरा 87

संदर्भित किया गया है

पैरा 87

संदर्भित किया गया है

पैरा 87

संदर्भित किया गया है

पैरा 91

संदर्भित किया गया है

पैरा 91

संदर्भित किया गया है

पैरा 91

संदर्भित किया गया है

पैरा 91

संदर्भित किया गया है

पैरा 92

संदर्भित किया गया है

पैरा 92

संदर्भित किया गया है

पैरा 92

संदर्भित किया गया है

पैरा 94

संदर्भित किया गया है

पैरा 95

संदर्भित किया गया है

पैरा 97

संदर्भित किया गया है

पैरा 99

संदर्भित किया गया है

पैरा 101

संदर्भित किया गया है

पैरा 102

संदर्भित किया गया है

पैरा 102

संदर्भित किया गया है

पैरा 102 92 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

[2014]

12

2007 (1) एससीआर 706

संदर्भित किया गया है

पैरा

1976 (3) एससीआर 237

पैरा

संदर्भित किया गया है

1973 (1) एससीआर 515

पैरा

संदर्भित किया गया है

1985 (2) पूरक। एससीआर 630

संदर्भित किया गया है

पैरा

1992 (3) पूरक। एससीआर 324

संदर्भित किया गया है

पैरा

1996 (4) पूरक। एससीआर 92

पैरा

संदर्भित किया गया है

1996 (2) एससीआर 23

संदर्भित किया गया है

पैरा

1996 (8) पूरक। एससीआर 193

संदर्भित किया गया है

पैरा

2003 (6) पूरक। एससीआर 151

संदर्भित किया गया है

पैरा

1954 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

1962 पूरक। एससीआर 156

	संदर्भित किया गया है	पैरा
2004 (5) पूरक। एससीआर 720		
		पैरा
(1999) 3 एस. सी. सी. 696	संदर्भित किया गया है	
	संदर्भित किया गया है	
(2002) 10 एस. सी. सी. 549		पैरा
	संदर्भित किया गया है	
(1973) 3 एस. सी. सी. 585		पैरा
	संदर्भित किया गया है	
1997 (2) पूरक। एससीआर 507		
	संदर्भित किया गया है	
(1998) 193 सीएलआर 173		पैरा
	संदर्भित किया गया है	
(1995) 514 अमेरिका 211		पैरा

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर 1916 पी. सी. 78

संदर्भित किया गया है

पैरा

1962 एससीआर 574

संदर्भित किया गया है

पैरा

पैरा

1960 एससी 1186

संदर्भित किया गया है

(1965) 2 एससीआर 547

संदर्भित किया गया है

पैरा

पैरा

1968 एससीआर 887

· तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 893

(1970) 3 एस. सी. सी. 656

संदर्भित किया गया है

पैरा 162

2003 (3) पूरक।एस. सी. आर. 152 संदर्भित

पैरा 165

(2006) 9 एस. सी. सी. 591

संदर्भित किया गया है

पैरा 176

पैरा 178

संदर्भित किया गया है

1984 (2) एससीआर 495

1990 (2) पूरक।एस. सी. आर. 212 को संदर्भित किया गया है

पैरा 178

2002 (2) एससीआर 1006

आयोजित किया गया

पैरा 178

अप्रयोज्य

(1962) 2 क्यूबी 677

पैरा 196

संदर्भित किया गया है

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: अनुच्छेद 131 के तहत

आई.

भारत का संविधान।

2006 का मूल सूट नंबर 3।

सुब्रमण्यम प्रसाद, एजी।, मोहन जैन, एएसजी।, विनोद

अरविंद बोबडे, डॉ. राजीव धवन, जी. उमापति, बी. बालाजी, आर.

मोहन वी. कटारकी, रमेश बाबू एम. आर., मुक्ति चौधरी, स्वाति सेतिया, दीपक मल्होत्रा,
एस. एस. रावत, विष्णु शंकर (डी. एस. के लिए) माहरा) उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय और आदेश इसके द्वारा दिया गया था

आर. एम. लोधा, सीजेआई। 1. यह न्यायालय अभी भी जब्त है

मुल्लापेरियार बांध के जल स्तर के संबंध में समस्या

इसे 27.02.2006 (मुल्लापेरियार पर्यावरण) पर हल किया गया था।

संरक्षण मंच 1) क्योंकि केरल राज्य विधानमंडल

इसके तुरंत बाद पूर्ण निर्धारण और सीमित करने के लिए कानून बनाया गया जलाशय का
स्तर (एफ. आर. एल.) 136 फुट तक।

मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण मंच बनाम। भारत संघ और अन्य।;

1 .

[(2006) 3 एस. सी. सी. 643] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12

एस. सी. आर.

894

मुल्लापेरियार बांध: 1886 लीज समझौता 2. मुल्लापेरियार बांध-एक चिनाई बांध-का
निर्माण दिनांकित पेरियार झील पट्टा समझौते के अनुसार किया गया था।

29.10.1886 (1886 लीज समझौता ") पेरियार नदी के पार। निर्माण लगभग आठ वर्षों तक
जारी रहा और था

1895 में पूरा हुआ। यह बांध थेक्कडी जिले में स्थित है। केरल में है और इसका स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है

तमिलनाडु। 1886 के पट्टा समझौते के अनुसार

त्रावणकोर के महाराजा और भारत के राज्य सचिव परिषद, उसमें निर्धारित पट्टे पर दिया गया क्षेत्र

01.01.1886 से 999 वर्षों के लिए पट्टा। मुख्य की लंबाई बांध 1200 फीट का है। (365.76) और बांध का शीर्ष 155 फीट है। (47.24

एम.) . ठोस पैरापेट का शीर्ष और सबसे गहरी नींव से बांध की अधिकतम ऊंचाई 158 फीट है। (48.16 मी.) और 176 फीट। (53.64), क्रमशः। बांध का एफआरएल 152 फीट है। (46.33

एम.) . बांध की मूल स्पिलवे क्षमता 10 वेंट्स की थी।

36 ' x 16 '(10.97 m. x 4.88 m.)। बेबी बांध की लंबाई 240 फीट है। (73.15 एम.)।

1

1979-1980 : बांध की सुरक्षा को लेकर विवाद

3. 1979 में मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा के संबंध में,

केरल सरकार ने तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखा

बांध को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाना।

इसके साथ ही केरल सरकार ने भी अनुरोध किया कि

केंद्र सरकार केंद्रीय जल से एक दल भेजेगी

आयोग (सी. डब्ल्यू. सी.) बांध का निरीक्षण करेगा और सुझाव देगा

सुदृढ़ीकरण के उपाय।

4. केरल सरकार के अनुरोध के अनुसरण में,

सी. डब्ल्यू. सी. के तत्कालीन अध्यक्ष ने बांध का निरीक्षण किया और 25.11.1979 पर एक बैठक की जिसमें तमिलनाडु के अधिकारी शामिल हुए

और केरल ने भाग लिया। उस बैठक में, बांध को मजबूत करने के लिए तीन स्तरीय उपायों, (i) आपातकालीन, (ii) मध्यम और (iii) दीर्घकालिक, का सुझाव दिया गया था। इस बीच, यह सिफारिश की गई थी

कि जलाशय में जल स्तर 136 फुट पर रखा जाए। (41.45 एम.)

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 895

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

5. 29.04.1980 पर आयोजित दूसरी बैठक में, यह था

उन्होंने कहा कि आपातकालीन और मध्यम अवधि के सुदृढीकरण उपायों के पूरा होने के बाद, जलाशय में जल स्तर को 145 फीट तक बहाल किया जा सकता है। (44.2 एम.)।

1998 : मुकदमा शुरू

6. तमिलनाडु का कहना है कि सभी उपाय-आपातकाल,

सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा सुझाए गए मध्यम और दीर्घकालिक

दोनों राज्य सरकारों (तमिलनाडु की) के बीच समझौता और केरल) मुल्लापेरियार जलाशय में जल स्तर बढ़ाने के लिए

136 फीट से अधिक। इसके कारण कई रिट याचिकाएं दायर की गईं। केरल उच्च न्यायालय के साथ-साथ मद्रास उच्च न्यायालय में

1998 में मुल्लापेरियार जलाशय में जल स्तर बढ़ाने और बांध की सुरक्षा के पक्ष और विपक्ष के मुद्दे पर। चूंकि विवाद दो उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित था और

परस्पर विरोधी निर्णयों की संभावना थी, इस न्यायालय के समक्ष कुछ स्थानांतरण याचिकाएं दायर की गई थीं।

7. 28.04.2000 पर, स्थानांतरण याचिकाओं में, इस न्यायालय ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से एक बैठक बुलाने की इच्छा व्यक्त की केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की बैठक

सौहार्दपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान करें। यह बैठक आयोजित की गई थी

19.05.2000 लेकिन बैठक में कोई सहमति नहीं बन सकी।

साथ ही। लेकिन उस बैठक में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया

बांध की सुरक्षा के विवरण में और उसे सलाह दें जलाशय में जल स्तर को बढ़ाना।

8. 14.06.2000 पर, विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नलिखित संदर्भ शर्तों के साथ किया गया था।

" (क) मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए

केरल में पेरियार नदी के सुदृढ़ीकरण के संबंध में

तमिलनाडु सरकार द्वारा बनाया गया बांध

सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा सुझाए गए सुदृढ़ीकरण उपायों के अनुसार और माननीय जल मंत्री को 896 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट/सलाह देना।

[2014]

12 एस सी आर।

बांध की सुरक्षा पर संसाधन।

(ख) माननीय जल संसाधन मंत्री को सलाह देना।

मुल्लापेरियार जलाशय में जल स्तर को 136 फीट से अधिक बढ़ाने के संबंध में।

(41.45 एम) के सुदृढ़ीकरण के परिणामस्वरूप ऊपर (क) के अनुसार बांध और इसकी सुरक्षा। ”

9. प्रारंभिक प्रतिरोध के बाद, केरल सरकार

विशेषज्ञ समिति में एक सदस्य को नामित किया गया।

10. विशेषज्ञ समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दी

16.03.2001 . जबकि यह मामला विशेषज्ञ समिति द्वारा विचाराधीन था, इसने कुछ अंतरिम निर्देश भी दिए। इसमें

रिपोर्ट, विशेषज्ञ समिति ने राय दी थी कि जल स्तर में

मुल्लापेरियार जलाशय को 142 फीट तक बढ़ाया जा सकता है। (43.28 एम.) के रूप में

यह मुख्य बांध की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा, जिसमें स्पिलवे, बेबी डैम और मिट्टी का बांध शामिल हैं।

इस न्यायालय के समक्ष पहला मुकदमा

11. विशेषज्ञ समिति की उपरोक्त सिफारिशों के बावजूद केरल सरकार ने विरोध करना जारी रखा जलाशय में जल स्तर को 136 फीट से अधिक बढ़ाना। यह तब था

कि मुल्लापेरियार पर्यावरण द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी

इस न्यायालय के समक्ष सीधे संरक्षण मंच जिसमें विविध प्रार्थनाएँ की गईं। इस अदालत ने रिट को भी स्थानांतरित कर दिया केरल उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाएँ और

मद्रास उच्च न्यायालय से इस न्यायालय तक।

12. दोनों राज्यों सहित पक्षों को सुनने के बाद, यह

अदालत ने जल स्तर की अनुमति देने के लिए 27.02.2006 पर अपना फैसला दिया मुल्लापेरियार बांध को 142 फीट तक बढ़ाया जाएगा। केरल राज्य और उसके अधिकारियों को भी किसी भी घटना को अंजाम देने से रोक दिया गया था।

उपरोक्त में बाधा। यह भी देखा गया कि सी. डब्ल्यू. सी. की संतुष्टि के लिए सुदृढ़ीकरण कार्य पूरा होने के बाद,

स्वतंत्र विशेषज्ञ इससे पहले सुरक्षा कोण की जांच करेंगे

जल स्तर को 152 फीट तक बढ़ाने की अनुमति है।

' तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 897

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

2003 अधिनियम

13. केरल सिंचाई और जल संरक्षण अधिनियम, 2003

संक्षेप में, "2003 अधिनियम") केरल विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था, जो 18.09.2003 पर लागू हुआ था। 2003 अधिनियम बनाया गया था

निर्माण से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना सिंचाई कार्य, सिंचाई के उद्देश्य से जल का संरक्षण और वितरण और बेहतरी, योगदान और

राज्य में सिंचाई कार्यों से लाभान्वित भूमि पर जल उपकर

केरल सरकार और पानी में किसानों की भागीदारी का प्रावधान करना।

उपयोग प्रणाली और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए। 2003 अधिनियम को न तो संदर्भित किया गया था और न ही भरोसा किया गया था

मुल्लापेरियार में सुनवाई के समय केरल द्वारा

पर्यावरण संरक्षण मंच 1. 2006 (संशोधन) अधिनियम

14. 18.03.2006 पर, निर्णय के तीन सप्ताह से भी कम समय में

मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण मंच 1 में, केरल राज्य विधानमंडल ने केरल सिंचाई और जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 [संक्षेप में, "2006 (संशोधन) अधिनियम"] द्वारा 2003 के अधिनियम में संशोधन किया।

2006 (संशोधन) अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

2 .

आई. धारा 2 में खंड (जे. ए.) 'संरक्षक' को राज्य सरकार के रूप में परिभाषित करता है।

जिसने किसी बांध को स्थापित किया है या चला रहा है या अन्यथा संचालित कर रहा है

केरल। इसके अलावा, खंड (अला) 'अनुसूचित बांध' को दूसरी अनुसूची में शामिल किसी भी बांध के लिए परिभाषित करता है। दूसरे में पहली प्रविष्टि

अनुसूची मुल्लई पेरियार बांध है।

ii. धारा 57 (1) में "निगरानी, निरीक्षण" शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है -

" सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना "

iii. मुख्य अध्याय XII में 57 (3) का परिचय-'बांध सुरक्षा का संविधान'

किसी अन्य विधि के होते हुए भी बारहवें अध्याय को प्रभावी बनाने का प्राधिकरण।

iv. मौजूदा धारा 62 (1) (ए) से (आई) को नई धारा 62 (1) (ए) से (जे) द्वारा प्रतिस्थापित करना। नव प्रतिस्थापित धारा 62 (1), जहाँ तक सामग्री है, इस प्रकार है:

62 (1) किसी अन्य कानून, निर्णय में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश या किसी संधि, समझौते, अनुबंध, लिखत में

या अन्य दस्तावेज, प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा अर्थात्:

(क) (ख) (ग) XXX 898 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

15. दूसरी अनुसूची में, 2006 में जोड़ा गया

(संशोधन) अधिनियम, मुल्लापेरियार बांध का स्वामित्व और रखरखाव

तमिलनाडु द्वारा वस्तु संख्या 1 के रूप में शामिल किया गया है जहाँ की ऊँचाई

एफआरएल को 136 फीट पर तय किया गया है।

इस न्यायालय के समक्ष दूसरा मुकदमा: तमिलनाडु द्वारा सूट

16. इसके तुरंत बाद तमिलनाडु राज्य

संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत वर्तमान मुकदमा दायर किया गया

केरल राज्य के खिलाफ भारत का। इसका विस्तार करना आवश्यक है। कुछ हद तक तथ्यों पर क्योंकि कार्यवाही मुकदमे की प्रकृति में होती है

इस न्यायालय की मूल अधिकारिता। शिकायत में कहा गया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के लागू होने पर (संक्षेप में,

" एस. आर. अधिनियम "), त्रावणकोर राज्य-कोच्चि (भाग-बी, राज्य) का गठन किया गया। केरल राज्य (प्रथम प्रतिवादी) है

त्रावणकोर राज्य के हित में उत्तराधिकारी-कोच्चि। द. परिषद में राज्यपाल, भारत के राज्य सचिव के हित में तमिलनाडु राज्य उत्तराधिकारी है। तमिलनाडु ने इस प्रकार,

निवेदन किया कि वादी और पहला प्रतिवादी में उत्तराधिकारी हैं
संविदाकारी पक्षों का हित

1886 लीज के मूल

समझौता।

(घ) संरक्षकों को किसी भी बांध में कोई बदलाव, सुधार, प्रतिस्थापन या सुदृढीकरण
उपाय करने का निर्देश देना।

मानव जीवन या संपत्ति के लिए;

(ई) संरक्षक को किसी भी बांध के कामकाज को निलंबित करने, किसी भी बांध को बंद
करने या सार्वजनिक होने पर किसी भी बांध के काम को प्रतिबंधित करने का निर्देश देना।

मानव जीवन या संपत्ति के लिए सुरक्षा या खतरा, इसलिए आवश्यक है;

(च) स्थल की जांच, डिजाइन, निर्माण में अपनाई जाने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं
के बारे में सरकार, संरक्षक या अन्य एजेंसियों को सलाह देना,

बांधों का संचालन और रखरखाव;

(छ) किसी भी बांध के अधिकतम जल स्तर या पूर्ण जलाशय स्तर को बढ़ाने या कम करने की
सलाह पर संरक्षक या किसी अन्य एजेंसी को अध्ययन, निरीक्षण और सलाह देना, जो एक
अनुसूचित बांध नहीं है।

संबंधित बांध की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए;

(ज) किसी भी बांध के अनुसूचित बांध न होने की स्थिरता या उपयुक्तता पर संरक्षक या
किसी भी एजेंसी को अध्ययन करना, निरीक्षण करना और सलाह देना, उसके जलाशय में पानी
रखना, अंतर्राष्ट्रीय, प्रतिष्ठित विशेषज्ञ की राय प्राप्त करना, और बांध-तोड़ विश्लेषण और
स्वतंत्र अध्ययन द्वारा सलाह देना और सुदृढीकरण उपायों को निर्देशित करना या उसके भीतर एक
नए बांध को चालू करने की आवश्यकता है।

मौजूदा बांध को बदलने के लिए निर्धारित की जाने वाली समय सीमा; "स्टेट ऑफ़
तमिल नाडु v.

केरल राज्य 899

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

17. तमिलनाडु का कहना है कि 29.05.1970 पर उसके और तमिलनाडु के बीच दो पूरक समझौते किए गए थे।

केरल। दो पूरक समझौतों ने नहीं बदला

1886 के पट्टा समझौते का मूल चरित्र। सबसे पहले पूरक समझौते के अनुसार, तमिलनाडु ने मछली पकड़ने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया

तमिलनाडु को प्रदत्त समझौता, उत्पन्न करने का अधिकार बिजली और बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं के निर्माण का अधिकार। 42. 7 एकड़ का अतिरिक्त क्षेत्र पट्टे पर दिया गया था।

उक्त उद्देश्यों के लिए तमिलनाडु और तदनुसार तमिल

समझौते में निर्दिष्ट राशि के अनुसार, तमिलनाडु को केरल को सालाना भुगतान करना पड़ता था। तमिलनाडु का दावा है कि दोनों

पूरक समझौतों की पुनः पुष्टि की गई है, पुनः पुष्टि की गई है और

1886 के पट्टा समझौते की पुष्टि की गई, जिसे एस. आर. अधिनियम की धारा 108 द्वारा वैधानिक रूप से संरक्षित और जारी रखा गया था। 2006 (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने के आधार

18. 2006 (संशोधन) अधिनियम को इस हद तक चुनौती

यह मुल्लापेरियार बांध को प्रभावित करता है जो विभिन्न पर शिकायत में रखा गया है आधार, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

(क) विवादित कानून हड़पने के बराबर है -

न्यायिक शक्ति केरल राज्य विधानमंडल के पास है

एक न्यायिक निकाय की भूमिका पर खुद को अभिभूत किया और स्वयं बांध की सुरक्षा और उठाने के बारे में प्रश्नों को निर्धारित किया है

जल स्तर जब ऐसे प्रश्न विशेष रूप से इसके भीतर आते हैं

न्यायपालिका का प्रांत और पहले से ही निर्धारित किया गया है इस न्यायालय ने अपने दिनांकित 27.02.2006 निर्णय में।

(ख) 2006 का संशोधन अधिनियम विधायी व्यवस्था से परे है।

एस. आर. अधिनियम की धारा 108 को ध्यान में रखते हुए मुल्लापेरियार बांध को प्रभावित करने के लिए केरल राज्य की क्षमता

संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत संसद द्वारा बनाया गया एक कानून है, जो सभी को पार करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है।

प्रविष्टि 17 सूची II सहित तीनों सूचियों में विधायी प्रविष्टियाँ।

[2014]

12 एस सी आर।

900 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ग) विवादित विधान, अपने अनुप्रयोग में

इस न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा के बाद। केरल में इस न्यायालय के समक्ष न्यायिक प्रक्रिया में भाग लिया

अपने मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकते हैं और इस न्यायालय के फैसले को उलटने की कोशिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह इसके खिलाफ गया है।

(घ) विवादित कानून न केवल तय करता है और सीमित करता है

एफआरएल से 136 फीट तक। इस न्यायालय के फैसले के सीधे उल्लंघन में लेकिन बांध सुरक्षा प्राधिकरण को अधिकृत करने के लिए भी आगे बढ़ता है केरल का-इस न्यायालय के फैसले की अवज्ञा और अवहेलना करना

निम्नलिखित द्वारा, अन्य प्रावधानों के साथ:

धारा 62 (1) (ई) प्राधिकरण को निर्देश देने का अधिकार देती है।

के कार्य का निलंबन या प्रतिबंध

कोई बांध या विघटन।

धारा 62 ए (1) को दूसरी अनुसूची के साथ पढ़ा जाता है। एक विधायी निर्णय कि मुल्लापेरियार बांध है

इसकी उम्र, क्षरण के कारण लुप्तप्राय,
संरचनात्मक या अन्य बाधाएँ और पानी को सीमित करती हैं।

स्तर 136 फीट तक।

उप-धारा (2) दूसरी अनुसूची में निर्धारित जल स्तर में वृद्धि को
प्रतिबंधित करती है।
किसी भी न्यायालय या किसी अन्य कानून या किसी संधि, अनुबंध, समझौते, साधन का निर्णय,
डिक्री या आदेश

या दस्तावेज़ को छोड़कर और उसके अनुसार

इस उद्देश्य के लिए कोई कार्य या कार्य करना।
उप-धारा (4) 901 के लिए किसी भी अधिनियम या कार्य का निर्देश देती है।

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

किसी भी निष्पादक द्वारा काम रोकने की तैयारी
तुरंत और प्राधिकरण की सहमति के लिए आवेदन करना।
धारा 68 ए प्राधिकरण और किसी भी अधिकारी की रक्षा करती है।
या किसी मुकदमे, अभियोजन या अन्य से कर्मचारी
इसके तहत की गई किसी भी चीज़ के संबंध में कानूनी कार्यवाही
अधिनियम और दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को भी हटा देता है।
2006 (संशोधन) अधिनियम मान्यता अधिनियम नहीं है लेकिन
अवहेलना करने, बाधा डालने और रद्द करने के लिए एक मात्र उपकरण
इस न्यायालय का निर्णय और संवैधानिक रूप से हस्तक्षेप
तमिल के कानूनी अधिकारों को सीमित या समाप्त करना

जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। विधानमंडल ऐसा नहीं कर सकता।

केवल घोषणा और अधिनियमन द्वारा और न्यायिक निर्णय को रद्द करें। प्रत्यक्ष वस्तु और

विवादित कानून का प्रभाव पलटने के लिए है

इस न्यायालय का निर्णय और केरल को अभिमानी बनाने के लिए

जिन कानूनी अधिकारों को पहले ही बरकरार रखा जा चुका है अदालत।

19. उपरोक्त आधारों पर, तमिलनाडु ने दो गुना मांग की है।

राहत, (i) द्वारा पारित 2006 (संशोधन) अधिनियम घोषित करना केरल विधानमंडल को अपने आवेदन में असंवैधानिक और

मुल्लापेरियार बांध पर प्रभाव और (ii) का आदेश पारित करना

प्रथम प्रतिवादी को रोकने वाला स्थायी निषेधाज्ञा

हस्तक्षेप करने वाले विवादित कानून को लागू करना और लागू करना या वादी को जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाने से रोकना। और निर्णय के अनुसार मरम्मत कार्यों को पूरा करने से

इस न्यायालय का दिनांक 27.02.2006 डब्ल्यू. पी. में। 2001 की (सिविल) संख्या 386 संबंधित मामलों के साथ। भारत संघ को शामिल किया गया है

प्रतिवादी नं. 2 सूट में। केरल द्वारा रक्षा

20. केरल ने योग्यता के आधार पर तमिलनाडु के दावे को दरकिनार कर दिया है

और रखरखाव के बारे में भी आपत्तियां उठाई हैं

सूट। केरल का बचाव यह है कि 902 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों के लिए 1886 का पट्टा समझौता

[2014]

12 एस सी आर।

999 धारा 7 (1) (बी) के प्रावधानों के तहत व्यपगत वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ("1947 का अधिनियम")। 1947 से 26.01.1950 तक, पट्टे को एक अस्थायी पट्टे के रूप में जारी रखा गया था।

वार्षिक आधार। 26.01.1950 के बाद, अस्थायी निरंतरता भी पट्टा समाप्त हो गया। धारित भूमि का अधिकार

और मदरास की तत्कालीन सरकार और अब तमिलनाडु द्वारा जारी रखा गया, 26.01.1950 के बाद इसका कोई न्यायिक आधार नहीं है।

21. केरल का कहना है कि 1886 का पट्टा समझौता

जिसके आधार पर तमिलनाडु ने अपना दावा किया है, वह है

अपनी अवधि (999 वर्ष) के कारण अनुचित अनुबंध के रूप में

साथ ही यह तथ्य कि पट्टा एक छोटे से किराए के लिए महत्वपूर्ण है केरल का संसाधन। यह पट्टा इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव द्वारा स्पष्ट रूप से त्रावणकोर के महाराजा, जो उनके जागीरदार थे, पर सर्वोच्चता की धमकी देकर प्राप्त किया गया था।

22. 1970 के दो पूरक समझौतों के संबंध में,

केरल का कहना है कि इन समझौतों को संविधान के अनुच्छेद 299 के अनिवार्य प्रावधानों के संदर्भ में लागू नहीं किया गया है।

संविधान और इसलिए, वे अनुबंधों का गठन नहीं करते हैं

कानून की नजर। किसी भी मामले में, ये समझौते बाध्य नहीं करते हैं

राज्य विधायिका बिल्कुल भी।

23. 2006 (संशोधन) अधिनियम के बारे में कहा गया है कि केरल

विधायिका ने 22 के भंडारण स्तर को विनियमित करने वाला अधिनियम अधिनियमित किया

धारा 62 ए (1) के साथ पठित दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध बांध, चूंकि ये बांध पूरी तरह से केरल के क्षेत्र में आते हैं और इन बांधों को उनके कारण लुप्तप्राय माना जाता है।

आयु, अपक्षय, क्षरण, संरचनात्मक या अन्य

बाधाएँ। केरल का कहना है कि ऐसा कानून पूरी तरह से वैध है। 2006 (संशोधन)
अधिनियम की धारा 62 ए (3) के तहत, एफआरएल

इसे 136 फीट से अधिक बढ़ाया जा सकता है। एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में
बांध सुरक्षा प्राधिकरण की पूर्व सहमति प्राप्त करने के बाद

उच्च न्यायालय। यदि तमिलनाडु धारा 62 ए (3) के तहत संपर्क करता है,

केरल प्रदर्शन करके इस तरह की याचिका का विरोध करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता
है।

इस तरह की वृद्धि से अप्रवाही जल कैसे आगे बढ़ेगा

155 फीट की समोच्च रेखा। और कैसे वनस्पतियों और जीवों सहित पारिस्थितिकी
नष्ट हो जाएगी। तमिलनाडु राज्य में भंडारण में वृद्धि का प्रभाव v.

केरल राज्य 903

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

बांध की सुरक्षा पर बांध सुरक्षा प्राधिकरण के समक्ष भी प्रदर्शन किया जाएगा। यह वह मामला
नहीं था जिस पर पिछले मामले में इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक था, क्योंकि

उस मामले में, केंद्र मुद्दा बांध की सुरक्षा और अखंडता पर ऊंचाई में वृद्धि का प्रभाव था।
2006

(संशोधन) अधिनियम इससे निपटने के लिए एक कार्य तंत्र बनाता है उन लोगों के
विस्थापन जैसी समस्या जिनकी भूमि की संभावना है

अप्रवाही जल प्रभाव से प्रभावित होना।

24. 2006 को अधिनियमित करने के लिए केरल विधानमंडल की क्षमता

(संशोधन) अधिनियम पर भरोसा करके इसे उचित ठहराने की कोशिश की जाती है

सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टियाँ 17 और 18 और प्रविष्टियाँ 17,17-ए

और सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची का 17-बी संविधान। केरल का यह भी कहना
है कि वह इसके लिए सक्षम है

केरल विधानसभा सार्वजनिक रूप से पट्टे की शर्तों में संशोधन करेगी ब्याज (यदि पट्टा तमिलनाडु द्वारा दिए गए दावे के अनुसार बचा हुआ है), अनुच्छेद 295 के तहत विरासत में प्राप्त पट्टा के रूप में

संविधान राज्य के विधानमंडल को बाध्य नहीं करता है और यह कि कानून द्वारा ऐसी शर्तों को संशोधित करने के लिए विधानमंडल हमेशा खुला रहता है।

25. मुल्लापेरियार बांध की संरचना के संबंध में केरल का कहना है कि इसका निर्माण पूरी तरह से मलबे से नहीं किया गया है चूने के मोर्टार में। सामने और पीछे के चेहरे बनाए गए हैं

चूने के मोर्टार में अनियंत्रित मलबे की चिनाई। दिल (केंद्र)

कोर) चूने के सुरखी कंक्रीट का है, इसलिए, बांध नहीं हो सकता है

किसी के तहत सजातीय चिनाई बांध माना जाता है परिस्थितियाँ। केरल को ध्यान में रखते हुए, एक बांध को लंबे समय तक रखने का इरादा कभी नहीं किया जा सकता था जब तक कि इसे बंद नहीं किया जाता।

कुछ समय के लिए। इस पृष्ठभूमि में केरल के लोग रहते हैं।

मुल्लापेरियार बांध के निचले क्षेत्र में वृद्धि हुई है

संरचना की सुरक्षा के खिलाफ गंभीर आशंकाएँ।

26. केरल ने इस बात से इनकार किया है कि पेरियार नदी एक अंतर-राज्य है।

नदी। इसने दावा किया है कि पेरियार नदी एक अंतर-राज्यीय नदी है क्योंकि यह केरल के क्विलोन जिले से निकलती है और केवल इसके माध्यम से गुजरती है।

अरब सागर में गिरने से पहले केरल का क्षेत्र। द.

पेरियार बेसिन का कुल जलग्रहण क्षेत्र 5398 वर्ग किलोमीटर है। किमी.

जिनमें से केवल 904 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट हैं।

[2014]

12 एस सी आर।

लगभग 113 या 114 वर्ग किलोमीटर। किमी. यह तमिलनाडु के क्षेत्र के भीतर स्थित है। यहां तक कि 113 वर्ग किलोमीटर का यह छोटा जलग्रहण क्षेत्र भी। किमी. तमिलनाडु में स्थित, मुल्लापेरियार बांध के निचले क्षेत्र में स्थित है। इसलिए,

इस जलग्रहण क्षेत्र से मुल्लापेरियार बांध की किट्टी में कोई पानी नहीं जाता है।

27. जहां तक इस न्यायालय के पहले के फैसले का संबंध है, केरल का रुख यह है कि फैसले ने सुरक्षा से संबंधित मुद्दे को समाप्त कर दिया।

लोगों का और पर्यावरण का क्षरण, इसके अलावा

संविधान के अनुच्छेद 363 से उत्पन्न होने वाला मुद्दा। सिद्धांत

रेस जुडिकाटा या रचनात्मक रेस जुडिकाटा की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

केरल विधानमंडल को विनियमित करने की शक्तियों के सवाल पर

व्यापक जनहित में मुल्लापेरियार बांध का भंडारण स्तर

कानून द्वारा। केरल का कहना है कि विवादित कानून

निर्णय के कानूनी आधार, यानी तमिल के अधिकार को हटा देता है।

और, इसलिए, तमिलनाडु के लिए किसी भी दावे की अनुमति नहीं है। मुल्लापेरियार बांध पर 136 फीट से अधिक पानी के भंडारण का अधिकार। केरल ने पहले के निष्कर्षों और निष्कर्षों पर हमला किया है।

सभी संभावित आधारों पर दिनांकित 27.02.2006 का निर्णय।

28. केरल ने रखरखाव के बारे में आपत्ति जताई है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत वर्तमान वाद। केरल के अनुसार, क्योंकि तमिल द्वारा किए गए दावे का आधार

तमिलनाडु 1886 के पट्टा समझौते में आता है जो एक संविदात्मक समझौता है।

और इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और इस तरह समझौता संधि और राज्य के अधिनियम की प्रकृति में है, जिसका प्रवर्तन संविधान के अनुच्छेद 131 के प्रावधान द्वारा वर्जित है। इसलिए तमिलनाडु प्रवर्तन की मांग नहीं कर सकता है।

इस न्यायालय के समक्ष 1886 का पट्टा विलेख।

29. केरल ने भी विशेषज्ञ की रिपोर्ट को चुनौती दी है।

बांध की संरचनात्मक सुरक्षा का आकलन करने के लिए समिति जो तमिल नाडु v.

केरल राज्य 905

[आर. एम. लोधा, सीजेआई ।]

इस न्यायालय द्वारा 27.02.2006 पर अपने फैसले में भरोसा किया गया था ।

केरल का कहना है कि अंतरिम रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट दोनों

विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत विसंगतियों से भरे हुए हैं और समिति के विचार नहीं हैं

एक आधिकारिक राय का गठन करता है । केरल ने इससे इनकार किया है । मुल्लापेरियार बांध में 136 फीट से अधिक का भंडारण । इससे कोई खतरा नहीं होगा ।

30. केरल का कहना है कि मुल्लापेरियार बांध में भंडारण

136 फीट से अधिक । सिंचाई की आवश्यकता नहीं होगी

तमिलनाडु के 5 दक्षिणी जिलों में 2,08,144 एकड़ की आवश्यकता, हालांकि मूल रूप से योजनाबद्ध सिंचाई अधिक नहीं थी

डेढ़ लाख एकड़ से अधिक । केरल ने तमिल के दावे का खंडन किया है ।

तमिलनाडु की सिंचाई प्रभावित हो रही है । केरल के अनुसार, तमिलनाडु मुल्लापेरियार के पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई करने में सक्षम था । जल स्तर को 136 फीट तक कम करने के बाद भी ।

31. केरल ने इस प्रकार प्रार्थना की है कि तमिलनाडु द्वारा दायर मुकदमे को लागत के साथ खारिज कर दिया जाए ।

मुद्दे

32. 13.12.2007 पर, न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दों को तैयार किया

मुकदमे में विचार के लिए:

" 1. क्या मुकदमा अनुच्छेद 131 के तहत बनाए रखने योग्य है

भारत का संविधान ।

2 .

(क) क्या केरल सिंचाई और जल

संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2006

असंवैधानिक और अति अधिकार, इसके आवेदन में
और मुल्लई पेरियार बांध पर प्रभाव?

(ख) क्या वादी स्थायी अधिकार का हकदार है।

प्रथम प्रतिवादी को प्रतिबंधित करने वाला निषेधाज्ञा

केरल सिंचाई को लागू करना और लागू करना

जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006

मुल्लई पेरियार बांध का संदर्भ?

1 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

3. क्या वादी के अधिकार, में स्पष्टीकृत हैं इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित
27.02.2006 का निर्णय

WP (C) No. 386/2001 को केरल राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा रद्द किया
जा सकता है?

4. (क) क्या इसका निर्णय दिनांकित 27.2.2006 है।

डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 386/2001 में न्यायालय रेस के रूप में संचालित है।

न्यायपालिका, सभी या किसी भी बचाव सेट के संबंध में

पहले प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित बयान में?

(ख) क्या वैधता और बाध्यकारी से संबंधित याचिकाएं

अपने बचाव में पहले प्रतिवादी द्वारा उठाया गया बांध आदि,
अंततः इस न्यायालय के फैसले से निर्णय लिया जाता है

डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या में दिनांकित 27.2.2006.386/2001, और

नतीजतन पहले प्रतिवादी को उठाने से रोक दिया जाता है

या इस वाद में उन मुद्दों और दलीलों को न्याय और रचनात्मक न्याय के सिद्धांत द्वारा फिर से शुरू करना।

न्याय?

5. क्या मुकदमा एक कानूनी अधिकार पर आधारित है जिसके तहत दावा किया गया है

सरकार के बीच निष्पादित पट्टा विलेख

त्रावणकोर के महाराजा और भारत के राज्य सचिव 29.10.1886 पर, अनुच्छेद 131 के प्रावधान द्वारा वर्जित है

भारत का संविधान?

6. क्या पहले प्रतिवादी को उठाने से रोक दिया गया है

याचिका में कहा गया है कि 29.10.1886 दिनांकित विलेख समाप्त हो गया है

पहले प्रतिवादी के बाद के आचरण और दिनांकित पूरक समझौतों का निष्पादन 29.05.1970

दिनांकित मूल विलेख के विभिन्न प्रावधानों की पुष्टि करना

29.10.1886 .

7. क्या पट्टा विलेख के बीच निष्पादित किया गया है

त्रावणकोर के महाराजा और भारत के राज्य सचिव की सरकार 29.10.1886 पर मान्य है, जो तमिल नाडु बनाम के पहले राज्य पर बाध्यकारी है।

केरल राज्य 907

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

प्रतिवादी और वादी द्वारा पहले के खिलाफ प्रवर्तनीय

प्रतिवादी।

8. क्या पहले प्रतिवादी को प्रतिवाद करने से रोक दिया गया है

कि पेरियार नदी एक अंतर-राज्यीय नदी नहीं है।

9. क्या पहले प्रतिवादी का प्रस्ताव, एक का निर्माण करने के लिए

निचले क्षेत्र में पेरियार नदी पर नया बांध

मुल्लई पेरियार बांध न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा और

वादी की आवश्यकताएँ।

10. क्या पहला प्रतिवादी वादी को बाधित कर सकता है

मुल्लई पेरियार बांध के जल स्तर को बढ़ाने से लेकर

142 फीट। और अनुसार मरम्मत कार्यों को पूरा करने से

डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 386/में इस न्यायालय का दिनांकित 27.2.2006 का निर्णय

2001 .

11. वादी किस राहत का हकदार है? ”

पक्षों द्वारा दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य

33. पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का प्रवेश/अस्वीकार 16.05.2008 पर पूरा किया गया था। दस्तावेज पूर्व। पी1 से

Ex. तमिलनाडु द्वारा टेंडर किए गए पी44 को केरल द्वारा भर्ती किया गया था और

दस्तावेज पूर्व। केरल द्वारा टेंडर किए गए डी1 से डी17 को भर्ती किया गया था। तमिलनाडु से। तमिलनाडु के दस्तावेज पूर्व। XP1 से XP4 और।

केरल के दस्तावेज पूर्व। XD1 से XD24 को दूसरे द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। एक तरफ।

34. मौखिक साक्ष्य के संबंध में, तमिलनाडु ने आर.

सुब्रमण्यन (पीडब्ल्यू-1) एकमात्र गवाह के रूप में। दूसरी ओर, केरल ने पांच गवाहों, वी. के. महानुदेवन (डी. डब्ल्यू.-1), को पेश किया। के. जयकुमार (डीडब्ल्यू-2), डॉ. ए. के. गोसैन (डीडब्ल्यू-3), डॉ. ध्रुवज्योति घोष (डीडब्ल्यू-4) और एम. के. परमेश्वरन नायर (डीडब्ल्यू-5)।

5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का संदर्भ

35. शुरू में, इस मामले की सुनवाई तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई थी।

आई. डी. 1 पर मामला संविधान पीठ 908 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. को भेजा गया था।

जैसा कि मुकदमे में बनाए गए कुछ मुद्दों में निर्णय शामिल था संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और विशेष रूप से:

संविधान के अनुच्छेद 246 के साथ पठित अनुच्छेद 3 और 4

((i)

संविधान;

((ii) संविधान के अनुच्छेद 32 के साथ पठित अनुच्छेद 131

(रेस-जुडिकाटा के संदर्भ में);

((iii) अनुच्छेद 295 के साथ पठित अनुच्छेद 131 का प्रावधान और

363 संविधान और इसका प्रभाव

संविधान (26 वां संशोधन) अधिनियम, 1971; और

((iv) मुल्लापेरियार में इस न्यायालय के निर्णय का प्रभाव।

पर्यावरण संरक्षण मंच 1 पूर्व-निर्दिष्ट संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में।

अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) का गठन

36. एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास हुआ जब

मामला शुरू में संविधान पीठ द्वारा उठाया गया था। संविधान पीठ ने यह महसूस किया कि मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा सहित मामले के सभी पहलुओं की जांच

अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) निर्णय लेने में न्यायालय की मदद कर सकती है।

प्रभावी ढंग से। तदनुसार, 18.02.2010 पर, संविधान पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि

डॉ. ए. एस. आनंद की अध्यक्षता में एक निर्वाचन आयोग का गठन करना,

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और दो सदस्यों से युक्त

केरल और तमिलनाडु राज्यों द्वारा नामित और दो

प्रसिद्ध तकनीकी विशेषज्ञ। निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया गया था कि वह मुकदमे के पक्षकारों को उन सभी मुद्दों पर सुने जो उसके समक्ष उठाए जा सकते हैं, जो मामले में अदालत के समक्ष उठाए गए मुद्दों तक सीमित नहीं हैं और जहां तक संभव हो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके गठन के छह महीने के भीतर। इसे चुनाव आयोग के लिए अपनी प्रक्रिया तैयार करने और उचित जारी करने के लिए खुला छोड़ दिया गया था

सुनवाई के साथ-साथ इसकी बैठकों के स्थान के बारे में निर्देश और

909 के रूप में इस तरह के और सबूत प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग पर भी छोड़ दिया गया था

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

उचित माना जाता है। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया कि 2006 की वैधता सहित कानूनी और संवैधानिक मुद्दे संशोधन अधिनियम, ऐसे मामले हैं जिन पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा।

37. ई. सी. ने समय-समय पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। द.

अंतिम रिपोर्ट देने का समय भी बढ़ा दिया गया था। रिपोर्ट अंततः अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 23.04.2012 पर प्रस्तुत की गई थी। सामान्य अवलोकन।

38. एक सामान्य अवलोकन के रूप में, इससे पहले कि हम शुरू करें

विविध मुद्दों पर चर्चा, यह कहा जाना चाहिए कि

इस प्रकृति का निर्णय बहुत तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए, जहाँ तक अभिवचन और प्रक्रियाएँ हैं।

चिंतित हैं। इस न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में दायर किया गया मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा शासित नहीं है। उस प्रक्रिया को छोड़कर जिसे सर्वोच्च न्यायालय के नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से लागू किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि

ध्यान रखें कि राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा का निपटारा किया जाना है

बड़े और व्यापक रूप से जो अकेले संबंधित वादियों की गरिमा बन जाता है (आंध्र प्रदेश राज्य 3)। दुर्भाग्य से,

एक पूर्व प्रमुख की अध्यक्षता में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इस न्यायालय के न्यायाधीश, दो राज्यों में से प्रत्येक में से एक नामित जो

इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और दो प्रसिद्ध तकनीकी हैं

विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों राज्यों के विचार अलग-अलग हैं, हालांकि चुनाव आयोग ने मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा पर तथ्यों पर बहुत थकाऊ और सूक्ष्म विचार के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

जिसमें तीन शीर्ष संगठनों के माध्यम से किए गए परीक्षणों, जांच और तकनीकी अध्ययनों की रिपोर्ट शामिल थी।

इसके अलावा अन्य विशेषज्ञ संगठनों के माध्यम से

भारत सरकार और विशेषज्ञ एजेंसियां और स्थल मूल्यांकन के बाद। इसके अलावा, जांच, परीक्षण और

3. आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य।; [(2013) 5 एससीसी

68] .

910 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2014]

12 एस सी आर।

निर्वाचन आयोग द्वारा दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों के सहयोग से तकनीकी अध्ययन करने का निर्देश दिया गया था।

मुद्दा संख्या। 1 , 5 , 6 और 7.

39. ये चार मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि इनमें से दो

ये मुद्दे 1886 के पट्टा समझौते की वैधता और बाध्यकारी प्रकृति और 1970 के पूरक समझौतों के प्रभाव से संबंधित हैं।

और अन्य दो मुद्दे मुकदमे की रखरखाव से संबंधित हैं

अनुच्छेद 131, यदि 1886 का पट्टा समझौता वैध, बाध्यकारी और लागू करने योग्य। व्यापक तर्क हमें संबोधित किए गए हैं।

में दो चुनाव लड़ने वाले राज्यों के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा

इन मुद्दों का सम्मान करें। लेकिन इस पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए।

कि केरल ने इस स्थिति पर विवाद नहीं किया कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 177 के तहत 1935 से पहले राज्य सचिव द्वारा किए गए मौजूदा अनुबंध (उद्देश्यों के लिए किए गए)

किसी प्रांत की सरकार का) प्रभाव होगा जैसे कि वे

उस प्रांत की ओर से बनाए गए थे। केरल द्वारा इस स्वीकृत स्थिति को देखते हुए, हम पहले देखेंगे कि क्या 1886 लीज समझौता मद्रास प्रांत की सरकार के उद्देश्यों के लिए किया गया एक मौजूदा अनुबंध था।

1935 का अधिनियम।

1886 पट्टा समझौता-क्या कोई मौजूदा अनुबंध है

1935 के अधिनियम के तहत

40. मद्रास प्रेसीडेंसी (फोर्ट सेंट जॉर्ज) था

पिट्स अधिनियम, 1784 द्वारा स्थापित। इसके बाद, द्वारा

भारत सरकार अधिनियम, 1858, के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र

परिषद में राज्य सचिव के रूप में संदर्भित अनुबंधों में प्रवेश करने के लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज की परिषद में राज्यपाल। 1886 लीज राज्य सचिव के बीच समझौता किया गया था

परिषद में और इस प्रावधान के तहत त्रावणकोर के महाराजा। भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने 911 के साथ स्थिति को नहीं बदला।

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

किले की अध्यक्षता के बाद से 1886 के पट्टा समझौते के संबंध में सेंट जॉर्ज को स्थानीय सरकार के उद्देश्यों के लिए प्रांत माना जाता था। 1935 के अधिनियम की धारा 46 के आधार पर,

फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्रेसीडेंसी, जिसे 1919 के अधिनियम के तहत एक प्रांत माना जाता था, गवर्नर का प्रांत बन गया

मद्रास।

41. 1935 के अधिनियम की धारा 177, अनावश्यक को हटाना

भाग में लिखा है, ". प्रारंभ से पहले किया गया कोई भी अनुबंध। राज्य सचिव द्वारा या उनकी ओर से इस अधिनियम के भाग III का

परिषद में, उस तारीख से-(क) यदि यह उन उद्देश्यों के लिए बनाया गया था जो इस अधिनियम के भाग III के प्रारंभ के बाद होंगे।

अधिनियम किसी प्रांत की सरकार के उद्देश्य होते हैं, जिनका प्रभाव पड़ता है

मानो यह उस प्रांत की ओर से बनाया गया था। "

इस प्रावधान के तहत, राज्य सचिव के मौजूदा अनुबंध परिषद में प्रभाव होगा जैसे कि उन पर बनाया गया था

प्रांत की ओर से। जब हम 1935 के अधिनियम की धारा 177 के आलोक में 1886 के पट्टा समझौते को देखते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है

मद्रास प्रेसीडेंसी (मद्रास प्रांत) की परिषद में राज्य सचिव द्वारा निष्पादित उस पट्टे पर प्रभाव जैसे कि यह राष्ट्रपति की ओर से किया गया था

मद्रास या उस मामले के लिए मद्रास प्रांत। इसे रखने के लिए अलग तरह से, धारा 177 (1) (ए) के तहत बनाई गई कानूनी कल्पना द्वारा,

मद्रास प्रेसीडेंसी (मद्रास प्रांत) के तहत पट्टेदार बन गया

1886 का पट्टा समझौता। इसलिए हमें कोई झिझक नहीं है।

श्री विनोद बोबडे के निवेदन को स्वीकार करते हुए, सीखा तमिलनाडु के लिए वरिष्ठ वकील कि की धारा 177 के आधार पर

1935 अधिनियम, 1935 अधिनियम के प्रारंभ से,

मद्रास प्रांत की सरकार को माना जाता है 1886 के पट्टा समझौते में पट्टेदार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया।

18.07.1947 और के बीच की घटनाओं का प्रभाव और प्रभाव

26.01.1950

42. उपरोक्त होल्डिंग के आलोक में, हमें प्रभाव देखना होगा

और कुछ घटनाओं का प्रभाव जो 18.07.1947 के बीच हुआ (जब 1947 का अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था) और

26.01.1950 (संविधान के प्रारंभ की तारीख)।

912 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

42.1 . 18.07.1947 पर, एक बुलेटिन जारी किया गया था

त्रावणकोर राज्य के महाराजा सभी समझौतों की निंदा करते हुए।

42.2 . कहा जाता है कि आई. डी. 1 पर त्रावणकोर के दीवान ने महाराजा को सौंपे गए अपने नोटों में कहा था कि वायसराय के साथ चर्चा की, उन्होंने स्पष्ट रूप से निंदा की थी

1886 का पट्टा समझौता और जिसे वायसराय ने स्वीकार कर लिया था

निंदा में अंतर्निहित अच्छी भावना।

42.3 . 10.08.1947 पर, अपने पत्र में, श्री सी. सी. देसाई,
अतिरिक्त सचिव ने आश्वासन दिया कि सभी समझौते फिर से बातचीत होगी।

42.4 . 12.08.1947 पर, विलय का साधन था
त्रावणकोर के शासक द्वारा निष्पादित यह घोषणा करते हुए कि त्रावणकोर
भारत के अधिराज्य में शामिल हो गया है।

42.5 . विलय के दस्तावेज के बाद, 12.08.1947 पर ही, राज्य के बीच एक ठहराव
समझौता किया गया था

त्रावणकोर और भारत का अधिराज्य।

42.6 . 14.08.1947 पर, भारत (अस्थायी संविधान)
आदेश, 1947 जारी किया गया था जिसके तहत, अन्य बातों के साथ, धारा 177 लागू की गई
थी।

1935 के अधिनियम को हटा दिया गया था।

42.7 . 15.08.1947 पर, 1947 का अधिनियम लागू हुआ।

42.8 . 24.05.1949 पर, दोनों राज्यों-त्रावणकोर और कोच्चि-का एक साथ विलय हो
गया।

क्या 1886 का पट्टा समझौता समाप्त हो गया?

43. श्री हरीश एन. साल्वे, केरल के विद्वान वरिष्ठ वकील,
उपरोक्त घटनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करता है कि 1886 लीज समझौता
समाप्त हो गया और 15.08.1947 पर और उससे जीवित नहीं रहा।

44. 1947 के अधिनियम द्वारा, स्थापना के लिए प्रावधान किए गए थे
भारत में क्रमशः दो भारतीय अधिराज्यों के बारे में जाना जाएगा
भारत और पाकिस्तान 15.08.1947 से। अधिनियम की धारा 7
1947 इस प्रकार पढ़ता है:

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 913

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

" 7. नए की स्थापना के परिणाम

प्रभुत्व। - (1) नियत दिन से

(क) यूनाइटेड किंगडम में महामहिम की सरकार

सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है

उन क्षेत्रों में से जो उस दिन से ठीक पहले थे

ब्रिटिश भारत में शामिल;

(ख) भारतीय पर महामहिम का आधिपत्य

राज्य समाप्त हो जाते हैं, और इसके साथ, सभी संधियाँ और समझौते

इस अधिनियम के पारित होने की तारीख को उसके बीच बल

महामहिम और भारतीय राज्यों के शासक, सभी कार्य के संबंध में उस तारीख को
महामहिम द्वारा प्रयोग करने योग्य

भारतीय राज्य, उस समय मौजूद महामहिम के सभी दायित्व

भारतीय राज्यों या उनके शासकों और सभी की ओर की तारीख

उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ, अधिकार, अधिकार या अधिकार क्षेत्र
द्वारा भारतीय राज्यों में या उनके संबंध में उस तारीख को महामहिम

संधि, अनुदान, उपयोग, पीड़ा या अन्यथा; और

(ग) इनमें कोई संधि या समझौते भी समाप्त हो जाते हैं।

इस अधिनियम के पारित होने की तारीख को उसके बीच बल

महामहिम और जनजातीय में अधिकार रखने वाले कोई भी व्यक्ति क्षेत्र, उस तिथि
पर मौजूद महामहिम के कोई भी दायित्व

ऐसे किसी भी व्यक्ति को या जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में, और
 में प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियाँ, अधिकार, प्राधिकरण या अधिकार क्षेत्र
 जनजातीय क्षेत्रों में या उनके संबंध में महामहिम की उस तारीख को
 संधि, अनुदान, उपयोग, पीड़ा या अन्यथा:

4

बशर्ते कि, पैराग्राफ में कुछ भी होने के बावजूद

किसी ऐसे समझौते का, जिसे उसमें निर्दिष्ट किया गया है, सीमा शुल्क, पारगमन
 और संचार, डाक और

तार, या इसी तरह के अन्य मामले, जब तक कि इन प्रावधानों में

भारतीय राज्य के शासक द्वारा प्रश्न की निंदा की जाती है या

एक ओर आदिवासी क्षेत्रों में अधिकार रखने वाला व्यक्ति,

या अधिराज्य या प्रांत या उसके अन्य भाग द्वारा 914 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014]
 12 एस. सी. आर.

दूसरी ओर संबंधित, या द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है

बाद के समझौते।

(2)

.....

45. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1947 का अधिनियम 15.08.1947 से लागू हुआ।
 धारा 7 के परिणामों से संबंधित है

नए प्रभुत्वों की स्थापना। धारा 7 की उप-धारा (1) का खंड (बी) घोषित करता है कि

भारतीय राज्य चूक जाते हैं। अधिराज्य के समाप्त होने पर, यह प्रदान करता है उसके बीच लागू सभी संधियों और समझौतों का समापन

समझौते जब तक कि इस तरह के समझौते में प्रावधान नहीं हैं भारतीय राज्य के शासक द्वारा निंदा की जाती है या उन्हें हटा दिया जाता है

एक बाद के समझौते द्वारा।

46. श्री हरीश एन. साल्वे का तर्क है कि सबसे पहले, 1886 का पट्टा समझौता मुख्य प्रावधान के आधार पर समाप्त हो गया

1947 के अधिनियम की धारा 7 (1) (बी) जैसा कि यह सभी को समझती है।

संधियाँ और समझौते और दूसरा, महाराजा

त्रावणकोर ने 1886 के पट्टे सहित सभी समझौतों की निंदा की समझौता।

47. यह सच है कि 1947 के अधिनियम की धारा 7 (1) (बी) का उपयोग करता है अभिव्यक्ति "सभी संधियों और समझौतों" लेकिन, हमारी राय में, "सभी" शब्द का उद्देश्य उन समझौतों को शामिल करना नहीं है जो वे राजनीतिक प्रकृति के नहीं हैं। यह उद्देश्य से स्पष्ट है कि

धारा 7 भारतीय राज्यों पर महामहिम के आधिपत्य के समाप्त होने और इसके समाप्त होने के परिणाम से संबंधित है।

अधिराज्य। जाहिर है, इस प्रावधान का उद्देश्य राजनीतिक के अलावा अन्य समझौतों और संधियों को शामिल करना नहीं था। हम,

तदनुसार, यह मानते हुए कि धारा 7 (1) (बी) केवल राजनीतिक संधियों और समझौतों से संबंधित है।

48. 1886 के पट्टा समझौते की प्रकृति नहीं है

इस न्यायालय द्वारा 2006 के फैसले (मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण मंच 1) में पहले ही राजनीतिक निष्कर्ष निकाला जा चुका है।

तमिल नाडु का यह न्यायालय राज्य v. केरल राज्य 915

[आर. एम. लोधा, सीजेआई] -

इसमें माना गया है-और हमारे पास एक अलग दृष्टिकोण लेने का कोई उचित कारण नहीं है कि 1886 का पट्टा समझौता एक सामान्य समझौता है। समझौता एक पट्टा समझौता है और यह पूरी तरह से गैर-राजनीतिक प्रकृति का है।

49. इस प्रकार, आगे दिए गए विवाद में कोई योग्यता नहीं है।

केरल की ओर से कि 1886 का पट्टा समझौता समाप्त हो गया

1947 अधिनियम की धारा 7 (1) (बी) का मुख्य प्रावधान।

50. अब, तर्क के दूसरे अंग पर विचार करने के लिए

श्री हरीश एन. साल्वे ने हमें संबोधित किया कि अन्यथा भी,

त्रावणकोर के महाराजा ने सभी समझौतों की निंदा की

1886 के पट्टा समझौते सहित, इसका उल्लेख करना आवश्यक है

धारा 7 (1) (बी) से जुड़ा परंतुक। अभिव्यक्ति

" परंतुक में भारतीय राज्य के शासक द्वारा निंदा की गई हमारी राय में, धारा 7 में संलग्न, स्पष्ट, स्पष्ट और स्पष्ट निंदा को संदर्भित करता है। केरल ने नहीं किया है

यह दिखाने के लिए कोई सामग्री या दस्तावेज प्रस्तुत किया कि वहाँ था

त्रावणकोर के शासक द्वारा उस प्रकृति की निंदा व्यक्त करना

जहाँ तक 1886 के पट्टा समझौते का संबंध है। हमें नहीं लगता कि 18.07.1947 पर जारी किया गया बुलेटिन स्पष्ट रूप से या अंत में

1886 के पट्टा समझौते की निंदा की।

51. इसके अलावा, एक वैध और प्रभावी निंदा होने के लिए

शासक और महामहिम के बीच हुए समझौते के बारे में होने के बाद निंदा की जानी चाहिए।

1947 के अधिनियम के लागू

मान लीजिए कि 1886 के पट्टे की कोई निंदा नहीं की गई है।
बाद त्रावणकोर शासक द्वारा समझौता।

15.08.1947 के

52. दिनांकित ठहराव समझौते का प्रासंगिक भाग

12.08.1947 इस प्रकार पढ़ता है:

" त्रावणकोर राज्य और राज्य के बीच समझौता

भारत का अधिराज्य

जबकि यह लाभ और लाभ के लिए है

भारत के साथ-साथ भारतीय राज्यों का प्रभुत्व जो

वर्तमान समझौतों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में

साझा चिंता के मामले, [2014] 12 एस. सी. आर. के लिए जारी रहने चाहिए।

916 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत अधिराज्य या किसी भी भाग के बीच का समय

उसके और भारतीय राज्य:

इसलिए अब त्रावणकोर के बीच सहमति बन गई है।

भारत का राज्य और अधिराज्य जो:

1 .

(1) जब तक इस संबंध में नए समझौते नहीं किए जाते,

अब मौजूद सामान्य चिंता के मामलों के बारे में सभी समझौते और
प्रशासनिक व्यवस्थाएँ

क्राउन और किसी भी भारतीय राज्य के बीच,

जहाँ तक उचित हो, भारत अधिराज्य के बीच या जहाँ तक स्थिति हो,
जारी रखें।

ऊपर उल्लिखित मामलों में मामले शामिल होंगे।
इस समझौते की अनुसूची में निर्दिष्ट "।

53. श्री हरीश एन. साल्वे का तर्क है कि गतिरोध बना हुआ है।

समझौता, जो पार्टियों के बीच उन लोगों से अलग है जो

1886 के पट्टा समझौते को लागू किया था, यह एक नया समझौता है

जो कुछ समय के लिए संविदात्मक रूप से लागू हुआ

त्रावणकोर के महाराजा और भारत अधिराज्य के बीच दायित्व। चूंकि पार्टियां अलग थीं और
अधिनियम

रियासतों, 1886 के पट्टे को जारी रखने का सवाल समझौता नहीं होता है। किसी भी
मामले में, विद्वान वरिष्ठ वकील

केरल का तर्क है कि गतिरोध समझौता टिक नहीं सका

1935 के अधिनियम की धारा 177 को हटाने के बाद। हम नहीं पाते हैं

इन तर्कों में योग्यता। यह गतिरोध समझौता भारत के डोमिनियन और त्रावणकोर राज्य के बीच
एक नया समझौता नहीं है

श्री हरीश एन. साल्वे के सुझाव के अनुसार। स्थगन समझौते का उद्देश्य उन पक्षों के लाभ के
लिए था जो समझौतों और व्यवस्थाओं के पक्षकार थे, जो इन मामलों के थे -

क्राउन और राज्य के बीच मौजूद सामान्य चिंता त्रावणकोर। विलय के साधन की
पृष्ठभूमि में, यह

कुछ व्यवस्था करना आवश्यक हो गया ताकि तमिलनाडु राज्य v.

केरल राज्य 917

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

क्राउन और के बीच मौजूदा समझौते और व्यवस्थाएँ भारतीय राज्यों ने जारी रखा। हम यह नहीं सोचते कि ठहराव समझौता राजनीतिक प्रकृति का है जैसा कि उनकी ओर से तर्क दिया गया है।

केरल।

54. यह तर्क कि समझौता रुका नहीं रह सका

धारा 177 के हटाए जाने के बाद से प्रभावी

15.08.1947 भारत (अनंतिम संविधान) आदेश के आधार पर, 1947 यह भी बिना पदार्थ के है। धारा 177 हटा दी गई थी।

क्योंकि यह अब काम नहीं कर सकता था और क्योंकि भारत का डोमिनियन डोमिनियन के हिस्से के रूप में प्रांतों के साथ अस्तित्व में आने वाला था

और परिषद में कोई राज्य सचिव नहीं होना था। हम श्री विनोद बोबडे के विद्वान वरिष्ठ वकील से सहमत हैं।

तमिलनाडु में धारा 177 को हटाने की संभावना थी और

यह उस अनुमान को प्रभावित नहीं करता था जो पहले से ही हो चुका था

1935. हमारे विचार में, यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 177 को हटाने से गतिरोध समझौते का सफाया हो गया है।

55. श्री हरीश एन. साल्वे ने सही कहा है कि

धारा 177 राज्य सचिव द्वारा किए गए मौजूदा अनुबंध 1935 से पहले का प्रभाव होगा जैसे कि वे संबंधित प्रांत की ओर से बनाए गए थे और इस प्रावधान के आधार पर,

मद्रास प्रांत ठहराव समझौते का लाभार्थी था।

लेकिन वह सही नहीं लगता जब वह कहता है कि यह स्थिति 14.08.1947 पर बदल गई जब भारत (अनंतिम)

12.08.1947 पर किया गया समझौता समाप्त हो गया मद्रास प्रांत का लाभ।
जैसा कि हम पहले कह चुके हैं,

पहले ही हो चुका था। यह श्री साल्वे के इस तर्क को भी नकारता है कि क्राउन के अधिकार, जो उनके द्वारा प्राप्त किए गए थे धारा 177 के तहत मद्रास प्रांत, उक्त धारा को हटाने पर समाप्त हो गया था क्योंकि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था

मुकुट।

56. यह तर्क कि क्राउन का कोई उत्तराधिकारी नहीं है

अप्रासंगिक क्योंकि धारा 177 के आधार पर,

मद्रास प्रांत 1886 918 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. में पहले ही पट्टेदार बन चुका था।

1935 में ही लीज समझौता माना गया। ठहराव

मद्रास प्रांत और त्रावणकोर राज्य के बीच 1886 का पट्टा समझौता जारी रहा। 1886 धारा के मुख्य प्रावधान के तहत पट्टा समझौता समाप्त नहीं हुआ

7 (i) (b) 1947 के अधिनियम का। कोई स्पष्ट नहीं था और धारा 7 (i) (b) के प्रावधान के तहत त्रावणकोर के शासक द्वारा 1886 के पट्टा समझौते की स्पष्ट निंदा। मद्रास प्रांत इस गतिरोध समझौते का लाभार्थी था।

निश्चित रूप से, धारा 177 को हटाने से इन अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है - मद्रास प्रांत।

57. बाबू राम साक्षनत पर भरोसा करते हुए, यह जोरदार है

श्री हरीश एन. साल्वे, केरल के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि दो राज्यों-त्रावणकोर और कोच्चि-के विलय पर

1949 पूर्ववर्ती राज्यों के शासकों द्वारा की गई सभी संधियाँ

पट्टा समझौता, कानूनी स्थिति के आलोक में समाप्त हो गया बाबू राम सक्सेना में प्रदर्शित। में वरिष्ठ वकील सीखा

इस संबंध में हिमाचल प्रदेश राज्य में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया गया।

बाबू राम सक्सेना

58. आइए हम बाबू राम सक्सेना पर ध्यान से विचार करें। द.

बाबू राम साक्षना में तथ्य इस प्रकार थे: बाबू राम

सक्सेना उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के सदस्य थे और उन्होंने विभिन्न पदों पर टोंक राज्य की सेवा की। यह आरोप लगाया गया कि

सेवा के दौरान, उन्होंने भुगतान के लिए भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त करने में टोंक के नवाब की मदद की।

Rs.14,00,000/- नवाब को अपने ऋणों के निर्वहन के लिए राज्य के खजाने से बाहर, और नवाब को धमकियों और धमकियों से प्रेरित किया। इस तरह की मदद के बदले में उसे भुगतान करने का धोखा, विभिन्न तिथियों पर कुल रु. 3,00,000/- की राशि देता है। डॉ. बाबू राम सक्सेना थे

4. , डॉ. बाबू राम सक्सेना बनाम राज्य; [ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 155)।

5. हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम। भारत संघ और अन्य।; [(2011) 13 एस. सी. सी. 344]

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 919

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

धारा 383,575 और 420 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया

अधिनियम ')। वारंट 1903 के अधिनियम की धारा 7 के तहत जारी किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल, जहाँ आरोपी था

उत्तर प्रदेश की सेवा में लौटने के बाद रहने वाले सरकार, उसे गिरफ्तार करने और जिले के हवाले करने के लिए

टोंक के मजिस्ट्रेट। अभियुक्त ने गुण-दोष के आधार पर बचाव किया

साथ ही वारंट की वैधता के लिए और चुनौती दी नैनीताल के मजिस्ट्रेट का संज्ञान लेने का अधिकार क्षेत्र

मामला दर्ज करें और अपीलार्थी को गिरफ्तार करें। उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया

सभी आपत्तियाँ और रिहाई के लिए आवेदन को खारिज कर दिया अपीलार्थी का। यह मामला इस अदालत में ले जाया गया था। अन्य बातों के साथ,

इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से विवाद था

कि संधि ब्रिटिश सरकार और टोंक राज्य के बीच 28.01.1869 पर हुई, हालांकि धारा 7 द्वारा घोषित की गई थी

1947 के अधिनियम का, जो 15.08.1947 से समाप्त हो गया था, उस पर किए गए ठहराव समझौते द्वारा लागू किया गया था

08.08.1947 ; कि वह संधि विशेष रूप से सभी मामलों को नियंत्रित करती थी

दोनों राज्यों के बीच प्रत्यर्पण से संबंधित, और वह, क्योंकि इसमें उन अपराधों को शामिल नहीं किया गया है जिनके खिलाफ अब आरोप लगाए गए हैं

अपीलार्थी का कोई प्रत्यर्पण नहीं हो सकता है माँगा या आदेश दिया। दूसरी ओर महान्यायवादी ने,

यह तर्क देते हुए जवाब दिया कि विभिन्न भारतीय राज्यों के साथ किया गया गतिरोध समझौता विशुद्ध रूप से अस्थायी था

यथास्थिति बनाए रखने के लिए बनाई गई व्यवस्थाएँ

सामान्य चिंता के कुछ प्रशासनिक मामलों का सम्मान

उन राज्यों का भारत अधिराज्य में विलय होने तक

और उन्हें विलय के साधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था

उन राज्यों के शासकों द्वारा निष्पादित। टोंक के 16.08.1947 पर डोमिनियन में शामिल होने के बाद, गतिरोध समझौते पर भरोसा किया गया

अपीलार्थी के लिए यह माना जाना चाहिए कि वह उस से समाप्त हो गया है।

तिथि. दूसरा, संधि अब अस्तित्व में नहीं थी और इसकी

निष्पादन असंभव हो गया, क्योंकि टोंक राज्य ने राजनीतिक रूप से और इस तरह की संप्रभुता के रूप में स्वीकार करना बंद कर दिया जो उसके पास था

बुझा दिया, जब यह कुछ अन्य राज्यों के साथ वाचा की, के साथ

920 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. को एकजुट और एकीकृत करने के लिए भारत सरकार की सहमति।

संयुक्त राज्य के नाम से आम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ एक राज्य में उनके क्षेत्र

राजस्थान ", ऐसी संधियों में से अंतिम जिसने

पहले वाले, 13.03.1949 पर दर्ज किए गए हैं। अंत में, महान्यायवादी ने तर्क दिया कि संधि अभी भी है

एक बाध्यकारी निष्पादन अनुबंध के रूप में संचालन में और इसके प्रावधानों को धारा 7 के आवेदन द्वारा किसी भी तरह से अपमानित नहीं किया गया था।

1903 के अधिनियम की उस धारा के तहत जारी प्रत्यर्पण वारंट और उसके अनुसरण में की गई गिरफ्तारी कानूनी थी।

और वैध है और धारा 491 के तहत प्रश्न में नहीं बुलाया जा सकता है

दंड प्रक्रिया संहिता।

59. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बाबू राम सक्सेना में, दो

इस न्यायालय द्वारा राय दी गई है, एक पतंजलि शास्त्री द्वारा।

संबंधित है, उनके लॉर्डशिप ने अटॉर्नी जनरल द्वारा उठाए गए पहले दो तर्कों पर कोई राय नहीं दी। यह बात साफ है। जब न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने कहा, "जैसा कि हमारी स्पष्ट राय है कि अपीलार्थी की दलीलें इस अंतिम आधार पर विफल होनी चाहिए, हम

महान्यायवादी द्वारा उठाए गए अन्य बिंदुओं पर उच्चारण करना अनावश्यक समझते हैं, विशेष रूप से क्योंकि इसमें शामिल मुद्दे हैं - विशुद्ध रूप से कानूनी नहीं बल्कि एक राजनीतिक चरित्र का भी, और उन बिंदुओं पर संबंधित अभियुक्तों के विचार हमारे पास नहीं हैं।

यह कहने के बाद, पतंजलि शास्त्री, जे. ने इस प्रश्न पर विचार किया

क्या 1903 के अधिनियम की धारा 7 के तहत किसी ऐसे अपराध के लिए प्रत्यर्पण, जो संधि के तहत प्रत्यर्पण योग्य नहीं है, किसी भी अर्थ में संधि के प्रावधानों का अपमान है जो

उच्च न्यायालय के संबंधित क्षेत्रों में किए गए कुछ निर्दिष्ट अपराधों के लिए अपराधियों के प्रत्यर्पण का प्रावधान है। अनुबंध करने वाले पक्ष।

59.1 . इस सवाल के संबंध में मुखर्जी, जे. द्वारा दी गई दूसरी राय में, दोनों के बीच प्रत्यर्पण संधि कितनी दूर थी।

टोंक राज्य और ब्रिटिश सरकार आठ अन्य राज्यों के साथ टोंक राज्य के विलय के कारण प्रभावित हुए।

इन नौ राज्यों के शासकों द्वारा संयुक्त राज्य राजस्थान में की गई वाचा को देखते हुए, यह माना गया है कि तमिलनाडु राज्य v.

केरल राज्य 921

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

समामेलन या विलय के परिणामस्वरूप, एक राज्य पहले से संपन्न संधि के विषय पर अपनी पूर्ण और स्वतंत्र कार्यवाही की शक्ति खो देता है, संधि को समाप्त होना चाहिए। मुखर्जी, जे. ने विलय के अनुच्छेद 6 और सामान्य राय का उल्लेख किया

अंतर्राष्ट्रीय न्यायविदों का कहना है कि जब कोई राज्य अपने जीवन को इस तरह से त्याग देता है

किसी अन्य राज्य में निगमन या अवशोषण के माध्यम से

स्वेच्छा से या विजय या विलय के परिणामस्वरूप, पूर्व की संधियाँ स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती हैं। मुखर्जी, जे।

निम्नलिखित रूप में देखा गया:

कहा जाता है कि परिणाम के कारण उत्पन्न होता है

विलुप्त होने के परिणामस्वरूप व्यक्तित्व का पूर्ण नुकसान

राज्य जीवन। इस संबंध में जिन मामलों पर चर्चा की गई है वे हैं -

आम तौर पर ऐसे मामले जहां स्वतंत्र राज्य समाप्त हो गए हैं
 द्वारा बाधित या स्वैच्छिक अवशोषण के माध्यम से ऐसा होना
 पूर्व की संधियों के परिचर विलुप्त होने के साथ एक और
 अन्य राज्यों के साथ। इस प्रकार का बलपूर्वक निगमन
 प्रशिया साम्राज्य में हनोवर ने नष्ट कर दिया
 हनोवर की पिछली संधियाँ। टेक्सास में प्रवेश

संयुक्त प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका

टेक्सास के स्वतंत्र गणराज्य की संधियों को समाप्त कर दिया। स्थिति वही है जब
 कोरिया का विलय हुआ था जापान।
 ओपेनहेम के अनुसार, जिनकी राय रही है

आम तौर पर ऐसे मामलों में होता है, और राजनीतिक और
 व्यक्तिगत संधियाँ एक के अस्तित्व का अनुमान लगाती हैं

अनुबंधित राज्य, वे पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं: यह एक विवादास्पद मुद्दा है कि
 क्या उत्तराधिकार मामलों में होता है।

विलय या विलय से बचे रहना "

59.2 . मुखर्जी, जे. की उपरोक्त टिप्पणियाँ आधारित थीं।

दो प्रसिद्ध पुस्तकों पर, (एक) हाइड ऑन इंटरनेशनल लॉ,

खण्ड. III, पीजी। 1529 और (दो) अंतर्राष्ट्रीय कानून पर ओपेनहेम, खण्ड. 1 ,
 पेज। 152 .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

59.3 . विचाराधीन वाचा से निपटना,

खेर्जिया, जे. ने आगे कहा:

" हालाँकि, ऊपर उद्धृत टिप्पणियाँ पर्याप्त नहीं लगती हैं।

वर्तमान विवरण के मामले के लिए उपयुक्त। यहाँ
 एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य का अवशोषण नहीं किया गया था जो
 पूर्व के राज्य जीवन को समाप्त कर देगा और
 उसके व्यक्तित्व को मिटा दें। यहाँ जो हुआ वह यह था कि कई राज्य स्वेच्छा से एकजुट और
 एकीकृत हुए
 उनके क्षेत्र ताकि एक बड़ा और समग्र राज्य बनाया जा सके
 घटक भाग। एक आम कार्यकारी होना था, विधायिका और न्यायपालिका और शासकों
 की परिषद में सभी करार करने वाले राज्यों के शासक शामिल होंगे। यह हो सकता है
 इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि करार करने वाले राज्यों ने अपना अधिकार खो दिया
 पूरी तरह से व्यक्तित्व और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि
 शासन के उत्तराधिकार और मतों की गिनती के उद्देश्य
 जनसंख्या और अन्य उद्देश्यों के बल पर
 विभिन्न राज्यों के क्षेत्रों के बीच। लेकिन फिर भी इस तरह का अलगाव एक के बीच
 कुछ उद्देश्यों के लिए मौजूद है।
 राज्य क्षेत्र और दूसरा, यह स्पष्ट है कि विलय की तारीख से सभी विभिन्न राज्यों के निवासी
 बन गए,
 राजस्थान के संयुक्त राज्य के विषय और उन्हें किसी विशेष राज्य के विषय के रूप में वर्णित नहीं
 किया जा सकता था।
 टोंक राज्य का कोई विषय मौजूद नहीं है।
 वर्तमान में और टोंक के शासक नहीं कर सकते हैं
 स्वतंत्र रूप से और अपने स्वयं के अधिकार में किसी भी रूप का अभ्यास करें
 टोंक क्षेत्र पर संप्रभुता या नियंत्रण। द.
 एक, भले ही इसमें अलग-अलग शासकों की आवाज हो। हमें ऐसा लगता है कि उन परिवर्तित
 परिस्थितियों में 1869 की प्रत्यर्पण संधि पूरी तरह से निष्पादन में असमर्थ हो गई है।
 टोंक राज्य, जो संविदाकारी पक्षों में से एक है, के लिए इसके अनुसार कार्य करना संभव नहीं है

संधि की शर्तें, क्योंकि इसमें अब कोई स्वतंत्र नहीं है

टोंक क्षेत्र पर अधिकार या संप्रभु अधिकार और तमिल नाडु v का कथन कर सकते हैं।

स्टेट ऑफ. केरल 923

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

न तो प्रत्यर्पण करते हैं और न ही मांग करते हैं। जब समामेलन या विलय के परिणामस्वरूप, कोई राज्य अपना पूर्ण अधिकार खो देता है और विषय पर कार्यवाई की स्वतंत्र शक्ति-एक का मामला

संधि जो पहले संपन्न हुई थी, संधि को अनिवार्य रूप से समाप्त होना चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता है कि टोंक की संप्रभुता

इस संबंध में राज्य अब संयुक्त राज्य में निहित है राजस्थान। जहाँ तक प्रत्यर्पण का संबंध था, प्राधिकरण पहले ही टोंक राज्य द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया था।

के साधन द्वारा डोमिनियन सरकार का पक्ष

प्रवेश। लेकिन यह मानते हुए भी कि ये संधि अधिकार कर सकते हैं

विलय की वाचा के अनुच्छेद 6 के कारण संयुक्त राज्य राजस्थान को हस्तांतरित करना, बाद वाला, ऐसा प्रतीत होता है

मुझे, शर्तों को प्रभावी बनाने में पूरी तरह से असमर्थ हो सकता है

वर्तमान में टोंक राज्य के विषय के रूप में ऐसी चीज संधि का क्षण और अनुच्छेद 2 जो प्रदान करता है

टोंक क्षेत्र के भीतर जघन्य अपराध करने और शरण मांगने के आरोपी टोंक विषयों का प्रत्यर्पण कहीं और पूरी तरह से निष्फल होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका

राजस्थान संभवतः इस अनुच्छेद के आधार पर प्रत्यर्पण की मांग नहीं कर सकता था, और यदि पारस्परिकता, जो सार है एक प्रत्यर्पण समझौते का, चला गया है, संधि को अमान्य और निष्क्रिय माना जाना चाहिए।

59.4 . जे. मुखर्जी के विचार से सहमति थी -

महाजन, जे. दास, जे. के तर्क से काफी हद तक सहमत थे

मुखर्जी, जे. फजल अली, जे. में तर्क की रेखा से सहमत थे।

पतंजलि शास्त्री, जे. और मुखर्जी, जे. द्वारा दिए गए दोनों निर्णय।

59.5 . निर्णय पर सावधानीपूर्वक विचार करना

मुखर्जी, जे. बाबू राम सक्सेना में दिखाएंगे कि उनका

लॉर्डशिप की राय गैर-राजनीतिक पर लागू नहीं होती है।

1886 लीज समझौते जैसे समझौते। मुखर्जी, जे. का अवलोकन, "जब सम्मेलन या विलय के परिणामस्वरूप,

एक राज्य अपनी कार्यवाही की पूरी स्वतंत्र शक्ति खो देता है

पहले की गई संधि की विषय वस्तु, संधि को [2014] 12 एस. सी. आर. होना चाहिए।

924

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनिवार्य रूप से चूक। "एक प्रत्यर्पण संधि के संदर्भ में है

जो विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रकृति का है। हमारे विचार में, बाबू राम सक्सेना * स्पष्ट रूप से अलग है और केरल के इस तर्क में मदद नहीं करता है कि 1886 का पट्टा समझौता विलय पर समाप्त हो गया था।

दो राज्यों, त्रावणकोर और कोच्चि के संयुक्त राज्य त्रावणकोर और कोच्चि में।

हिमाचल प्रदेश राज्य

60. श्री हरीश एन. साल्वे ने भी इस पर बहुत अधिक भरोसा किया

हिमाचल राज्य के मामले में इस न्यायालय का निर्णय

प्रदेश 5. उस मामले में विवाद राज्य के बीच था

एक ओर हिमाचल प्रदेश और दूसरी ओर भारत संघ,

बिजली से संबंधित दूसरी ओर पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य, राजस्थान राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाओं में उत्पन्न। इनमें से एक

विचाराधीन मुद्दे थे कि क्या विलय के बाद

भारत के अधिराज्य के साथ बिलासपुर राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य के पास अभी भी मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कोई कारण हो सकता है। इस मुद्दे पर विचार करते समय, इस न्यायालय ने संदर्भित किया

बिलासपुर विलय समझौता दिनांक 15.08.1948, विशेष रूप से,

इसका अनुच्छेद 1। उस प्रावधान को ध्यान में रखने के बाद, यह न्यायालय

रिपोर्ट के पैराग्राफ 48 में (पृष्ठ 359-360) निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

" 48. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बिलासपुर विलय समझौते से

दिनांक 15-8-1948 बिलासपुर के राजा ने

डोमिनियन सरकार पूर्ण और अनन्य अधिकार,

के लिए और उसके संबंध में अधिकारिता और शक्तियाँ

राज्य का शासन और हस्तांतरण के लिए सहमत

डोमिनियन सरकार को राज्य का प्रशासन

12-10-1948 पर। इसके बाद, भारत सरकार,

विधि मंत्रालय ने दिनांक 20-7-1949 (अतिरिक्त) पर एक अधिसूचना जारी की। डी-4/2 ए) की धारा 290-ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए

भारत सरकार अधिनियम, 1935 राज्यों को विलय (मुख्य आयुक्तों के प्रांत) आदेश, 1949, जो 1-8-1949 से लागू हुआ। इन राज्यों के तहत

-विलय (मुख्य आयुक्तों के प्रांत) आदेश, 1949,

बिलासपुर को हर तरह से प्रशासित किया जाना था जैसे कि यह तमिलनाडु राज्य बनाम।

केरल राज्य 925

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

एक मुख्य आयुक्त का प्रांत। संविधान के तहत

भारत सरकार ने भी शुरू में बिलासपुर को मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में प्रशासित किया और इसे शामिल किया गया।

भाग सी राज्य के रूप में संविधान की पहली अनुसूची में। अनुच्छेद 295 (बी) के तहत सभी अधिकार, देनदारियां और दायित्व

भारत अधिराज्य की सरकार, चाहे वह उत्पन्न हो रही हो

किसी भी अनुबंध से या अन्यथा, भारत सरकार के अधिकार, देनदारियाँ और दायित्व बन गए। ये

बिलासपुर विलय समझौते के प्रावधान दिनांक 15-8 1948 (विस्तार। डी-4/1-ए), राज्यों का विलय (प्रमुख)

आयुक्तों के प्रांत) आदेश, 1949, पहला

संविधान यह स्पष्ट करता है कि बिलासपुर इसका हिस्सा बन गया। भारत अधिराज्य और उसके बाद प्रशासित किया गया था

सरकार द्वारा मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में

भारत सरकार और बिलासपुर के राजा के सभी अधिकार भारत सरकार में निहित थे। इसलिए हम मानते हैं कि वादी

विलय से पहले बिलासपुर के राजा के किसी भी अधिकार के आधार पर कोई दावा करने का कोई कारण नहीं होगा।

भारत के अधिराज्य के साथ बिलासपुर राज्य।

61. हिमाचल राज्य में उपरोक्त अवलोकन

प्रदेश 5 को बिलासपुर विलय के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।

समझौता दिनांक 15.08.1948 जिसके तहत बिलासपुर के राजा

डोमिनियन सरकार को पूर्ण और अनन्य अधिकार सौंप दिया गया,

शासन के लिए और उसके संबंध में अधिकारिता और शक्तियाँ

राज्य और बिलासपुर के राजा के सभी अधिकार निहित थे

भारत सरकार। हमें यह समझने में मुश्किल होती है कि ये कैसे निरंतरता के रूप में
टिप्पणियों का कोई अनुप्रयोग है

1886 के पट्टा समझौते के बाद, के विलय

त्रावणकोर राज्य और कोचीन राज्य एक नए राज्य में,

अर्थात्, त्रावणकोर और कोच्चि के संयुक्त राज्य का संबंध है। हिमाचल प्रदेश राज्य में इस
न्यायालय का निर्णय,

हमारा विचार है कि प्रस्तुत करने के लिए कोई आवेदन नहीं है

केरल की ओर से।

926 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2014]

12 एस सी आर।

विलय पर भारतीय राज्यों की स्थिति

62. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीयों का विलय

भारत अधिराज्य के राज्यों ने उन राज्यों को संस्थाओं के रूप में समाप्त नहीं किया। वे केवल
भारत अधिराज्य का हिस्सा बन गए

पूर्ववर्ती अंग्रेजों के प्रांतों के साथ घटक राज्य भारत। हम यह मानने में असमर्थ हैं कि
भारत अधिराज्य में शामिल होने वाले राज्यों की संस्थाओं का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया
था।

तमिलनाडु के निवेदन में योग्यता है कि तथ्य यह है कि

24.05.1949 पर त्रावणकोर और कोच्चि राज्यों का एक साथ विलय भी यह स्थापित करता है कि भारतीय राज्य जिन्होंने स्वीकार किया डोमिनियन संस्थाओं के रूप में जारी रहा।

63. उपरोक्त के आलोक में, हम केरल के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि मदरास का पट्टेदार होना बंद हो गया है।

15.08.1947 . यहाँ यह देखना उचित है कि केरल ने प्रवेश किया है। 1970 में तमिलनाडु के साथ पूरक समझौतों में। में।

इन पूरक समझौतों, 1886 के पट्टे की निरंतरता को स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में बताया गया है। अगर 1886 का पट्टा समझौता 15.08.1947 पर और उससे चालू होना बंद हो गया था, केरल के लिए पूरक में प्रवेश करने का कोई अवसर नहीं था

1970 में तमिलनाडु के साथ समझौते। पहले पूरक समझौते द्वारा, तमिलनाडु ने मछली पकड़ने के अधिकारों को आत्मसमर्पण कर दिया।

पट्टे पर दी गई भूमि और पट्टे पर दी गई भूमि के किराए में वृद्धि करने पर भी सहमति व्यक्त की। दूसरा पूरक समझौता

तमिलनाडु को बिजली उत्पादन का अधिकार और अधिकार प्रदान किया गया

बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं का निर्माण करना। अ. उक्त उद्देश्यों के लिए तमिलनाडु को 42.7 एकड़ का अतिरिक्त क्षेत्र पट्टे पर दिया गया था। श्री हरीश एन. साल्वे, विद्वान वरिष्ठ वकील

केरल ने तर्क दिया कि 1970 के पूरक समझौते और

1886 के पट्टा समझौते को जारी रखने के बारे में बयान कानून की गलती (गलत धारणा) पर आधारित था

1886 के पट्टे की निरंतरता। केरल के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की प्रस्तुति को शायद ही स्वीकार किया जा सकता है, हमारे निष्कर्ष को देखते हुए कि 1886 का पट्टा समझौता जारी रहा और

15.08.1947 से और दूसरा, इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए

आंध्र प्रदेश राज्य में न्यायालय 3, जिसमें तीन न्यायाधीश तमिलनाडु राज्य बनाम।

केरल राज्य 927

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

इस न्यायालय की पीठ हममें से एक (आर. एम. लोधा, जे., जैसा कि उन्हें तब देखा गया था), "जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई समझौता किया जाता है, तो उन्हें सहायता मिलती है -

उनके पास सक्षम, कानूनी और तकनीकी दिमाग उपलब्ध हैं। राज्यों में मसौदा तैयार करने की क्षमता की कमी नहीं है। इस तरह का समझौता

प्रशिक्षित दिमागों द्वारा प्रदान किया गया। " 1970 का पूरक

दो उच्च पक्षों, केरल राज्य और तमिलनाडु राज्य द्वारा किए गए समझौतों के कारण, यह मुश्किल से हो सकता है

मान लीजिए कि यह 15.08.1947 पर समाप्त हो गया था। केरल स्पष्ट रूप से उनके पास सक्षम और कानूनी दिमाग उपलब्ध होना चाहिए

जब 1970 में तमिलनाडु के साथ पूरक समझौते किए गए थे। केरल के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि

पूरक समझौते कानून की गलती पर आधारित थे।

क्या 1886 का पट्टा समझौता राज्य का एक अधिनियम है?

64. क्या 1886 का पट्टा समझौता राज्य का एक अधिनियम है या

अंतर्राष्ट्रीय संधि? जवाब नकारात्मक होना चाहिए। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि राज्य का एक अधिनियम संप्रभु का अधिग्रहण है। किसी राज्य द्वारा उस क्षेत्र के संबंध में शक्तियाँ जो तब तक उसका भाग नहीं था, विजय, संधि, समर्पण या अन्यथा द्वारा, और

नए संप्रभु द्वारा मान्यता प्राप्त नगरपालिका न्यायालयों के पास है

जांच करने और केवल इस तरह का पता लगाने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र

अधिकारों के रूप में नए संप्रभु ने मान्यता देने के लिए चुना है या

ऐसी मान्यता व्यक्त की जा सकती है या परिस्थितियों से निहित हो सकती है। 1886 पट्टा समझौता एक सामान्य अनुबंध है। लीज पर। केवल इसलिए कि अनुबंध बीच में ही हो गया था

राज्य सचिव और त्रावणकोर के माध्यम से ताज

राज्य-एक रियासत भारतीय राज्य-अनुबंध की प्रकृति नहीं है बदल गया और यह एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं बन जाता है। के रूप में

ऊपर उल्लेख किया गया है, यह न्यायालय मुल्लापेरियार पर्यावरण में

प्रोटेक्शन फोरम 1 पहले ही घोषणा कर चुका है कि 1886 लीज

समझौता राजनीतिक प्रकृति का नहीं होता है। हम इस विचार से सहमत हैं। यही तर्क ठहराव पर भी समान रूप से लागू होता है

समझौता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2014]

12 एस सी आर।

928

विरेन्द्र सिंह

1

65. श्री हरीश एन. साल्वे, केरल के विद्वान वरिष्ठ वकील

विरेन्द्र सिंह के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। विरेन्द्र सिंह की संविधान पीठ भारतीय राज्यों में स्थित संपत्ति के संवैधानिक अधिकारों के बारे में सवाल से संबंधित थी जो ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे।

संविधान लेकिन जो संविधान से कुछ समय पहले भारत के प्रभुत्व में शामिल हो गया और इसका एक अभिन्न अंग बन गया

इसके बाद भारतीय गणराज्य। चरखारी और सरिला स्वतंत्र थे।

ब्रिटिश क्राउन को अधिराज्य शक्ति के रूप में स्वीकार किया। भारत स्वतंत्रता प्राप्त की और के कारण एक डोमिनियन बन गया

1947 का अधिनियम। दो राज्यों-चरखारी और सरिला-को फांसी दी गई।

विलय के उपकरण और प्रभुत्व में प्रवेश। में

विलय के साधन, विलय करने वाले राज्यों की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई और उनकी रक्षा की गई। सरिला के शासक 28.01.1948 पर, रिट याचिकाकर्ताओं को एक गाँव दिया गया और चरखारी के शासक ने भी कुछ गाँव दिए

याचिकाकर्ता। 13.03.1948 पर, बुंदेलखंड में पैंतीस राज्य

और बघेलखंड (चरखारी और सरिला सहित) सहमत हुए एक राज्य में खुद को एकजुट करें जिसे बुलाया जाना था। संयुक्त राज्य विंध्य प्रदेश। कुछ दिनों के बाद,

उपरोक्त समझौते पर सभी पैंतीस लोगों ने एक वाचा पर हस्ताक्षर किए थे शासक जो नए राज्य को अस्तित्व में लाए। यह

व्यवस्था घरेलू व्यवस्था थी और इसके साथ कोई संधि नहीं थी

भारत का प्रभुत्व। इसके तुरंत बाद, के राजस्व अधिकारी

नवगठित विंध्य प्रदेश संघ ने उपरोक्त शासकों द्वारा दिए गए अनुदान में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। एकीकरण नहीं हुआ

संतोषजनक तरीके से काम करें। इसलिए, 26.12.1949 पर, उन्हीं पैंतीस शासकों ने उनके शासन को निरस्त करने के लिए एक और समझौता किया।

01.01.1950 . उसी उपकरण द्वारा प्रत्येक शासक ने उसी तारीख से भारतीय अधिराज्य की सरकार को समर्पण कर दिया। द. उपकरण को विंध्य प्रदेश विलय समझौता कहा जाता था।

6. विरेन्द्र सिंह और अन्य। वी. उत्तर प्रदेश राज्य; [(1955) 1 एससीआर 415: एयर 1954 एससी 447]।

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

भारतीय अधिराज्य की सरकार भी इसमें पक्षकार थी समझौता। डोमिनियन सरकार ने संभाला

विंध्य प्रदेश का गठन करने वाले राज्यों का प्रशासन 01.01.1950 और उन्हें मुख्य आयुक्त का प्रांत बनाने का फैसला किया। संविधान लागू हुआ जिस पर

26.01.1950 . जागीरों और मुआफ़ियों द्वारा दिया गया अनुदान

चरखारी और सरिला के शासकों को कहीं न कहीं वापस ले लिया गया था।

अगस्त, 1952। यह निरसन का आदेश था जो था

के अनुच्छेद 32 को लागू करके इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई

संविधान।

65.1 . ऊपर उल्लिखित मुद्दे पर विचार करते समय और बार में उद्धृत विभिन्न निर्णयों के आलोक में, इस न्यायालय ने इस रूप में खुलासा किया

निम्नलिखित है:

" अब यह निर्विवाद है कि परिग्रहण और

भारत अधिराज्य द्वारा उनकी स्वीकृति के कार्य थे

राज्य जिसकी क्षमता में कोई नगरपालिका न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता है और न ही संविधान के बाद भारत में कोई न्यायालय,

अनुच्छेद 363 और अनुच्छेद 131 के परंतुक के कारण उनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को निपटाने के लिए अधिकारिता स्वीकार करना;

वे विलय के तथ्य को पंजीकृत कर सकते हैं; भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 6 देखें

राज्यों का विलय। लेकिन फिर क्या? प्रिंसी काउंसिल का दृष्टिकोण सही है या मुख्य न्यायाधीश मार्शल द्वारा अपनी व्यापक रूपरेखा में सामने रखा गया है, यह अधिक उचित है।

अधिकारी इस बात पर सहमत हैं कि यह क्षमता के भीतर है

मौजूदा अधिकारों को मान्यता देने के लिए नया संप्रभु

विजय प्राप्त या सौंपे गए क्षेत्रों में और, कानून द्वारा
या अन्यथा, उन पर अपने स्वयं के कानून लागू करने के लिए; और ये कानून
हो सकता है, और वास्तव में जब अवसर आता है, तो होना चाहिए
नगरपालिका न्यायालयों द्वारा जांच और व्याख्या की गई
अवशोषित राज्य "।

65.2 . द्वारा उपरोक्त कानूनी स्थिति की व्याख्या

संविधान पीठ शायद ही किसी संदेह को स्वीकार करती है। जाहिर है कि
भारत अधिराज्य में एक भारतीय राज्य का विलय और 930 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014]
12 एस. सी. आर.

अधिराज्य द्वारा इसे स्वीकार करना राज्य और न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के कार्य हैं जो
इसकी क्षमता में जाने या किसी भी मामले को निपटाने के लिए हैं।

उनसे उत्पन्न होने वाले विवाद अनुच्छेद 363 के तहत स्पष्ट रूप से वर्जित हैं।

और अनुच्छेद 131 का परंतुक। जैसा कि हम पहले ही मान चुके हैं-और 2006 के फैसले में भी
यही माना गया है-कि

1886 पट्टा समझौता एक सामान्य समझौता है और यह

प्रकृति में राजनीतिक नहीं है, अनुच्छेद 363 का प्रतिबंध और

अनुच्छेद 131 का कोई प्रावधान लागू नहीं होता है।

अनुच्छेद 363 और अनुच्छेद 131 का दायरा

66. संविधान का अनुच्छेद 363 एक प्रतिबंध है

उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद से निपटने के लिए उच्चतम न्यायालय सहित न्यायालय

किसी संधि, समझौते, वाचा, अनुबंध, सनद या

अन्य समान लिखत जो संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी शासक द्वारा दर्ज या निष्पादित की गई थी

एक भारतीय राज्य और जिसके लिए अधिराज्य की सरकार

भारत की या उसके पूर्ववर्तियों में से कोई भी सरकार एक पक्ष थी और इसके बाद भी इसका संचालन जारी रहा है। प्रारंभ करें। न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र भी वर्जित है -

363. कुछ मामलों से उत्पन्न होने वाले विवादों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने पर रोक

7 .

संधियाँ, समझौते आदि-(1) इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, लेकिन अनुच्छेद 143 के प्रावधानों के अधीन, न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय को किसी संधि, समझौते, वाचा, अनुबंध, सनद या अन्य के किसी भी प्रावधान से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद में अधिकारिता होगी। समान उपकरण जो पहले दर्ज किया गया था या निष्पादित किया गया था

किसी भारतीय राज्य के किसी शासक द्वारा इस संविधान का प्रारंभ और जिसके लिए भारत अधिराज्य की सरकार या उसकी पूर्ववर्ती सरकार में से कोई एक पक्ष था और जो इस तरह के प्रारंभ के बाद भी चालू है या जारी है, या इस संविधान के किसी भी प्रावधान के तहत उपार्जित किसी अधिकार के संबंध में किसी विवाद में या ऐसी किसी संधि, समझौते, वाचा से संबंधित किसी भी दायित्व या दायित्व से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद में,

(2) इस लेख में -

((क)

"भारतीय राज्य"। इसका अर्थ है इस संविधान के प्रारंभ से पहले महामहिम या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी क्षेत्र।

ऐसा राज्य होने के नाते भारत का अधिराज्य; और

(ख) "शासक" में किसी भारतीय राज्य के शासक के रूप में महामहिम या भारत अधिराज्य की सरकार द्वारा इस तरह के प्रारंभ से पहले मान्यता प्राप्त राजकुमार, प्रमुख या अन्य व्यक्ति शामिल हैं।

" तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 931

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

अधीन उपार्जित किसी अधिकार के संबंध में किसी भी विवाद में हस्तक्षेप करना

ऐसी किसी संधि, समझौते से संबंधित इस संविधान के किसी भी प्रावधान से उत्पन्न होने वाला कोई दायित्व या दायित्व,

वाचा, सगाई, सनद या इसी तरह का अन्य साधन।

67. अनुच्छेद 363 का एक सादा अध्ययन कोई तरीका नहीं छोड़ता है

संदेह है कि यदि विवाद उस विवरण के दस्तावेज के संबंध में उत्पन्न होता है और यदि ऐसा दस्तावेज पहले निष्पादित किया गया था संविधान के प्रारंभ में, अदालतों द्वारा हस्तक्षेप वर्जित है। अनुच्छेद 363 में उल्लिखित दस्तावेज वे हैं -

जो प्रकृति में राजनीतिक हैं। इस संबंध में कोई विवाद दस्तावेज गैर-न्यायसंगत हैं। अनुच्छेद 363 के पीछे का उद्देश्य भारतीय शासकों को संधियों, समझौतों, समझौतों के साथ बांधना है।

सगाई, सनद या इसी तरह के अन्य उपकरणों में प्रवेश किया गया

या संविधान के प्रारंभ से पहले निष्पादित किया गया और

भारतीय शासकों को इस तरह के समझौतों से रोकने के लिए कि भारत की अखंडता को हर कीमत पर बनाए रखा जाना था और कुछ विवादों को उठाने से प्रभावित नहीं किया जा सकता था। यह हो सकता है

तैयार किए गए भारतीय राज्यों पर श्वेत पत्र के संदर्भ में प्रासंगिकता

1948 में भारत सरकार द्वारा

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जिसे अपनाने की आवश्यकता थी

अनुच्छेद 363 में प्रावधान। इसमें कहा गया है, "इसलिए अनुच्छेद 363 बनाया गया है। संविधान में सन्निहित जो विशेष रूप से शामिल नहीं है

अधिकार क्षेत्र से विलय के समझौते और करार

उन मामलों को छोड़कर जो राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को भेजे जा सकते हैं।

68. संविधान का अनुच्छेद 131 3 मूल से संबंधित है

8 .

कला. 131. उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता। - विषय के अधीन

इस संविधान के प्रावधानों को हटाते हुए, सर्वोच्च न्यायालय

किसी भी अन्य न्यायालय का, किसी भी विवाद में मूल अधिकार क्षेत्र है

भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच; या

(अ)

भारत सरकार और एक तरफ के किसी भी राज्य या राज्यों के बीच

(ख)

और एक या एक से अधिक अन्य राज्य; या

(ग)

दो या अधिक राज्यों के बीच,

यदि और जहाँ तक विवाद में कोई प्रश्न (चाहे कानून का हो या तथ्य का) शामिल है जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है:

932 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

इस न्यायालय की अधिकारिता। संविधान के प्रावधानों के अधीन, इस न्यायालय के पास किसी भी विवाद में मूल अधिकार क्षेत्र है,

अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार और किसी राज्य के बीच या

एक ओर राज्य और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्य यदि और जहाँ तक विवाद में कोई प्रश्न (चाहे वह कानून का हो या तथ्य का) शामिल है जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता है।

तथापि, उसमें संलग्न परंतुक द्वारा, इसकी अधिकारिता न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है यदि पहली अनुसूची के भाग बी में निर्दिष्ट कोई राज्य उस विवाद का पक्षकार है जिसके कारण विवाद उत्पन्न होता है।

किसी संधि, समझौते, वाचा, अनुबंध, सनद या इसी तरह के अन्य साधन का कोई प्रावधान संविधान के प्रारंभ से पहले किया गया था या निष्पादित किया गया था और

इस तरह की शुरुआत के बाद संचालन में जारी रखा गया।

69. अनुच्छेद 363 में प्रावधान की समानता है और

बस्तियाँ। अनुच्छेद 363 जैसे प्रावधान करके और अनुच्छेद 131 के प्रावधान के अनुसार, राजनीतिक समझौते किए गए हैं

न्यायिक घोषणाओं के दायरे से बाहर। अनुच्छेद 131 में संलग्न प्रावधान किसी भी संधि से उत्पन्न होने वाले विवाद को प्रस्तुत करता है,

समझौता, वाचा, सगाई, सनद या इसी तरह का साधन

जिसे प्रारंभ से पहले राजनीतिक प्रकृति से निष्पादित किया जाता है।

संविधान की और जो प्रवर्तन में है या जारी है, इस न्यायालय की गैर-न्यायसंगत और अधिकारिता वर्जित है।

एक सामान्य समझौते से उत्पन्न विवाद के संबंध में इस न्यायालय की अधिकारिता को नहीं हटाया जाता है। वाद्ययंत्र

परंतुक में संदर्भित और वर्णित केवल वे हैं जो राजनीतिक प्रकृति के हैं। गैर-राजनीतिक साधन इसके अंतर्गत नहीं आते हैं -

प्रावधान।

बशर्ते कि उक्त अधिकार क्षेत्र का विस्तार किसी संधि, समझौते, वाचा, अनुबंध, सनद या अन्य समान लिखत से उत्पन्न होने वाले विवाद तक नहीं होगा, जो इससे पहले किया गया हो या निष्पादित किया गया हो। इस संविधान का

प्रारंभ, इस तरह के प्रारंभ के बाद भी जारी है, या जो यह प्रावधान करता है कि उक्त अधिकार क्षेत्र ऐसे विवाद तक नहीं बढ़ेगा। तमिलनाडु राज्य v.

केरल राज्य 933

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

70. 1886 पट्टा समझौते में समाधान का प्रावधान है -

मध्यस्थता के माध्यम से समझौते के पक्षों के बीच विवाद; इसमें एक मध्यस्थता खंड शामिल है।
प्रस्तुत करना

केरल जो मध्यस्थता के तहत किसी भी निर्णय को लागू करता है खंड राजनीतिक
प्रकृति का होगा जो गलत है। केरल की यह धारणा कि 1886 का पट्टा समझौता न्यायोचित
नहीं था और

संविधान से पहले कानून की अदालत में लागू करने योग्य क्योंकि त्रावणकोर में कोई भी
अदालत स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ दावे को स्वीकार नहीं करेगी।

महाराजा और त्रावणकोर राज्य के बाहर कोई अदालत नहीं है।

त्रावणकोर के महाराजा पर अधिकार क्षेत्र में प्रासंगिक नहीं है

सभी और किसी भी योग्यता से रहित।

71. हम द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण मंच 1 में यह न्यायालय

कि 1886 का पट्टा समझौता इस दायरे में नहीं आएगा।

अनुच्छेद 363 और इस न्यायालय की अधिकारिता वर्जित नहीं है। एक आवश्यक परिणाम के
रूप में, 1886 के पट्टे से उत्पन्न विवाद समझौता अनुच्छेद 131 के प्रावधान के
तहत भी वर्जित नहीं है।

इसके अलावा, मुकदमे में रखी गई प्रमुख चुनौती से संबंधित है - 2006
(संशोधन) अधिनियम की संवैधानिक वैधता जिसके लिए अनुच्छेद

363 या उस मामले के लिए अनुच्छेद 131 परंतुक के तहत नहीं आता है

बिल्कुल भी संचालन में।

अनुच्छेद 224 और अनुच्छेद 295

72. अनुच्छेद 295 के आधार पर, सभी संपत्तियाँ तुरंत

संविधान के प्रारंभ से पहले जो निहित था

9. 294. संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार

कुछ मामले। - इस संविधान के प्रारंभ से

(अ)

((ख) भारत अधिराज्य की सरकार और प्रत्येक राज्यपाल के प्रांत की सरकार के सभी अधिकार, देनदारियाँ और दायित्व, चाहे वे किसी अनुबंध से उत्पन्न हों या अन्यथा, भारत सरकार और प्रत्येक राज्य की सरकार के क्रमशः अधिकार, देनदारियाँ और दायित्व होंगे।

संबंधित राज्य,

पाकिस्तान अधिराज्य या पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी प्रांतों के इस संविधान के प्रारंभ से पहले निर्माण के कारण किए गए या किए जाने वाले किसी भी समायोजन के अधीन

पंजाब।

934 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

अधिराज्य की सरकार के उद्देश्यों के लिए महामहिम

भारत का संघ और उन सभी संपत्तियों में निहित होना जो प्रत्येक राज्यपाल की सरकार के प्रयोजनों के लिए महामहिम में निहित हैं।

भारत सरकार और प्रत्येक संबंधित राज्य की सरकार। में। दूसरे शब्दों में, यह लेख घोषित करता है कि कौन सी संपत्ति निहित होगी

संघ और जो राज्य सरकार में निहित होगा। वहाँ

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 295 (बी) के आधार पर प्रथम के साथ पढ़ा जाता है

संविधान में संलग्न अनुसूची, पट्टा अधिकार

1886 के पट्टे के तहत मद्रास राज्य को हस्तांतरित किया गया

समझौता।

73. अनुच्छेद 295 1 0 संपत्ति, परिसंपत्तियों के उत्तराधिकार से संबंधित है।

10. अनुच्छेद 295-संपत्ति, संपत्ति, अधिकार, देनदारियों का उत्तराधिकार और

अन्य मामलों में दायित्व। -

(1) इस संविधान के प्रारंभ से

(क) ऐसी सभी संपत्ति और परिसंपत्तियाँ जो इस तरह के प्रारंभ से तुरंत पहले पहली अनुसूची के भाग ख में निर्दिष्ट राज्य के अनुरूप किसी भी भारतीय राज्य में निहित थीं, संघ में निहित होंगी, यदि वे उद्देश्य जिनके लिए ऐसी संपत्ति और परिसंपत्तियाँ इस तरह के शुरू होने से तुरंत पहले आयोजित की गई थीं।

तत्पश्चात प्रारंभ संघ के किसी भी उद्देश्य से संबंधित उद्देश्य होंगे -

संघ सूची में सूचीबद्ध मामले, और

(ख) पहली अनुसूची के भाग ख में निर्दिष्ट राज्य के अनुरूप किसी भी भारतीय राज्य की सरकार के सभी अधिकार, देनदारियाँ और दायित्व, चाहे वे किसी अनुबंध से उत्पन्न हों या अन्यथा, भारत सरकार के अधिकार, देनदारियाँ और दायित्व होंगे, यदि वे उद्देश्य जिनके लिए ऐसे अधिकार प्राप्त किए गए थे या देनदारियाँ या दायित्व ऐसे प्रारंभ से पहले किए गए थे, उसके बाद भारत सरकार के उद्देश्य होंगे।

संघ सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले से संबंधित,
भारत सरकार द्वारा उस राज्य की सरकार के साथ उस ओर से किए गए किसी भी समझौते के अधीन।

(2) उपरोक्त के अधीन रहते हुए, पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य का सरकार, इस संविधान के प्रारंभ से, सभी संपत्ति और परिसंपत्तियों और सभी अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों के संबंध में संबंधित भारतीय राज्य की सरकार का उत्तराधिकारी होगा, चाहे वे किसी अनुबंध से उत्पन्न हों या अन्यथा, खंड (1) में निर्दिष्ट लोगों के अलावा।

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 935

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

अधिकार, देनदारियाँ और दायित्व। खंड 1 (ए) में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से सभी संपत्ति और परिसंपत्तियाँ जो इस तरह के प्रारंभ से ठीक पहले निहित थीं। प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के अनुरूप भारतीय राज्य में संघ निहित होगा, यदि -

जो ऐसी संपत्ति और परिसंपत्तियाँ धारित की गई थीं, उनके उद्देश्य होंगे -

संघ। खंड 1 (बी) में प्रावधान है कि किसी भी भारतीय राज्य की सरकार के सभी अधिकार और देनदारियाँ और दायित्व प्रथम के भाग बी में निर्दिष्ट राज्य के अनुरूप

अनुसूची, चाहे वह किसी अनुबंध से उत्पन्न हो या अन्यथा सरकार के अधिकार, देनदारियाँ और दायित्व

भारत यदि वे उद्देश्य जिनके लिए ऐसे अधिकार अर्जित किए गए थे या

देनदारियाँ और दायित्व किए गए थे, जिनके उद्देश्य थे

प्रथम के भाग बी में निर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की सरकार अनुसूची सभी संपत्ति और परिसंपत्तियों और सभी अधिकारों, देनदारियों के संबंध में संबंधित राज्य का उत्तराधिकारी होगी और

दायित्व, चाहे वे किसी अनुबंध से उत्पन्न हों या अन्यथा, खंड (1) में निर्दिष्ट लोगों के अलावा। यह भारत सरकार द्वारा उस ओर से किए गए किसी भी समझौते के अधीन है।

संबंधित राज्य सरकार के साथ। अनुच्छेद में 'संबंधित भारतीय राज्य की सरकार' अभिव्यक्ति

295 (2) , हमारी राय में, भाग बी की सरकार के संदर्भ में

त्रावणकोर राज्य-कोच्चि का मतलब केवल विलय नहीं था

पूर्ववर्ती त्रावणकोर और कोचीन राज्य, लेकिन इसके घटक भी। इस प्रकार, अनुच्छेद 295 (2) के आधार पर,

भाग बी की सरकार त्रावणकोर राज्य-कोच्चि बन गया संबंधित त्रावणकोर राज्य के उत्तराधिकारी

1886 के पट्टे से उत्पन्न होने वाले सभी अधिकार, देनदारियाँ और दायित्व समझौता।

मुद्दा संख्या पर निष्कर्ष। 1 , 5 , 6 और 7

74. उपरोक्त के आलोक में, मुद्दा संख्या पर हमारा निष्कर्ष। 1 , 5 , 6

और 7 हैं:

(i) तमिलनाडु राज्य द्वारा दायर किया गया मुकदमा विचारणीय है।

संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत।

936 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

((ii) महाराजा की सरकार के बीच निष्पादित पट्टा विलेख के तहत दावा किए गए कानूनी अधिकार के आधार पर मुकदमा। त्रावणकोर और 29.10.1886 पर परिषद में भारत के राज्य सचिव को संविधान के अनुच्छेद 131 के प्रावधान द्वारा वर्जित नहीं किया गया है।

(iii) केरल राज्य (प्रथम प्रतिवादी) से अलग किया गया है।

याचिका दायर करते हुए कि पट्टा विलेख दिनांक 29.10.1886 है व्यपगत, दिनांकित पूरक समझौतों को देखते हुए

:

28.05.1970 .

((iv) सरकार के बीच निष्पादित पट्टा विलेख

त्रावणकोर के महाराजा और भारत के राज्य सचिव

प्रतिवादी। मुद्दा संख्या। 2 (ए), 3,4 (ए), 4 (बी) और 10

75. ये मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं और इसलिए ये हैं -

एक साथ चर्चा करें।

तमिलनाडु की ओर से दलीलें

76. श्री. तमिलनाडु के विद्वान वरिष्ठ वकील विनोद बोबडे ने प्रस्तुत किया कि 2006 के फैसले ने एक निष्कर्ष दिया था

जल स्तर बढ़ाने के लिए मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा पर तथ्य

142 फीट। 2006 (संशोधन) अधिनियम को हटाया नहीं जा सकता था

निर्णय से बहने वाला तमिलनाडु का कानूनी अधिकार। 2006 (संशोधन) अधिनियम की धारा 62 (ए) सीधे तौर पर

बांध को लुप्तप्राय घोषित करके इस न्यायालय का निर्णय

और जल स्तर की ऊँचाई 136 फुट तय करके। यह बांध सुरक्षा प्राधिकरण को फैसले को रद्द करने के लिए भी अधिकृत करता है

और स्वयं निर्णय करना कि जल स्तर को बढ़ाने की अनुमति दी जाए या नहीं।

2006 के फैसले में इस अदालत द्वारा। 2006 की धारा 62 (1) (ई) (संशोधन) अधिनियम विषय बांध पर अपने अनुप्रयोग में, चाहता है

बांध सुरक्षा को अधिकृत करके सुरक्षा की खोज को दूर करने के लिए

अन्य बातों के साथ-साथ बांध को बंद करने का आदेश देने का अधिकार। द 937

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

इस प्रकार, निर्णय का निरस्तीकरण स्पष्ट और स्पष्ट है। एक समापन

निर्णय, एक बार प्रस्तुत होने के बाद, संचालित होता है और तब तक लागू रहता है जब तक कि

न्यायालय द्वारा उचित कार्यवाही में परिवर्तन किया गया। वह प्रस्तुत करता है कि किसी निर्णय को रद्द करने वाला एकतरफा कानून संवैधानिक रूप से है

अस्वीकार्य।

77. पृथ्वी में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए

कॉटन 1 1, तमिलनाडु के विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि

किसी निर्णय के कानूनी आधार को हटाए बिना उसे रद्द करना हड़पने की श्रेणियों में से एक है। एक प्रश्न पर निर्णय

तथ्य को रद्द नहीं किया जा सकता है इसलिए निर्णय का प्रभाव भी, जो

कानूनी अधिकार लागू करता है। लियानेज 1 2 में प्रिवी काउंसिल के फैसले पर भरोसा करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी लंबित मामले में न्यायिक प्रक्रिया भी हड़पने के बराबर होती है।

न्यायिक शक्ति। हड़पने की दोनों श्रेणियों में जवाब

किसी निर्णय या न्यायिक कार्यवाही पर कानून के कानूनी प्रभाव पर विचार करने के बाद प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। श्री.

विनोद बोबडे प्रस्तुत करते हैं कि कानून का वास्तविक उद्देश्य,

जिस जल्दबाजी में इसे लागू किया गया था, और आसपास

परिस्थितियाँ, प्रासंगिक परिस्थितियाँ हैं।

78. यह तमिलनाडु के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा तर्क दिया जाता है।

कि यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि क्या कोई निर्णय रद्द कर दिया गया है यह देखने के लिए कि क्या कानून और निर्णय असंगत और अपरिवर्तनीय हैं ताकि दोनों एक साथ खड़े न हो सकें। यह खोज

वास्तव में इस न्यायालय द्वारा 2006 के फैसले में कि बांध सुरक्षित है

कानूनी कल्पना द्वारा कभी भी काल्पनिक नहीं माना जाता है जो तब

इसके विपरीत को वास्तविक मानने के लिए आगे बढ़ता है, अर्थात्, कि बांध

खतरे में है। जल स्तर की ऊँचाई को सीमित करने का प्रावधान

136 फीट तक, इस न्यायालय के फैसले के 15 दिनों के भीतर अधिनियमित बांध को सुरक्षित देखना और जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाने की अनुमति देना।, कानून के वास्तविक उद्देश्य को दर्शाता है,

जिस स्थिति में इसे निर्देशित किया गया था और अवज्ञा करने का स्पष्ट इरादा

श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड और अन्र। वी. ब्रोच बरो नगरपालिका

11 .

और ओआरएस।; [(1969) 2 एस. सी. सी. 233] .

12. डॉन जॉन फ्रांसिस डगलस लियानेज एंड ओआरएस। वी. रानी; [(1966) 1 सभी

ई. आर. 650]।

938 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2014]

12 एस सी आर।

और इस न्यायालय के निर्णय पर अपील करने वाले न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करें।
79. श्री विनोद बोबडे प्रस्तुत करते हैं कि जब इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था और जब केरल राज्य विधानमंडल द्वारा 2006 (संशोधन) अधिनियम लागू किया गया था, तब के बीच कोई नया तथ्य सामने नहीं आया और न ही कोई बदलाव हुआ था

परिस्थितियों में। केरल सरकार और केरल राज्य

विधानमंडल के पास तथ्य की एक भी जानकारी नहीं थी

उससे पहले भूकंपीय गुणांक मूल्यों के संबंध में, संभावित अधिकतम बाढ़ (पी. एम. एफ.) स्तर या कोई अन्य मामला या सामग्री जो 2006 में इस न्यायालय के निष्कर्ष का खंडन करती है या यहां तक कि संदेह करती है।

निर्णय जो विशेषज्ञ के निष्कर्षों पर आधारित था

समिति।

80. विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा इसका पुरजोर आग्रह किया जाता है

तमिलनाडु कि एक बार विवाद एक अदालत और पक्षों के समक्ष होता है तथ्य के किसी भी प्रश्न पर मुद्दा है, उस प्रश्न पर निर्णय केवल अदालत द्वारा दिया जा सकता है न कि

विधायिका या कार्यपालिका। विधायिका यह तय नहीं कर सकती कि

जल स्तर 136 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। जब यह मुद्दा था

अदालत ने फैसला सुनाया।

81. तमिलनाडु के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि

जल स्तर के लिए बांध की सुरक्षा के बारे में तथ्य का पता लगाना जो कि 142 फीट तक है। न्याय संगत है और दोनों राज्यों को बांधता है। इसके भीतर नहीं है

केरल विधानमंडल का प्रांत निर्णय में बैठने के लिए
 इस न्यायालय का निष्कर्ष और निर्देश देकर इसे उलटने का तात्पर्य
 जल स्तर 136 फुट पर बना रहेगा। तमिलनाडु के अनुसार,
 यह एक कानून नहीं है; यह "निरंकुश विवेक" का प्रयोग है और कानून के शासन और अलग
 करने के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

शक्तियाँ।

82. इंदर साहनी 1 3 में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह तमिल के
 विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा तर्क दिया जाता है।

कि धारा 62 ए में तथ्य की विधायी घोषणा कि

- 13 . इंदर साहनी बनाम। भारत संघ और अन्य; [(2000) 1 एस. सी. 168]।

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 939

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

दूसरी अनुसूची के बांध अपनी उम्र, अपघटन, क्षरण, संरचना या अन्य कारणों से खतरे में हैं।
 बाधाएं न्यायिक जांच से परे नहीं हैं और यह खुली हैं न्यायालय सत्य तथ्यों की जाँच करे।

83. श्री विनोद बोबडे का तर्क है कि 2006 (संशोधन) अधिनियम
 एक मान्यकारी अधिनियम नहीं है क्योंकि (i) इस का निर्णय
 अदालत बांध की सुरक्षा के बारे में निष्कर्ष पर नहीं पहुंची
 किसी भी कानून पर आधारित जिसे किसी भी बीमारी से पीड़ित माना जाता था
 संवैधानिक दोष या दोष; (ii) ऐसा कोई अवसर नहीं था कि किसी भी बुराई को दूर
 करें या किसी भी कानून में किसी भी दोष को ठीक करें और एक
 अभ्यास को मान्य करना; और (iii) वास्तव में, 2006 (संशोधन) अधिनियम इस
 न्यायालय द्वारा पाए गए किसी भी दोष को ठीक करने का उद्देश्य नहीं है

कानून। इस संबंध में निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है।

कोर्ट इन पृथ्वी कॉटन 1 1, मदन मोहन पाठक 1 4, पीपुल्स

नागरिक स्वतंत्रता संघ (पी. यू. सी. एल.) 1 5, नगर निगम अहमदाबाद शहर
और अन्र 1, और जनपद सभा 1 7।

84. श्री विनोद बोबडे का तर्क है कि कानूनों को मान्य करना

कानून में खामियों को दूर करने के बाद विधायिका द्वारा पारित किया जाता है

जिन्हें निरस्त कर दिया गया है लेकिन जहां एक तथ्य का निर्णय लिया जाता है

विधायिका या कार्यपालिका में बैठने की कोई शक्ति नहीं है

तथ्य के विवादित प्रश्न पर निर्णय और

उस न्यायालय के लिए अपने स्वयं के "विधायी निर्णय" को प्रतिस्थापित करें। सीखा है।

वरिष्ठ वकील इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं

कावेरी संदर्भ 1 8 में।

85. इस प्रकार, यह तमिल के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा तर्क दिया जाता है।

कहा कि 2006 (संशोधन) अधिनियम असंवैधानिक है।

मदन मोहन पाठक और अन्र। वी. भारत संघ और अन्य; [(1978) 2

14 .

एससीसी 50]।

15. पीपुल्स यूनिन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) और ए. एन. आर. वी. भारत
संघ और

एन. आर. ; [(2003) 4 एस. सी. सी. 399]

16. अहमदाबाद और अन्र शहर का नगर निगम। वी. न्यू श्रॉक एस. पी. जी.

और डब्ल्यूवीजी। कं. लिमिटेड [(1970) 2 एस. सी. सी. 280]।

17. जनपद सभा छिंदवाड़ा बनाम। सेंटरल प्रोविंस सिंडिकेट लिमिटेड और अन्र। ;

[(1970) 1 एससीसी 509)।

18. कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, पुनः; [1993 पूरक (1) एस. सी. सी. 96 (2)]।

मैं अदालत की रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. का समर्थन करता हूँ।

940

केरल की ओर से दलीलें

86. श्री हरीश एन. साल्वे, केरल के विद्वान वरिष्ठ वकील

दूसरी ओर यह तर्क दिया जाता है कि केरल विधानमंडल अनुबंधों को खत्म करने और मुल्लापेरियार की सुरक्षा को विनियमित करने में सक्षम है

पेरियार नदी के पार अपने क्षेत्र के भीतर स्थित बांध। यहाँ तक कि

विदेशी संप्रभुओं के बीच किए गए समझौतों को विधायी शक्तियों के प्रयोग में ओवरराइड किया जा सकता है। वह इस पर निर्भर है कि

ठाकुर जगन्नाथ बक्श 19, महाराज में इस न्यायालय के निर्णय

उमेग सिंह 20, मैनिगॉल्ट 21 और रॉडरिक ई. का एक लेख।

वालस्टन का शीर्षक "जल अधिकार संदर्भ में सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत" 22 है।

87. केरल के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि

"आयु", आदि के आधार पर, सुरक्षा मानकों के रूप में, केरल विधानमंडल ने एक एहतियाती उपाय के रूप में घोषणा की है कि 22 बांध हैं - " के आधार पर लुप्तप्राय और उसके तहत प्रतिबंधित भंडारण

धारा 62 (ए) (1) और (2) को दूसरी अनुसूची के साथ पढ़ा जाता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ब्रदरहुड ऑफ लोकोमोटिव पर निर्भर करते हैं फायरमैन 23, रेमंड मोटर ट्रांसपोर्टेशन 24, रेमंड

कासेल 25, अमेरिकन ट्रकिंग एसोसिएशन 26 और फाइजर एनिमल

और जोखिम विनियमन और अंतर्राष्ट्रीय कानून "जैकलीन द्वारा 19. ठाकुर जगन्नाथ
बख्श सिंह बनाम। संयुक्त प्रांत; [73 IA 123]।

20. महाराज उमेग सिंह और अन्य। वी. बॉम्बे राज्य और ओआरएस।; [(1955) 2
एससीआर

164] .

21. आर्थर एम. मैनिगॉल्ट बनाम अल्फ्रेड ए. स्प्रिंग्स और अन्य; [(1905) 199 यूएस
473]। 22. " रोडरिक ई. द्वारा जल अधिकार संदर्भों में सार्वजनिक न्यास सिद्धांत।

वाल्स्टन; 29 नेचुरल रिसोर्सेज जर्नल 585।

23. लोकोमोटिव फायरमैन और इंजनमैन आदि का भाईचारा। वी. शिकागो, रॉक आइलैंड एंड
पैसिफिक रेल-रोड कंपनी आदि।; [(1968) 393 यूएस 129]।

24. रेमंड मोटर ट्रांसपोर्टेशन, इंक. आदि। वी. ज़ेल एस. राइस और अन्य।; [(1978)
434

यूएस 429]।

25. रेमंड कैसल और अन्य। वी. समेकित माल ढुलाई निगम

डेलावेयर; [(1981) 450 यूएस 662]।

26. अमेरिकन ट्रकिंग एसोसिएशन, इंक. बनाम। थॉमस डी. लार्सन; [(1982) 683

एफ. 2 डी 787]।

27. फाइजर एनिमल हेल्थ एसए वी। यूरोपीय संघ की परिषद; [(2002) ईसीआर II

03305] .

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 941

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

पील 28 जिसमें फाइजर एनिमल हेल्थ 2 7 को संदर्भित किया गया है।

88. श्री हरीश साल्वे, केरल के विद्वान वरिष्ठ वकील

तर्क है कि विधायिका आधार को हटाने के लिए सक्षम है
 निर्णय लें और इसके प्रभाव को बेअसर करें। विवाद के जवाब में
 तमिलनाडु का कि 2006 (संशोधन) अधिनियम का गठन
 न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग, विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि
 धारा 3 और 4 और इसी प्रकार धारा 30 पर भी विचार करें। 2003 एक्ट करें। यह
 माना गया था कि 1956 के अधिनियम की धारा 108
 1886 के पट्टे से उत्पन्न होने वाले संविदात्मक अधिकारों को बचाएगा। समझौता और
 कथित रूप से पूरक द्वारा जारी रखा गया
 केरल के लिए वरिष्ठ वकील, इस प्रकार, प्रस्तुत करते हैं कि जहां एक निर्णय इनक्यूरीयम के
 अनुसार है, एक उपाय आगे उचित है। कानून।
 89. केरल के लिए वरिष्ठ वकील के रूप में सीखा
 2003 के अधिनियम के प्रावधानों को व्यापक रूप से संदर्भित तर्क
 बांध और संरक्षक को निर्देश जारी करने की शक्ति है बांध सुरक्षा प्राधिकरण को
 किसी के बावजूद प्रदान किया गया
 किसी भी न्यायालय की डिक्री, और इसमें निहित किसी भी चीज़ के बावजूद
 कोई संधि, अनुबंध, लिखत या अन्य दस्तावेज और
 प्रस्तुत किया कि 2003 अधिनियम और 2006 (संशोधन) अधिनियम ने जल स्तर
 को विनियमित करने के लिए एक वैधानिक ढांचा बनाया गया
 केरल राज्य के भीतर बांधों का सम्मान, दोनों अनुसूचित और
 गैर-अनुसूचित। 2006 (संशोधन) अधिनियम एक वैधानिक व्यवस्था स्थापित करता है
 प्राधिकरण, जो इसे कुछ लेने की शक्ति प्रदान करता है
 सार्वजनिक सुरक्षा के हित में उपाय। इस पर फैसला
 केरल ने 2006 में कहा था कि अदालत ने सुझाव भी नहीं दिया
 दूर की बात है कि केरल विधानमंडल के पास उपाय करने की शक्ति नहीं है

28. " विज्ञान और जोखिम विनियमन और अंतर्राष्ट्रीय कानून "जैकलीन पील द्वारा;
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2010 द्वारा प्रकाशित।

[2014]

12 एस सी आर।

942 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जलाशय के संबंध में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए
राज्य।

90. श्री हरीश साल्वे का तर्क है कि बांध को असुरक्षित घोषित करने में, विधानमंडल तथ्य का निष्कर्ष नहीं देता है। यह.

बांध को असुरक्षित मानता है और विनियमन के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करता है
एक विशेष तरीके से बांध। विनियमन के लिए वैधानिक तंत्र स्थापित करने के लिए विधायिका
की विधायी क्षमता

के हित में राज्य के भीतर स्थित बांध में जल स्तर

एक लुप्तप्राय बांध का गठन विधायी नीति का विषय है और सुरक्षा को मुख्य रूप से
नीति का मामला माना जाता है। एक अदालत

न्यायनिर्णयन प्रक्रिया के माध्यम से निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और न्यायनिर्णयन हमेशा
लागू कानून के अनुसार होता है। एक बार कानून

परिवर्तित होने पर, निर्णय अपने आप नहीं टिक सकता है। के अनुसार

श्रीमान साल्वे, तमिलनाडु का यह तर्क कि विवादित कानून न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग है,
गलत धारणा है।

91. केरल के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील इस पर निर्भर करते हैं

व्हीलिंग ब्रिज 29 इस सिद्धांत के समर्थन में कि निजी अधिकार निर्णयों में पारित होते हैं लेकिन
सार्वजनिक अधिकारों में नहीं और प्रस्तुत भी करते हैं

कि व्हीलिंग ब्रिज 29 सिद्धांत में लागू किया गया है

बाद के मामले।, द क्लिंटन ब्रिज 3 0, होजेस 3 1 और
चार्ल्स बी. मिलर 3 2.

आई.

92. श्री हरीश एन. साल्वे का तर्क है कि 2006 (संशोधन)

अधिनियम सख्त अर्थ में एक वैधीकरण अधिनियम नहीं है। निर्णय लेते समय

इस आधार पर आगे बढ़ें कि विधायिका अपने लोगों और अपने कानूनों की जरूरतों को समझती है और सही ढंग से उनकी सराहना करती है अपने अनुभव द्वारा प्रकट की गई समस्याओं की ओर निर्देशित किए जाते हैं और पर्याप्त आधारों पर आधारित होते हैं। सीखी हुई वरिष्ठ सलाहकार

29. पेन्सिलवेनिया राज्य बनाम। द व्हीलिंग एंड बेलमोंट ब्रिज कंपनी,

आदि।; [(1855) 59 यू. एस. 421]

30. क्लिंटन ब्रिज मामला; [(1870) 77 यू. एस. 454]

31. होजेस एट अल। वी. स्नाइडर एट अल।; [(1923) 261 यूएस 600]

32. चार्ल्स बी. मिलर, अधीक्षक, पेंडलटन सुधार सुविधा आदि। वी.

रिचर्ड ए. फ्रेंच और अन्य।; [(2000) .

530 यू. एस. 327] स्टेट ऑफ तमिल नाडु बनाम। केरल राज्य 943

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

केरल के लिए एल्फिंस्टन में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर है

स्पनिंग 33 ने संजीव कोक 34 और डॉयपैक सिस्टम 3 5 में पहले के निर्णयों को मंजूरी दी।
भारतीय संविधान: शक्तियों का पृथक्करण

शक्तियों का पृथक्करण। हालांकि, हमारे में प्रदान की गई संरचना संविधान इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता कि

शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान के माध्यम से होता है। यह है।

इस कारण से कि इस न्यायालय ने अलगाव को मान्यता दी है

संविधान की एक बुनियादी विशेषता के रूप में शक्ति और एक आवश्यक कानून के शासन का घटक। पृथक्करण का सिद्धांत

हालाँकि, शक्तियाँ संविधान में स्पष्ट रूप से अंकित नहीं हैं।

संविधान। भारतीय संविधान ने इसके बिना सीमांकन किया है। तीन अंगों-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच औपचारिक रेखाएँ खींचना।

महल चंद सेठिया

94. महल चंद सेठिया 3 6 में, के साथ काम करते हुए

तर्क दिया कि हालाँकि यह राज्य विधानमंडल के लिए खुला था पश्चिम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश द्वारा एक अधिनियम और राज्यपाल

बंगाल आपराधिक कानून संशोधन (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1949,

यह उनमें से किसी के लिए एक आदेश को मान्य करने में अक्षम था

स्थानांतरण जिसे एक रिट के जारी होने से रद्द कर दिया गया था

उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र और स्थानांतरण का आदेश

वस्तुतः मृत, राज्यपाल द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सका या

33. भारत संघ बनाम। एल्फिंस्टन स्पनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। ;

[(2001) 4 एससीसी 139]।

34. संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एम/एस। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्र। ;

[(1983) 1 एससीसी 147]।

35. एम/एस। डॉयपैक सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड वी. भारत संघ और ओआरएस। ; [(1988) 2 एससीसी

299] .

36. महल चंद सेठिया बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य; क्रि. 1969 का ए. सं. 75,

10 सितंबर, 1969 को निर्णय लिया गया; [1969 (2) यूजे 616 एससीजे।

944 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2014]

12 एस सी आर।

विधायिका और मान्य करने वाले उपाय किसी को भी नहीं छू सके
न्यायालय द्वारा निर्णय। अदालत की ओर से बोलते हुए जे. मित्तर ने कहा
कानूनी स्थिति:

..... किसी राज्य का विधानमंडल किसी भी विधान को पारित करने के लिए सक्षम
है।

उपाय जो इसके तहत विधायी क्षमता के भीतर है

भारत का संविधान। बेशक, यह विषय है

एक की शक्ति बनाने वाले अध्यादेश द्वारा या तो अधिनियमित
के संबंध में राज्यपाल या किसी राज्य का विधानमंडल

उपयुक्त सूची में प्रविष्टियों द्वारा कवर किए गए विषय

संचालन में। कानून की अदालत वैधता पर फैसला दे सकती है।
किसी भी कानून का और उसे अमान्य घोषित करता है यदि वह

विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे था

या यदि यह भाग III में निहित अधिकारों का उल्लंघन करता है
संविधान। यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि यह नीचे गिर सकता है या घोषित कर सकता
है।

फिर भी अलग। यह किसी न्यायालय के किसी भी निर्णय की घोषणा नहीं कर सकता है।
कानून का शून्य या अप्रभावी होना। ”

(जोर दिया गया)

पृथ्वी कॉटन

95. विधायी पर इस न्यायालय के प्रमुख मामलों में से एक

न्यायालय के निर्णय की तुलना में योग्यता पृथ्वी कॉटन 1 1 है।

उस मामले में, गुजरात द्वारा करों के अधिरोपण की वैधता

नगरपालिका (वैधीकरण) अधिनियम, 1963 की ओर से हमला किया गया था

याचिकाकर्ताओं। मान्यता अधिनियम को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया जाना था

पटेल गोरधनदास हरगोविंदास 3 7 में इस न्यायालय के निर्णय का। विधिमान्यकरण अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि

किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद

न्यायालय या न्यायाधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण का आदेश, कोई कर नहीं

37. पटेल गोरधनदास हरगोविंदास बनाम। नगर आयुक्त, अहमदाबाद

; [(1964) 2 एससीआर 608]।

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 945

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]।

किसी भवन या भूमि के पूँजी मूल्य के आधार पर नगरपालिका द्वारा मूल्यांकन या कथित रूप से मूल्यांकन किया गया है और अधिरोपित किया गया है,

नगरपालिका द्वारा पहले किसी भी समय एकत्र या पुनर्प्राप्त किया गया

वैधीकरण अधिनियम का प्रारंभ माना जाएगा -

अवैध रूप से मूल्यांकन किया गया है, लगाया गया है, एकत्र किया गया है या बरामद किया गया है और इस प्रकार निर्धारित कर का अधिरोपण, संग्रह या वसूली

वैध होगा और हमेशा वैध माना जाएगा।

और केवल इस आधार पर प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा कि

के पूँजी मूल्य के आधार पर कर का निर्धारण

भवन या भूमि कानून द्वारा अधिकृत नहीं थी और तदनुसार कोई

वैधीकरण शुरू होने से पहले इस प्रकार निर्धारित कर

अधिनियम और ऐसे प्रारंभ से पहले की अवधि के लिए अधिरोपणीय लेकिन

इस तरह के प्रारंभ से पहले एकत्र या पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है संबंधित के अनुसार एकत्र या पुनर्प्राप्त किया गया

नगरपालिका कानून। संविधान पीठ ने खुलासा किया कि

किसी विधि की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या

विधायिका के पास वह क्षमता है जिसका वह दावा करता है

विषय वस्तु और क्या सत्यापन करने में इसने उस दोष को हटा दिया जो अदालतों ने मौजूदा कानून में पाया था और

करों के वैध अधिरोपण के लिए विधिमान्यकरण में पर्याप्त प्रावधान किए गए। संविधान पीठ के शब्दों में:

" जब कोई विधानमंडल घोषित कर को मान्य करने के लिए निकलता है

एक अमान्य कानून, प्रभावहीनता या अयोग्यता का कारण सत्यापन लेने के लिए कहा जा सकता है से पहले हटा दिया जाना चाहिए

प्रभावी ढंग से जगह। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि विधानमंडल के पास लागू करने की शक्ति होनी चाहिए।

कर, क्योंकि, यदि ऐसा नहीं होता है, तो कार्रवाई कभी भी अप्रभावी और अवैध बनी रहना चाहिए। विधायी क्षमता प्रदान की गई, यह

न तो उसके पास है और न ही व्यायाम। अदालत का निर्णय हमेशा बाध्यकारी होना चाहिए जब तक कि वे शर्तें जिन पर यह आधारित हो इतना मौलिक रूप से बदल गया कि निर्णय नहीं हो सकता था

परिवर्तित परिस्थितियों में दिया गया।

आम तौर पर, एक अदालत 5 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

एक कर अमान्य रूप से लगाया जाना है क्योंकि करने की शक्ति

कर की आवश्यकता है या कानून या नियम या दोनों अमान्य हैं।

या पर्याप्त रूप से अधिकार क्षेत्र का निर्माण न करें। का सत्यापन

इस प्रकार अवैध घोषित कर केवल तभी किया जा सकता है जब आधार अवैधता या अयोग्यता को हटाने में सक्षम हैं और

वास्तव में हटा दिए जाते हैं और इस प्रकार कर को वैध बना दिया जाता है। कभी-कभी यह अधिकार क्षेत्र प्रदान करके किया जाता है जहाँ

इससे पहले अधिकार क्षेत्र का ठीक से निवेश नहीं किया गया था।

कभी-कभी यह पूर्वव्यापी रूप से पुनः अधिनियमित करके किया जाता है

वैध और कानूनी कर प्रावधान और फिर काल्पनिक निर्माण द्वारा पुनः अधिनियमित कानून के अंतर्गत आने के लिए पहले से ही एकत्रित कर।

कभी-कभी विधानमंडल अपना अर्थ देता है और

उस कानून की व्याख्या जिसके तहत कर एकत्र किया गया था और विधायी आदेश द्वारा नए अर्थ को बाध्यकारी बनाता है

अदालतें। विधानमंडल किसी एक या सभी तरीकों का पालन कर सकता है। उनमें से और जब यह ऐसा करता है तो यह प्रभाव को बेअसर कर सकता है

न्यायालय का पूर्व निर्णय जो प्रभावहीन हो जाता है

कानून में बदलाव के बाद। जो भी तरीका अपनाया जाए

यह विधायिका की क्षमता के भीतर होना चाहिए और

ऐसा वैध कानून और इसे पूर्वव्यापी रूप से बनाएँ ताकि बाध्य किया जा सके यहाँ तक कि पिछले लेनदेन भी। एक वैध कानून की वैधता,

इसलिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या विधानमंडल

वह योग्यता रखता है जिसका वह दावा करता है

विषय-वस्तु और क्या इसे मान्यता देने में

उस दोष को दूर करता है जिसे अदालतों ने पाया था विद्यमान कानून और में पर्याप्त प्रावधान करता है

कर के वैध अधिरोपण के लिए कानून को मान्य करना।

(जोर दिया गया)

नपद सभा

96. जनपद सभा में संविधान पीठ 17,

विधायी शक्ति और तमिलनाडु राज्य बनाम के संबंध में स्थिति को दरकिनार कर दिया।

केरल राज्य 947

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

उच्चतम न्यायालय का निर्णय और निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए टिप्पणियाँ:

"अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों पर, यह स्पष्ट है कि

विधानमंडल ने निर्णय को रद्द करने या रद्द करने का प्रयास किया

इस न्यायालय से। कि, हमारे निर्णय में, के लिए खुला नहीं है

विधायिका को हमारी संवैधानिक योजना के तहत करना है। यह है।

संशोधन के लिए कुछ सीमाओं के भीतर विधानमंडल के लिए खुला किसी अधिनियम के प्रावधान पूर्वव्यापी रूप से और क्या घोषित करने के लिए

कानून माना जाएगा, लेकिन यह खुला नहीं है

विधायिका को यह कहने के लिए कि किसी न्यायालय का निर्णय ठीक से

में अपनी शक्तियों के प्रयोग में गठित और प्रस्तुत किया गया

इसके समक्ष लाया गया मामला अप्रभावी माना जाएगा।

और कानून की व्याख्या इस प्रकार से भिन्न होगी

न्यायालय द्वारा घोषित। ”

(हमारे द्वारा प्रदान किया

गया जोर)

अहमदाबाद शहर का नगर निगम

97. उपरोक्त तीन निर्णय और एक और निर्णय

इस न्यायालय ने समामेलित कोयला क्षेत्रों में 38 का उल्लेख किया था

दो-नगर निगम में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ अहमदाबाद शहर 1 6. यह स्वीकार करते हुए कि हमारे संविधान के तहत विधायिका के पास निर्धारित सीमाओं के भीतर शक्तियां हैं

संभावित और साथ ही पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाना और उन शक्तियों का प्रयोग करके, विधायिका को हटा सकता है

एक सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का आधार

उस निर्णय को अप्रभावी बनाना लेकिन किसी भी विधायिका के पास शक्ति नहीं है

स्टेफ के उपकरणों को अवज्ञा या उपेक्षा करने के लिए कहना

अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय।

मदन मोहन पाठक

98. 7-न्यायाधीश द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय

इस विषय पर इस न्यायालय की संविधान पीठ मदन है।

मोहन पाठक 1 4. पी. एन. भगवती, जे. अपने लिए बोलते हुए, 38. एम. पी. बनाम राज्य समामेलित कोलफील्ड्स लिमिटेड और ए. एन. आर.; [(1970) 1 एस. सी. सी. 509)।

948 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

कृष्णा लायर और देसाई, जे. जे. संविधान से निपटते हुए

जीवन बीमा निगम (निपटान संशोधन) अधिनियम, 1976 की वैधता, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में इम्पोस्ट या कर अमान्य होने के लिए, यह देखा गया कि चाहे

विवादित अधिनियम संवैधानिक रूप से वैध था या नहीं, जीवन

बीमा निगम अनिवार्य आदेश का पालन करने के लिए बाध्य था। कलकत्ता उच्च
न्यायालय द्वारा जारी किया गया। एम. एच. बेग, सी. जे., सहमत हैं

पी. एन. भगवती, जे. के दृष्टिकोण से कि अधिकारों के लाभ

कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा मान्यता प्राप्त हो सकता है आक्षेप की धारा 3
के तहत अप्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया जाएगा

चुनिंदा रूप से अधिनियम में कहा गया है कि यदि निर्णय द्वारा प्रदत्त अधिकार को स्वतंत्र रूप
से अलग करने की मांग की जाती है, तो धारा 3

न्यायिक शक्ति को कम करने के लिए अमान्य होगा। एम. एच. बेग, सीजे.

आगे कहा:

" हालाँकि, मैं यह देख सकता हूँ कि भले ही वास्तविक वस्तु

अधिनियम का आदेश के परिणाम को अलग रखना हो सकता है

कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया, फिर भी, धारा

इस वस्तु का बिल्कुल भी उल्लेख न करें। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि

उच्च न्यायालय की अधिकारिता और इसकी प्रभावशीलता

संसद का सामान्य अधिनियम। भले ही अधिनियम की धारा 3
के निर्णय का आधार छीनना चाहता है

कलकत्ता उच्च न्यायालय, इसका उल्लेख किए बिना, क्या अधिनियमित करता है

एक कानून प्रतीत हो सकता है, फिर भी, मुझे लगता है कि, जहां अधिकार हैं
राज्य के खिलाफ नागरिक चिंतित हैं, हमें चाहिए

एक ऐसी व्याख्या अपनाएँ जो उन अधिकारों को बनाए रखे।

इसलिए, व्याख्या के अनुसार मैं गोद लेना पसंद करता हूँ।

अधिकार जो एक में सन्निहित लोगों को पारित किए गए थे
निर्णय और से एक मैडमस का आधार बन गया

इस मामले में उच्च न्यायालय को अप्रत्यक्ष रूप से हटाया नहीं जा सका।

फैशन "।

(हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 949

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

पी. संबमूर्ति

99. न्यायिक समीक्षा की शक्ति का महत्व

पी. संबमूर्ति 3 9 में कानून को महत्वपूर्ण रूप से उजागर किया गया है। में।

उस मामले में, इस न्यायालय ने खंड (5) के उस परंतुक को अभिनिर्धारित करते हुए अनुच्छेद 371-डी मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन था, जिसमें कहा गया था कि यदि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जाता है

राज्य सरकार द्वारा ओवरराइड करके शून्य पर सेट किया जा सकता है इसके खिलाफ निर्णय, यह नियम की मौत की घंटी की तरह लगेगा

कानून से। इस अदालत ने सावधानी बरतते हुए कहा कि नियम

कानून का कोई अर्थ नहीं रहेगा यदि राज्य

सरकार को कानून की अवहेलना करनी थी और फिर भी इससे बचना था।

कावेरी संदर्भ

100. कावेरी संदर्भ 1 8 में, यह न्यायालय संबंधित था।

कर्नाटक कावेरी बेसिन सिंचाई की वैधता के साथ

संरक्षण अध्यादेश, 1991। मदन मोहन पाठक 14 और पी. संबमूर्ति 3 9,1 में अपने पिछले फैसलों पर भरोसा करते हुए

इस न्यायालय ने अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि उसने न्यायिक शक्ति पर प्रभाव डालने वाले न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

राज्य से।

पी. यू. सी. एल

101. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) 1 5 में,

तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचाराधीन प्रश्न

यह न्यायालय लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 2002 की वैधता था। संशोधन का पालन किया गया

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में इस न्यायालय का निर्णय। 40

एम. बी. शाह, जे. ने बहुमत के लिए बोलते हुए पहले देखा

पी. संबमूर्ति 39, कावेरी में इस न्यायालय के निर्णय संदर्भ 1 8 के शहर के नगर निगम

अहमदाबाद 1 6, पृथ्वी कॉटन 1 1 और महल चंद सेठिया 3,6 और कहा गया:

39. पी. संबमूर्ति और अन्य। वी. ए. पी. और ए. एन. आर. का राज्य ; [(1987) 1 एससीसी 362]।

40. भारत संघ बनाम। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड एन. आर. ; [(2002) 5

एस. सी. सी. 294]।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

950

" विधायिका उस आधार को बदल सकती है जिसके आधार पर कोई निर्णय लिया जाता है।

इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और सामान्य रूप से कानून में परिवर्तन किया जाता है।

हालाँकि, इस शक्ति का प्रयोग इसके अधीन किया जा सकता है -

संवैधानिक प्रावधान, विशेष रूप से, विधायी क्षमता

और यदि यह संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ऐसा कानून अमान्य होगा जैसा कि प्रावधान किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत। विधायिका भी

न्यायालय के किसी भी निर्णय को अमान्य घोषित नहीं कर सकते।
या कोई प्रभाव नहीं "।

केशवानंद भारती, इंदिरा नेहरू गांधी, बाल मुकुंद साह और आई. आर. कोएल्हो

102. विधायिका के बीच शक्तियों का विभाजन,

कार्यपालिका और न्यायपालिका संविधान की मूल संरचना है जिसे सी. जे. सीकरी ने केशवानंद में स्पष्ट रूप से कहा है।

भारत 1 1. शेलत और ग़ोवर, जे. जे. सीकरी के विचारों को दोहराते हुए, जे. ने कहा कि विधायिका के बीच शक्ति का सीमांकन,

कार्यपालिका और न्यायपालिका को बुनियादी माना जा सकता है। संवैधानिक संरचना के तत्व। इंदिरा मामले में इस न्यायालय के बाद के फैसलों में भी यही विचार व्यक्त किया गया है।

नेहरू गांधी 2, बाल मुकुंद साह 1 3 और आई. आर. कोएल्हो। उन नौ आई. आर. कोएल्हो 44 में न्यायाधीश संविधान पीठ ने वर्णन किया है कि समानता, कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा और शक्तियों का पृथक्करण।

संविधान की मूल संरचना के भाग हैं। आई. आर. कोएल्हो में अदालत ने कहा:

इनमें से प्रत्येक अवधारणा घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।

अगर कानून के सामने समानता नहीं है तो कानून का शासन नहीं हो सकता है। ये अर्थहीन होंगे यदि उल्लंघन किया गया था

41. परम पूज्य केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम। केरल राज्य और

एन. आर. ; [(1973) 4 एससीसी 225]।

42. श्रीमती. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण और अन्र; [1975 (पूरक) एससीसी

1] . .

43. बिहार और अन्र राज्य। वी. बाल मुकुंद साह और अन्य; [(2000) 4 एससीसी 640]।

44. एल. आर. द्वारा आई. आर. कोएल्हो (मृत)। वी. टी. एन. राज्य ; [(2007) 2 एससीसी 1)।

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 951

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं। यह सब होगा

अनावश्यक यदि विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ एक अंग में निहित हैं।
इसलिए, निर्णय लेने का कर्तव्य

क्या सीमाओं का उल्लंघन किया गया है

न्यायपालिका पर रखा गया "।

सक्सेना

103. विधायी और न्यायिक के बीच अंतर करना

आई. एन. सक्सेना में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया (पैरा 21)

22 रिपोर्ट):

" 21. एक "विधायी" अधिनियम और एक के बीच का अंतर

" न्यायिक अधिनियम सर्वविदित है, हालांकि कुछ विशिष्ट उदाहरणों में वह रेखा जो एक श्रेणी को न्यायिक अधिनियम से अलग करती है।

अन्य आसानी से समझ में नहीं आ सकते हैं। का निर्णय

द्वारा अधिनियमित कानून के अनुसार पक्षों के अधिकार

विधायिका एक न्यायिक कार्य है। इस प्रदर्शन में

कार्य, न्यायालय विधानमंडल के आशय और अधिदेश की व्याख्या करता है और उसे प्रभावी बनाता है जैसा कि कानून में सन्निहित है। दूसरी ओर, यह विधायिका को निर्धारित करना है

कानून, आचरण के मानदंड निर्धारित करना जो पक्षों को नियंत्रित करेगा और लेन-देन और न्यायालय से प्रभाव देने की अपेक्षा करना

उस कानून को।

22. जबकि, विधायी और विधायी के बीच इस अंतर को देखते हुए

न्यायिक कार्य, विधायिका बेयर द्वारा नहीं कर सकते हैं

घोषणा, अधिक के बिना, सीधे रह, उल्टा या

एक न्यायिक निर्णय को ओवरराइड करता है, यह अभ्यास में किसी भी समय हो सकता है

अनुच्छेद 245 द्वारा प्रदत्त पूर्ण शक्तियों और 246 संविधान एक न्यायिक निर्णय को अप्रभावी बनाता है

अपने विधायी क्षेत्र के भीतर किसी विषय पर एक वैध कानून बनाकर

मौलिक रूप से पूर्वव्यापी के साथ परिवर्तन या परिवर्तन,

उपचारात्मक या तटस्थकारी प्रभाव उन स्थितियों पर पड़ता है जिन पर

निर्णय आधारित है। जैसा कि रे, सी. जे. ने इंदिरा में बताया है।

नेहरू गांधी बनाम. राज नारायण, अप्रभावी प्रतिपादन

सक्षम न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णय या आदेश

विधायी अधिनियम द्वारा उनके आधार को बदलना एक अच्छी तरह से 952 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. है।

कानून जो प्रभावहीनता के कारणों को दूर करता है
या कार्रवाई या कार्यवाही की अयोग्यता एक नहीं है

न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण "।

103.1 . आई. एन. सक्सेना 45 में, इस न्यायालय ने पहले एक

हरि सिंह 46 में निर्णय जिसमें सात न्यायाधीशों की एक पीठ

इस न्यायालय ने एक की वैधता का न्याय करने के लिए दो परीक्षणों को नोट किया

कानून को मान्य करना: (i) क्या विधायिका के पास है
विषय-वस्तु पर योग्यता, और, (ii) क्या
मान्यता, विधायिका ने उस दोष को हटा दिया है जो
अदालतों ने पिछले कानून में पाया है। इन दोनों का अनुसरण करते हुए
परीक्षण, चार- / में न्यायाधीश पीठ। एन. सक्सेना⁴⁵ ने तीसरा परीक्षण जोड़ा: क्या
यह भाग III के प्रावधानों के अनुरूप है
संविधान। पी. कन्नदासन

104. पृथ्वी कॉटन 1 1 को हिंदुस्तान गम में फॉलो किया गया है।

और केमिकल्स 47, विजय मिल्स कंपनी 48 और पी।

कन्नदासन 1 9. इस निर्णय पर बोझ डालना आवश्यक नहीं है।

तीनों निर्णय, हमारे विचार में, उनमें से एक के संदर्भ में, यानी पी. कन्नदासन पर्याप्त
होंगे। पी. कन्नदासन 9 में यह न्यायालय

उल्लेख किया कि भारत के संविधान ने इस सिद्धांत को मान्यता दी

राज्य के तीन अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण,

अर्थात्, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। द.

अदालत ने कहा:

" 15 यह याद रखना चाहिए कि हमारा संविधान

अलगाव के सिद्धांत को पहचानता है और शामिल करता है

46. हरि सिंह और ओआरएस। वी. सैन्य संपदा अधिकारी और ए. एन. आर. ; [(1972) 2
एससीसी 239]। 47. हिंदुस्तान गम एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम। हरियाणा राज्य
और अन्य; [(1985)

4 एससीसी 124]।

48. विजय मिल्स कम्पनी लिमिटेड और अन्य बनाम। गुजरात राज्य और अन्य। ;
[(1993)

1 एस. सी. सी. 345]

49. पी. कन्नदासन और अन्य बनाम टी. एन. और अन्य की स्थिति; [(1996) 5 एससीसी 670]।

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 953

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

राज्य के तीन अंगों के बीच की शक्तियाँ।, द.

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भले ही

संविधान ने सरकार के संसदीय रूप को अपनाया है जहां विधायिका के बीच विभाजन रेखा है।

और कार्यपालिका कमजोर हो जाती है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अभी भी मान्य है।
हमारा भी एक संघीय रूप है सरकार। वे विषय जिनके संबंध में संघ और

राज्य कानून बना सकते हैं जिन्हें सूची I में अलग से निर्धारित किया गया है

और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II क्रमशः। (सूची III निश्चित रूप से एक
समवर्ती सूची है।) द.

संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में निवेश किया है।

संवैधानिक सीमाएँ। जहाँ किसी राज्य द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम विधायिका
को अदालतों द्वारा इस आधार पर अमान्य कर दिया जाता है कि

राज्य विधानमंडल इसे अधिनियमित करने के लिए सक्षम नहीं था,

राज्य विधानमंडल यह घोषणा करते हुए कोई कानून नहीं बना सकता है कि

न्यायालय का निर्णय कार्य नहीं करेगा; यह खारिज नहीं कर सकता है।

या अदालत के फैसले को रद्द कर दें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि

कि अन्य विधायिका जो उस कानून को लागू करने के लिए सक्षम है, उस कानून को लागू नहीं
कर सकती है। यह हो सकता है। इसी तरह, यह एक के लिए खुला है

विधायिका द्वारा बताए गए निर्णय के आधार को बदलने के लिए इस न्यायालय द्वारा श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम. ब्रोच

नगर पालिका-सभी का पालन करते हुए

संवैधानिक सीमाएँ; ऐसे मामले में, का निर्णय

न्यायालय इस अर्थ में अप्रभावी हो जाता है कि आधार

जिस पर इसे प्रस्तुत किया जाता है, उसे बदल दिया जाता है। इस तरह बनाए गए नए कानून या संशोधित कानून को अन्य तरीकों से चुनौती दी जा सकती है।

आधार पर लेकिन इस आधार पर नहीं कि यह अप्रभावी होना चाहता है

या अदालत के फैसले को दरकिनार करें। यह वह है जो

"नियंत्रण और संतुलन" का अर्थ सरकार की एक प्रणाली में निहित है जिसमें अलग करने की अवधारणा को शामिल किया गया है शक्तियाँ। इस न्यायालय द्वारा श्री से शुरू होने वाले कई फैसलों में इस पहलू पर बार-बार जोर दिया गया है।

पृथ्वी कॉटन मिल्स। हमारे संविधान के तहत, कोई भी विंग दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है।

प्रत्येक शाखा अपनी शक्ति और 954 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. प्राप्त करती है।

संविधान से अधिकार क्षेत्र। प्रत्येक को अपने भीतर काम करना चाहिए इसे आवंटित क्षेत्र। एक पंख को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करना

दूसरे में एक असंतुलन पेश करना होगा

प्रणाली और पृथक्करण की मूल अवधारणा का निषेध हमारी सरकार की प्रणाली में निहित शक्तियाँ।

इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी

105. भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी 50 में, एक

इस न्यायालय को संबोधित दलीलें यह थीं कि केरल

विधायिका के पास विवादित अधिनियम की धारा 11 को लागू करने की कोई शक्ति नहीं थी।

पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लेवी को मान्य करने वाला अधिनियम

न्यायालयों की न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण करना। जबकि इस विवाद से निपटने के लिए, न्यायालय ने इस न्यायालय के पहले के फैसलों का उल्लेख किया और निम्नलिखित सिद्धांतों को तैयार किया:

(पैरा 56; पीजीएस। 662-663 रिपोर्ट):

" (1) पक्षकारों के अधिकारों का निर्णय आवश्यक न्यायिक कार्य है। विधायिका को निर्धारित करना होगा

आचरण या नियमों के मानदंड जो पक्षों को नियंत्रित करेंगे और

लेन-देन और अदालत से उन्हें प्रभावी बनाने की आवश्यकता है;

(2) संविधान में नाजुक संतुलन को चित्रित किया गया है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा संप्रभु शक्ति का प्रयोग;

(3) कानून के शासन द्वारा शासित लोकतंत्र में, विधायिका

अनुच्छेद 245 और 246 और अन्य के तहत शक्ति का प्रयोग करता है

संबंधित में प्रविष्टियों के साथ पढ़े गए साथी लेख

कानून बनाने के लिए सातवीं अनुसूची में सूचीबद्ध करता है जो

इसमें कानून में संशोधन करने की शक्ति शामिल है।

(4) न्यायालयों को न्यायिक शक्ति को समान रूप से बनाए रखने के लिए उनकी चिंता और प्रयास में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए

तीन संप्रभु अधिकारियों के बीच संविधान द्वारा तैयार किया गया नाजुक संतुलन। कानून के उस शासन के लिए

50. भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी और अन्य बनाम। केरल राज्य और अन्य;

[(1996) 7 एस. सी. सी. 637]

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 955 आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

स्थापना के संवैधानिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्याप्त एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था, संबंधित संप्रभु

कार्यकर्ताओं को अपने जोड़ों में स्वतंत्र रूप से खेलने की आवश्यकता होती है ताकि मार्च सामाजिक प्रगति और व्यवस्था निर्बाध बनी हुई है। स्वादिष्ट भोजन के साथ बनाया गया चिकना संतुलन हमेशा होना चाहिए

बनाए रखा;

(5) न्यायिक शक्ति की रक्षा करने की अपनी चिंता में, यह है

अति उत्साही होना और घुसपैठ करना अनावश्यक है वैध कानून को अमान्य करते हुए न्यायिक संरक्षण में

कुशलता से बनाया गया; (6) इसलिए अदालत को कानून की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है।

पता लगाएँ: (क) क्या न्यायालय द्वारा उप इंगित किया गया है और

पिछले कानून द्वारा झेली गई अयोग्यता का अनुपालन करके इलाज किया जाता है

कानूनी और संवैधानिक आवश्यकताएँ; (बी) क्या

संविधान का भाग III। (7) न्यायालय के पास अमान्य को मान्य करने की शक्ति नहीं है।

कानून बनाना या अवैध रूप से बनाए गए और एकत्र किए गए कर को वैध बनाना या अमान्य होने के मानदंड को हटाना या कोई उपाय प्रदान करना।

ये न्यायिक कार्य नहीं हैं बल्कि अनन्य प्रांत हैं। विधायिका से। इसलिए, वे अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं

न्यायिक शक्ति।

(8) विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, विधायिका मात्र

घोषणा, बिना किसी और चीज़ के, किसी न्यायिक निर्णय को सीधे तौर पर रद्द, संशोधित या ओवरराइड नहीं कर सकती है। यह न्यायिक कार्य कर सकता है।

अपने विधायी क्षेत्र के भीतर विषय पर वैध कानून लागू करके इसके मौलिक रूप से परिवर्तन या परिवर्तन करके अप्रभावी निर्णय

चरित्र पूर्वव्यापी रूप से। बदला या बदला गया

न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यदि वे शर्तें थीं कानून को अमान्य घोषित करने के समय मौजूद था। इसे सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. के साथ पूर्वव्यापी कानून को लागू करने का भी अधिकार है।

956

एक निश्चित तिथि या एक विशेष तिथि से प्रभावी। द.

विधायिका कर या शुल्क के स्वरूप को बदल सकती है
अनुज्ञेय कर के लिए अनुज्ञेय नहीं है लेकिन कर या लेवी होनी चाहिए

इस तरह के चरित्र का जवाब दें और विधायिका सक्षम है

हटाने पर इस तरह के कर को मान्य करने वाले अमान्य कर की वसूली करें

विषय से वसूली के लिए अमान्य आधार या राज्य से वसूली को अप्रभावी बनाता है।
इसके लिए सक्षम है

विधायिका पूर्वव्यापी प्रभाव से कानून बनाएगी और

अपनी एजेंसियों को उस पर कर लगाने और एकत्र करने के लिए अधिकृत करें।

इस आधार पर, संग्रहित शुल्क और वसूली लागू करें

द्वारा घोषित किए जाने के बावजूद, वैध किए गए कर का

न्यायालय या उसकी वसूली के लिए दिया गया निर्देश।

(9) सुसंगत धागा जो सभी निर्णयों के माध्यम से चलता है

इस न्यायालय का कहना है कि विधायिका सीधे तौर पर खारिज नहीं कर सकती है।

निर्णय लेना या कोई निर्देश देना जो उस पर बाध्यकारी नहीं है लेकिन

इसे हटाकर निर्णय को अप्रभावी बनाने की शक्ति है
जिस आधार पर निर्णय दिया गया था, वह सुसंगत था
संविधान और विधायिका के कानून के साथ
ऐसा करने की क्षमता रखें "।

अरूरन शक्कर

106. अरूरन शुगर 51 में मामला इस अदालत में पहुंचा
मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय से। मद्रास से पहले
उच्च न्यायालय, संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी
टी. एन. भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा का निर्धारण) संशोधन
विभिन्न आधारों पर अधिनियम, 1978। की डिवीजन बेंच
मद्रास उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। तमिल राज्य
अदालत। विधायिका की शक्ति से निपटने के दौरान, इस न्यायालय की संविधान
पीठ ने कहा: किसी कानून को संशोधित करने, हटाने या मिटाने या अधिनियमित करने की
विधायिका की शक्ति
एक कानून पर संभावित या पूर्वव्यापी रूप से सवाल नहीं उठाया जा सकता है। और
चुनौती दी जब तक कि अदालत का विचार न हो कि इस तरह का अभ्यास
51. राज्य टी. एन. वी. अरूरन शुगर लिमिटेड ; [(1997) 1 एससीसी 326]।

957

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसकी जरूरत नहीं है।
प्रभावित किया कि जब भी कोई अधिनियम या संशोधन लाया जाता है

पूर्वव्यापी बल या अधिनियम के किसी भी प्रावधान को हटा दिया जाता है
 पूर्वव्यापी रूप से, इस प्रक्रिया में कुछ के अधिकार होने के लिए बाध्य हैं
 एक या दूसरे तरीके से प्रभावित। हर मामले में, यह आग्रह नहीं किया जा सकता है कि
 विधायिका द्वारा एक नया विधेयक पेश करते समय अभ्यास किया जाए।

पूर्वव्यापी प्रावधान या मौजूदा प्रावधान को हटाना

प्रभाव स्वयं संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

यदि उस स्थिति को स्वीकार कर लिया जाता है, तो आवश्यक परिणाम होगा -

कि विधायिका के पास पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है,

क्योंकि उस घटना में एक निहित अधिकार प्रभावित होता है; बेशक, एक में विशेष
 स्थिति इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि इस तरह की कवायद थी

यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। संविधान

पीठ ने कहा कि विवादित अधिनियम के प्रावधान नहीं हैं

किसी भी निहित या अर्जित अधिकार को प्रभावित करने का तात्पर्य है, यह केवल पुनर्स्थापित
 करता है

वह स्थिति जो उस समय मौजूद थी जब मूल अधिनियम लागू था।

इसने आगे कहा कि संशोधन अधिनियम राज्य के साधनों को अवज्ञा या अवहेलना करने के लिए
 नहीं कहता है

उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय लेकिन उसने जो किया है वह यह है कि

अपने निर्णय के आधार को हटा दिया है।

एल्फिंस्टन स्पनिंग एंड वीविंग कंपनी

107. एल्फिंस्टन में इस न्यायालय की संविधान पीठ

कताई और बुनाई कंपनी 3 3 निर्धारित की गई: (a) वहाँ है

हमेशा एक धारणा है कि विधायिका अपने से अधिक नहीं है

अधिकारिता, (ख) यह स्थापित करने का भार कि विधायिका

संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन हमेशा उस व्यक्ति पर होता है जो इसके अधिकारों को चुनौती देता है, और (सी) जब तक कि यह स्पष्ट नहीं हो जाता है

उचित संदेह से परे कि विचाराधीन कानून ने संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन किया है, इसकी अनुमति दी जानी चाहिए खड़े हो जाओ।

धरम दत्त

108. सिद्धांत कि रंगीन कानून का सिद्धांत

958 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. की ओर से प्रामाणिक या दुर्भावनापूर्ण कार्य शामिल नहीं है।

इस न्यायालय द्वारा धरम दत्त 52 में विधायिका पर प्रकाश डाला गया है। भरोसा करना। के. सी. गजपति नारायण देव 53 में पहले के निर्णयों पर और

आयुर्वेदिक और यूनानी टिबिया कॉलेज 54, धरम में न्यायालय

दत्त 52 ने आगे कहा:

" 16 पूरा सिद्धांत खुद को इस प्रश्न में हल करता है

एक अधिनियम बनाने के लिए एक विशेष विधानमंडल की क्षमता का विशेष कानून। यदि विधायिका एक पारित करने के लिए सक्षम है

अप्रसंगिक। दूसरी ओर, यदि विधायिका का अभाव है योग्यता, उद्देश्य का सवाल बिल्कुल नहीं उठता है।

इसलिए हम विधायी व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

विवादित अधिनियम बनाने के लिए संसद की क्षमता

कानून। यदि संसद के पास अपेक्षित क्षमता है -

विवादित अधिनियम को अधिनियमित करना, उद्देश्य की जांच जो संसद को इस अधिनियम को पारित करने के लिए राजी करने का कोई मतलब नहीं होगा

बिल्कुल भी उपयोग करें। "

108.1 . पिछले के प्रभाव के सवाल पर

विवादित विधान पर उच्च न्यायालय का निर्णय, यह

धरम दत्त 52 में अदालत ने मदन मोहन पाठक 1 4 को संदर्भित किया, पृथ्वी
कॉटन 1 1, इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी, इंदिरा नेहरू

गाँधी 1 2 और इस न्यायालय के अन्य निर्णय और अनुच्छेद 69 (पृ. रिपोर्ट का
753) इस प्रकार हैं:

" 69. विद्वान एकल न्यायाधीश के उस निर्णय को नहीं छोड़ा गया था

निर्विरोध। वास्तव में, के निर्णय की शुद्धता

विद्वान एकल न्यायाधीश को संघ द्वारा जारी किया गया था

भारत एक अंतर-न्यायालय अपील दायर करके। याचिका दायर करना
अपील के तहत निर्णय की अंतिमता को नष्ट कर देता है। द.

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्धारित मुद्दे खुले थे

डिवीजन बेंच के समक्ष विचार के लिए। हालांकि,

डिवीजन बेंच को सुनवाई के अवसर से वंचित कर दिया गया और

52. धरम दत्त और ओआरएस। वी. भारत संघ और ओआरएस। ; [(2004) 1 एससीसी
712]।

53. श्री श्री के. सी. गजपति नारायण देव बनाम। उड़ीसा राज्य; [ए. आई. आर. 1953
एस. सी. 375]

54. न्यासी मंडल, आयुर्वेदिक और यूनानी टिबिया महाविद्यालय, दिल्ली बनाम। दिल्ली राज्य
(अब दिल्ली प्रशासन) और एएनआर। ; [ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 458]

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 959

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

पीड़ित पक्ष भी निर्णय के लिए दबाव नहीं डाल सका

योग्यता के आधार पर अपील, जैसा कि पहले किया जा सकता था

अध्यादेश का संचालन बंद होने के कारण इसे निष्फल बना दिया गया था। भारत संघ,

चाहे उसने कितना भी दुखी महसूस किया हो

विद्वान एकल न्यायाधीश की घोषणा, नहीं थी इसे आगे बढ़ाने के लिए उपाय उपलब्ध
छोड़ दिया गया। का निर्णय

खंड पीठ ने इसकी शुद्धता पर ध्यान देने से इनकार कर दिया

एकल न्यायाधीश के फैसले का प्रभाव छोड़ने का था मामला व्यापक है। पहले के लैप्स
होने पर

डिवीजन बेंच के समक्ष अपील लंबित अध्यादेश,

की अवैधता के बारे में एकल न्यायाधीश का निर्णय

पूर्ववर्ती अध्यादेश, अब इस न्यायालय को इससे रोक नहीं सकता है एक नए कानून की
वैधता के बारे में उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना,

भले ही नए कानून में इसी तरह के प्रावधान हों।

108.2 . हालाँकि, न्यायालय ने आक्षेप को अमान्य नहीं किया

अदालत ने अनुच्छेद 70 (pg.753) में यही कहा है।

ऑर्ट:

" शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत और

राज्य के तीन अंगों का संवैधानिक सम्मेलन, एक-दूसरे के लिए सम्मान और सम्मान
होना ही काफी है

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाई गई याचिका का
जवाब दें। हम.

हम उस कानून को निरस्त नहीं कर सकते जो हमारे पास है

उच्च न्यायालय का गलत निर्णय और त्रुटि से पहले स्वयं व्यपगत अध्यादेश की अपील
में सुधार किया जा सकता है।

यह याद रखना होगा कि विवादित अधिनियम द्वारा

संसद ने उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज नहीं किया है
न ही इसने उसी कानून को वैध घोषित किया है जिसे न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया गया है।

इसमें 960 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. होंगे।

बेहतर होगा यदि विधेयक को किसी अधिनियम में पारित करने से पहले
संसद का ध्यान विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था
एक पूर्ववर्ती सामग्री अध्यादेश का तथ्य
उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त। यदि कोई अध्यादेश अमान्य कर दिया गया है
उच्च न्यायालय को अभी भी एक अधिनियम में फिर से अधिनियमित किया गया है
उच्च न्यायालय द्वारा घोषणा, बाद का अधिनियम
यह पता चलने पर एक बार फिर रद्द किया जा सकता है कि
उच्च न्यायालय अवैधता का दृष्टिकोण लेने में सही था
अध्यादेश का, जो उसने किया। लेकिन जैसा कि हमारे पास है
के सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर रद्द किया गया
शक्तियों का पृथक्करण "।

विरेन्द्र सिंह हुड्डा (द्वितीय)

109. विरेन्द्र सिंह हुड्डा (द्वितीय) 55 में यह न्यायालय था -

हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी) की वैधता से संबंधित शाखा और संबद्ध सेवाएँ और
अन्य सेवाएँ, सामान्य /

संयुक्त परीक्षा अधिनियम, 2002 (संक्षेप में, 'अधिनियम')। द.

उस मामले में याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि अधिनियम राज्य विधायिका द्वारा
न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग

विरेन्द्र में इस न्यायालय के निर्णयों को निरस्त करने की दृष्टि से

सिंह हुड्डा (1) और संदीप सिंह 57। को ध्यान में रखते हुए

याचिकाकर्ताओं की दलीलें, द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों में से एक

निर्धारण के लिए न्यायालय था, क्या अधिनियम, हद तक

विरेन्द्र सिंह हुड्डा (1) और संदीप सिंह 57 मामलों में निर्णय। न्यायालय ने नोट किया कि के पहलुओं में से एक विचाराधीन प्रश्न यह था कि क्या मंडमस का एक रिट है

विधायिका के अधिनियमन द्वारा अप्रभावी बनाया जा सकता है।

55. विरेन्द्र सिंह हुड्डा (द्वितीय) और अन्य। वी. हरियाणा राज्य और एक अन्य;

[(2004) 12 एस. सी. सी. 588]

56. विरेन्द्र सिंह हुड्डा (आई) और अन्य। वी. हरियाणा राज्य और एक अन्य; [(1999)

3 एस. सी. सी. 696]

57. संदीप सिंह बनाम। हरियाणा और अन्तर राज्य।; [(2002) 10 एस. सी. सी. 549]

961

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

विधायी शक्ति से निपटने के लिए, न्यायालय ने कहा, "पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कानून बनाने की विधायी शक्ति अच्छी है।

पहचाने जाते हैं। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि हालांकि विधायिका ने

लेकिन, यह कानून बनाने की क्षमता के अधीन है, उस आधार को हटाने की शक्ति जिसके कारण न्यायालय का निर्णय हुआ। द. विधायिका के पास पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कानून बनाने की शक्ति है लेकिन

अदालत के फैसले को बदलने की भी कोई शक्ति नहीं है

पूर्वव्यापी या संभावित रूप से। संविधान स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है

विधायी शक्ति और न्यायिक शक्ति की सीमाएँ। कोई नहीं कर सकता।

दूसरे से ढके खेत का अतिक्रमण करें। बनाए गए हैं कानून विधायिका द्वारा संवैधानिक के अनुरूप होना चाहिए

प्रावधान "।

109.1 अदालत ने आगे कहा: “यह अच्छी तरह से तय है कि यदि

विधायिका के पास विषय-वस्तु पर अधिकार है और

एक वैध कानून और इसे पूर्वव्यापी रूप से बनाएँ ताकि अतीत को भी बांध सकें लेन-देन। अतः किसी मान्यता देने वाले कानून की वैधता निर्भर करती है।

इस पर कि क्या विधायिका के पास वह क्षमता है जो

यह विषय वस्तु पर दावा करता है और क्या सत्यापन करने में यह उस दोष को दूर करता है जिसे अदालतों ने पाया था मौजूदा कानून "।

109.2 . अदालत ने यह भी कहा: “यह समान रूप से अच्छी तरह से तय है कि

विधायिका एक खुली घोषणा द्वारा, बिना किसी और चीज़ के, किसी न्यायिक निर्णय को सीधे खारिज, उलट या ओवरराइड नहीं कर सकती है।

यह किसी भी समय प्रदत्त पूर्ण शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

संविधान द्वारा उस पर किसी न्यायिक निर्णय को उसके विधायी क्षेत्र के भीतर किसी विषय पर एक वैध कानून बनाकर अप्रभावी बना दिया जाता है,

मौलिक रूप से पूर्वव्यापी, उपचारात्मक या तटस्थ प्रभाव के साथ परिवर्तन या परिवर्तन उन शर्तों पर होता है जिन पर इस तरह का निर्णय लिया जाता है। आधारित '।

109.3 . अतिक्रमण के बीच अंतर करते समय

न्यायिक शक्ति और एक के प्रभाव के शून्यीकरण पर

कानून को पूर्वव्यापी रूप से बदलकर न्यायिक निर्णय, न्यायालय 962 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

तीरथ राम राजिंदर नाथ 58 को संदर्भित किया और कहा, "पूर्व विधायिका की क्षमता से बाहर है लेकिन बाद वाला है

अपनी अनुमेय सीमाओं के भीतर। इसका कारण यह है कि

हमारे संविधान द्वारा अपनाई गई शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा

योजना। पक्षकारों के अधिकारों का निर्णय

कानून एक न्यायिक कार्य है। विधायिका को निर्धारित करना होगा

आचरण के मानदंडों को निर्धारित करने वाला कानून जो पक्षों को नियंत्रित करेगा और

लेन-देन और अदालत से उस कानून को लागू करने की मांग करना।

109.4 . एस. एस. बोला 9 9 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए,

विरेन्द्र सिंह हुड्डा (द्वितीय) मामले में न्यायालय ने कहा:

" 49. जब किसी विशेष नियम या अधिनियम की व्याख्या एक

विधि की अदालत एक निर्दिष्ट तरीके से और विधि-निर्माण प्राधिकरण यह राय बनाता है कि ऐसी व्याख्या

पक्षकारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और

घोर अन्यायपूर्ण होना और तदनुसार नियमों का एक नया सेट होना

या कानून बनाए जाते हैं, इसे अक्सर चुनौती दी जाती है

यह आधार है कि विधायिका ने न्यायिक शक्ति को हड़प लिया है।

ऐसे मामले में अदालत को जांच करने का एक नाजुक काम है।

विधायिका द्वारा अधिनियमित कानूनों का नया सेट और खोजने के लिए

पता लगाएँ कि क्या वास्तव में विधायिका ने प्रयोग किया है

केवल पूर्ववर्ती न्यायिक की घोषणा करके विधायी शक्ति

अवैध और अप्रभावी होने का निर्णय या विधायिका ने विधान के स्वरूप को परिवर्तित और परिवर्तित किया जो

अंततः न्यायिक निर्णय अप्रभावी हो सकता है।

लेन-देन

110. इस बारे में अच्छी संख्या में निर्णयों का सर्वेक्षण करने के बाद

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर अदालत, यह समय है कि हम

इस पहलू पर कुछ प्रमुख विदेशी निर्णयों पर विचार करें। इस श्रेणी का पहला निर्णय जो विचार योग्य है,

जिसका उल्लेख श्री विनोद बोबडे ने भी किया था, तमिलनाडु के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील लियानगे 1 2 हैं। लियानगे 1 2 में तथ्य

58. तीरथ राम राजिंदर नाथ, लखनऊ बनाम। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य। ; [(1973) 3

एस. सी. सी. 585]

59. एस. एस. बोला और अन्य। वी. बी. डी. सरदाना और अन्य। ; [(1997) 8 एस. सी. सी. 522]

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 963

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

द्वारा न्यायिक कार्य के हड़पने का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान करें

एक लंबित मामले में विधायिका। उस मामले में, न्यायिक

प्रिवी काउंसिल की समिति ने माना कि आपराधिक कानून

(1962 का विशेष प्रावधान) अधिनियम संख्या 1 ने न्यायिक शक्ति को हड़प लिया और उसका उल्लंघन किया और इसलिए यह अमान्य था। इस अधिनियम में संशोधन किया गया

सीलोन में लागू दंड प्रक्रिया संहिता

तख्तापलट के प्रयास के संबंध में जेल में बंद व्यक्तियों की हिरासत को पूर्व-उत्तर कार्यतः वैध बनाना, अपराधों के वर्ग को व्यापक बनाना।

जिसके लिए तीन न्यायाधीशों द्वारा मुकदमा चलाया जाता है, जिन्हें मंत्री द्वारा नामित किया जाता है जूरी के बिना बैठे न्याय को मान्य करने का आदेश दिया जा सकता है

वारंट के बिना किए गए कुछ अपराधों के लिए पूर्वव्यापी गिरफ्तारी और अपराध के लिए नए न्यूनतम दंड निर्धारित करने के लिए

रानी के खिलाफ युद्ध छेड़ना। यह कानून बनाया गया था कि

न्यायपालिका में एक गंभीर और जानबूझकर घुसपैठ शामिल है।

क्षेत्र "जो संविधान द्वारा आवश्यक विधायी शक्ति से न्यायिक शक्ति के पृथक्करण के साथ असंगत था

सीलोन। लियानाज 1 2 प्रभावी रूप से यह बताता है कि न्यायिक शक्ति है हड़पा गया (i) जब किसी विशिष्ट मामले में विधायी हस्तक्षेप होता है।

कार्यवाही, (ii) हस्तक्षेप लंबित मुकदमेबाजी को प्रभावित करता है और (iii) हस्तक्षेप न्यायिक प्रक्रिया को ही प्रभावित करता है, अर्थात्,

न्यायपालिका या अधिकारों, प्राधिकरण का विवेकाधिकार या निर्णय

लिखित संविधान वाले देशों के मामले में शक्तियां होनी चाहिए से संविधान की शर्तों के अनुसार प्रयोग किया गया

जिनसे वे व्युत्पन्न हुए हैं। वास्तविक प्रकृति पर अवलोकन करना

न्यायपालिका के कार्य में संसद द्वारा किए गए परिवर्तन न्यायपालिका में एक गंभीर और जानबूझकर की गई घुसपैठ

गोल। यह निम्नलिखित अंश पर ध्यान देने योग्य है

लियानाज 1 2:

" यदि इस प्रकार के अधिनियम वैध थे तो न्यायिक शक्ति

विधानमंडल द्वारा पूरी तरह से अवशोषित किया जा सकता है और न्यायाधीशों के हाथों से लिया जा सकता है। यह सराहना की जाती है कि विधानमंडल का ऐसा कोई सामान्य इरादा नहीं है। यह घिरा हुआ था

एक गंभीर स्थिति और इससे निपटने के लिए गंभीर उपाय किए गए यह सोचकर, किसी को यह मान लेना चाहिए कि उसके पास ऐसा करने की शक्ति थी

↑ सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

964

और सही काम कर रहा था। लेकिन यह विचार अप्रासंगिक है,

और संविधान का उल्लंघन करने वाले कार्यों को कोई वैधता नहीं देता है। एक बार जो किया जाता है, अगर इसकी अनुमति दी जाती है, तो उसे फिर से किया जा सकता है।

और कम संकट और कम गंभीर परिस्थितियों में। और

इस प्रकार न्यायिक शक्ति का क्षय हो सकता है। इस तरह का क्षरण है

संविधान के स्पष्ट इरादे के विपरीत।

110.1 . लियानाज 1 2 निहित के सिद्धांत पर आधारित है

विधायी शक्ति पर सीमाएँ। यह पद स्वीकार किया जाता है।

केशवानंद भारती में हमारे अपने न्यायालय द्वारा 41 (प्रति शेल्ट और गुरोवर, जे. जे.) .

निकोलस

111. जहां तक ऑस्ट्रेलिया में संवैधानिक स्थिति का संबंध है, यह

यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि ऑस्ट्रेलिया का एक संविधान है

सरकार के विधायी और न्यायिक अंगों के बीच शक्तियों का कठोर सीमांकन। ऑस्ट्रेलियाई संविधान

अनिवार्य रूप से तीन शाखाओं को अलग कर दिया है

सरकार, और प्रत्येक को अपने अधिकार से सौंपा है

उपयुक्त अंग।

112. निकोलस में, ऑस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय,

न्यायिक शक्ति का उल्लंघन और दुरुपयोग, इस आधार पर कानून को अमान्य ठहराया कि इसने अंतिम को संशोधित किया

शक्तियों के पृथक्करण के उल्लंघन में एक संघीय अदालत का निर्णय।

यह बताता है कि हड़प तब होता है जब विधायिका अपनी ओर से न्यायिक शक्ति का प्रयोग किया।

व्हीलिंग ब्रिज

113. व्हीलिंग ब्रिज 28 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय थोड़ा विस्तृत विचार के योग्य है क्योंकि एक महान

श्री हरीश साल्वे ने इस फैसले पर निर्भरता का सौदा किया है। उस मामले में विवाद नौपरिवहन से संबंधित था

ओहायो नदी। समान पक्षों को शामिल करने वाले पहले के निर्णय में,

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के पुल को माना था

60. निकोलस वी। रानी; [(1998) 193 सी. एल. आर. 173]।

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य। 965

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

एक गैरकानूनी संरचना इस हद तक कि यह नौवहन में बाधा डालती है ओहियो नदी पर संघीय कानूनों के उल्लंघन में और इस तरह

मुक्त नौवहन के सार्वजनिक अधिकार में बाधा डालना। राज्य का मुकदमा दायर करने वाले पेन्सिलवेनिया को निषेधाज्ञा से राहत दी गई। प्रतिवादी (व्हीलिंग एंड बेलमोंट ब्रिज कंपनी) था

पुल को हटाने, या इसे स्तर तक उठाने का आदेश दिया कानून द्वारा निर्धारित। इसके बाद कांग्रेस ने कानून बनाया

कानून जिसके द्वारा पुल को एक वैध संरचना बनाया गया था

और जहाजों को संशोधित करने के लिए अनिवार्य किया गया था ताकि हस्तक्षेप न हो

पुल के साथ। जैसा कि भाग्य रहा होगा, पुल था

तेज हवाओं से नष्ट। पेन्सिलवेनिया राज्य ने आवेदन किया

एक तरीके को छोड़कर पुल के पुनर्निर्माण से निषेधाज्ञा

पूर्व में न्यायालय के आदेश के अनुरूप कार्यवाही जो मंजूर की गई थी। इसके बावजूद कंपनी

निषेधाज्ञा आदेश पुल के निर्माण के लिए आगे बढ़ा

जो मूल अदालत के आदेश द्वारा आवश्यक है। राज्य का

पेनसिल्वेनिया ने मामले को फिर से अदालत के समक्ष लाया। द.

जिस पर मूल निर्णय निरर्थक था। द. विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या कानून

जिसने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले को पलट दिया पहले के मुकदमे में निषेधाज्ञा का रूप संवैधानिक था?

नेल्सन, जे., जिन्होंने अदालत की बहुमत राय दी,

सामान्य प्रस्ताव को स्वीकार किया कि कांग्रेस के एक अधिनियम का निर्णय को रद्द करने के लिए प्रभाव और संचालन नहीं हो सकता है

न्यायालय ने पहले ही प्रदान कर दिया है, या इसके द्वारा निर्धारित अधिकार। यह भी देखा गया कि निजी अधिकारों पर निर्णय

जिन पक्षों ने निर्णय दिया है, वे बन गए हैं

निरपेक्ष और इसे लागू करना न्यायालय का कर्तव्य है। नेल्सन, जे।

आयोजित: " लेकिन बाधा को कम करने का निर्देश देने वाली डिक्री का वह हिस्सा निष्पादन है, एक निरंतर डिक्री है, जिसके लिए आवश्यक है

न केवल पुल को हटाना बल्कि प्रतिवादियों को किसी भी पुनर्निर्माण या निरंतरता के खिलाफ आदेश देता है। अब क्या ऐसा है

भविष्य में मौजूदा या निरंतर बाधा इस बात पर निर्भर करती है कि

सवाल यह है कि क्या यह नौवहन के अधिकार में हस्तक्षेप करता है या नहीं।

966 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

यदि, इस बीच, डिक्री के बाद से, यह अधिकार दिया गया है सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित, ताकि पुल नहीं है

लंबे समय तक एक गैरकानूनी बाधा, यह काफी स्पष्ट है अदालत को लागू नहीं किया जा सकता है। अब कोई हस्तक्षेप नहीं है

कानून के साथ असंगत सार्वजनिक अधिकार के आनंद के साथ, नहीं

जहाँ स्वयं वादी के पास था वहाँ से अधिक होगा फरमान जारी होने के बाद उन्होंने इस पर सहमति व्यक्त की। "नेल्सन,

जे. ने कहा कि हालांकि पुल अभी भी एक बाधा हो सकता है

वास्तव में लेकिन कानून के विचार में ऐसा नहीं था। नतीजतन, अदालत ने अपने निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया। नेल्सन, जे. प्रतिष्ठित

सार्वजनिक अधिकारों पर निर्णय से निजी अधिकारों पर निर्णय और अभिनिर्धारित किया गया:

" किसी राज्य की इन विशुद्ध रूप से आंतरिक धाराओं के संबंध में,

नौवहन का सार्वजनिक अधिकार विशेष रूप से नियंत्रण में है और राज्य विधानमंडल का विनियमन; और ऐसे मामलों में जहां

ये निर्माण या नौवहन में बाधाएं हैं

उपशमन के अधीन है, और न ही वह व्यक्ति जिसके पास हो सकता है उनके हस्तक्षेप से विशेष क्षति हुई

सार्वजनिक उपयोग अपने नुकसान के लिए किसी भी उपाय का हकदार है। जहाँ तक

धारा के सार्वजनिक उपयोग का संबंध है, विधायिका

इसे नियंत्रित करने और विनियमित करने की शक्ति रखने के लिए, कानून

संरचना को अधिकृत करना, हालांकि यह नौवहन के लिए एक वास्तविक बाधा हो सकती है, इसे वैध बनाती है। "

113.1 . नेल्सन, जे. की राय, जो बहुमत की राय है।

द व्हीलिंग बिरज में 29 हालांकि सामान्य रखरखाव करता है शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार अंतिम निर्णयों की अनुल्लंघनीयता का सिद्धांत लेकिन इसे इसके अधीन बनाया गया है

योग्यता कि निजी अधिकारों के विपरीत, सार्वजनिक अधिकार पारित नहीं होते हैं

निर्णयों में। नेल्सन, जे. की राय में, न्यायिक उपचार की प्रकृति प्रासंगिक है; निषेधाज्ञा जैसी न्यायसंगत राहत नहीं है। कांग्रेस की शक्ति की पहुंच से परे लेकिन एक डिक्री

नुकसान या लागत बाद के कानून से अप्रभावित है।

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 967

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

113.2 . मैकलीन, जे., जो बहुमत से असहमत थे

दूसरी ओर, राय ने व्हीलिंग बिरज 29 में इस बात पर जोर दिया कि पहले का आदेश न्यायिक जांच का परिणाम था, सुनवाई के दौरान सुनिश्चित किए गए तथ्यों पर आधारित और

यह पूरी तरह से एक न्यायिक प्रश्न था। शिकायत यह थी कि

पुल द्वारा वाणिज्य में बाधा, नुकसान के लिए शिकायतकर्ता, और अदालत ने तथ्य को आरोप के अनुसार पाया

बिल। मुख्य न्यायाधीश मार्शल के इस कथन के बाद कि कांग्रेस कई काम कर सकती है लेकिन यह एक तथ्य को नहीं बदल सकती है,

मैकलीन, जे. ने अपनी राय में कहा:

" न्यायिक शक्ति का प्रयोग मामलों के निर्णय में किया जाता है;

विधायी, द्वारा सामान्य विनियम बनाने में

कानूनों का अधिनियमन। उत्तरार्द्ध के विचारों से कार्य करता है

एक मामला। इस दृष्टिकोण से यह तुरंत देखा जाता है कि कांग्रेस पेनसिल्वेनिया की शिकायत सुनने का बीड़ा नहीं उठा सके

इस मामले में, गवाही दें या इसे लें,

इंजीनियरों के सर्वेक्षणों और रिपोर्टों की जांच करें, निर्णय लें
कानून के प्रश्न जो प्रवेश पर उत्पन्न होते हैं

गवाही दें, और अंतिम डिक्री में साक्ष्य को उचित और कानूनी प्रभाव दें। ऐसा करना उचित है। न्यायिक शक्ति का कर्तव्य। और कांग्रेस के उपरोक्त अधिनियम के पारित होने से पहले इस अदालत ने यही किया था।

अदालत ने माना कि पुल ओहियो नदी के नौवहन में बाधा डालता है, और इसके परिणामस्वरूप, यह एक

उपद्रव। अधिनियम ने पुल को कानूनी घोषित किया

संरचना, और, परिणामस्वरूप, कि यह एक उपद्रव नहीं था। अब, क्या यह एक विधायी या न्यायिक अधिनियम है? चाहे वह एक

उपद्रव हो या न हो, यह बाधा के तथ्य पर निर्भर करता है; और

यह एक न्यायिक प्रश्न प्रतीत होता है, जिसका निर्णय किसी मामले में पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर किया जाता है। एम.

113.3 . अल्पमत की राय में, मैकलीन। जे. ने कांग्रेस के कार्य को निष्क्रिय और अमान्य घोषित किया और दोहराया कि

पहले से पारित डिक्री को इसके अनुसार लागू किया जाए

सच्चा इरादा।

968 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

113.4 . व्हीलिंग ब्रिज 2 9 में एक अन्य अल्पमत राय में,

वेन, जे., बहुमत के साथ असहमति जताते हुए और उनके साथ सहमत होते हुए

जे. मैकलीन ने कहा कि कांग्रेस के पास हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं थी

के नाटक के तहत अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

जनता पर पुलों की संरचना को वैध बनाने की शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका की नौगम्य नदियाँ, या तो राज्यों के भीतर,

या राज्यों को एक दूसरे से विभाजित करना, या वाणिज्यिक के तहत

राज्यों के बीच वाणिज्य को विनियमित करने के लिए कांग्रेस की शक्तियाँ।

क्लिंटन ब्रिज

114. नेल्सन, जे।, जिन्होंने व्हीलिंग में बहुमत की राय दी

ब्रिज 29 ने क्लिंटन ब्रिज 30 में यू. एस. सुप्रीम कोर्ट की राय भी दी। हालांकि व्हीलिंग ब्रिज में 29 ए पुल के खिलाफ अदालत द्वारा आदेश दिया गया था,

जबकि क्लिंटन ब्रिज 30 में कारण लंबित था

अनिश्चित, लेकिन उन्होंने व्हीलिंग में बहुमत की राय का पालन किया

ब्रिज 29.

मैनिगोल्ड

115. श्री हरीश साल्वे, राज्य के विद्वान वकील

केरल, आर्थर एम. मैनिगॉल्ड 2 1 पर निर्भर रहा। उस में

मामला, यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत का पालन किया कि

अनुबंधों के दायित्व को बाधित करने वाले कानूनों का निषेध

राज्य को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकता है जो हैं -

सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इसमें निहित हैं, या हैं

प्रभावित हुए। यह समझाते हुए कि इस शक्ति के रूप में जाना जाता है ' पुलिस शक्ति ', यह संप्रभु अधिकार का एक अभ्यास है

जीवन, स्वास्थ्य, नैतिकता, आराम की रक्षा के लिए सरकार और

लोगों का सामान्य कल्याण, और किसी भी अधिकार के लिए सर्वोपरि है

व्यक्तियों के बीच अनुबंधों के तहत। यह कहा गया है कि कुछ मामलों में सीमाओं के अधीन, व्यापक विवेकाधिकार है विधायिका की ओर से यह निर्धारित करने में कि क्या है और क्या है

आवश्यक नहीं है। इस तरह के विवेकाधिकार में, अदालतें आम तौर पर ऐसा नहीं करेंगी हस्तक्षेप करें। तमिलनाडु राज्य से प्रवाहित कानून की व्याख्या से निपटना v.

केरल राज्य 969

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

इसके पिछले कुछ निर्णय, यू. एस. सुप्रीम कोर्ट,

यह देखा गया:

. हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि यही सिद्धांत क्यों नहीं होना चाहिए।

यह उन मामलों पर लागू होता है जहां राज्य विधायिका, अपनी पुलिस शक्ति का प्रयोग करते हुए, एक निश्चित बांध बनाने का निर्देश देती है, और इस तरह संयोग से बांध के ऊपर की भूमि तक पहुंच को बाधित करती है। में।

दोनों मामलों में संप्रभु अपने संवैधानिक प्रयोग कर रहा है

ठीक है, एक मामले में नदी के नौवहन में सुधार करने में, और दूसरी ओर, इसकी निचली भूमि को निकालने में, और इस तरह कृषि उद्देश्यों के लिए उनके मूल्य को बढ़ाने में।

हाँज

116. हाँजेस 3 1 में, यू. एस. सुप्रीम कोर्ट, निम्नलिखित

क्लीलिंग ब्रिज 2 9 निम्नानुसार आयोजित किया गया:

" क्लीलिंग ब्रिज मामले में, जैसे कि क्लिंटन ब्रिज में

वर्तमान वाद में, एक के रखरखाव का आदेश देना अवैध स्कूल जिला और इसके बांड जारी करना है

इसी तरह वादी द्वारा अन्य सभी के साथ साझा किया गया एक सार्वजनिक अधिकार निवासी करदाता। और जबकि व्हीलिंग बिर्ज मामले में विधेयक राज्य द्वारा दायर किया गया था, हालांकि आंशिक रूप से इसके रेलवे, सिद्धांत कि एक निर्णय सार्वजनिक घोषित करता है अधिकार को बाद के विधान द्वारा निरस्त किया जा सकता है, वर्तमान वाद में समान बल के साथ लागू होता है, हालांकि

व्यक्ति मुख्य रूप से अपने स्वयं के लाभ के लिए; शामिल अधिकार और निर्णय लिया, एक मामले में और दूसरे में, सार्वजनिक होने के नाते, और निजी नहीं।

116.1 . हाँजेस 3 1 एक ऐसा मामला था जहाँ यू. एस. सुप्रीम अदालत ने एक के गठन के खिलाफ एक निषेधाज्ञा को भंग कर दिया कानून के बाद समेकित स्कूल जिला जो इस तरह के समेकन को अधिकृत किया, और फिर भी नुकसान के पुरस्कार के लिए पिछले निर्णय लेने में निर्णय को बरकरार रखा।

970 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

लोकोमोटिव फायरमैन का भाईचारा

117. ब्रदरहुड ऑफ लोकोमोटिव फायरमैन 2 3 में, यू. एस. उच्चतम न्यायालय को इस सवाल का सामना करना पड़ा कि क्या अरकंसास "पूर्ण-चालक दल" कानून न्यूनतम संख्या को निर्दिष्ट करते हैं ऐसे कर्मचारी जिन्हें कुछ नियमों के तहत ट्रेन चालक दल के हिस्से के रूप में काम करना चाहिए

परिस्थितियाँ, वाणिज्य खंड या चौदहवें का उल्लंघन करती हैं

अमेरिकी संविधान का संशोधन। की संवैधानिकता

इन अरकंसास कानूनों को विशेष रूप से उनके खिलाफ बरकरार रखा गया था।

तीन में समान संवैधानिक प्रावधानों के तहत चुनौती

पहले लिए गए निर्णय। हालाँकि, उस मामले से जो यू. एस. तक पहुँचा।
 उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय ने पाया कि इसके परिणामस्वरूप
 पिछले निर्णय के बाद से आर्थिक और तकनीकी विकास
 इस विषय पर, कानूनों को अब सुरक्षा के रूप में उचित नहीं ठहराया गया था
 उपाय-वह आधार जिस पर वे पहले थे
 कायम रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया
 के वाणिज्य खंड के विपरीत विवादित कानून
 चौदहवें के संविधान और उचित प्रक्रिया खंड
 संशोधन। ब्लैक, जे., जिन्होंने अपनी ओर से राय दी
 बहुमत ने माना कि जिला न्यायालय राज्य की समीक्षा करने के लिए अपने सीमित अधिकार से
 परे पूरी तरह से एक विधायी निर्णय में शामिल था
 वाणिज्य खंड के अधीन विधान। अदालत ने कहा कि
 जिला न्यायालय के लिए एक मूल्य रखने के लिए खुला नहीं था
 देखने के लिए डॉलर और सेंट के संदर्भ में अतिरिक्त सुरक्षा
 क्या न्यायालय द्वारा गणना किए गए इस मूल्य ने
 रेल सड़कों की वित्तीय लागत। इस प्रकार, बहुमत का विचार है,
 निष्कर्ष निकाला:

" सभी परिस्थितियों में हम जाने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

इस न्यायालय के पिछले निर्णयों से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि
 अरकंसास के पूर्ण-चालक कानून अंतरराज्यीय वाणिज्य पर अनुचित बोझ नहीं डालते हैं या
 अन्यथा संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं।

निस्संदेह गरमागरम विवाद जारी रहेंगे।

जिनमे ये आई. ए. डब्ल्यू. सुरक्षा और अन्य जनता में योगदान करते हैं।

ब्याज, और इस तरह के योगदान किस हद तक हैं
अतिरिक्त श्रमशक्ति की लागत द्वारा उचित ठहराया गया। ये
विधानमंडलों में 971 विवादों को सुलझाना जारी रहेगा।

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

और सामूहिक सौदेबाजी के विभिन्न रूपों में
प्रबंधन और संघ। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं।
जिनका उपयोग अंतरराज्यीय रेलगाड़ियों के संचालन के लिए किया जाएगा
व्यापार। कांग्रेस की कार्यवाही के अभाव में,
हालाँकि, हम अमान्य करने के लिए न्यायिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं
अरकंसास के लोगों और उनके निर्वाचित लोगों का यह निर्णय
समाज को जिस कीमत का भुगतान करना चाहिए, उसके बारे में प्रतिनिधि
रेल उद्योग में सुरक्षा को बढ़ावा देना।

रेमंड मोटर परिवहन

118. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के दो और फैसले, एक,
रेमंड मोटर परिवहन 2 4 और दूसरा, रेमंड
कास/25 पर अब विचार किया जा सकता है। रेमंड मोटर
परिवहन 2 4 इस सवाल से संबंधित था कि क्या
विस्कॉन्सिन राज्य के प्रशासनिक नियम
अनुबंधों की लंबाई और विन्यास जो संचालित किए जा सकते हैं
राज्य के भीतर वाणिज्य खंड का उल्लंघन किया गया। तीन-न्यायाधीश

जिला न्यायालय ने माना कि नियम किसी भी आधार पर असंवैधानिक नहीं थे। जिला न्यायालय के दृष्टिकोण को परेशान करते हुए,

पॉवेल, जे., जिन्होंने न्यायालय की राय दी, ने सबसे पहले सामान्य नियम को नोट किया, जहां कानून समान रूप से विनियमित होता है।

एक वैध स्थानीय लोक हित और उसके प्रभावों को प्रभावी बनाना।

अंतरराज्यीय वाणिज्य केवल आकस्मिक है, इसे बरकरार रखा जाएगा

जब तक कि इस तरह के व्यापार पर लगाया गया बोझ स्पष्ट रूप से नहीं है

अनुमानित स्थानीय लाभों के संबंध में अत्यधिक "। पॉवेल, जे.,

तब यह निष्कर्ष निकाला गया कि चुनौती दिए गए नियमों ने उल्लंघन किया

वाणिज्य खंड क्योंकि उन्होंने एक बड़ा बोझ डाला

अंतरराज्यीय वाणिज्य पर और उन्हें अधिक बनाने के लिए नहीं कहा जा सकता है

राजमार्ग सुरक्षा में अधिकांश सट्टा योगदान से अधिक।

118.1 . ब्लैकमन, जे., जिनके साथ ब्रेनन, सीजे। और

रेहंक्विस्ट, जे. ने सहमति व्यक्त की कि यदि सुरक्षा औचित्य थे

भ्रमपूर्ण नहीं, न्यायालय दूसरा स्थान नहीं लेगा-विधायी निर्णय का अनुमान लगाएं
972 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. पर संबंधित बोझ की तुलना में
उनके महत्व के बारे में।

अंतरराज्यीय व्यापार। ब्लैकमुन जे, ने भी आयोजित किया:

यह विधायी विकल्प नहीं बनाता है। इसके बजाय,
पक्षों द्वारा विकसित तथ्यात्मक अभिलेख की खोज करते हुए, यह

निष्कर्ष निकाला कि सुरक्षा हितों को नहीं दिखाया गया है

कानून के रूप में अस्तित्व में होना "।

रेमंड कैसल

रेमंड कैसल 25 में, उसके बाद

119 .

साक्ष्य दर्ज करना और मुकदमे का समापन, जिला न्यायालय

रेमंड मोटर में स्वीकार किए गए मानक को लागू किया गया

परिवहन 2 4 और यह निष्कर्ष निकाला कि राज्य का कानून अनिवार्य रूप से

अंतर-राज्यीय वाणिज्य पर बोझ पैदा किया। अपील का न्यायालय जिला न्यायालय के निष्कर्षों और दृष्टिकोण को स्वीकार किया। इस तरह से

मामला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। पॉवेल, जे., जो

स्टीवंस जे. जे. शामिल हुए, देखा: " जबकि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के नियमों को अमान्य करने के लिए सबसे अधिक अनिच्छुक रहा है जो सुरक्षा, विशेष रूप से राजमार्ग सुरक्षा, इस तरह की संवैधानिकता

नियम फिर भी संवेदनशील विचार पर निर्भर करते हैं

सीमा के आलोक में राज्य नियामक चिंता का वजन और प्रकृति अंतरराज्यीय वाणिज्य के मार्ग पर लगाया गया बोझ।

119.1 . ब्रेनन, जे., जिनके साथ मार्शल जे. शामिल हुए,

फैसले से सहमति जताते हुए कहा गया: " इस अदालत का

राज्य के कानून निर्माताओं के निर्णयों का सम्मान बढ़ाना

सुरक्षा का क्षेत्र काफी हद तक न्यायिक अनिच्छा के कारण है।

अन्य सामाजिक हितों के खिलाफ सुरक्षा के हित को तौलना,

जैसे कि मुक्त प्रवाह में आर्थिक हित

व्यापार "।

प्लॉट

120. प्लूटो 1 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत महत्वपूर्ण और योग्य है

61. प्लॉट एट अल। वी. स्पेंडथिरफ्ट फार्म, इंक., आदि।; [(1995) 514 यू. एस. 211]।

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 973

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

उचित विचार। उस मामले में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

इस प्रश्न के साथ प्रस्तुत किया गया था कि क्या प्रतिभूति विनियम अधिनियम, 1934 की धारा 27 ए (बी) का उल्लंघन था

संविधान की शक्तियों का पृथक्करण या उचित प्रक्रिया खंड

पाँचवाँ संशोधन इस हद तक कि इसके लिए संघीय न्यायालयों को धारा के तहत निजी नागरिक कार्रवाइयों में अंतिम निर्णयों को फिर से खोलने की आवश्यकता थी

10 ((ख) अधिनियम। स्कैलिया, जे., जिन्होंने बहुमत की राय दी,

राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित प्रथम उद्घाटन भाषण का उल्लेख किया गया

लिनकन जिसमें राष्ट्रपति ने समझाया कि राजनीतिक क्यों

शाखाएँ निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थीं और उन्हें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी:

" मैं कुछ लोगों द्वारा धारण की गई स्थिति को नहीं भूलता, कि

संवैधानिक प्रश्नों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना है

अदालत; और न ही मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि ऐसे निर्णय किसी भी मामले में, किसी मुकदमे के पक्षों पर, के उद्देश्य के रूप में बाध्यकारी होने चाहिए

उस सूट को। . . . और जबकि यह स्पष्ट रूप से संभव है कि इस तरह

निर्णय किसी भी मामले में गलत हो सकता है, फिर भी इसके बाद होने वाला बुरा प्रभाव, उस विशेष मामले तक सीमित होने के कारण

यह संभावना कि यह अधिक शासित हो सकता है, और कभी भी अन्य मामलों के लिए एक मिसाल नहीं बन सकता है, बेहतर तरीके से सहन किया जा सकता है

एक अलग अभ्यास की बुराईयाँ "।

120.1 . स्कैलिया, जे. ने थॉमस कूली (एक संवैधानिक विद्वान) के विचारों का भी उल्लेख किया जिन्होंने कहा था:

" यदि विधायिका इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालयों की कार्यवाही को नियंत्रित नहीं कर सकती है, तो उन्हें कानून के निर्माण की आवश्यकता होती है।

अपने स्वयं के विचारों के अनुसार, यह बहुत स्पष्ट है कि यह ऐसा नहीं कर सकता है।

सीधे, उनके निर्णयों को दरकिनार करके, उन्हें मजबूर करके

नए मुकदमों को मंजूरी देना, अपराधियों को दोषमुक्त करने का आदेश देना, या निर्देश देना कि इस मामले में क्या विशेष कदम उठाए जाएंगे।

न्यायिक जाँच की प्रगति "।

120.2 . स्कैलिया जे, ने देखा कि अंतिम का विश्लेषण करने की शक्ति

निर्णय "न्यायिक शक्ति की एक धारणा" थी और इसलिए,

वर्जित है। अंतिमता नियम को प्रमुखता दी गई थी। यह उनकी निम्नलिखित टिप्पणियों से स्पष्ट हो जाता है: हालाँकि, अंतिमता प्राप्त करने के बाद, एक न्यायिक निर्णय 974 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. का अंतिम शब्द बन जाता है।

किसी विशेष मामले या विवाद के संबंध में न्यायिक विभाग, और कांग्रेस पूर्वव्यापी द्वारा घोषणा नहीं कर सकती है

कानून कि उस मामले में लागू कानून अदालतों ने जो कहा था, उससे कुछ अलग था।

120.3 . प्लॉट 1 में, बहुमत की राय यह भी है कि

विचार जैसे कि उस कानून द्वारा प्रेरित किया गया था सार्वजनिक नीति को लागू करने के लिए वास्तविक चिंता अप्रासंगिक थी। द.

बहुमत की राय ने इस निषेध (शक्ति का पृथक्करण) को उजागर किया

उल्लंघन किया गया था जब एक व्यक्तिगत अंतिम निर्णय विधायी रूप से होता है

सबसे अच्छे कारणों से भी रद्द किया गया, जैसे कि विधायिका का वास्तविक विश्वास (सभी पेशेवरों द्वारा समर्थित) भूमि) कि निर्णय गलत था, "।

120.4 . इस प्रकार, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से घोषणा की कि अधिनियम की धारा 27 ए (बी) अलगाव का उल्लंघन थी शक्तियों का सिद्धांत।

के तहत शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का सारांश भारतीय संविधान

121. उपरोक्त चर्चा के गहन प्रतिबिंब पर, हमारे के बीच शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, संक्षेप में, हो सकता है

संक्षेप में इस प्रकार है:

(i) के पृथक्करण के स्पष्ट प्रावधान के बिना भी शक्तियाँ, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत एक मजबूत है

भारत के संविधान में सिद्धांत। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संवैधानिक संरचना को सूचित करता है और यह एक कानून के शासन का अनिवार्य घटक। दूसरे शब्दों में, सिद्धांत

यद्यपि सत्ता के पृथक्करण को संविधान में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसका विस्तार, संचालन और दृश्यता स्पष्ट है

भारतीय संविधान की योजना से। संविधान ने बनाया है

तीनों के बीच औपचारिक रेखाएं खींचे बिना सीमांकन

अंग-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस अर्थ में, शक्ति के पृथक्करण के लिए स्पष्ट प्रावधान के अभाव में भी, तमिलनाडु राज्य v.

[आर. एम. लोधा, सीजेआई ।]

विधायिका, कार्यपालिका और सरकार के बीच शक्ति का पृथक्करण न्यायपालिका उन देशों के संविधानों से अलग नहीं है जिनमें शक्तियों के पृथक्करण के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं।

((ii) कार्यपालिका से न्यायालयों की स्वतंत्रता और

विधायिका कानून के शासन के लिए मौलिक है और भारतीय संविधान के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। न्यायिक शक्ति का पृथक्करण एक

संविधान के तहत महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत

भारत।

((iii) तीन अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी कुछ और नहीं बल्कि एक अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांतों का परिणाम

भारत का संविधान। तदनुसार, अलगाव का उल्लंघन न्यायिक शक्ति के तहत समानता का निषेध हो सकता है

अनुच्छेद 14. इस प्रकार कहा गया है कि एक कानून को अमान्य किया जा सकता है

शक्तियों के पृथक्करण के उल्लंघन का आधार क्योंकि इस तरह का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का निषेध है।

((iv) उच्च न्यायपालिका (उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय)

विधायिका (संसद और राज्य विधानसभाओं) द्वारा यदि यह पाया जाता है कि उसने संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन किया है या यदि यह संविधान के भाग III में निहित अधिकारों का उल्लंघन करता है।

((v) शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अंतिम पर लागू होता है

न्यायालयों के निर्णय। विधानमंडल कोई घोषणा नहीं कर सकता है

कानून की अदालत का निर्णय अमान्य या अप्रभावी होना। यह हो सकता है,

हालाँकि, इंगित दोषों को दूर करने के लिए एक संशोधन अधिनियम पारित करें

कानून की अदालत द्वारा या इसके बारे में पता चलने पर। अन्य में

शब्दों में, एक अदालत का निर्णय हमेशा बाध्य होना चाहिए जब तक कि जिन शर्तों पर यह आधारित है, उन्हें मौलिक रूप से नहीं बदला जाता है।

कि निर्णय परिवर्तित में नहीं दिया जा सकता था

परिस्थितियाँ।

((vi) यदि विधायिका के पास विषय-वस्तु पर अधिकार है और एक मान्य कानून बनाने की क्षमता है, तो वह किसी भी समय कर सकती है।

इस तरह का एक मान्य कानून बनाएँ और इसे पूर्वव्यापी बनाएँ।

976 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

अतः किसी विधि की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या विधायिका के पास वह क्षमता है जिसका वह दावा करती है -

विषय-वस्तु और क्या सत्यापन कानून बनाने में यह

उस दोष को दूर करता है जिसे अदालतों ने मौजूदा में पाया था

कानून।

((vii) विधायिका द्वारा अधिनियमित कानून स्पष्ट रूप से हो सकता है

ऐसा लगता है कि यह अपनी क्षमता के भीतर है लेकिन फिर भी सार में है यदि यह है

अलगाव के सिद्धांत का उल्लंघन करने पर कानून अमान्य हो सकता है। शक्तियों का।
ऐसी स्थिति में, एक पर कानून का कानूनी प्रभाव

निर्णय या न्यायिक कार्यवाही की बारीकी से जांच की जानी चाहिए,

विधायी प्रिस्क्रिप्शन या निर्देश को ध्यान में रखते हुए। द.

पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, (i) क्या विधायी निर्देश है?

या विधायी निर्देश न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं? ((ख)

क्या कानून तय किए गए मामले पर लक्षित है या क्या

विवादित कानून को पहले से ही अंत में एक मामले में इसके आवेदन की आवश्यकता होती है तय किया? ((iii) कानून की शर्तें क्या हैं; जिन मुद्दों के साथ

यह उस निर्णय की प्रकृति से संबंधित है जिसने अंतिमता प्राप्त कर ली है? यदि (i) से (ii) का उत्तर सकारात्मक और प्रश्न (iii) में उल्लिखित पहलुओं पर पर्याप्त रूप से विचार

यह स्थापित करता है कि विवादित कानून न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप करता है

कार्य, न्यायालय कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।

मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण का विश्लेषण

फोरम जजमेंट (2006 जजमेंट)

122. उपरोक्त संवैधानिक सिद्धांतों के आलोक में

विधायिका, कार्यपालिका और संस्थाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण करना।

न्यायपालिका, अब हम इसकी संवैधानिक वैधता की जांच करेंगे

2006 (संशोधन) अधिनियम को लागू करने और उस पर प्रभाव डालने के लिए

मुल्लापेरियार बांध। इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए, पहले मुल्लापेरियार मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना उचित है।

पर्यावरण संरक्षण मंच 1 कुछ समय के लिए। कि

इस न्यायालय द्वारा मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण मंच द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका में निर्णय दिया गया था।

भारत का संविधान और कुछ हस्तांतरित मामले। उस मामले में, याचिकाकर्ता का दावा था कि जलाशय में जल स्तर तमिल नाडु v का कथन नहीं कर सकता है।

केरल राज्य 977

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

अपने वर्तमान स्तर 136 फुट से ऊपर उठाया जाए। केरल का भी यही रुख था। केरल के अनुसार, मुल्लापेरियार बांध का जीवनकाल

निर्माण की तारीख से पचास साल थे लेकिन यह पहले से ही था

जीवन। केरल के विचार में, जल स्तर को 136 फीट से ऊपर उठाने की अनुमति देना खतरनाक था। और गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप आसपास के तीन जिलों का पूरी तरह से सफाया हो गया। दूसरी ओर, तमिलनाडु ने यह मामला स्थापित किया कि

इस न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार जल स्तर को 142 फुट तक बढ़ाया जा सकता है। एक अंतरिम उपाय के रूप में

और कुछ कदम उठाने पर और निष्पादन के बाद बेबी बांध, मिट्टी के बांध के संबंध में सुदृढ़ीकरण उपाय

152 फीट के एफआरएल पर पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। तमिलनाडु की मांग की गई जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाने के लिए विशिष्ट दिशा। और मजबूत होने के बाद, 152 फीट के अपने पूर्ण स्तर तक।

122.1 . न्यायालय ने निम्नलिखित संदर्भ शर्तों को नोट किया

और विशेषज्ञ समिति को दिया गया कार्य:

" (क) मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए

केरल में पेरियार नदी के सुदृढ़ीकरण के संबंध में

तमिलनाडु सरकार द्वारा सुझाए गए सुदृढ़ीकरण उपायों के अनुसार बांध बनाया गया

सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा और माननीय जल मंत्री को रिपोर्ट/सलाह देना

बांध की सुरक्षा पर संसाधन।

(ख) माननीय जल संसाधन मंत्री को सलाह देना।

मुल्लापेरियार जलाशय में जल स्तर बढ़ाने के संबंध में

के सुदृढ़ीकरण के परिणामस्वरूप 136 फीट (41.45 m) से परे ऊपर (ए) के रूप में बांध और इसकी सुरक्षा।

समिति बांध का दौरा करेगी

बांध के सुरक्षा पहलुओं की जानकारी और आकलन करना। यह सिंचाई सचिव के साथ चर्चा करेगा।

केरल सरकार के साथ-साथ सचिव, पीडब्ल्यूडी,
सुरक्षा के संबंध में तमिलनाडु सरकार

बांध और अन्य संबंधित मुद्दे। "3 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

122.2 . फिर न्यायालय ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया

विशेषज्ञ समिति निम्नानुसार है:

" 1. बेबी बांध से संबंधित सुदृढ़ीकरण उपाय

और मिट्टी का बांध, जैसा कि सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा पहले ही सुझाया जा चुका है और
तमिलनाडु सरकार द्वारा तैयार किया जाना चाहिए
जल्द से जल्द किया गया।

2. केरल सरकार को फांसी की अनुमति देनी चाहिए। बेबी बांध, मिट्टी के बांध को
मजबूत करने के उपाय और

पैरापेट दीवार के लगभग 20 मीटर के शेष हिस्से पर

ई. एल. 160 फीट तक मुख्य मुल्लापेरियार बांध। (48.77 एम) तुरंत।

3. सी. डब्ल्यू. सी. स्थापना के लिए उपकरण को अंतिम रूप देगा

मुख्य बांध। इसके अलावा, उपकरण लगाए जाएंगे।

मिट्टी सहित बेबी बांध को मजबूत करने के दौरान बांध, ताकि मुल्लापेरियार बांध के
स्वास्थ्य की निगरानी,

बेबी डैम और मिट्टी का बांध निरंतर किया जा सकता है।

आधार।

4. मुल्लापेरियार जलाशय में जल स्तर बढ़ाया जाए उस स्तर तक जहाँ बेबी डैम में
तन्यता तनाव होता है

2. 85 टन/वर्ग मीटर से अधिक नहीं (जैसा कि श्री द्वारा सुझाया गया है)

बी. आई. एस. के अनुसार स्थिति ई (भूकंप के साथ पूर्ण जलाशय स्तर) कोड आई.
एस. 6512-1984 आह = 0.12 ग्राम के साथ और विश्लेषण के अनुसार

खंड 3.4.3 और 7.3। 1 बी. आई. एस. कोड 1893-1984।

5. समिति के सदस्यों ने उठाने के मुद्दे पर चर्चा की

अध्ययन के बाद ई. एल. 136.00 फीट (41.45 एम) से ऊपर जल स्तर का स्तर

बेबी डैम की सुरक्षा का विश्लेषण। प्रो. ए.

पैरा 4 के आलोक में राय दी गई कि जल स्तर होना चाहिए कम से कम EL 143.00
ft (43.59 m) तक तन्यता के रूप में उठाया गया

दबाव अनुमेय सीमा के भीतर हैं। श्री एम. के

केरल सरकार के सदस्य परमेश्वरन नायर ने ऐसा किया।

ई. एल. 136.00 फीट (41.45 स्टेट ऑफ तमिल नाडु v.) से ऊपर जल स्तर बढ़ाने के लिए
सहमत नहीं हैं।

केरल राज्य 979

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

एम)। हालांकि, समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद,

राय है कि मुल्लापेरियार जलाशय में जल स्तर

EL 142.00 ft (43.28 m) तक उठाया जाएगा जो नहीं होगा

स्पिलवे सहित मुख्य बांध की सुरक्षा को खतरे में डालना, बेबी डैम और मिट्टी का
बांध। के सारांश

तनाव विश्लेषण के लिए गणना अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं।

XIX।

6. जलाशय के स्तर को उस स्तर तक बढ़ाना जहां

तन्यता तनाव के दौरान 2.85 टन/एम 2 से अधिक नहीं है

(मुल्लापेरियार जलाशय का मूल डिजाइन एफआरएल) बेबी डैम पर सुदृढीकरण
उपायों को पूरा करने के बाद अध्ययन किया जाता है।

122.3 न्यायालय ने निम्नलिखित पाँच प्रश्न तैयार किए:

साइडरेशन:

" 1. क्या राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 108,

1956 क्या यह असंवैधानिक है?

2. क्या इस न्यायालय की अधिकारिता को देखते हुए वर्जित है

अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 11 के साथ पठित अनुच्छेद 262 का?

3. क्या संविधान का अनुच्छेद 363 प्रतिबंध लगाता है

इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र?
हैं?

4. क्या विवाद मध्यस्थता के लिए भेजे जाने योग्य

5. क्या जलाशय का जल स्तर 136 फुट से बढ़ाकर 142 फुट करने से जलाशय की सुरक्षा
खतरे में पड़ जाएगी।

लोग और पर्यावरण का क्षरण भी?

122.4 प्रश्न संख्या 1 पर विचार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत कानून बनाने की शक्ति

,

बयान सर्वोपरि था और यह न तो अनुच्छेद 246 के अधीन था और न ही सातवें 980 सर्वोच्च
न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. की सूची II और III के अधीन था।

अनुसूची. न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि संसद की शक्ति

अनुच्छेद 3 और 4 के तहत कानून पूर्ण था और सभी पर लागू होता है।

उचित व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक विधायी विषय

राज्यों का पुनर्गठन। तदनुसार, न्यायालय ने पाया कि नहीं राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 108 की वैधता को चुनौती देने में योग्यता।

122.5 प्रश्न संख्या 2 पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि

मुल्लापेरियार में जल स्तर बढ़ाने से संबंधित विवाद बांध एक जल विवाद नहीं था क्योंकि तमिलनाडु का अधिकार था

पेरियार जलाशय से पानी को एकीकृत करने के लिए तमिलनाडु की ओर मोड़ा गया

सिंचाई का उद्देश्य या बिजली पैदा करने के लिए पानी का उपयोग करना या

अन्य उपयोगों के लिए कोई विवाद नहीं था। यह देखा गया कि 1886 में तमिलनाडु को दिए गए पट्टे को लेकर कोई विवाद नहीं था

या 1970 के और 1979 तक के पूरक समझौतों के बारे में

जल स्तर को लेकर कोई विवाद नहीं था। 1979 में,

जल स्तर को 136 फीट तक नीचे लाया गया था। तमिल को सुविधाजनक बनाने के लिए

तमिलनाडु कुछ सुझाए गए सुदृढीकरण उपायों को लागू करेगा

सीडब्ल्यूसी द्वारा। इस प्रकार, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि बांध की सुरक्षा

जल स्तर को बढ़ाकर 142 फीट करना। संविधान के अनुच्छेद 262 या अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों से प्रभावित मुद्दा नहीं था

अधिनियम, 1956।

122.6 प्रश्न संख्या 3 के संबंध में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाधित करने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि अनुच्छेद 363 इस तरह के समझौते पर लागू नहीं होता है।

1886 लीज समझौते के रूप में जो एक सामान्य समझौता है पट्टे पर देना और यह कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं है।

122.7 प्रश्न संख्या 4 पर न्यायालय ने कहा कि

विवाद अधिकारों, शक्तियों और दायित्वों के बारे में नहीं था या

समझौते के किसी भी भाग की व्याख्या लेकिन विवाद

यह इस बात तक सीमित था कि जलाशय में जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं। जिसके लिए पहले से ही एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट थी।

122.8 प्रश्न संख्या 5 पर विचार करने के लिए, न्यायालय

981 के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को ध्यान से संदर्भित किया गया

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

जल स्तर पर बांध की सुरक्षा को देखते हुए इसे बढ़ाकर 142 किया जा रहा है

निर्णय के पैरा 30 में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 30. बांध की सुरक्षा के मुद्दे पर जल स्तर को वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 142 फुट किया जा रहा है।

136 फीट, विभिन्न रिपोर्टों ने सुरक्षा कोण की जांच की है

भूकंप प्रतिरोध के दृष्टिकोण सहित गहराई में।

आशंकाओं को निराधार पाया गया है। में।

वास्तव में, रिपोर्टों पर एक अवरोधक रवैये का सुझाव देते हैं

केरल राज्य का हिस्सा। विशेषज्ञ समिति थी इसमें स्वतंत्र अधिकारी शामिल होते हैं।
भूकंपीय बल के अनुसार

प्रावधानों को ध्यान में रखा गया और संरचनात्मक

सुदृढ़ीकरण करते समय तदनुसार बनाए गए डिजाइन उपाय। द्वारा गठित समिति की
अंतिम रिपोर्ट

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार अध्ययन करेगी

बांध का जल सुरक्षा पहलू और पानी को बढ़ाना

स्तर ने मामले की विस्तार से जांच की है। के अध्यक्ष

यह समिति केंद्रीय जल के सदस्य (डी एंड आर) थी।

आयोग, केंद्रीय जल के दो मुख्य अभियंता

आयोग, निदेशक, बांध सुरक्षा, सरकार

मध्य प्रदेश और सेवानिवृत्त इंजीनियर-इन-चीफ, उत्तर प्रदेश

तमिल सरकारों के दो प्रतिनिधियों के अलावा

तमिलनाडु और केरल इस समिति के सदस्य थे। सभी प्रतिनिधि को छोड़कर उनके हस्ताक्षर संलग्न किए गए

केरल सरकार। स्थिरता के परिणामों का सारांश

मुल्लापेरियार बेबी डैम के विश्लेषण में एक टिप्पणी है जो

यह दर्शाता है कि अनुमेय तन्यता शक्ति चिनाई थी

परीक्षण के आधार पर उसमें उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार

उस समय सी. एस. एम. आर. एस., दिल्ली द्वारा संचालित और द्वारा सहमत

केरल के प्रतिनिधि सहित समिति के सभी सदस्य

यह सुझाव दिए गए विभिन्न सुदृढ़ीकरण उपायों को भी दर्शाता है सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा तमिलनाडु पीडब्ल्यूडी द्वारा पूरा किया गया

आर. सी. सी. समर्थन प्रदान करने सहित बांध पर

दाम। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बच्चे की पैरापेट दीवार

बांध और मुख्य बांध को 160 फीट (48.77 m) तक बढ़ा दिया गया है।

अस्वीकार किए जाने के कारण मुख्य बांध पर 20 मीटर के हिस्से को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

केरल सरकार द्वारा अनुमति। कुछ अन्य

जैसा कि उसमें कहा गया है, कार्यों को करने की अनुमति नहीं थी

केरल राज्य द्वारा। निरीक्षण के बाद सी. डब्ल्यू. सी. की रिपोर्ट मुख्य बांध, दीर्घाएँ, बेबी बांध, मिट्टी का बांध

और स्पिलवे, निष्कर्ष निकालता है कि बांध सुरक्षित है और नहीं

अत्यधिक रिसाव देखा जाता है और मुल्लापेरियार बांध में

हाल ही में मजबूत किया गया। बांध के मुख्य भाग और रिसाव में कोई दिखाई देने वाली दरारें नहीं हैं

माप से पता चलता है कि ऊपर की ओर कोई दरार नहीं है।

द डैम। हमारा ध्यान भी विभिन्न बातों की ओर खींचा गया है।

क्रॉस-सेक्शन सहित दस्तावेज़ और चित्र

सुदृढीकरण उपायों को प्रदर्शित करने के लिए पेरियार बांध।

इसके अलावा, यह ध्यान रखना उचित है कि बांध तुरंत

मुल्लापेरियार बांध के बाद की रेखा इडुक्की बांध है। यह है मामला

केरल राज्य कि "प्रचुर वर्षा" के बावजूद,

इडुक्की जलाशय अपनी क्षमता के अनुसार नहीं भरा है, जबकि

जलाशय की क्षमता 70.500 टी. एम. सी. है, इसे केवल भरा गया था 57.365 टी. एम. सी. तक। इससे यह भी पता चलता है कि

यह मानते हुए कि सबसे बुरा होता है, 11 टी. एम. सी. से अधिक पानी

इडुक्की बांध द्वारा लिया जाएगा। उप निदेशक, बांध सुरक्षा, निगरानी निदेशालय, केंद्रीय जल

आयोग, जल संसाधन मंत्रालय ने हलफनामे में अप्रैल 2004 में, अन्य बातों के साथ-साथ, कहा गया है कि हाल ही में

केरल सरकार द्वारा भूकंप का उल्लेख किया गया है हलफनामा, सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा बांध को किसी नुकसान की सूचना नहीं दी गई थी

अधिकारी जिन्होंने बांध का निरीक्षण किया। विशेषज्ञों ने दी जानकारी
 बांध और केरल की सुरक्षा के बारे में सूचित किया
 सरकार ने एक अवरोधक दृष्टिकोण अपनाया है, अब इस दलील के तहत शरण
 लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि
 ये तथ्य के विवादित प्रश्न हैं। कोई रिपोर्ट नहीं है
 सुझाव दें कि बांध की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी
 यदि वर्तमान में जल स्तर को बढ़ाकर 142 फीट कर दिया जाए। द.
 रिपोर्ट इसके विपरीत है।

(हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)

122.9 उपरोक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, यह कोर्ट स्टेट ऑफ तमिल नाडु v.

केरल राज्य 983

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

केरल और उसके अधिकारियों को किसी भी तरह की बाधा डालने से रोका गया
 तमिलनाडु द्वारा और अधिक सुदृढीकरण के उपाय करने से
 सी. डब्ल्यू. सी. और तमिलनाडु द्वारा सुझाए गए सुझाव के अनुसार अनुमति दी गई थी
 मुल्लापेरियार बांध का जल स्तर बढ़ाकर 142 फीट करना।

122.10 . मुल्लापेरियार पर्यावरण में निर्णय

प्रोटेक्शन फोरम 1 का उच्चारण 27.02.2006 पर किया गया था।

123. 14/15.03.2006 को केरल का एक विशेष सत्र

विधान सभा बुलाई गई और एक विधेयक पेश किया गया

2003 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए, जिसे 15.03.2006 पर पारित किया गया था।
 उस पर

18.03.2006 , विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई और यह उस दिन से प्रभावी एक अधिनियम बन गया।

124. इस प्रकार, यह देखा गया है कि मुल्लापेरियार में इस न्यायालय के समक्ष सीधे विचार के लिए आने वाले मुद्दों में से एक

पर्यावरण संरक्षण मंच 1 यह था कि क्या

जलाशय का जल स्तर 136 फीट से 142 फीट तक। इसका परिणाम होगा

लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालना? विभिन्न क्षेत्रों से

विशेषज्ञ समिति, न्यायालय की रिपोर्ट सहित प्रतिवेदन

उन्होंने कहा कि इन रिपोर्टों में केरल की आशंकाओं (तीन जिलों का सफाया) को आधारहीन पाया गया था और

ऐसा कुछ नहीं है जिससे बांध की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए

यदि जल स्तर को बढ़ाकर 142 फीट कर दिया जाए। फैसले के अभिलेख

जल स्तर पर बांध की सुरक्षा के बारे में निष्कर्ष

इसे 142 फीट तक बढ़ाया गया है। 136 फीट के वर्तमान स्तर से।, इन शब्दों में: " विभिन्न रिपोर्टों ने सुरक्षा कोण की गहराई से जांच की है।

भूकंप प्रतिरोध के दृष्टिकोण सहित। द.

मुख्य बांध, दीर्घाओं, भवनों के निरीक्षण के बाद सी. डब्ल्यू. सी. की रिपोर्ट बांध, मिट्टी का बांध और स्पिलवे, यह निष्कर्ष निकालते हैं कि बांध सुरक्षित है

125. इन कारणों से, और अन्य में निहित

निर्णय में, यह न्यायालय इस दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचा कि जल स्तर को 136 फीट से बढ़ाया गया है। 142 फीट तक। खतरे में नहीं डालेंगे

किसी भी तरह से बांध की सुरक्षा। नतीजतन, इस न्यायालय ने केरल और उसके अधिकारियों को 984 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. में कोई बाधा डालने से रोक दिया।

तमिलनाडु द्वारा और अधिक सुदृढीकरण के उपाय करने से

सी. डब्ल्यू. सी. और तमिलनाडु द्वारा सुझाए गए सुझाव के अनुसार अनुमति दी गई थी

मुल्लापेरियार बांध का जल स्तर बढ़ाकर 142 फीट करना।

126. 27.02.2006 पर इस न्यायालय का निर्णय

सुनवाई के दौरान। यह पूरी तरह से एक न्यायिक सवाल था। द. केरल राज्य का दावा था कि जल स्तर नहीं हो सकता है

यह अपने वर्तमान स्तर 136 फीट से ऊपर उठाया गया है। दूसरी ओर, तमिल तमिलनाडु ने जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाने के लिए निर्देश की मांग की। और,

मजबूत होने के बाद, 152 फीट के अपने पूर्ण स्तर तक। द्वारा बाधा

मुल्लापेरियार बांध में केरल का जल स्तर बढ़ाया जा रहा है

142 फीट तक। सुरक्षा के आधार पर असमर्थनीय पाया गया, और,

अपना निर्णय, इस न्यायालय ने इस प्रकार घोषित किया।

क्या 2006 (संशोधन) अधिनियम अपने अनुप्रयोग में

मुल्लापेरियार बांध न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग है

127. अब सवाल यह है: क्या विवादित कानून है

न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग और क्या यह उल्लंघनकारी है

कानून का शासन?

128. जैसा कि निर्णय के पूर्व भाग में उल्लेख किया गया है, 2003

संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियम बनाया गया था।

सिंचाई कार्यों का निर्माण, संरक्षण और वितरण

अन्य आनुषंगिक मामले। धारा 2 (बी) "प्राधिकरण" को परिभाषित करती है जो अर्थात् केरल बांध सुरक्षा प्राधिकरण जिसके अधीन गठित किया गया है

सभी जलाशय जिनका उपयोग आपूर्ति, संग्रह के लिए किया जा सकता है, कृषि
उद्देश्यों के लिए जल का भंडारण या प्रतिधारण और

पानी की आपूर्ति के लिए जलाशय स्थापित किए गए। धारा 2 (ए. क्यू.) परिभाषित करती है

" जलमार्ग "जिसका अर्थ है एक नदी, धारा, झरने, चैनल,

तमिल नाडु के निजी राज्य के अलावा झील या पानी का कोई प्राकृतिक संग्रह।

केरल राज्य 985

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

भूमि और इसमें किसी भी नदी, धारा की कोई सहायक या शाखा शामिल है,

स्प्रिंग्स या चैनल। धारा 3 गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होती है।

और यह प्रावधान करता है कि सभी जल मार्ग और ऐसे पानी में सभी पानी राज्य में
पाठ्यक्रम सरकार (केरल सरकार) की संपत्ति होगी और सरकार इसका हकदार होगी।

ऐसे जलमार्गों के उपयोग का संरक्षण और विनियमन करना और सिंचाई के उद्देश्यों के
लिए उन सभी जलमार्गों में पानी

और बिजली का उत्पादन और संबंधित मामलों के लिए

इसके साथ या दोनों के लिए। धारा 4 विनियमन के लिए प्रावधान करती है।

जलमार्ग से जल के अवशोषण पर। धारा 5 प्रदान करती है

जलाशयों, एनीकट आदि के निर्माण पर विनियमन के लिए। अनुभाग

30 दूसरे राज्य या संघ को पानी के वितरण से संबंधित क्षेत्र। धारा 30 में यह
प्रावधान किया गया है कि पानी से कोई पानी नहीं

राज्य में पाठ्यक्रम किसी अन्य राज्य को वितरित किया जाएगा या

केंद्र शासित प्रदेश, एक समझौते के अनुसार को छोड़कर

राज्य सरकार और ऐसी सरकार के बीच उस संकल्प के संदर्भ में अन्य राज्य या केंद्र
शासित प्रदेश

57 निगरानी, निरीक्षण और रखरखाव पर सलाह के उद्देश्य से बांध सुरक्षा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान राज्य के क्षेत्र के भीतर स्थित बांधों का। इस धारा के प्रयोजनों के लिए "बांध" का अर्थ है कोई कृत्रिम अवरोध।

एक नदी के पार निर्मित सहायक कार्य सहित या

इसके लिए पानी को रोकने या मोड़ने की दृष्टि से इसकी सहायक नदियां

सिंचाई, पेयजल आपूर्ति या किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

धारा 62 प्राधिकरण के कार्यों का वर्णन करती है। इस धारा में कहा गया है कि किसी भी संधि में कुछ भी निहित होने के बावजूद, समझौता या साधन, बांध सुरक्षा प्राधिकरण, अन्य बातों के साथ-साथ,

सभी के सुरक्षा मूल्यांकन की व्यवस्था करने के लिए (1) कार्य हैं

राज्य में बांध; (2) सरकार को किसी भी बांध के कामकाज को निलंबित करने की सलाह देना यदि सार्वजनिक सुरक्षा की आवश्यकता है; (3)

जनहित में किसी भी बांध की अनिश्चितता की जांच करना और इसे बंद करने सहित इसकी सिफारिशें प्रस्तुत करना।

(4) सरकार को निरीक्षण और सलाह देना।

बढ़ाने या कम करने की सलाह पर सरकार

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी बांध का जलाशय स्तर

बांध से संबंधित और इसमें शामिल पर्यावरणीय पहलू; और 986 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

अपने जलाशय में पानी रखने के लिए किसी भी बांध का। उप.
में यह प्रावधान है कि जहां सलाह या

धारा 62 की धारा (3)

प्राधिकरण की सिफारिशें स्वामित्व वाले बांध से संबंधित हैं या
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नियंत्रित, यह विधिसम्मत होगा

सरकार के अलावा

सरकार के लिए आदेश या निर्देश जारी करने के लिए जो वह उचित समझती है, जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसके पास ऐसा अधिकार या नियंत्रण हो।

इस तरह के उपाय करने या इस तरह की चीजों को करने के लिए

सलाह को प्रभावी बनाने के लिए उसमें निर्दिष्ट समय

या सिफारिशें, और ऐसा व्यक्ति अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

सरकार द्वारा जारी आदेशों और निर्देशों के साथ।

129. श्री हरीश एन. साल्वे, विद्वान वरिष्ठ वकील

केरल ने तर्क दिया कि इन प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया था मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण मंच 1 में अपने निर्णय में इस न्यायालय द्वारा विचार और इसलिए,

यह न्यायालय आकस्मिकता के अनुसार है।

130. हम इस तर्क से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। 2003

मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण मंच 1 में सुनवाई के समय केरल द्वारा न तो अधिनियम का उल्लेख किया गया था और न ही उस पर भरोसा किया गया था।

यह सही था क्योंकि 2003 के अधिनियम का इस पर कोई सीधा असर नहीं था।

जिन मुद्दों पर विचार किया जा रहा था। धारा 3 का उल्लेख है -

धारा 2 में जलमार्ग और "जलमार्ग" की परिभाषा

(aq) में मुल्लापेरियार बांध जैसे बांध शामिल नहीं हैं। केरल

जब बहस हुई तो बांध सुरक्षा प्राधिकरण मौजूद नहीं था।

मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण मंच 1

निष्कर्ष निकाला। हमें सूचित किया जाता है कि बांध सुरक्षा प्राधिकरण आया है

इस मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाए जाने से कुछ दिन पहले, 18.2.2006 पर गठित किया जाना है। हमारे पास है।

2003 के संशोधित अधिनियम के प्रावधानों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया और,

हमारे विचार में, 2003 के अधिनियम को जिस भी तरह से देखा जाए, कोई नहीं था।

इस न्यायालय के लिए प्रश्न पर विचार करने और निर्णय लेने में बाधा
 चाहे जल स्तर को 136 फीट से बढ़ाया जाए। 142 फीट तक। होगा। बांध की
 सुरक्षा को खतरे में डालना। इस अदालत ने जवाब दिया कि
 अभिलेख पर सामग्री के आधार पर प्रश्न, नकारात्मक में। द.
 मुल्लापेरियार पर्यावरण 1 में इस न्यायालय का निर्णय

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 987

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

संरक्षण मंच 1 को किसी भी तरह की कल्पना नहीं कहा जा सकता है।
 इनक्वैरियम के अनुसार। यह फैसला केरल सहित सभी पक्षों को पूरी तरह से बाध्य करता है।

131. केरल विधानमंडल ने 2003 के अधिनियम में संशोधन किया
 2006 (संशोधन) अधिनियम। 2006 (संशोधन) अधिनियम द्वारा,
 धारा 2, खंड (जे. ए.) और (जे. बी.) "संरक्षक" और "बांध" को परिभाषित करते हुए
 खंड (जे) के बाद जोड़ा गया था। खंड (अला) "अनुसूचित" को परिभाषित करता है
 मूल अधिनियम की धारा 57, "निगरानी" शब्द, निरीक्षण को "सुरक्षा सुनिश्चित
 करने और" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था

सुरक्षा "। धारा 57 की उप-धारा (2) में दिए गए स्पष्टीकरण को हटा दिया गया। मूल
 अधिनियम की धारा 62 को नए द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था

धारा 62. नई धारा 62, अन्य बातों के साथ, बांध को सशक्त बनाती है।

निम्नलिखित कार्यों के साथ सुरक्षा प्राधिकरण:

" (1) XXX

XXX

XXX

(क) सभी बांधों की सुरक्षा और संरक्षा का मूल्यांकन करना ।

अन्य कारकों के बीच, आयु पर विचार करते हुए राज्य

संरचनाएँ, भूगर्भीय और भूकंपीय कारक, अपक्षय

या समय के साथ या अन्यथा होने वाले क्षरण;

((b) से (d)

XXX XXX

XXX

बांध, किसी भी बांध को निष्क्रिय करने या कार्य को प्रतिबंधित करने के लिए
यदि सार्वजनिक सुरक्षा या मानव जीवन के लिए खतरा है या

संपत्ति की आवश्यकता होती है;

(च) सरकार, संरक्षक या अन्य एजेंसियों को सलाह देना ।

साइट पर अपनाई जाने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में
अन्वेषण, डिजाइन, निर्माण, संचालन और

बांधों का रखरखाव;

(छ) अध्ययन करना, निरीक्षण करना और संरक्षक को सलाह देना ।

या बढ़ाने की सलाह पर कोई अन्य एजेंसी या

अधिकतम जल स्तर या पूर्ण जलाशय स्तर को कम करना 988 सर्वोच्च न्यायालय
रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

किसी भी बांध का, एक अनुसूचित बांध नहीं होने के कारण,

संबंधित बांध की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए;

(ज) से (जे)

XXX

132. बांध सुरक्षा प्राधिकरण को प्रदत्त कार्य

नई धारा 62 के तहत निर्णय, डिक्री या आदेश को ओवरराइड किया जाता है।

किसी न्यायालय या किसी संधि, समझौते, अनुबंध, लिखत या

कोई अन्य दस्तावेज। नई धारा 62 की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि जहां बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा निर्देश जारी किया जाता है

उप-धारा (1) के तहत, संरक्षक या कोई अन्य एजेंसी

जिसे यह निर्देशित किया जाता है, वह इसके भीतर तत्काल कदम उठाएगा

प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय सीमा या करना या करने से बचना

ऐसी चीजें जो निर्धारित समय सीमा के भीतर हों और

प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करना। धारा 62 के बाद,

दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट। उप-धारा (2) और (3) से नई धारा 62 ए प्रावधानों को ओवरराइड करती है, जो इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गत:

" (1) XXX

XXX

XXX

(2) किसी अन्य कानून में निहित किसी भी चीज के बावजूद या

किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश में,

या कोई संधि, अनुबंध, समझौता, लिखत या दस्तावेज,

पूर्ण जलाशय को बढ़ाएँ, बढ़ाएँ, जोड़ें या विस्तारित करें स्तर स्थिर या किसी अन्य तरीके से कोई कार्य करें या छोड़ दें

जल स्तर को बढ़ाने के लिए निर्धारित और निर्धारित किया गया
दूसरी अनुसूची। ऐसा स्तर नहीं होगा
इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तन किए गए
किसी भी अनुसूचित बांध के संबंध में।

किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, निर्देश में या
कोई संधि, अनुबंध, समझौता, लिखत या दस्तावेज, तमिलनाडु राज्य v.

केरल राज्य 989

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

कोई सरकार, संरक्षक या कोई अन्य अभिकरण जिसका इरादा हो
किसी संधि, अनुबंध के तहत कोई अधिकार प्राप्त करना या प्राप्त करना,
समझौता, साधन या दस्तावेज या किसी अन्य माध्यम से
भंडारण को बढ़ाने, बढ़ाने, जोड़ने या विस्तारित करने के लिए
किसी भी जलाशय की क्षमता या पूर्ण जलाशय स्तर में वृद्धि
अनुसूचित बांध, इसके लिए कोई कार्य या कार्य नहीं करेगा।
लिखित में पूर्व सहमति के बिना उद्देश्य
प्राधिकरण और ऐसी अनुमति देने वाला आदेश प्राप्त किए बिना
प्राधिकरण द्वारा कार्य।

(4)

और (5)

XXX XXXXX "

XXX

133. धारा 62 बी बांध को दीवानी न्यायालय की शक्तियां देती है।

सुरक्षा प्राधिकरण उसमें निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, जबकि बढ़ाने के लिए लिखित रूप में सहमति के लिए आवेदनों से निपटना,

भंडारण क्षमता को बढ़ाना, जोड़ना या विस्तारित करना या

जल प्रसार क्षेत्र या अधिकतम जल स्तर बढ़ाने के लिए

या अनुसूचित बांधों के लिए पूर्ण जलाशय स्तर तय किया गया है। धारा 68 ए

सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निपटाने, निर्णय लेने या निर्णय लेने से रोकता है।

जो 2003 के अधिनियम के तहत, 2006 द्वारा संशोधित (संशोधन) अधिनियम को निपटाने, तय करने या निपटाने की आवश्यकता है या

बनो।

अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित। दूसरी अनुसूची में,

मद संख्या 1 पर "मुल्लापेरियार बांध" विषय है जिसके लिए एफआरएल है। सबसे गहरे बिंदु से 41.45 मीटर (136 फीट) पर तय किया गया है।

मुख्य बांध के स्थल पर पेरियार नदी का स्तर।

134. तमिलनाडु का कहना है कि 2006 (संशोधन) अधिनियम

जिस हद तक यह मुल्लापेरियार बांध पर लागू होता है वह रद्द करने का प्रयास करता है

मुल्लापेरियार पर्यावरण में इस न्यायालय का निर्णय

संरक्षण मंच 1 बांध को लुप्तप्राय घोषित करके और जल स्तर की ऊंचाई 136 फीट तय करके। ; जिसे यह अधिकृत करता है

बांध सुरक्षा प्राधिकरण निर्णय की अवहेलना करेगा और स्वयं निर्णय लेगा कि जल स्तर बढ़ाने की अनुमति दी जाए या नहीं और

खोज के बावजूद बांध का विघटन इस न्यायालय द्वारा 2006 के निर्णय में अभिलिखित सुरक्षा और इस प्रकार, 2006 (संशोधन) अधिनियम असंवैधानिक है जो 990 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. का उल्लंघन करता है।

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत और परिणामस्वरूप कानून का शासन।

135. दूसरी ओर श्री हरीश एन. का तर्क।

केरल के विद्वान वरिष्ठ वकील साल्वे ने कहा कि विधायिका

प्रत्येक राज्य के पास न केवल शक्ति है बल्कि लेने का दायित्व भी है।

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित विधायी उपाय और

अपने निवासियों की सुरक्षा। जहाँ किसी राज्य का विधानमंडल है संतुष्ट है कि
उपयोग या भंडारण में कटौती करने की आवश्यकता है

अपने नागरिकों की रक्षा के लिए जलाशय और अधिनियम बनाने के लिए चुना गया

के विधायी क्षमता से अधिक कहा जाए राज्य यदि यह विधान के भीतर जलाशय और
बांध से संबंधित है

राज्य। केरल विधानमंडल ने एहतियाती उपाय किए हैं

बांधों के भंडारण स्तर पर अस्थायी प्रतिबंध लगाकर

धारा 62 ए (2) के साथ पठित दूसरी अनुसूची में उल्लिखित

2006 (संशोधन) अधिनियम और उक्त प्रतिबंध हैं -

केरल विधानमंडल के विधायी ज्ञान के आधार पर कि ये बांध अपनी उम्र के कारण लुप्तप्राय हैं,
अपघटन, अपघटन, संरचनात्मक या अन्य बाधाएँ।

संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेते हुए श्री हरीश साल्वे का तर्क है कि न्यायालय को इस आधार
पर आगे बढ़ना चाहिए कि

विधायिका जरूरतों को समझती है और सही ढंग से समझती है

इसके अपने लोगों और इसके कानूनों की समस्याओं की ओर निर्देशित किया जाता है

अपने अनुभव से प्रकट किया गया है और पर्याप्त पर आधारित हैं

आधार।

136. श्री हरीश एन. साल्वे, केरल के विद्वान वरिष्ठ वकील

बहुत हद तक 'एहतियाती सिद्धांत' और 'सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत' पर निर्भर करता है और तर्क देता है कि केरल विधानमंडल सक्षम था

अनुबंधों को खत्म करना और मुल्लापेरियार की सुरक्षा को विनियमित करना

पेरियार नदी के पार अपने क्षेत्र के भीतर स्थित बांध। बिनि।

निवेदन यह है कि संप्रभु के रूप में राज्य जारी है

ऐसे अधिकार दिए जाने के बाद भी पर्यवेक्षण। इसमें माना जाता है कि उनके द्वारा फाइजर पशु स्वास्थ्य 2 7 पर मजबूत निर्भरता रखी गई है।

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 991

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

137. फाइजर एनिमल हेल्थ 27 में, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस

यूरोपीय समुदाय (थर्ड चैंबर) का संबंध था विनियमों की वैधता और वैधता जो, अन्य बातों के साथ-साथ,

विचाराधीन पदार्थ के विशेष उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। फाइजर तर्क दिया कि यह सीधे प्रतिस्पर्धा से संबंधित था

विनियमन क्योंकि यह वर्जिनियामाइसिन के प्राधिकरण को वापस लेता है। द. यूरोपीय संघ के वकील ने तर्क दिया कि नियम

सामान्य अनुप्रयोग के लिए अधिनियमित किया गया था जो लागू था

वस्तुनिष्ठ रूप से निर्धारित परिस्थितियाँ और वे प्रतिबंध लगाते हैं

विचाराधीन पदार्थ का विशेष उपयोग, क्या वे हैं

फाइजर या किसी अन्य द्वारा एक अलग नाम के तहत विपणन किया गया। न्यायालय ने कहा कि निवारक लेने के उद्देश्य से

कार्रवाई, उत्पादों के उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों की प्रतीक्षा करने के लिए

आवश्यकता नहीं थी।

138. एहतियाती सिद्धांत से निपटते हुए, न्यायालय ने कहा

ये टिप्पणियां:

" सबसे पहले, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि, जब एहतियाती

अनिश्चितता और यह कि पूर्ण जोखिम उठाना असंभव है
उपलब्ध समय में मूल्यांकन रोकने वाला नहीं है

निवारक कार्रवाई करने से सक्षम सार्वजनिक प्राधिकरण

यदि ऐसे उपाय आवश्यक प्रतीत होते हैं तो सुरक्षात्मक उपाय,

मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम के स्तर को ध्यान में रखते हुए जो सार्वजनिक
प्राधिकरण ने तय किया है वह महत्वपूर्ण सीमा है

वैज्ञानिक आधार, अतिरिक्त की उपलब्धता लंबित
वैज्ञानिक प्रमाण।

992 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

यह न्यायालय के लिए नहीं है कि वह दोनों में से किसी के गुण-दोष का आकलन करे।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने इसके समक्ष तर्क दिया और प्रतिस्थापित किया

सामुदायिक संस्थानों के लिए इसका मूल्यांकन

जिसे संधि उस संबंध में एकमात्र जिम्मेदारी प्रदान करती है।

139. केरल ने भी इस लेख पर भरोसा किया है, "द पब्लिक"

रॉडरिक ई. द्वारा जल अधिकार संदर्भ में विश्वास सिद्धांत।

वालस्टन 22। लेखक ने निम्नलिखित चार सिद्धांतों का वर्णन किया है -

सार्वजनिक न्यास सिद्धांत:

" (1) संप्रभु राज्य के रूप में "निरंतर पर्यवेक्षी बना हुआ है

नौगम्य जल और अंतर्निहित तल पर नियंत्रण;

(2) विधायिका को, या तो प्रत्यक्ष रूप से या जल अधिकार एजेंसी के माध्यम से, उपयोगी जल प्रदान करने का अधिकार है

अपरिहार्य रूप से नुकसान, ट्रस्ट स्रोत धारा में उपयोग करता है; "

(3) राज्य का जनता को स्वीकार करने का "सकारात्मक कर्तव्य" है

योजना बनाने और पानी आवंटित करने में विश्वास रखें

संसाधन; और

(4) राज्य का "निरंतर पर्यवेक्षण का कर्तव्य" है

ऐसे अधिकार दिए जाने के बाद भी जल अधिकार।

139.1 सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत, रॉडरिक ई. वाल्टस्टन कहते हैं,

कुछ लोगों द्वारा इसे संप्रभु राज्य नियामक का अभ्यास माना जाता है,

पुलिस शक्ति के समान।

140. हमारी राय में, 'सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत' का सिद्धांत

रॉडरिक ई. वाल्टस्टन द्वारा निकाले गए जल अधिकारों के संदर्भ में या फाइजर एनिमल में समझाया गया 'एहतियाती सिद्धांत' स्वास्थ्य 2 7 पर शायद ही संदेह किया जा सकता है लेकिन इन सिद्धांतों में कोई संदेह नहीं है।

मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा के संदर्भ में आवेदन

जल स्तर को वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 142 फीट कर दिया गया है।, जो

यह सीधे मुद्दे में था और स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से और तमिलनाडु बनाम का राज्य रहा है।

केरल राज्य 993

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

स्पष्ट रूप से

न्यायालय द्वारा निर्धारित। इस अदालत ने पाया है

- विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट द्वारा समर्थित-कि सुरक्षा

यदि जल स्तर को वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 142 फीट कर दिया जाता है तो विषय बांध का स्तर बिल्कुल भी खतरे में नहीं पड़ता है। केरल, जो है

चुनाव लड़ने वाला दल, 'सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत' को लागू करके या

'एहतियाती उपाय', कानून के माध्यम से कोई कार्य नहीं कर सकते

अंतिमता प्राप्त की। यदि किसी कानून का उल्लंघन किया गया है स्थापित संवैधानिक सीमा जैसे कि शक्तियों का पृथक्करण, इसे जाना पड़ता है और इसे रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

141. यह सच है कि राज्य के संप्रभु हित प्रदान करते हैं

सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत की नींव लेकिन न्यायिक कार्य भी राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रभु कार्य है और

कानून के शासन की नींव। विधायिका आह्वान करके नहीं कर सकती है

'सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत' या 'एहतियाती सिद्धांत' अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालयों की कार्यवाही को नियंत्रित करता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारित करता है।

न्यायालय द्वारा तथ्य के आधिकारिक और बाध्यकारी निष्कर्ष को एक तरफ रखते हुए, विशेष रूप से, ऐसी स्थितियों में जहां कार्यकारी शाखा

(राज्य सरकार) मुकदमे में एक पक्ष थी और

उन्हें सुनने के बाद अंतिम फैसला सुनाया गया।

142. 2006 (संशोधन) अधिनियम के लागू होने और प्रभाव में

मुल्लापेरियार बांध पर निम्नलिखित प्राप्त करना चाहते हैं:

(क) यह धारा 62 को एक नए प्रावधान के साथ प्रतिस्थापित करता है जिसके तहत,

इस न्यायालय के निर्णय के बावजूद और इसके बावजूद

किसी भी संधि, अनुबंध, 1886 पट्टे में निहित कुछ भी

समझौता और 1970 के पूरक समझौते, कार्य

मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा और बिजली का मूल्यांकन तमिलनाडु को संरक्षक के रूप में निर्देश जारी करने के लिए बांध सुरक्षा प्राधिकरण को सौंपा गया है;

(ख) बांध सुरक्षा प्राधिकरण को, अन्य बातों के साथ-साथ, मुल्लापेरियार बांध के कामकाज को प्रतिबंधित करने और/या संचालन करने का अधिकार है।

अधिकतम को बढ़ाने या कम करने की सलाह पर अध्ययन

जल स्तर या पूर्ण जलाशय स्तर; 994

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

(ग) मुल्लापेरियार बांध पर केरल विधानमंडल द्वारा विचार किया जाता है।

लुप्तप्राय होने के लिए और धारा 62 (ए) के आधार पर, यह एफ. आर. एल. को बढ़ाने, विस्तार करने या किसी भी मामले में तमिलनाडु के अधिकार को छीन लेता है।

जिस तरह से दूसरे में निर्धारित जल स्तर को बढ़ाया जाए

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार को छोड़कर अनुसूची;

(घ) धारा 62 ए (4) के तहत, तमिलनाडु को संरक्षक के रूप में

इसके लिए बांध सुरक्षा प्राधिकरण को एक आवेदन जमा करें

जल स्तर में वृद्धि के लिए सहमति;

(ई) यह अधिकार सहित तमिलनाडु के सभी अधिकारों को छीन लेता है।

जिसे बढ़ाने के लिए इस न्यायालय का निर्णय पारित किया गया है जल स्तर;

(च) बांध सुरक्षा प्राधिकरण के पास आदेश देने की शक्ति है

मुल्लापेरियार बांध को चालू करना।

143. मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण में यह न्यायालय

फोरम 1, केरल राज्य को सुनने के बाद, राजी नहीं हुआ

केरल के इस तर्क से कि मुल्लापेरियार बांध असुरक्षित था या उस बांध में पानी का भंडारण नहीं बढ़ाया जा सकता है। बल्कि यह तमिलनाडु को वर्तमान जल स्तर बढ़ाने की अनुमति दी गई 136 फीट। 142 फीट तक। और केरल को तमिल में हस्तक्षेप करने से रोक दिया मुल्लापेरियार बांध में जल स्तर बढ़ाने में तमिलनाडु का अधिकार 142 फीट तक। इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा दोनों राज्यों के बीच सुरक्षा के संबंध में एक निर्णय दिया गया है।

वास्तव में पक्षों के बीच उत्पन्न होता है और इसके सामने लाया जाता है अदालत। आवश्यक रूप से, ऐसा निर्णय बाध्यकारी होना चाहिए

सिद्धांत कि विधायिका न्यायिक निर्णय दे सकती है तमिलनाडु राज्य बनाम अपने विधायी क्षेत्र के भीतर वैध कानून लागू करके अप्रभावी।

केरल राज्य 995

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

मौलिक रूप से इसके चरित्र को पूर्वव्यापी रूप से बदलने या बदलने का कोई अनुप्रयोग नहीं है जहां न्यायिक निर्णय दिया गया है।

तथ्य की खोज को दर्ज करके। सत्ता के झांसे में,

विधायिका, दिए गए निर्णय के प्रभाव को बेअसर नहीं कर सकती है

साक्ष्य/सामग्री के माध्यम से तथ्य का पता लगाने के बाद

विवाद के लिए पक्षों द्वारा रखा गया। एक निर्णय जो तथ्यों पर निष्कर्ष देकर मामले का निपटारा करता है, के लिए खुला नहीं है

विधायिका द्वारा परिवर्तन। एक अंतिम निर्णय, एक बार प्रस्तुत किया गया, न्यायालय द्वारा परिवर्तित किए जाने तक कार्य करता है और लागू रहता है

उचित कार्यवाही।

144. 2006 (संशोधन) अधिनियम स्पष्ट रूप से रद्द करने का प्रयास करता है इस न्यायालय का निर्णय जो संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।

इसके अलावा, केरल द्वारा यह विवादित नहीं है कि 2006 (संशोधन) अधिनियम एक सत्यापन अधिनियम नहीं है। चूँकि विवादित कानून है एक मान्य कानून नहीं है, यह पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या विधानमंडल ने दोष को दूर कर दिया है

जिसे न्यायालय ने मौजूदा कानून में पाया है। वर्ष 2006 (संशोधन) मुल्लापेरियार पर इसके अनुप्रयोग और प्रभाव में अधिनियम बांध काफी हद तक विधायी के अलावा एक अन्य कानून है क्योंकि यह है इसके पूर्व और आधिकारिक निर्णय को रद्द करने के उद्देश्य से

इस न्यायालय के अंतिम निर्णय को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए संशोधित करना संवैधानिक सिद्धांत कि इस तरह के अंतिम निर्णय का संशोधन विशेष रूप से न्यायालय के विवेक के भीतर रहना चाहिए।

145. धारा 62 ए बांध को लुप्तप्राय घोषित करती है।

अधिनियम में संलग्न दूसरी अनुसूची की ऊंचाई तय करती है जल स्तर 136 फीट है। हालाँकि इस न्यायालय ने अपने फैसले में मुल्लापेरियार बांध को सुरक्षित घोषित किया और इसकी वृद्धि की अनुमति दी जल स्तर 142 फीट तक पहुंच गया है। इसके अलावा, 2006 (संशोधन) अधिनियम बांध सुरक्षा प्राधिकरण को इसकी सुरक्षा का निर्णय लेने के लिए अधिकृत करता है जल स्तर को बढ़ाने दें। प्रावधान की सीधी अवहेलना की जा रही है

इस न्यायालय के निर्णय से। धारा 62 ए सभी कार्यों को भी रोक देती है।

इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांकित निर्णय में अनुमत बांध पर

27.2.2006 . हमारी राय में, 2006 (संशोधन) अधिनियम द्वारा,

केरल विधानमंडल ने 996 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. के हित में एक अंतिम निर्णय को पलट दिया है।

अपनी खुद की कार्यकारी सरकार। विवादित कानून की राशि
इस न्यायालय के निर्णय को उलटने के लिए जो निर्धारित करता है
सीधे मुल्लापेरियार बांध के निर्माण के लिए सुरक्षा का सवाल
जल स्तर 142 फीट तक। और जिसके तहत तमिलनाडु का कानूनी अधिकार है
निर्धारित किया गया है।

146. केरल की ओर से, श्री द्वारा इसका जोरदार तर्क दिया जाता है।

हरीश साल्वे ने कहा कि लोगों की सुरक्षा का अधिकार जनता का है
अधिकार इस अदालत के 2006 के फैसले में पारित नहीं हो सकता था।
इस संबंध में बहुमत के फैसले पर बहुत अधिक निर्भरता रखी गई है।
व्हीलिंग ब्रिज 29. सबसे पहले, सार्वजनिक अधिकार योग्यता
व्हीलिंग ब्रिज 29 का वर्तमान मामले में कोई आवेदन नहीं है क्योंकि
आक्षेपित प्रावधानों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है
हमारे सामने और वे प्रावधान जो अमेरिका के सामने विवादित थे
व्हीलिंग ब्रिज में सुप्रीम कोर्ट 2 9. बुनियादी सवाल
व्हीलिंग ब्रिज 2 9 में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष था
क्या समझौता एक प्रतिबंध के रूप में काम कर सकता है या नहीं
संविधान के तहत न्यायालयों की विनियमन करने की शक्ति

कई राज्यों के बीच व्यापार। तर्क के जवाब में इसके समक्ष आग्रह किया गया कि
कांग्रेस को रद्द करने का प्रभाव नहीं हो सकता है

न्यायालय का निर्णय जो पहले ही दिया जा चुका है या अधिकार

इस प्रकार निर्धारित एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया गया था लेकिन इस प्रस्ताव को इन मामलों में लागू नहीं माना गया था

सार्वजनिक अधिकारों पर निर्णय। हमारे विचार में, एक कानून शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करने से बचा नहीं जा सकता है

एक अपवाद बनाकर जिसे विधायिका ने विनियमित किया है

एक वैध नियामक उपाय प्राप्त करने से उल्लंघन में अधिनियमित ऐसे कानून के लिए संवैधानिक प्रतिरक्षा प्रदान नहीं होती है शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत या दूसरे शब्दों में, कानून का शासन।

ऐसा अंतिम निर्णय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसे मामलों में, अदालतें, यदि उनके सामने लाई जाती हैं, तो ऐसे मामलों को फिर से खोला जा सकता है

अपने विवेक का प्रयोग करें।

147. हमारे विचार में, व्हीलिंग ब्रिज 29 तमिलनाडु राज्य द्वारा योग्यता बनाम।

केरल राज्य 997

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

यदि व्हीलिंग ब्रिज 29 प्रस्ताव देता है कि एक निर्णय सार्वजनिक अधिकार घोषित करने को बाद में रद्द किया जा सकता है

श्री हरीश साल्वे द्वारा प्रतिवाद किया गया कानून, तो हम कहते हैं,

हमें ऐसा करना चाहिए कि हम इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए राजी न हों

व्हीलिंग ब्रिज 29 में बहुमत का निर्णय। दोनों अलग-अलग

व्हीलिंग ब्रिज में राय 29 एक मैकलीन जे. और दूसरे द्वारा

वेन जे. द्वारा-हालांकि अल्पमत में-भी इस तरह को स्वीकार नहीं किया

प्रस्ताव।

148. उपरोक्त चर्चा को भी इस तर्क का जवाब देना चाहिए।

श्री हरीश साल्वे का कहना है कि अंतर-पक्षीय मुकदमेबाजी के नियम नहीं हैं

अपने लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य के दायित्व का निर्धारण करना।

हम नहीं समझते कि इस राय पर विचार करना आवश्यक है। वीरामेंद्री, जे.
गोब्सिकोवो में-नागिमरोस परियोजना (आईसीजे)

विवरण। वीरामेंद्री, जे. द्वारा इस बात पर जोर दिया गया है कि मुद्दा क्या है।

गंभीर या विनाशकारी पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न होता है,

न्यायालय को अंतर-पक्षीय प्रतिकूल प्रक्रियाओं से परे देखना चाहिए।

149. यह सच है कि बांध की सुरक्षा एक ऐसा पहलू है जो

अलग-अलग परिस्थितियों में समय-समय पर बदलते रहते हैं लेकिन फिर

किन परिस्थितियों के आधार पर यह दिखाया जाना चाहिए

पहले की खोज से प्रस्थान करना आवश्यक हो जाता है।

यह हमेशा किसी भी पक्ष के लिए अदालत से संपर्क करने के लिए खुला है और

सुरक्षा पहलू के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करें लेकिन परिस्थितियों में अनुपस्थित परिवर्तन,
पिछली कार्यवाही में तथ्यात्मक निर्धारण

यहाँ तक कि बांध की सुरक्षा जैसे प्रश्नों पर भी पक्षकार बाध्य होते हैं।

यदि परिस्थितियाँ बदल गई हैं जिसके कारण सुरक्षा के पहलू पर फिर से विचार करने की
आवश्यकता है, तो न्यायालय स्वयं अपने निर्णय का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मामले
को फिर से खोलने का विवेकाधिकार लेकिन विधायी निरस्तीकरण

सबसे अच्छे कारणों और वास्तविक कारणों के लिए भी निर्णय

सार्वजनिक सुरक्षा के लिए चिंता विधायिका को कानून द्वारा अदालत के फैसले को रद्द करने के
लिए तैयार नहीं करती है।

150. श्री हरीश साल्वे का तर्क कि घोषणा करके

लेकिन असुरक्षित, विधायिका ने किसी भी तथ्य को प्रस्तुत नहीं किया है; वह इसे असुरक्षित मानती है और इसे विनियमित करने के लिए एक प्राधिकरण का गठन करती है, जो 998 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. है।

अस्वीकार किए जाने का उल्लेख किया। न्यायिक द्वारा तथ्य के रूप में क्या पाया गया है

निर्धारण को कानूनी रूप से लागू करके अन्यथा घोषित नहीं किया जा सकता है

काल्पनिक। हालाँकि, हम निवेदन स्वीकार करने के लिए राजी हैं। तमिलनाडु के वरिष्ठ वकील श्री विनोद बोबडे ने कहा कि

इस तथ्य से पता चला कि मुल्लापेरियार बांध सुरक्षित है

न्यायालय और तथ्य के उस निष्कर्ष को कभी भी नहीं माना जा सकता है

एक कानूनी कल्पना द्वारा काल्पनिक जो फिर मान लेने के लिए आगे बढ़ता है

वास्तविक होने के विपरीत, अर्थात्, कि बांध खतरे में है। यह है।

विधायी नीति का मामला नहीं है जैसा कि इसे बनाया जा रहा है,

बल्कि हमारी राय में, यह न्यायिक प्रक्रिया में घुसपैठ है और

न्यायिक अंग के कार्य। दूसरी अनुसूची की मद संख्या 1 के साथ पठित धारा 62 ए की घोषणा में कोई तरीका नहीं छोड़ा गया है -

संदेह है कि अधिनियम का उद्देश्य प्रश्न तक पहुँचना है न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया।

151. सवाल यह है कि क्या विधायिका ने न्यायिक शक्ति को हड़प लिया है या इसका उल्लंघन करते हुए कोई कानून बनाया है

किसी निर्णय पर कानून के वास्तविक प्रभाव पर विचार करने के बाद मामला या न्यायिक कार्यवाही। यह निर्धारित करने के लिए परीक्षणों में से एक

एक निर्णय को रद्द कर दिया जाता है यह देखने के लिए कि क्या कानून और निर्णय असंगत और अपरिवर्तनीय हैं ताकि दोनों खड़े न हो सकें

एक साथ। जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, वह है

यह बहुत स्पष्ट है कि एक ओर तथ्य की खोज है आधार पर पक्षों को सुनने पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया

के निर्णय में अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य/सामग्रियों का

मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण मंच 1 में यह न्यायालय

और दूसरी ओर 2006 (संशोधन) अधिनियम में, केरल

विधायिका ने बांध को लुप्तप्राय घोषित कर दिया है और

बांध में जल स्तर 136 फीट तय किया गया। यदि मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण फोरम 1 में इस न्यायालय का निर्णय और

जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा के लिए 2006 (संशोधन) अधिनियम को साथ-साथ रखा गया है।

136 फीट। 142 फीट तक। संबंधित है, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय का निर्णय और केरल राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून

एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं और वे अपरिवर्तनीय हैं और असंगत। विवादित कानून निरस्तीकरण का एक उत्कृष्ट मामला है।

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 999

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

एक निर्णय का सरलीकरण, जैसा कि इस न्यायालय के निर्णय में

बांध की सुरक्षा का सवाल इस आधार पर निर्धारित किया गया था कि

इसके सामने रखी गई सामग्री और किसी की व्याख्या पर नहीं

मौजूदा कानून और विधायिका के लिए कोई अवसर नहीं था जिस आधार पर निर्णय दिया गया था, उसे बदलकर कानून में संशोधन करें।

स्थापित किया गया। जब विवादित कानून एक सत्यापन कानून नहीं है, तो वहाँ विधायिका द्वारा दोष को हटाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि न्यायालय ने मौजूदा कानून में कोई बुराई नहीं पाई है और घोषणा की है इस तरह का कानून बुरा है।

152. एक और पहलू यह है कि संघीय विवादों में, 1000 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

दूसरे राज्य के साथ किसी भी विवाद के मामले में अपने स्वयं के कारण में। कानून का शासन जो हमारे संविधान की मूल विशेषता है, मना करता है।

संघ और राज्यों को कानून द्वारा किसी विवाद का निर्णय लेने से दो राज्यों के बीच या संघ और एक या अधिक राज्यों के बीच राज्यों। यदि संविधान के तहत इसकी अनुमति दी गई थी, तो संघ और वे राज्य जिनके बीच कोई विवाद है

दूसरे के खिलाफ अपने दावे या अधिकार को स्थापित करने के लिए कानून बनाएगा और इससे विरोधाभासी और अपरिवर्तनीय कानून बनेंगे। द.

संविधान निर्माताओं ने विरोधाभासी और अपरिवर्तनीय कानूनों के अधिनियमित होने की किसी भी संभावना को दूर करने के लिए संघीय विवादों के स्वतंत्र निर्णय के लिए प्रावधान। संविधान का अनुच्छेद 131 मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है -

सरकार के बीच विवादों के संबंध में यह न्यायालय

भारत और एक या अधिक राज्यों या सरकार के बीच

भारत का और किसी भी राज्य या राज्यों का एक तरफ और एक या अधिक

जहां तक विवाद के रूप में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के राज्यों में कोई भी प्रश्न शामिल है जिस पर अस्तित्व या विस्तार शामिल है। कानूनी अधिकार निर्भर करता है। अनुच्छेद 131 में जोड़ा गया परंतु

इस न्यायालय की अधिकारिता के लिए एक अपवाद बनाता है संधि, समझौते, वाचा, अनुबंध, सनद या इसी तरह के अन्य साधनों से उत्पन्न होने वाला विवाद

प्रारम्भ होने से पहले प्रवेश किया गया या निष्पादित किया गया
संविधान और इस तरह के प्रारंभ के बाद भी जारी है, जो राजनीतिक प्रकृति के हैं। के संबंध में
अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवाद,

अनुच्छेद 262 उनके लिए न्यायाधिकरण या मंच के निर्माण का प्रावधान करता है।

न्यायनिर्णयन। संघीय विवादों में, संसद या राज्य

कानून द्वारा विधायिकाएँ, यदि दोनों के बीच विवाद का फैसला करना चाहते हैं

राज्यों के बीच या संघ और एक या अधिक राज्यों के बीच सीधे

या अप्रत्यक्ष रूप से, अनुच्छेदों में प्रदान किया गया न्यायिक तंत्र

131 और संविधान के 262 को निरर्थक बना दिया जाएगा।

और इसलिए, ऐसा विधान संवैधानिक रूप से नहीं हो सकता है।

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन माना जाता है।

153. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे का कहना सही है कि किसी कानून को कभी भी
चुनौती नहीं दी जा सकती है।

रेस जुडिकाटा के सिद्धांत और यह कि यह एक पक्ष को बांधता है और नहीं

विधायिका। यहाँ सवाल यह नहीं है कि 2006

(संशोधन) अधिनियम के आधार पर असंवैधानिक है

न्यायिक लेकिन सवाल यह है कि कब एक स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है

जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाने के लिए सुरक्षित। और पानी की अनुमति दी बांध के
लीवर को 142 फीट तक बढ़ाया जा रहा है। और उस फैसले में है

पार्टियों के बीच अंतिम और बाध्यकारी बन जाता है, क्या केरल ने

विधायिका ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन किया इस तरह का कानून बनाना? जिस पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है, सवाल का जवाब सकारात्मक होना चाहिए और हम इस तरह पकड़ें।

154. जहाँ दो राज्यों के बीच पहले से ही विवाद है इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था, जिसे यह अधिकार दिया गया है किसी एक पक्ष द्वारा अधिनियमित किसी भी एकतरफा कानून से निपटने के लिए कि अंतिम निर्णय को पलटने का परिणाम बुरा है, इसलिए नहीं कि यह रेस जुडिकाटा के सिद्धांतों से प्रभावित है लेकिन क्योंकि यह शक्तियों के पृथक्करण और कानून के शासन के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, इस तरह के कानून द्वारा, विधायिका ने स्पष्ट रूप से न्यायिक व्यवस्था को हड़प लिया है। शक्ति। रेस-जुडिकाटा

155. यह सच है कि 2006 का फैसला अभ्यास में दिया गया था के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता संविधान और वे याचिकाएँ जो इस तमिलनाडु राज्य को हस्तांतरित की गई थीं v.

केरल राज्य 1001

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

अनुच्छेद 139 ए के तहत अदालत लेकिन यह कहने के लिए कि इस तरह का निर्णय करता है इस न्यायालय की कल्पना को किसी भी तरह से नहीं माना जा सकता है अधिकारिता के बिना दिया गया निर्णय। इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में दर्ज किया गया निष्कर्ष उतना ही प्रभावी है।

और किसी भी अन्य कार्यवाही की तरह अंतिम।

156. रेस जुडिकाटा का नियम केवल एक तकनीकी नियम नहीं है।

लेकिन यह उच्च सार्वजनिक नीति पर आधारित है। नियम में ए शामिल है सार्वजनिक नीति का सिद्धांत, जो बदले में, एक अनिवार्य हिस्सा है

कानून का शासन। डचेस ऑफ किंगस्टन 62 में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स

(सर विलियम डी ग्रे की राय में) ने कहा है: इन से

साक्ष्य में दिए जाने वाले निर्णयों से संबंधित मामलों की विविधता

दीवानी मुकदमों में, ये दो कटौती आम तौर पर सच प्रतीत होती हैं: पहला, कि समवर्ती अधिकारिता के न्यायालय का निर्णय,

सीधे मुद्दे पर, एक याचिका, एक बार, या सबूत के रूप में है,

निर्णायक, एक ही पक्षकारों के बीच, एक ही मामले पर, सीधे दूसरे न्यायालय में विचाराधीन; दूसरा, कि निर्णय

अनन्य अधिकारिता वाले न्यायालय का, सीधे इस बिंदु पर, है,

समान तरीके से, एक ही मामले पर निर्णायक, के बीच

एक ही पक्ष, संयोग से दूसरे न्यायालय में एक अलग उद्देश्य के लिए प्रश्न में आते हैं।

157. कॉर्पस ज्यूरिस बताते हैं कि रेस जुडिकाटा एक नियम है

प्रत्येक सुव्यवस्थित प्रणाली में व्याप्त सार्वभौमिक कानून

न्यायशास्त्र, और दो आधारों पर रखा गया है, जिसमें सन्निहित है

सामान्य कानून के विभिन्न सिद्धांत; एक, सार्वजनिक नीति और

आवश्यकता, जो राज्य के हित में है कि वहाँ

मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए; और दूसरा, कठिनाई पर

व्यक्ति कि उसे एक ही कारण से दो बार परेशान किया जाना चाहिए।

158. श्योपरसन सिंह 63 में सर लॉरेंस जेनकिंस ने उल्लेख किया है

लॉर्ड कोक द्वारा घोषित कानून का बयान, 'ब्याज रिपब्लिका

62. डचेस ऑफ किंगस्टन; 2 स्मिथ लीड कैस 13 एड। पीपी। 644 , 645 .

63. श्योपरसन सिंह बनाम। रामनंदन प्रसाद नारायण सिंह; [ए. आई. आर. 1916 पी. सी.

78] .

1002 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

'नहीं तो बहुत बड़ा उत्पीड़न किया जा सकता है। रंग और कानून के ढोंग के तहत। -
(6 कोक, 9 ए।)

159. दरियाव 4 में, पी. बी. गजेंद्रगडकर, जे. व्याख्या करते हुए
रेस जुडिकाटा के नियम में कहा गया है कि सामान्य विचारों पर
ऐसा लगता है कि सार्वजनिक नीति का कोई कारण नहीं है कि रेस का शासन क्यों
न्यायपालिका को अस्वीकार्य या अप्रासंगिक माना जाना चाहिए, जबकि
अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं से निपटना
संविधान। पी. बी. गजेंद्रगडकर, जे. जिनका उल्लेख पहले किया गया था
एम. एस. एम. शर्मा 65 में इस न्यायालय का निर्णय जिसमें के तहत दायर एक
याचिका पर न्यायपालिका के नियम का आवेदन
अनुच्छेद 32 पर विचार किया गया और यह देखा गया कि
इस न्यायालय के पिछले निर्णय द्वारा निर्धारित प्रश्न
इसे फिर से नहीं खोला जा सकता है और अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करना चाहिए
पक्षकार जो बाद में समान हैं।

160. गुलाब चंद छोटालाल पारिख में, इस न्यायालय ने कहा कि एक रिट याचिका में एक
निर्णय बाद के मामले में न्यायिक है।

सूट।

161. नानक सिंह 7 में सवाल है कि क्या निर्णय लिया गया है।

एक रिट याचिका में बाद के मुकदमे में रेस जुडिकाटा के रूप में काम करता है
कार्रवाई के एक ही कारण पर दायर किया गया है। नानक में
सिंह 7, इस अदालत ने कहा कि कोई अच्छा कारण नहीं है
रिट में विवादग्रस्त मामलों पर निर्णय लेने से रोकें
संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही
बाद के नियमित मुकदमों में रेस जुडिकाटा के रूप में काम करने से समान पक्षों के बीच
विवाद में समान मामले और,
इस प्रकार, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के बाद निर्णय की अंतिमता के सिद्धांत को सीमित प्रभाव देना।

162. नानक सिंह 67 के बाद तीन न्यायाधीश आए हैं।

64. दरियाव और ओआरएस। वी. यू. पी. और अन्य राज्य।; [ए. आई. आर 1961 एस. सी. 1457]

65. पंडित एम. एस. एम. शर्मा बनाम डॉ. श्री कृष्ण सिन्हा और अन्य।; [ए. आई. आर. 1960 एससी

1186]

66. गुलाब चंद छोटोतल पारिख बनाम। बॉम्बे राज्य; [(1965) 2 एस. सी. आर. 547]

67. भारत संघ बनाम। नानक सिंह; [(1968) 2 एससीआर 887: ए. आई. आर 1968 एस. सी. 1370)

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 1003

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

बुआ दास कौशाफ में इस न्यायालय की पीठ। हमारी राय में, नियम रेज़ जुडिकाटा जो
सार्वजनिक नीति पर आधारित है, नहीं रोकता है

केवल बाद के मुकदमे में एक नया निर्णय लेकिन यह भी रोकता है

नया शोध। यह प्रतिवादी को एक स्थापित करने से रोकता है एक बाद के मुकदमे में
याचिका जो के बीच तय किया गया था

पिछली कार्यवाहियों में पक्षकार। कानूनी स्थिति के साथ

न्यायपालिका के शासन के संबंध में काफी अच्छी तरह से तय किया गया है कि रिट कार्यवाही
(संविधान का अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32) में विवादग्रस्त मामले पर निर्णय न्यायपालिका
के रूप में कार्य करता है।

के बीच विवाद में एक ही मामलों पर बाद के मुकदमे में

वही पार्टियाँ। न्यायपालिका के नियम की प्रयोज्यता के लिए यह

यह आवश्यक नहीं है कि पिछले वाद में निर्णय वाद में निर्णय होना चाहिए ताकि किसी मामले में
न्यायिक निर्णय के रूप में कार्य किया जा सके।

बाद का सूट। पिछली कार्यवाही में एक निर्णय, जैसे कि

संविधान का अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226, जो मुकदमा नहीं है,

बाद के मुकदमे में पक्षों पर बाध्यकारी होगा

रेस जुडिकाटा का सिद्धांत।

163. रेस जुडिकाटा के नियम की प्रयोज्यता के लिए,

इस मुद्दे पर अदालत ने फैसला सुनाया है। पिछली कार्यवाही में तथ्य के मुद्दे पर निर्णय-ऐसी
कार्यवाही मुकदमे की प्रकृति में नहीं हो सकता है-न्यायपालिका का गठन करता है
बाद का सूट।

164. उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में, यदि 2006

निर्णय देखा जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि विचार करने के बाद

पक्षों की दलीलें और उनकी रिपोर्टों की जांच करना

विशेषज्ञ समिति, इस न्यायालय ने इस मुद्दे को निर्धारण के लिए रखा जल स्तर को
142 तक बढ़ाने के लिए बांध की सुरक्षा के बारे में

फीट। और एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचे कि बांध सुरक्षित था

परिच्छेद के अंत में न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा किया और जल स्तर की अनुमति देकर संबंधित मामले

मुल्लापेरियार बांध को 142 फीट तक बढ़ाया जा रहा है। और अनुमति भी दी गई

68. पंजाब राज्य बनाम। बुआ दास कौशल; [(1970) 3 एससीसी 656)।

1004 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार बांध को और मजबूत करना

सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा नियुक्त समिति। पुनर्विचार याचिका दायर की गई

27.7.2006 . 2006 का फैसला अंतिम हो गया है और बाध्यकारी, निश्चित रूप से उक्त कार्यवाही में तय किए गए मुद्दे

संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर मुकदमे में न्यायाधीश के रूप में कार्य करना।

संविधान।

165. श्री हरीश साल्वे, केरल के विद्वान वरिष्ठ वकील,

एन. डी. जयाब 9 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा।

में। एन. डी. जयाल 6 9 धर्माधिकारी, जे. ने सामान्य टिप्पणियां कीं। बांध सुरक्षा पहलू पर जो अदालत की तरह याचिका दायर करता है

उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित पहले के निर्णय नहीं हो सकते हैं

उठाने की अनुमति दी। द्वारा की गई टिप्पणियाँ

धर्माधिकारी, जे. एन. डी. जाये में एक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए

उन मामलों में रेज़ जुडिकाटा नियम का अपवाद जहां, उनके द्वारा बहुत प्रकृति, तथ्यात्मक स्थिति में भारी बदलाव आया है

समय के साथ। यदि परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं

सुरक्षा के मुद्दे पर पहले के निष्कर्ष से प्रस्थान, न्यायालय से संपर्क किया जा सकता है और उस स्थिति में न्यायालय स्वयं सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखते हुए फिर से खोलने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है।

परिस्थितियों में या आकस्मिक स्थिति में भारी परिवर्तन

बांध की सुरक्षा के बारे में। हमारे विचार में, एक न्यायिक निर्णय, अंतिमता प्राप्त करने के बाद, अंतिम शब्द बन जाता है और इसे फिर से खोला जा सकता है परिवर्तित परिस्थितियों में केवल उस न्यायालय द्वारा और किसी के द्वारा नहीं

और भी।

166. केरल की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता

के भाग III द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन

विवादों के संबंध में संविधान को हटा दिया जाता है या बाहर रखा जाता है

दो या अधिक राज्यों के बीच: चूंकि ऐसे विवाद इसके अंतर्गत आते हैं

अनुच्छेद 131 के तहत इस न्यायालय की मूल अधिकारिता की सीमा

के तहत गठित एक न्यायाधिकरण के संविधान या अधिकार क्षेत्र

69. एन. डी. जयाल और अनुर। वी. भारत संघ और ओआरएस।; [(2004) 9 एससीसी 362]।

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 1005

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 262 के प्रावधानों के साथ पढ़ें। इस प्रकार,

यह प्रस्तुत किया गया था कि 2006 का निर्णय बाध्यकारी नहीं है और

इस स्थिति में रेस जुडिकाटा के नियम को शायद ही आकर्षित किया जा सकता है।

167. हम प्रस्तुत करने को स्वीकार करने में असमर्थ हैं

रेज़ जुडिकाटा के सिद्धांत यदि मामला बाद में मुद्दा है इसके पहले के निर्णय से मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका है।

समान पक्षों के बीच न्यायालय। 2006 का फैसला था - न्यायिक जाँच का परिणाम, जो तथ्यों पर आधारित है

सुनवाई के दौरान। इसके अधिकार क्षेत्र की कमी का अनुरोध

न्यायालय को पिछली कार्यवाही में दोनों आधारों पर लिया गया था,

अर्थात्।, (1) क्या इस न्यायालय की अधिकारिता को देखते हुए वर्जित है

अंतर-राज्यीय नदी की धारा 11 के साथ पठित अनुच्छेद 262

जल विवाद अधिनियम, 1956 और (2) क्या संविधान का अनुच्छेद 363

संविधान इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करता है। इन दोनों के बारे में

प्रश्नों के निष्कर्ष केरल के खिलाफ दर्ज किए गए थे। यह भी है

केरल के लिए यह कहना काफी है कि 2006 का फैसला अधिकार क्षेत्र के बिना है, और बाध्यकारी नहीं है।

168. रेस जुडिकाटा का नियम धारा 117 0 में व्यक्त किया गया है।

सिविल प्रक्रिया संहिता।

70. धारा 11 आर. एस. न्यायपालिका

कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या मुद्दे की सुनवाई नहीं करेगा जिसमें मामला प्रत्यक्ष रूप से और

समान पक्षों के बीच पूर्व वाद में, या उन पक्षों के बीच, जिनके तहत वे या उनमें से कोई एक ही शीर्षक के तहत वाद दायर करने का दावा करते हैं, ऐसे बाद के वाद या उस वाद का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से मुद्दा बना हुआ है जिसमें ऐसा मुद्दा दायर किया गया है।

बाद में उठाया गया, और सुनवाई की गई और अंत में ऐसे न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया। स्पष्टीकरण I-"पूर्व वाद" पद एक ऐसे वाद को

दर्शाता है जो वाद से पहले तय किया गया है कि क्या यह उससे पहले स्थापित किया गया था या नहीं।

स्पष्टीकरण आईएल। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अपील के अधिकार के रूप में किसी भी प्रावधान के बावजूद न्यायालय की क्षमता निर्धारित की जाएगी।

ऐसे न्यायालय के निर्णय से।

स्पष्टीकरण III। - पूर्ववर्ती वादमे ऊपर उल्लिखित मामलामे 1006 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. अनिवार्य अछि।

169. उपरोक्त में स्पष्टीकरण VII और VIII जोड़े गए थे।

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रावधान

डब्ल्यू. ई. एफ. 1.2.1977। इस संबंध में स्पष्टीकरण VIII काफी प्रासंगिक है।

इस प्रकार, रेस जुडिकाटा के सिद्धांतों को लागू किया गया है।

जिन मामलों की सुनवाई सीमित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों द्वारा की जाती है। सीमित अधिकारिता वाले न्यायालयों के निर्णय, जहाँ तक कि

निर्णय सीमित न्यायालयों की क्षमता के भीतर होते हैं।

अधिकारिता, एक बाद के मुकदमे में न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है,

हालांकि, सीमित क्षेत्राधिकार का न्यायालय जिसने निर्णय दिया

पिछला वाद ऐसे बाद के वाद या उस वाद का परीक्षण करने के लिए सक्षम नहीं हो सकता है जिसमें ऐसा प्रश्न बाद में उठाया जाता है। यदि ए. सीमित अधिकारिता के न्यायालय का निर्णय, जो इसके भीतर था

इसकी क्षमता, बाद के मुकदमे में रेस जुडिकाटा के रूप में काम करती है

यहां तक कि जब बाद का मुकदमा इसके द्वारा परीक्षण योग्य नहीं है, एक फोर्टियोरी,

एक ऐसे मुद्दे पर दिया गया जिसे सीधे उठाया गया, विचार किया गया और निर्णय को बाद के मुकदमे में न्यायिक प्रक्रिया के रूप में काम करना चाहिए

स्पष्टीकरण IV। - कोई भी मामला जिसे ऐसे पूर्व मुकदमे में बचाव या हमले का आधार बनाया जा सकता था और जिसे बनाया जाना चाहिए था, उसे ऐसे मुकदमे में प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से मुद्दा माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 5-
वाद में दावा की गई कोई भी राहत, जो डिक्री द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए अस्वीकार की गई मानी जाएगी।

स्पष्टीकरण VI. - जहाँ व्यक्ति किसी सार्वजनिक अधिकार या अपने और दूसरों के लिए समान रूप से दावा किए गए निजी अधिकार के संबंध में ईमानदारी से मुकदमा करते हैं, वहाँ ऐसे अधिकार में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस तरह से मुकदमा करने वाले व्यक्तियों के तहत दावा करने वाला माना जाएगा।

स्पष्टीकरण VII। - इस धारा के प्रावधान किसी डिक्री के निष्पादन के लिए किसी कार्यवाही पर लागू होंगे और इस धारा में किसी वाद, निर्गम या पूर्व वाद के संदर्भों का अर्थ क्रमशः डिक्री के निष्पादन के लिए किसी कार्यवाही, ऐसी कार्यवाही में उत्पन्न होने वाले प्रश्न और उस डिक्री के निष्पादन के लिए पूर्व कार्यवाही के संदर्भ के रूप में किया जाएगा।

स्पष्टीकरण गाँव। - सीमित अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सुना गया और अंत में निर्णय लिया गया कोई मुद्दा, जो इस तरह के मुद्दे का फैसला करने के लिए सक्षम है, बाद के मुकदमे में प्रति-न्यायिक के रूप में काम करेगा, इसके बावजूद कि सीमित अधिकारिता वाला ऐसा न्यायालय ऐसे बाद के मुकदमे या उस मुकदमे का मुकदमा करने के लिए सक्षम नहीं था जिसमें ऐसा मुद्दा बाद में उठाया गया है।

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 1007

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारण योग्य। इस संबंध में कोई अन्य दृष्टिकोण असंगत होगा।

उच्च सार्वजनिक नीति और कानून के शासन के साथ। इस न्यायालय का निर्णय सीधे इस मुद्दे पर एक याचिका, एक बार या सबूत के रूप में है,

समान पक्षों के बीच निर्णायक, एक ही मामले पर, सीधे इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न में, हालांकि, अधिकार क्षेत्र का लेबल

अलग होता है।

170. रेस जुडिकाटा के सिद्धांत स्पष्ट रूप से आकर्षित होते हैं

वर्तमान मामला। पिछली कार्यवाही में केरल का दावा कि जल स्तर को उसके वर्तमान स्तर 136 से नहीं बढ़ाया जा सकता है

फीट। स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया था और केरल द्वारा बाधा

मुल्लापेरियार बांध में जल स्तर को बढ़ाकर 142 किया जा रहा है

फीट। सुरक्षा के आधार पर असमर्थनीय पाया गया। इस न्यायालय का दिनांकित 27.2.2006 का निर्णय, इस प्रकार, न्यायिक निर्णय के रूप में कार्य करता है।

बांध की सुरक्षा के मुद्दे को बढ़ाने के संबंध में

जल स्तर 136 फीट से। 142 फीट तक।

171. यह तर्क विद्वान वरिष्ठ श्री हरीश साल्वे ने दिया है।

केरल के लिए वकील, कि विदेशी संप्रभुओं के बीच किए गए समझौतों को भी विधायी शक्तियों के प्रयोग में ओवरराइड किया जा सकता है। उनका तर्क है कि अगर तमिलनाडु का तर्क है कि

1886 पट्टा समझौता एक साधारण पट्टा समझौता था

सही और यह मानते हुए कि इस तरह का समझौता जारी रखा गया था, यह स्पष्ट रूप से केरल राज्य के विधानमंडल के लिए खुला था इस तरह के अनुबंध को ओवरराइड करें। उनके अनुसार, क्राउन द्वारा सनदों, संधियों आदि के माध्यम से अनुबंध भी हो सकते हैं।

भारत सरकार अधिनियम और भारत के संविधान के बाद भी, विधायी शक्ति का प्रयोग करके ओवरराइड किया जाए।

172. इसके समर्थन में केरल के लिए वरिष्ठ वकील से बात की

विवाद ठाकुर जगन्नाथ बक्श 19 और महाराज उमेग सिंह 20 में प्रिवी काउंसिल के फैसले पर निर्भर था। सीखा है।

वरिष्ठ वकील यह भी प्रस्तुत करते हैं कि एस. आर. अधिनियम की धारा 108 यदि एस. आर. अधिनियम की धारा 108 को स्थायी 1008 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. लागू करने के लिए समझा जाता है, तो 1886 के पट्टा समझौते को रद्द करने के लिए केरल पर विधायी शक्ति का प्रयोग करने पर कोई सीमा नहीं बनती है।

राज्य की विधायी शक्ति पर बाधा डालते हुए, ऐसा प्रावधान है -
असंवैधानिक है।

173. यह तुरंत कहा जा सकता है कि संवैधानिकता केरल द्वारा एस. आर. अधिनियम के बारे में लिखित रूप में नहीं उठाया गया है।
बयान। वास्तव में, इसके द्वारा कोई मुद्दा नहीं बनाया गया है इस संबंध में न्यायालय। बल्कि, पहले के मुकदमे में एस. आर. अधिनियम की धारा 108 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी।
2006 के फैसले में, एक प्रश्न के लिए तैयार किया गया था विचार यह था कि क्या एस. आर. अधिनियम की धारा 108 असंवैधानिक है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कानून बनाने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 सर्वोपरि थे और यह था न तो सातवीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 और सूची II (राज्य सूची) और III (समवर्ती सूची) के अधीन और न ही उसके अधीन। अदालत ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि संसद को अनुच्छेदों के तहत कानून बनाने की शक्ति है 3 और 4 पूर्ण है और सभी विधायी विषयों से गुजरता है।
के उचित पुनर्गठन के लिए आवश्यक हैं राज्यों। नतीजतन, अदालत ने चुनौती में कोई योग्यता नहीं पाई एस. आर. अधिनियम की धारा 108 की वैधता के बारे में।

174. इसलिए हम इस पर विचार करने के लिए राजी नहीं हैं एस. आर. अधिनियम की धारा 108 (1) की संवैधानिक वैधता फिर से।
इसके अलावा, इस पहलू पर विचार करना आवश्यक नहीं है

हमारा निष्कर्ष है कि केरल द्वारा अधिनियमित 2006 (संशोधन) अधिनियम विधायिका असंवैधानिक है।

175. ठाकुर जगन्नाथ बक्श 1 9 और महाराज उमेग सिंह 2 0 में प्राप्त होने वाली स्थिति के लिए कोई आवेदन नहीं है वर्तमान मामला। एक निर्णय का प्रभाव जो एक कानूनी को लागू करता है एक अनुबंध से प्रवाहित होने का अधिकार यह है कि अधिकार को इस रूप में शामिल किया गया है निर्णय के तहत एक अधिकार और ऐसा अधिकार नहीं हो सकता है विधायिका द्वारा ओवरराइड किया गया क्योंकि यह एक ओवरराइड करने के समान है निर्णय।

176. केरल के विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी उड़ीसा राज्य में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया। उड़ीसा राज्य में 7 1,

71. उड़ीसा राज्य बनाम ए. पी. राज्य ; [(2006) 9 एससीसी 591]।

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 1009

[आर. एम. लोधा, सीजेआई] .

अनुच्छेद 131 पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा, "अनुच्छेद 131

हालाँकि, अनन्य अधिकार क्षेत्र दो सीमाओं के अधीन है। अनुच्छेद के प्रारंभिक शब्दों में निहित एक, अर्थात्,

" इस संविधान और अन्य के प्रावधानों के अधीन।

जो अनुच्छेद के परंतुक में निहित है।

177. इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी समस्या को हल करने का अधिकार क्षेत्र दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद

संविधान के अनुच्छेद 131 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय। हालांकि, यह तार्किक रूप से इसका पालन नहीं करता है कि द्वारा दिया गया निर्णय अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय दो राज्यों के बीच अन्य के बीच निर्णायक नहीं है और ऐसे राज्यों पर बाध्यकारी। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, 2006

इस न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दिया गया निर्णय

अनुच्छेद 32 केरल और तमिलनाडु को बांधता है। हमारे पास कोई नहीं है। संकोच और हम पूरे जोर के साथ कहते हैं कि एक खोज दर्ज की गई है

इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए दोनों पक्षों के बीच बाध्यकारी, बाद के मुकदमे में

अनुच्छेद 131 के तहत दोनों राज्य।

मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा एस साक्ष्य और ईसी रिपोर्ट

178. हमला करते हुए केरल के लिए वरिष्ठ वकील का अध्ययन किया

2006 में दर्ज मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा पर तथ्य का पता लगाना

निर्णय, और उसके तर्क के समर्थन में कि यह नहीं है

जैसे-जैसे परिस्थितियाँ बदल गई हैं, उन्होंने न्यायपालिका का गठन किया है

3) संभावित अधिकतम बाढ़ (पीएमएफ) के प्रभाव पर, साक्ष्य भूकंपीय बलों के प्रभाव पर डॉ. डी. के. पॉल और कुछ

तमिलनाडु के गवाह पीडब्लू-1 का प्रवेश। श्री हरीश साल्वे

तर्क है कि अंतिमता का सिद्धांत इस न्यायालय को बाधित नहीं करता है

गलतियों को सुधारने के लिए।

इस संबंध में वरिष्ठ वकील 1010 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

ए. आर. में इस न्यायालय के तीन फैसलों पर भरोसा करता है।

अंतुले 72, इसाबेला जॉनसन और रूपा अशोक हुरा 74।

179. देश की सर्वोच्च अदालत होने के नाते, यह अदालत

उपचारात्मक याचिका में निर्णय को सही करने की शक्तियाँ होती हैं

यदि रूपा अशोक हुरा 74 में निर्धारित मापदंड हैं

संतुष्ट। वर्तमान मामला मानदंडों के अंतर्गत नहीं आता है। रूपा अशोक हुरा 74 में
स्थापित। हालांकि ऐसा नहीं है

बांध सुरक्षा पहलू को फिर से खोलने का औचित्य

इस न्यायालय का निर्णय 27.2.2006 पर पारित हुआ, फिर भी हमारे लिए

इस बात से संतुष्ट कि क्या कोई खतरा है

मुल्लापेरियार बांध, तमिलनाडु द्वारा सुदृढ़ीकरण उपायों के अनुसार बांध को मजबूत करने के
बावजूद सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा सुझाए गए, हम संक्षेप में इस पहलू पर गौर करने का
इरादा रखते हैं।

180. केरल के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि

(i) संभावित अधिकतम बाढ़ (पी. एम. एफ.) अर्थात् बाढ़ का प्रभाव। जो बांध को
प्रभावित करता है; (ii) अधिकतम माना जाने वाला प्रभाव

भूकंप (एमसीई), अर्थात्, यदि भूकंप आता है, तो इसका प्रभाव

बांध पर ऐसी घटना; और (iii) संरचनात्मक अपघटन पर प्रभाव, यानी उम्र के साथ, बांध
संरचना को किया गया है

असुरक्षित बना दिया। केरल का जोर इस बात पर है कि 2006 के फैसले में इस अदालत ने
गलत तरीके से 2.12 लाख के पीएमएफ का समर्थन किया था

1986 में सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा अनुमानित क्यूसेक। केरल का कहना है कि

1943 में मुल्लापेरियार बांध में 2.98 लाख की बाढ़ देखी गई थी।

क्यूसेक और तमिलनाडु के अपने गवाह (पीडब्लू-1) के अनुसार,

पीएमएफ को देखी गई बाढ़ से अधिक होना चाहिए। इसलिए, अनुमान

1986 में सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा 2 लाख 12 हजार क्यूसेक के रूप में पी. एम. एफ.

कम आंकलन।

181. एमसीई के प्रभाव के संबंध में, केरल ने बहुत अधिक भरोसा किया है

डॉ. डी. के. पॉल और डॉ. एम. एल. द्वारा किए गए अध्ययन पर। शर्मा, आई.
आई. टी. रुड़की के प्रोफेसर। केरल का कहना है कि ये दोनों

72. आर. एस. नायक बनाम ए. आर. अंतुले; [(1984) 2 एस. सी. सी. 183]।

73. इसाबेला जॉनसन (श्रीमती) बनाम। एल. आर. एस. द्वारा एम. ए. सुसाई (मृत)। ;
[(1991) 1 एस. सी. सी. 494]

74. रूपा अशोक हुर्ग बनाम। अशोक हुर्ग और अनुर। ; [(2002) 4 एस. सी. सी. 388]

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 1011

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

विशेषज्ञों ने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला है कि "... दोनों

मुख्य मुल्लापेरियार बांध और बेबी बांध के गुजरने की संभावना है क्षति जो स्थैतिक
और भूकंप के तहत विफलता का कारण बन सकती है

स्थिति और इसलिए गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है। "

182. केरल का कहना है कि 1930 और 1960 के बीच बांध को भारी चूने का नुकसान हुआ
था, जिससे तमिलनाडु को निश्चित रूप से भू-क्षरण करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

542 इस अवधि में एम. टी. सीमेंट।

183. संरचनात्मक क्षरण के प्रभाव के पहलू पर केरल का कहना है कि मुल्लापेरियार बांध एक
मिश्रित बांध है।

चूने के सुरखी मोटार और चूने के सुरखी से निर्मित गुरुत्वाकर्षण बांध

कंक्रीट; बांध का वह आंतरिक केंद्र, जो 62 प्रतिशत का गठन करता है

कुल मात्रा, निश्चित रूप से चूने सुरखी कंक्रीट से बनी होती है;

और यह कि मुल्लापेरियार बांध को चूने के भारी रिसाव का सामना करना पड़ा है और प्रति वर्ष 30.48 मीटरक टन का नुकसान हुआ है

तमिलनाडु की विशेषज्ञ समिति, जिसे द्वारा स्वीकार किया गया है

1895 में माना गया कि 1986 में 135 पाउंड/सी. एफ. टी. और इस तरह की क्रमिक कमी मुल्लापेरियार के संरचनात्मक क्षरण की गवाही देती है। दाम।

184. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जब मामला शुरू में लिया गया था

संविधान पीठ द्वारा यह महसूस किया गया कि इसके सभी पहलू

मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा सहित मामले की आवश्यकता है एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा जांच की जाती है, जो मामले को प्रभावी ढंग से तय करने में न्यायालय की मदद कर सकती है। तदनुसार,

18.2.2010 संविधान पीठ ने केंद्र सरकार को डॉ. की अध्यक्षता में एक निर्वाचन आयोग का गठन करने का निर्देश दिया।

ए. एस. आनंद, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और

केरल और तमिलनाडु राज्यों द्वारा नामित दो सदस्य और दो प्रसिद्ध तकनीकी विशेषज्ञ। केरल नामांकित

न्यायमूर्ति के. टी. थॉमस, इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और तमिल

नाडु द्वारा नामित न्यायमूर्ति (डॉ.) इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए. आर. लक्ष्मणन ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया। दो प्रसिद्ध तकनीकी विशेषज्ञ,

डॉ. सी. डी. थट्टे और श्री डी. के. मेहता को 1012 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. में नामित किया गया था।

संदर्भ, ई. सी. आगे सबूत प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र था क्योंकि यह उचित माना जाता है। दो विशेषज्ञ, डॉ. सी. डी. थेटे और

श्री डी. के. मेहता को जल के सभी पहलुओं में लंबा अनुभव है।

अन्य संगठनों के अलावा तीन शीर्ष संगठनों के माध्यम से किया गया भारत सरकार के विशेष संगठन और,

विशेष रूप से, दोनों राज्यों के विविध रुख की सराहना करने की दृष्टि से विशेषज्ञ एजेंसियां। कुल मिलाकर 12 जांच और

कुछ स्थल अध्ययनों के अलावा तकनीकी अध्ययनों को निर्देशित किया गया था

के रुख की सराहना करने के लिए ईसी की सहायता के लिए किया जाना चाहिए

दो राज्य और इस न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए। द.

निर्वाचन आयोग ने मुल्लापेरियार बांध (मुख्य बांध), बेबी बांध और

पेरियार झील के किनारे के साथ-साथ मिट्टी का बांध नीचे की ओर। निर्वाचन आयोग के समक्ष दोनों राज्यों के प्रतिनिधि

मौजूदा बांध के सिद्धांतों की व्याख्या की। दोनों तकनीकी सदस्यों ने जल निकासी दीर्घाओं और जल निकासी मार्ग का दौरा किया। बांध स्थल का बेहतर मूल्यांकन। दोनों विशेषज्ञों ने फिर दौरा किया

स्थल मूल्यांकन के लिए बांध स्थल और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

185. रिपोर्ट और जांच, परीक्षण और अध्ययन (आई. टी. एस.)

रिपोर्ट) 50 सीडी और 4 डीवीडी में निहित हैं। की रिपोर्ट

ई. सी. में 8 अध्याय हैं। पहले अध्याय का शीर्षक है "बांध-एक"

सर्वोच्च न्यायालय में मुल्लापेरियार बांध विवाद। अध्याय III ई. सी. द्वारा हल किए गए मुद्दों को संदर्भित करता है। अध्याय IV में शामिल हैं -

(i) मुल्लापेरियार बांध स्थल/क्षेत्रों में निर्वाचन आयोग के दौरे की रिपोर्ट।

19-22.12.2010 के दौरान; (ii) दिनांकित निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव 21.12.2010 , 7.1.2011 और 5.12.2011; और (iii) यात्रा की रिपोर्ट

दो तकनीकी सदस्यों (डॉ. सी. डी. थट्टे और श्री डी. के. मेहता) 22-26.12.2011 के दौरान। पाँचवाँ अध्याय प्रतिक्रियाओं को दर्ज करता है

निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किए गए मुद्दों के पक्षकारों के बारे में संक्षेप में। अध्याय VI

तकनीकी रिपोर्टों का मूल्यांकन और विश्लेषण है

जाँच, परीक्षण और अध्ययन। अध्याय VII अभिलेख निष्कर्ष निकालते हैं। अध्याय VIII सामान्य अवलोकन से संबंधित है -

शीर्षक, "आगे का रास्ता-एक सौहार्दपूर्ण समाधान की ओर"।

टू स्टेट ऑफ तमिल नाडु v. केरल राज्य 1013

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

एक टिप्पणी निर्वाचन आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति के. टी. थॉमस की ओर से, और

न्याय से दूसरा (डॉ।) निर्वाचन आयोग के सदस्य ए. आर. लक्ष्मणन को भी निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के अध्याय VIII पर जोड़ा गया है।

रिपोर्ट में।

186. अध्याय III में, निर्वाचन आयोग ने मुद्दों को दर्ज किया है

विचार करें। मुद्दों में से एक, अर्थात्।, अंक संख्या 4 के लिए

विचार में लिखा है, "क्या जलाशय का स्तर ऊपर उठाया जाना चाहिए?

136 फीट।? यदि हां, तो इसे मजबूत करने के लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं?

मौजूदा बांध, क्या दोनों पक्षों ने जलाशय के स्तर को 136 फीट से बढ़ाने की अनुमति देने की परिकल्पना की है। 142 फीट तक। और उससे आगे?"

187. पाँचवें अध्याय में, निर्वाचन आयोग ने तमिल लोगों की प्रतिक्रियाओं को नोट किया है

इसके द्वारा बनाए गए मुद्दों पर तमिलनाडु और केरल।

188. अध्याय VI, जिसमें आई. टी. एस. का मूल्यांकन और विश्लेषण

रिपोर्ट बनाई गई है, जिससे पता चलता है कि निम्नलिखित परीक्षण और अध्ययन

चिंताओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार किए गए थे और

दोनों राज्यों की शिकायतें:

" ए. हाइड्रोलॉजिक ओजीआई सुरक्षा

आई. टी. एस. का उद्देश्य

शीर्षक

1. निर्धारित करने के लिए सत्यापन:

संभावित अधिकतम बाढ़

संभावित।

अधिकतम

(पी. एम. एफ.) संगणनाएँ (i)

बाढ़ (पीएमएफ)

पुनरीक्षण के लिए बाढ़ मार्ग

स्पिलवे क्षमता।

(ii) बहिर्वाह पी. एम. एफ.

हाइड्रोग्राफ

और इसका संयम

मुल्ला पेरियार बांध

तक

इडुक्की जलाशय की

नोक।

(iii) बहिर्वाह पी. एम. एफ.

हाइड्रोग्राफ

इडुक्की जलाशय।

((iv) अधिकतम जल स्तर

(एम. डब्ल्यू. एल.)

विभिन्न के लिए

संचालन के परिदृश्य/1014 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

निष्क्रियता को रोकने

के लिए

विभिन्न एफ. आर. एल. के लिए द्वार।

(v) मुक्त बोर्ड

बांध टूटने का आकलन

करने के लिए

2. एकीकृत बांध टूटना।

बाढ़ जो हो सकती है

मुल्ला से बाढ़ का अध्ययन

अलग-अलग कारणों से

पेरियार बांध से इडुक्की तक

विफलता/कैस्केड के तरीके

बांध और उससे आगे

प्रभाव के मामले में

एक की तैयारी को सक्षम करें

एमपीडी की घटना

आपातकालीन कार्य योजना।

तोड़ते हैं। पहचान करने के

लिए

नमूना तैयार करना

सबसे खराब स्थिति

संभावित बाढ़ मानचित्र

पेरियार नदी से नीचे

एम. पी. डी. से इडुक्की जलाशय

टिप (पहले चरण में) और

परे (अन्य 2 में)

चरण)। तय करने के लिए

अधिकतम बाढ़

बैंकों

के लिए

दोनों

में से

तैयारी

आपातकालीन कार्य

योजना

आपदा

के तहत

प्रबंधन योजना।

एफ्लक्स का निर्धारण

करने के लिए

3. पश्च-जल अध्ययन

(सूजन) ऊपर

मुल्ला के सिरे के ऊपर की ओर

ऊपर की ओर एम.

डब्ल्यू. एल.

पेरियार जलाशय में

जलाशय के सिरे से

मुख्य तना और सहायक नदियाँ।

प्रवाह के कारण

4. जलाशय का समोच्च मानचित्र

भीड़भाड़।

वर्तमान जल से क्षेत्र

स्तर 165 फीट (50.29 m)

उन्नयन।

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 1015

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

5. कम्प्यूटरीकृत जलाशय

हानि का निर्धारण करने

के लिए

के लिए तलछट सर्वेक्षण

भंडारण के कारण

वर्तमान का मूल्यांकन

अवसादन और इसका

ऊँचाई-क्षेत्र-क्षमता

प्रभाव (यदि कोई हो)

संबंध। मूल्यांकन में

संभावित अधिकतम

द्वारा ऊँची ऊँचाई

बाढ़ क्षीणन।

रिमोट सेंसिंग।

ध्यान दें: आई. टी. एस. की साइड आइटम i) स्पिलवे से बने बांधों से संबंधित हैं।
पीएमएफ से कम बाढ़ की योजना बनाना, ii) तमिल के लिए पानी की उपलब्धता

नाइ, और iii) पर्यावरणीय प्रवाह की आवश्यकता।

B. शारीरिक सुरक्षा

6. ऊपर की ओर का मानचित्रण

ऊपर की ओर स्कैन

करने के लिए

पानी के ऊपर बांध का चेहरा

के लिए बांध का चेहरा

के माध्यम से स्तर

असंतुलन, दरारें,

फोटोग्राफी

खोखले, रिक्त स्थान

और जोड़

जल स्तर से ऊपर आदि

आधारित

गिरड

द्वारा

फोटोग्राफी।

7. पानी के नीचे स्कैनिंग

करने के लिए

बांध का ऊपरी चेहरा

दूरस्थ रूप से

संचालित वाहन

और जोड़

उसकी स्थिति का आकलन करें।

संचालित वाहन।

8. रिसाव का अध्ययन और (i) मापा गया संकलन

इसकी मुफ्त चूने की सामग्री।

करना।

ऊपर की ओर स्कैन

के लिए बांध का चेहरा

असंतुलन, दरारें,

खोखले, रिक्त स्थान

दूरस्थ साधन

रिसाव के मूल्य

डैम बॉडी से और

फाउंडेशन।

((ii) अनुपात निर्धारित

सीपेज 1016 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

[2014]

12 एस सी आर।

प्रवाह जाल द्वारा नींव

अध्ययन करते हैं।

(iii) लीचड का निर्धारण

करना।

मुफ्त चूने की सामग्री

रिसाव।

9. इन-सीटू/का निर्धारण

कोर ड्रिलिंग करने के

लिए

बांध निकाय/नींव में

एक्स-सीटू ताकत और

निम्नलिखित को सक्षम

करने के लिए

बांध निकाय की अखंडता

सामग्री और नींव

भौतिक और

रासायनिक,

इन-सीटू और एक्स-

सीटू (इन)

सुरक्षा में उपयोग करने के लिए /

प्रयोगशालाएँ)

परीक्षण।

स्थिरता

स्थिति

मूल्यांकन।

इन-सीटू परीक्षणः

(i) ध्वनि परीक्षण

((ii) गामा-गामा /

न्यूट्रॉन-न्यूट्रॉन

(iii) डाई ट्रेसर

((iv) विद्युत प्रतिरोधकता और

जियोफिजिकल

टोमोग्राफिक अध्ययन

पूर्व-स्थिति परीक्षणः

(i) संपीड़न शक्ति

((ii) तन्य शक्ति

(iii) मॉडचूलस ऑफ

इलास्टिसिटी

(स्थैतिक और साथ ही

गतिशील)

((iv) पॉइसन का अनुपात

(v) घनत्व

(vi) फ्री लाइम

(vii) का रासायनिक विश्लेषण

तमिल नाडु का राज्य v. केरल राज्य 1017

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

10. हानि का मापन

के लिए

नमूने में पहले से तनाव

दबाव वाली केबल

हैं

रूप में

सुदृढ़ीकरण के उपाय।

ध्यान दें: आई. टी. एस. की साइड आइटम i) तापीय गुणों से संबंधित हैं।
कंक्रीट और इंटरफेस पर प्रभाव, ii) इंस्ट्रुमेंटेशन,

और iii) मुख्य और छोटे बांध की स्थिरता।

सी. एस. ई. एस. एम. सी. सुरक्षा

11. परिमित तत्व विधि

करने के लिए

(एफ. ई. एम.)

विश्लेषण

नियोजित करना (प्रतिक्रिया)

स्पेक्ट्रा)/(समय इतिहास)

हानि का निर्धारण करने

पूर्व-तनाव और इसलिए

में अवशिष्ट पूर्व-तनाव

केबल एंकर लगाए गए

1981 में, के हिस्से के

बैकिंग

तन्यता निर्धारित

तनाव के कारण

भूकंप की ताकतें

इन पर आधारित:

बांध की स्थिरता का आकलन करना

डिजाइन आधार पर/(i) 2 डी 2 डी एफ. ई. एम. अध्ययन

प्रतिक्रिया के

आधार पर

अधिकतम

विश्वसनीय

स्पेक्ट्रा विधि (दो

में)

भूकंप बल।

भाग) द्वारा प्रस्तुत

किया गया

सोक।

((ii) 3 डी एफ. ई. एम.

अध्ययन (दो)

समय) द्वारा प्रस्तुत

एसओटीएन।

((iii) 2 डी एफ. ई. एम.

अध्ययन (दो में)

भाग) समय पर

आधारित

इतिहास का विश्लेषण।

12. सबूत की पहचान करें

एक पार करने के

लिए और

यदि कोई हो,

में भूगर्भीय दोष

आसपास के क्षेत्र

बेबी डैम।

सबूत की पहचान करें

संदिग्धों में से

में भूगर्भीय दोष

बेबी डैम फाउंडेशन।

1018 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

ध्यान दें: आई. टी. एस. के साइड आइटम 1) 3 डी एफ. ई. एम. विश्लेषण के अध्ययन से संबंधित हैं।

प्रो. भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर के आर. एन. अयंगर,

ii) मुल्ला पेरियार बांध के भूकंपीय डिजाइन मापदंड, और iii)

हाल के भूकंप की घटनाओं का प्रभाव "।

189. उपरोक्त रिपोर्टों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया है।

और आई. टी. एस. रिपोर्टों के मूल्यांकन के आधार पर, ई. सी. ने माना

कि संभावित अधिकतम वर्षा (पी. एम. पी.) पर पहले विचार किया गया था

सही था और देखी गई अधिकतम बाढ़ का निर्धारण

1943 में यह विश्वसनीय नहीं था। ई. सी. का आकलन पी. एम. एफ. का शिखर है।

मुल्लापेरियार बांध जलाशय/परिधीय/ऊपर की ओर पहुंचना

टिप 2.12 लाख क्यूसेक (6003 क्यूमेक) पर बना हुआ है।

190. ई. सी. का मानना है कि स्पिलवे को डिजाइन किया गया है।

स्वीकार्य है। ई. सी. ने दोनों अध्ययनों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया।, ((i) फोटोग्राफी द्वारा जल स्तर से ऊपर अध्ययन करें, और (ii) नीचे अध्ययन करें।

दूरस्थ संचालित वाहन के माध्यम से जल स्तर, एक तक

सुरक्षित रूप से पहुँच योग्य स्तर, और दोनों स्कैन/मूल्यांकन पर एक साथ पढ़े गए अध्ययनों ने चिंता का कारण नहीं समझा

बांध के लिए किसी भी संकट की अभिव्यक्ति के बारे में।

191. निर्वाचन आयोग ने भी चिंताओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया है

(क) रिसाव मापन के संबंध में केरल द्वारा व्यक्त किया गया

और मुक्त चूने के नुकसान का आकलन; (बी) बांध की ताकत का नुकसान

चूने के नुकसान के कारण शरीर के घटक; और (सी) के कारण भेद्यता

मुक्त चूने का नुकसान। ई. सी. मूल्यांकन के अनुसार, कुल चूना

बांध के अस्तित्व के 116 वर्षों में रिसाव लगभग 3.66% था,

जो 15-20% की ऊपरी अनुमेय सीमा से कम है। ई. सी.

अभिनिर्धारित किया कि चूने के नुकसान का आकलन अनुमेय सीमा के भीतर था

हद तक, मुल्लापेरियार बांध की ताकत के नुकसान के बारे में चिंता का कोई कारण नहीं है।

192. बांध निकाय सामग्री के भौतिक गुण भी हैं

यथास्थिति में आवेदन करके समीक्षा और मूल्यांकन किया गया विनाशकारी परीक्षण, अर्थात्।, (ए) बांध के ऊपर की ओर से ध्वनि परीक्षण;

(बी) न्यूट्रॉन-लॉगिंग और ट्रेसर अध्ययन; (सी) भूभौतिकीय टोमोग्राफिक अध्ययन; और (डी) तमिलनाडु राज्य के बोर की आंतरिक सतह की स्कैनिंग।

केरल राज्य 1019

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग प्रणाली का उपयोग करके छेद दीवारें। इसी भी तमिलनाडु से मुख्य नमूने प्राप्त करने और उनका परीक्षण करने का अनुरोध किया गया

डैम बॉडी/फाउंडेशन रॉक, इन सीटू परीक्षणों के अलावा

मुल्लापेरियार बांध पर 150 मिमी और उससे अधिक आकार के 9 गड्ढों में,

जो तमिलनाडु ने किया था। ये परीक्षण रिपोर्टें थीं

इस पर भी विचार किया गया। निर्मित सामग्री पर रासायनिक परीक्षण बांध निकाय और जलाशय के पानी में भी उपयोग किया गया था।

परीक्षण के परिणाम इन सभी सामग्रियों की हानिरहित प्रकृति का संकेत देते हैं।

193. मुल्लापेरियार बांध के रिसाव के सभी समय के आंकड़े हैं

इसी द्वारा मूल्यांकन और विश्लेषण किया गया, जो इंगित करता है कि यह इसके भीतर है

अनुमेय सीमाएँ। एक अनग्लूटेड केबल एंकर का परीक्षण

बचे हुए पूर्व-तनाव को पूरा कर लिया गया। विश्लेषण भी किया गया है। बैकिंग कंक्रीट के तापीय गुणों और उन पर प्रभाव

इंटरफेस। आई. टी. एस. रिपोर्टों का विस्तृत मूल्यांकन और विश्लेषण

मुल्लापेरियार बांध पर भूकंपीय डिजाइन मानकों से पता चलता है कि

हाल के भूकंप की घटनाएं क्षणिक और अप्रासंगिक हैं।

194. केरल द्वारा उजागर की गई आशंकाओं में से एक यह है कि

बांध टूटने पर बाढ़ से बड़े पैमाने पर तबाही होगी। यह

ई. सी. द्वारा "बांध" शीर्षक के तहत पहलू पर विचार किया गया है।

बाढ़ और संभावित कैस्केडिंग प्रभाव को तोड़ें "। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने पाया है कि केरल ने उसे बाढ़ मानचित्रों की आपूर्ति नहीं की है

यहां तक कि 50,100 साल जैसी वापसी अवधि के साथ सामान्य बाढ़ के लिए भी

बांधों के लिए आपातकालीन कार्य योजना का कार्यान्वयन, मई, 2006 '। इसी, तदनुसार, उपयोग करके विकसित मानचित्रों पर निर्भर करता है आर्काइव्ड सैटेलाइट इमेजरी एंड सर्वे ऑफ इंडिया टॉपशीट,

'मैपसेट' के माध्यम से, और कुशल सचित्र प्रतिरूपण

मुल्लापेरियार बांध और इडुक्की परिसर के बीच का क्षेत्र। ई. सी. ने यह पाया गया कि केरल के सभी अनुमान/चिंताएं गणना/अध्ययन पर आधारित नहीं थीं। अनुरोध के बावजूद केरल को समोच्च मानचित्र की आपूर्ति करने के लिए, केरल ने ऐसा नहीं किया।

ईसी के पास

[2014] 12 एस. सी. आर. हैं।

1020 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आगे यह देखा गया कि केरल का प्रक्षेपण अनुमानात्मक है क्योंकि संभावित जलमग्न क्षेत्र के आकलन में कमी है। ई. सी., इसलिए, बांध टूटने की बाढ़ के डर को स्वीकार नहीं किया।

195. विस्तृत और विस्तृत मूल्यांकन करने और

विशाल परीक्षणों और विशेषज्ञों की रिपोर्टों का विश्लेषण और

केरल द्वारा व्यक्त चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा, ईसी ने इसका सारांश दिया है

तीन पहलुओं पर निष्कर्ष, अर्थात्।, (क) जल सुरक्षा; (ख)

संरचनात्मक सुरक्षा; और (ग) भूकंपीय सुरक्षा निम्नानुसार है:

" ए) जल सुरक्षा

23. एम. पी.

डी. जलविज्ञान की दृष्टि से सुरक्षित पाया गया है। संभावित

2. 12 लाख के अधिकतम प्रवाह के साथ अधिकतम बाढ़ (पीएमएफ)

क्यूसेक (6003 क्यूमेक) ईसी द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसे रूट किया जा सकता है।

जलाशय के ऊपर से सुरक्षित रूप से गुजरने के लिए एफआरएल 142 फीट (43.28 मीटर)

13 फाटकों के संचालन के साथ एमपीडी स्पिलवे, जिसके परिणामस्वरूप एक 1,43,143 क्यूसेक (4053 क्यूमेक) का अधिकतम प्रवाह, बढ़ रहा है अधिकतम जल स्तर (एम. डब्ल्यू. एल.) से ऊँचाई 153.47 फुट तक

(46.78 एम) क्षणिक रूप से। यहां तक कि एक गेट के निष्क्रिय रहने के परीक्षण मामले के लिए भी, एम. डब्ल्यू. एल. ऊँचाई 154.10 तक बढ़ जाता है। फीट (46.97 मीटर) जब पीएमएफ एफआरएल 142 पर जलाशय को बाधित करता है

ft (42.28 m)।

ख) संरचनात्मक सुरक्षा

लेकिन इसे एक समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए: (i) ऊपर की सतह का उपचार, ii) जल निकासी का पुनर्निर्माण

छेद, iii) उपकरण, iv) आवधिक निगरानी, विश्लेषण और पैर के अंगूठे से रिसाव को दूर करना।

नदी के नीचे की ओर बांध, v) जियोडेटिक री-कन्फर्मेशन, आदि, vi) बांध के शरीर को ठीक से ग्राउट किया जाना चाहिए। महीन सीमेंट/उपयुक्त रसायन/तमिलनाडु राज्य का अभिकल्पित ग्राउट मिश्रण।

केरल राज्य 1021

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार एपॉक्सी/पॉलिमर ताकि इसकी

सुरक्षा बनी हुई है।

(c)

भूकम्पीय सुरक्षा

25. एमपीडी भूकम्पीय रूप से एफआरएल 152 फीट (46.33 मीटर)/एमडब्ल्यूएल 155 फीट (47.24 मीटर) के लिए भूकम्पीय रूप से सुरक्षित पाया गया है।

त्वरण समय इतिहास के साथ डिज़ाइन मापदंड

इसके तहत मूल्यांकन किए गए संभावित तनावों/प्रभावों के खिलाफ विश्लेषण करें। इसके अलावा, केबल एंकरों की आरक्षित संख्या

बांध को और सुरक्षित बनाता है। बेबी डैम फाउंडेशन में भूवैज्ञानिक दोष होने का संदेह है
बाहर निकलें। बांध क्षेत्र में हाल ही में भूकंप की गतिविधि है

भूकंपीय सुरक्षा के लिए कोई परिणाम नहीं माना जाता है। साथ ही, इससे एम. पी. डी./इडुक्की बांधों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ”

196. केरल ने चुनाव आयोग की रिपोर्ट को जोरदार तरीके से चुनौती दी है और

उनके निष्कर्ष। केरल के वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे का तर्क है कि आई. टी. एस. रिपोर्ट 50 सी. डी. और 4 में निहित है।

डी. वी. डी. स्वीकार्य नहीं हैं और इन्हें इसका हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।

इस न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर सामग्री। वह प्रस्तुत करता है कि ई. सी. सुओ

मोटु ने जांच, परीक्षण और अध्ययन करने का निर्णय लिया

शीर्ष अदालत के माध्यम से मामले से संबंधित विभिन्न पहलू

राज्यों के प्रतिनिधियों को समन्वय समिति का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन उनकी भूमिका एक सदस्य होने तक सीमित थी। अध्ययन आदि के संबंध में पर्यवेक्षक और एकतरफा निर्णय।

डॉ. सी. डी. थट्टे द्वारा लिया गया था, जो प्रतिकूल थे

5.12.2011 परिणामों की प्रतियों का खुलासा करने और आपूर्ति करने से इनकार कर दिया और आई. टी. एस. पूर्वाग्रह के सवाल से निपटने के बिना रिपोर्ट करता है। इसके बाद, निर्वाचन आयोग ने इस न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और

अदालत ने रजिस्ट्री को 4.5.2012 पर इसकी प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

निर्वाचन आयोग की पक्ष राज्यों को रिपोर्ट और तदनुसार, रजिस्ट्री 1022 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

इस न्यायालय ने रिपोर्ट की एक फोटोकॉपी उपलब्ध कराई। द.

रजिस्ट्री द्वारा केरल को दी गई रिपोर्ट में शामिल नहीं था

रिपोर्ट के अनुलग्नक 6.1 में सूचीबद्ध आई. टी. एस. के परिणाम और रिपोर्ट

लेकिन बाद में इस न्यायालय के दिनांक 31.8.2012 के आदेश के अनुसार, केरल के वकील को सभी 50 सीडी और 4 डीवीडी की आपूर्ति की गई थी।

केरल की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि निष्पक्ष प्रक्रिया और

प्राकृतिक न्याय के नियमों ने मांग की कि इसी को होना चाहिए

आई. टी. एस. की स्वीकार्यता पर केरल को अवसर दिया गया रिपोर्ट करते हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा इसका पुरजोर आग्रह किया जाता है

केरल ने कहा कि आई. टी. एस. रिपोर्ट विशेषज्ञों की राय है और,

इसलिए, निर्वाचन आयोग ऐसे परिणामों पर भरोसा नहीं कर सकता था और

प्रतिकूल का सामना करने का अवसर दिए बिना रिपोर्ट करें

विषय-वस्तु और केरल को लेखकों की जांच करने और विशेषज्ञों के साक्ष्य का नेतृत्व करने का अधिकार है, यदि कोई हो तो

आई. टी. एस. के प्रतिकूल परिणाम और रिपोर्ट। इस संबंध में, केरल 21.11.2011 पर इसी के समक्ष किए गए आवेदन को संदर्भित किया गया।

केरल ने भी क्वींस बेंच के फैसले पर भरोसा किया रेजिना 75।

197. हम श्री की दलीलों से सहमत नहीं हैं।

हरीश साल्वे। यह सच है कि इस आदेश के अनुसार केरल को आई. टी. एस. रिपोर्ट वाली 50 सी. डी. और 4 डी. वी. डी. की आपूर्ति की गई थी। द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद न्यायालय दिनांक 31.8.2012

ई. सी. लेकिन तथ्य यह है कि ई. सी. ने फैसला किया

विभिन्न पहलुओं पर जांच, परीक्षण और अध्ययन करना।

इस न्यायालय द्वारा दिए गए कार्य के अनुसार शीर्ष संगठनों के माध्यम से मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा से संबंधित। द.

ई. सी. ने अपनी दिनांकित 17.2.2011 की कार्यवाही में एक समन्वय का गठन किया
 समिति जिसमें दोनों के प्रतिनिधि शामिल थे
 राज्यों। यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि समन्वय समिति में राज्यों के प्रतिनिधियों की
 भूमिका
 यह एक पर्यवेक्षक होने तक सीमित था। आई. टी. एस. की रिपोर्ट में कहा गया है
 संगठनों और निकायों द्वारा दिया गया है जो विशेषज्ञ हैं नौकरी में। हमें यह मानने में
 कोई संकोच नहीं है कि

75. रेजिना वी। उप औद्योगिक चोट आयुक्त, पूर्व पक्ष जोन्स; [(1962)
 2 क्यूबी 677]।

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 1023

[आर. एम. I.ODHA, सीजेआई।]

जाँच, परीक्षण और तकनीकी अध्ययन के लिए निर्देशित किया गया था
 के प्रतिनिधियों के सहयोग से इसी द्वारा किया गया
 दोनों राज्य।

198. इसके अलावा, इस अदालत ने खुद को आश्वस्त करने के लिए चुनाव आयोग
 को नियुक्त किया

मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा के बारे में। ई. सी., हमें कहना चाहिए, प्रत्येक में
 अच्छी तरह से जाकर अपने कार्य को सराहनीय रूप से पूरा किया है।

और मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा का हर पहलू। हम नहीं करते। केरल की आपत्तियों
 को चुनौती देने में कोई योग्यता खोजें

जल सुरक्षा पर इसी के निष्कर्ष और निष्कर्ष,

बांध की संरचनात्मक सुरक्षा और भूकंपीय सुरक्षा। के निष्कर्ष

जांच, परीक्षणों की रिपोर्टों के विस्तृत विश्लेषण के साथ निर्वाचन आयोग

और अध्ययन एक और केवल एक निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं कि वहाँ है

मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा पर दिए गए पहले के निष्कर्ष से प्रस्थान की आवश्यकता वाली परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं

इस न्यायालय ने 2006 के फैसले में। वास्तव में, वहाँ नहीं है

मुल्लापेरियार बांध के सुरक्षा पहलू को फिर से खोलने को उचित ठहराते हुए परिस्थितियों या आपात स्थिति में इस न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णय में निर्धारित किया गया।

अंक संख्या पर निष्कर्ष। 2 (ए), 3,4 (ए), 4 (बी) और 10

199 .

उपरोक्त चर्चा के आलोक में,

अंक संख्या पर हमारे निष्कर्ष। 2 (a), 3,4 (a), 4 (b) और 10 इस प्रकार हैं

निम्नलिखित है:

केरल सिंचाई और जल संरक्षण

(i.)

(संशोधन) अधिनियम, 2006 असंवैधानिक और असंवैधानिक है।

इसके अनुप्रयोग में अधिकार और उस पर प्रभाव

मुल्लापेरियार बांध।

((ii.) तमिलनाडु के अधिकार, निर्णय में स्पष्ट किए गए

इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. पी. में पारित दिनांक 27.2.2006 (सी)

No.386/2001 को किसी कानून द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है।

केरल राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया।

(iii.) इस न्यायालय का पूर्व निर्णय 1024 को दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

27.2.2006 के मुद्दे पर रेस जुडिकाटा के रूप में कार्य करता है
जल स्तर बढ़ाने के लिए मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा
142 फीट तक। और अंत में 152 फीट तक। पूरा होने के बाद
को और मजबूत करने के उपाय
मुल्लापेरियार बांध।

(iv.) पट्टा विलेख के संबंध में केरल द्वारा दायर याचिका

दिनांकित 29.10.1886 और संरचनात्मक सुरक्षा
मुल्लापेरियार बांध को आखिरकार तय कर लिया गया है
इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.2.2006 और केरल
इन्हें उठाने या फिर से आंदोलन करने से रोका जाता है
वर्तमान वाद में मुद्दे।

(वी.) केरल तमिलनाडु को बढ़ने से नहीं रोक सकता है।

मुल्लापेरियार बांध का जल स्तर 142 फीट तक पहुंच गया है। और
निर्णय के अनुसार मरम्मत कार्य करने से
दिनांकित 27.2.2006।

अंक संख्या 8.

200. यह मुद्दा इस विवाद को शामिल करता है कि क्या
केरल इस तर्क से वंचित है कि पेरियार नदी एक नदी नहीं है।
अंतर-राज्यीय नदी।

201. तमिलनाडु ने शिकायत में इस प्रकार कहा है:
" वादी, प्रतिवादी नं। 1 , केरल राज्य दो हैं -

नदी तटीय राज्य जिनके माध्यम से अंतर-राज्यीय नदी पेरियार बहती है

बहती है। यह नदी राज्य की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है केरल का, इसके जलग्रहण क्षेत्र के एक हिस्से के साथ

तमिलनाडु राज्य...

202. तमिलनाडु की उपरोक्त दलीलों को ध्यान में रखते हुए,

केरल ने यह मामला स्थापित किया है कि पेरियार नदी एक अंतर नदी नहीं है। राज्य नदी लेकिन यह राज्य के भीतर बहने वाली नदी है; कि यह क्विलोन जिले में निकलती है।

केरल में और केवल केरल के क्षेत्र से होकर गुजरता है।

अरब सागर में गिरने से पहले।

203. अपनी प्रतिकृति में, तमिलनाडु ने स्पष्ट किया है कि तमिल नाडु के किसी भी राज्य में v.

केरल राज्य 1025

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

इससे पहले की कार्यवाही में केरल ने याचिका दायर की थी

संविधान के अनुच्छेद 262 के संदर्भ में नदी जल विवादों पर विचार करने के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की कमी

अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम की धारा 11 के साथ,

1956. यह याचिका इस आधार पर उठाई गई थी कि पेरियार नदी

एक अंतर-राज्यीय नदी। तमिलनाडु ने इस प्रकार याचिका दायर की है कि

केरल को यह दलील देने से रोक दिया गया है कि पेरियार नदी नहीं है।

एक अंतर-राज्यीय नदी।

204. श्री हरीश साल्वे, केरल के विद्वान वरिष्ठ वकील,

तर्क है कि पेरियार नदी केरल में उगती है और एक लंबाई के लिए बहती है

244 कि. मी.। केरल तट पर समुद्र में प्रवेश करने से पहले।

पेरियार नदी तमिलनाडु के किसी भी हिस्से को नहीं छूती है। वह.

प्रस्तुत करता है कि पिछली कार्यवाही में, केरल ने नहीं किया था

उन्होंने स्वीकार किया कि पेरियार नदी एक अंतर-राज्यीय नदी थी। सीखा है।

वरिष्ठ वकील का तर्क है कि पेरियार नदी एक अंतर-राज्यीय नदी है।

और पिछली कार्यवाही में केरल के कथन नहीं हैं। इसे यह दलील देने से रोकें कि
पेरियार नदी एक अंतर नदी नहीं है।

राज्य नदी।

205. 2006 के फैसले में, एक बिंदु पर विचार किया गया और

इस न्यायालय द्वारा तय किया गया है कि क्या इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है

संविधान के अनुच्छेद 262 को देखते हुए वर्जित अंतर-राज्य नदी जल विवाद
अधिनियम, 1956 की धारा 11।

यह मुद्दा केरल द्वारा नहीं उठाया गया होगा, बल्कि तथ्य के लिए उठाया गया होगा।

वह नदी पेरियार एक अंतर-राज्यीय नदी थी। जबकि

इस बिंदु को तय करते हुए, जाहिर है, अदालत ने आधार पर आगे बढ़ाया

वह नदी पेरियार एक अंतर-राज्यीय नदी है। इस अदालत ने यह फैसला सुनाया

केरल के खिलाफ अंक। ऐसा प्रतीत होता है कि पुनरीक्षण याचिका में,

केरल ने पहली बार यह विशिष्ट दलील दी कि पेरियार एक

अंतर-राज्य नदी लेकिन एक अंतर-राज्य समझौते द्वारा कवर की गई। द.

इस न्यायालय द्वारा 27.7.2006 पर समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई है।

206. यह सच है कि पिछली कार्यवाही में केरल की पेरियार नदी को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं
किया गया था एक अंतर-राज्यीय नदी है, लेकिन अधिकार क्षेत्र की कमी की याचिका

इस न्यायालय ने अनुच्छेद 262 की प्रयोज्यता पर विचार करने के लिए,

ऊपर उल्लिखित, केरल द्वारा नहीं उठाया जाता अगर नदी 1026 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

पेरियार एक राज्य के भीतर बहने वाली नदी थी। इसके अलावा, पूरे क्षेत्र नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहने वाली नदी को नदी बेसिन कहा जाता है। जल कानूनों में यह अच्छी तरह से समझा गया है कि किसी भी नदी का बेसिन

इसमें नदी घाटी भी शामिल है। पेरियार नदी का स्थलाकृतिक मानचित्र

बेसिन से पता चलता है कि पेरियार बेसिन का हिस्सा (लगभग 114 वर्ग कि. मी.)

तमिलनाडु में। यह केरल के जल एटलस से स्थापित किया गया है।

जल संसाधन विकास केंद्र द्वारा प्रकाशित और प्रबंधन, कझिकोड, केरल। हालांकि पेरियार बेसिन

तमिलनाडु में आने वाला क्षेत्र बहुत छोटा है लेकिन, हमारे विचार में, कि

पेरियार की स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता

अंतर-राज्यीय नदी का संबंध नदी से है। तथ्य यह है कि

वह 114 वर्ग कि. मी. किमी. पेरियार बेसिन क्षेत्र तमिलनाडु में पड़ता है। यह

लोक निर्माण की अग्रिम रिपोर्ट द्वारा भी मजबूत किया गया है विभाग, केरल सरकार, जो अन्य बातों के साथ-साथ कहता है,

" जिन नदियों का जल निकासी क्षेत्र अधिक है

एक राज्य को अंतर-राज्य की श्रेणी में लाया गया है। इसमें नदियों और एक समेकित अध्ययन को स्वीकार किया गया है।

" पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से जो

अध्याय। उनके जलग्रहण क्षेत्र का एक हिस्सा मद्रास राज्य में है

.....(iv) पेरियार।

हैं।

207. केरल के गवाह एम. के. परमेश्वरन नायर ने

यह स्वीकार किया कि अध्याय एलएक्सआईआई में "अंतरराज्यीय" शीर्षक के तहत

पब्लिक द्वारा प्रकाशित "केरल के जल संसाधन" से जल निर्माण विभाग, केरल सरकार, 1958 में, पेरियार ने

इसका उल्लेख एक अंतर-राज्यीय नदी के रूप में किया गया है। यह गवाह भी

यह स्वीकार करता है कि केरल का जल एटलस जिसमें पेरियार का विवरण है बेसिन से पता चलता है कि बेसिन का हिस्सा पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में पड़ता है।

208. चूंकि केरल ने यह दलील दी है कि पेरियार नदी

एक अंतर-राज्यीय नदी, जाहिर है, यह साबित करने का बोझ केरल पर है

तथ्य। केरल, सिवाय इस दावे के कि पेरियार नदी का उद्गम और प्रवेश करने से पहले केवल केरल के क्षेत्र में पार करता है

अरब सागर और तमिलनाडु में भूमि का कोई भी हिस्सा नदी के पास नहीं है

पेरियार ने यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए हैं कि पेरियार नदी राज्य के भीतर बहने वाली एक नदी है। केरल ने छुट्टी नहीं दी है।

न्यायालय की संतुष्टि के लिए इसका बोझ।

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य 1027

[आर. एम. लोधा, सीजेआईजे]

209. यह सच है कि शिकायत में तमिलनाडु का कथन है कि

ये दोनों राज्य-केरल और तमिलनाडु-नदी तटीय राज्य हैं।

यह पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि तमिलनाडु नदी तटीय क्षेत्र नहीं है।

राज्य लेकिन अंतर-राज्यीय नदी के रूप में पेरियार नदी की स्थिति,

यह केरल के लिए पूरी तरह से असंगत याचिका लेने के लिए खुला नहीं है और पेरियार नदी की स्थिति के बारे में नया विवाद शुरू करें

इस आधार पर कि पहले की याचिका कुछ गलत पर आधारित थी

आधार। हमारे विचार में, केरल को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

कि पेरियार नदी अंतर-राज्यीय नदी नहीं है।

अंक संख्या 8 पर खोज

210. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह माना जाता है कि केरल

यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि पेरियार नदी एक अंतरराज्यीय नदी है। अंक संख्या 8 का उत्तर तदनुसार दिया जाता है। मुद्दा संख्या 9

211. यह मुद्दा केरल द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर आधारित है।

तमिलनाडु में पेरियार नदी पर एक नया बांध बनाया जाएगा मुल्लापेरियार बांध का डाउनस्ट्रीम क्षेत्र। ई. सी. ने अध्याय VIII में "आगे का रास्ता-एक सौहार्दपूर्ण दिशा में" शीर्षक के तहत

संकल्प "ने इस पहलू को पहले विकल्प के रूप में देखा है और

निम्नानुसार सुझाव दिया गया है:

" 1. कि एस. ओ. के. अपने दम पर एक नया बांध बना सकता है

अपनी स्वयं की धारणाओं को पूरा करने के लिए खर्च, यदि तकनीकी

योजना आयोग द्वारा आर्थिक रूप से स्वीकृत, और

एमओईएफ द्वारा उनके नियमों के अनुसार मंजूरी दी गई। द.

एक नए बांध का निर्माण, मुद्रास्फीति के लिए उचित मार्जिन देना

आदि, सरकारी खजाने पर एक रुपये से अधिक खर्च हो सकता है

हजारों करोड़। वैधानिक मंजूरी, एक निर्माण एजेंसी का निर्धारण, प्रारंभिक कार्य, वास्तविक

विध्वंस के साथ निर्माण और विघटन

मौजूदा बांध में 8 से 10 साल लगने की संभावना है। मौजूदा बांध को ध्वस्त या ध्वस्त नहीं किया जाएगा। जब तक नए बांध का निर्माण 28 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों तक नहीं हो जाता, तब तक इसे बंद कर दिया गया है

[2014] 12 एस

सी आर।

पूरा हो जाता है और यह चालू हो जाता है। इस समय तक, मुल्ला के सभी जल पर मौजूदा बांध में एस. ओ. टी. एन. के अधिकार 1886 के पट्टा विलेख से उत्पन्न पेरियार बांध और 1970 के समझौतों का पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा।

2. हालांकि, नए बांध का संचालन होगा

इसके बाद ही शुरू करें:

2 (क) सोक और के बीच एक नया समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जाता है।

एसओटीएन।

2 (ख) नियंत्रण, प्रबंधन, संचालन, रखरखाव और

नए बांध के पानी को विनियमित करना, और

स्वतंत्र समिति/बोर्ड, जिसकी अध्यक्षता करेंगे

भारत संघ का एक प्रतिनिधि, जिसके साथ

सोक और एस. ओ. टी. एन. के प्रतिनिधि इसके रूप में

सदस्यों को जगह दी जाती है;

2 (ग) कि किराया/शुल्क आदि की शर्तें जिनके द्वारा देय हों

एस. ओ. टी. एन. से एस. ओ. के. तय हो गया है और बिजली दोनों राज्यों के उत्पादन अधिकारों का निपटारा किया गया है

पहले से;

2 (घ) नए बांध के निर्माण से पहले और उसके बनने तक

चालू होने पर, मौजूदा बांध होगा
द्वारा सुझाए गए उपायों द्वारा मजबूत किया गया

सी. डब्ल्यू. सी., जिसमें बांध सुरक्षा आवश्यकताएं शामिल हैं

पहले से ही आवाज दी गई है, जिसे अभी भी किया जाना बाकी है।

2 (ङ) कि एस. ओ. टी. एन. लीज डीड के तहत सभी जल स्तरों सहित अपने सभी मौजूदा
अधिकारों का हकदार होगा।

1886 और 1970 का समझौता।

2 (च) कि मौजूदा का विघटन या विध्वंस

बांध 2 (ए) से 2 (ई) शर्तों के अधीन होगा।
दोनों पार्टी राज्यों द्वारा मुलाकात की जा रही है।

2 (छ) अधिकार प्राप्त समिति ने बनाया था

1029 को सुनवाई के दौरान दोनों राज्यों को सुझाव

तमिलनाडु राज्य v. केरल राज्य

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

2 जनवरी, 2012। पक्षकारों के लिए विद्वान सलाहकार

राज्यों से परामर्श करने और उन्हें दाखिल करने के लिए समय मांगा था
प्रतिक्रियाएँ। पक्षकारों के वकील ने बाद में कहा

उनकी प्रतिक्रियाएँ सामान्य शब्द हैं, लेकिन वहाँ है

कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया या विरोध नहीं किया गया

विकल्प सुझाए गए "।

212. वर्तमान विवाद का कोई भी सौहार्दपूर्ण समाधान

दोनों राज्यों के बीच वास्तव में अच्छा होता

इन राज्यों के लोग लेकिन यह संभव नहीं हुआ है क्योंकि दोनों राज्यों में इस विषय पर तीखा टकराव है और उनके

मुद्रा कठोर, लचीली और कठोर होती है। केरल द्वारा नए बांध के निर्माण के लिए दिए गए प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है।

तमिलनाडु। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुल्लापेरियार बांध

पहले विशेषज्ञ द्वारा लगातार सुरक्षित पाया गया है

समिति, और फिर, इस न्यायालय द्वारा 2006 के फैसले में। द.

मुल्लापेरियार की जलवैज्ञानिक, संरचनात्मक और भूकंपीय सुरक्षा

ई. सी. द्वारा भी बांध की पुष्टि की गई है।

अंक संख्या 9 पर खोज

213. नए निर्माण के लिए मामले के इस दृष्टिकोण में

खैर, दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए। यह है प्रस्ताव केरल द्वारा बनाई गई फिल्म को तमिलनाडु पर थोपा नहीं जा सकता है। मुद्दा

इसलिए, केरल के खिलाफ नंबर 9 का फैसला किया जाना है और यह इस तरह से आयोजित किया जाता है।

214. ई. सी. ने निम्नलिखित सुझाव भी दिया है

वैकल्पिक:

" 2. बांध सुरक्षा संगठन केंद्रीय जल आयोग, भारत सरकार (जल मंत्रालय)

संसाधन), ने मानदंड और दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं भंडारण जलाशयों को खाली करना, निचले स्तर के आउटलेट का आकार बढ़ाना

और जलाशयों की प्रारंभिक पूर्ति।

i) मानदंडों के अनुसार, आम तौर पर, बांध

निम्न स्तर के आउटलेट प्रदान किए जाने चाहिए

जलाशय के जल स्तर को कम करने के लिए पर्याप्त क्षमता 30 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

निरीक्षण, रखरखाव के लिए एक निर्दिष्ट ऊंचाई तक

और मरम्मत, और (ii) जलाशय की दर को नियंत्रित करना।

प्रारंभिक भरने के दौरान पूल वृद्धि।

दिशानिर्देशों में सिफारिश की गई है कि एक आउटलेट होना चाहिए

(ख)

किस स्तर पर आउटलेट प्रदान किया जाना है
संबंधित बांध के मालिक निकाय पर छोड़ दिया जाता है। इसका स्तर

बांध के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा

स्थिति, उस स्थान पर एक निर्णय जिस पर संकट है
कारण हो सकता है, इसकी प्रकृति और समय

पूरा करने के लिए आवश्यक निकासी

बहाली के उपाय।

3. मौजूदा एम. पी. डी. परियोजना में, जैसा कि अध्याय-1 (बी) (उपर्युक्त) में उल्लेख किया गया है, डी-धारा 12 के साथ एक सुरंग तैयार की गई थी।

फुट चौड़ा और 7.5 फुट ऊँचा स्लुइस हेड गेट के प्रावधान के साथ एल 106.5 फुट पर पानी के मोड़ के लिए तलहटी है।

एस. ओ. टी. एन. में पेरियार जलाशय से वैगई बेसिन तक। यह सुरंग

वर्ष 1958 में चौड़ीकरण और अस्तर द्वारा इसका आधुनिकीकरण किया गया था।

सुरंग जलाशय को नीचे 106.5 फुट तक खींचने की अनुमति दे सकती है। (i) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार। एल 106.5 फीट से कम भंडारण

संभावित मूल्यांकन के आधार पर एक चिन्हित ऊंचाई तक

दुख को वर्तमान के माध्यम से नहीं खींचा जा सकता है एस. ओ. टी. एन. के लिए पानी निकालने की व्यवस्था

मौजूदा सुरंग। 4. इसके अलावा, ई. एल. 50 फीट पर एक नई सुरंग की खुदाई।, में से

पाठ्यक्रम, सर्वेक्षण, डिजाइन और टेक्नो आयोजित करने के बाद

आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन, आवश्यक स्लुइस गेट के साथ

ई. एल. 106.5 फुट से जलाशय के पानी को 50 फुट तक निकालना। इन अध्ययनों को एक के भीतर करना होगा निर्दिष्ट समय सीमा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि नई सुरंग से पानी के प्रवाह का उपयोग बिजली के लिए किया जा सकता है

सृजन या परिवर्तन करके किसी अन्य उद्देश्य के लिए

अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे में। तमिल नाडु बनाम के निर्णय के आधार पर।

केरल राज्य 1031

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

नई सुरंग के निकास का उन्नयन, निकासी

संबंधित में एम. पी. डी. जलाशय संभव होगा।

अवधि।

नई सुरंग का निर्माण करने की आवश्यकता होगी

एस. ओ. टी. एन., मौजूदा बांध के स्वामित्व के बाद से

उस पर सूट पहने। निर्माण के लिए कुल व्यय

नई सुरंग एस. ओ. टी. एन. द्वारा वहन की जानी चाहिए। द.

नए बांध के प्रतिस्थापन की लागत की तुलना में लागत कम हो सकती है। एस. ओ. टी. एन. चाहिए

एक वर्ष के भीतर एक नई सुरंग बनाने का प्रस्ताव। एल 50 फीट पर नई सुरंग एस. ओ. टी. एन. को सक्षम बनाएगी।

भंडारण में उपलब्ध अतिरिक्त पानी का उपयोग करना

ईएल 106 फीट से 50 फीट के बीच। वर्तमान में ये जल अप्रयुक्त रह जाते हैं।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि इस विकल्प को लागू किया जाता है

समय की एक सहमत अवधि में, भय की धारणा

सोक के लोगों के दिमाग को आराम मिलेगा। वे तब समझ सकते हैं कि नई सुरंग है

भंडारण को तेजी से निकालने में मदद करने के लिए जा रहा है और

बेहतर होगा, अगर बांध पर कोई संकट पैदा हो जाए। के रूप में

एक गुरुत्वाकर्षण बांध शायद ही कभी अचानक आता है, जैसे निकासी से बांध टूटने की बाढ़ (डी. बी. एफ.) में कमी आएगी।

बड़े पैमाने पर। हालांकि, एस. ओ. के. की 1 टी. एम. सी. की मांग

पर्यावरणीय प्रवाह के लिए पानी की पुष्टि नहीं की जाती है,

फिर भी, एक वैध आवश्यकता जिसका मूल्यांकन किया जाना बाकी है,

एफ. आर. एल. को 142 फीट तक बढ़ाने के बाद पूरा किया जा सकता है। ए. दाएँ
से एक उपयुक्त व्यास का छोटा पाइप आउटलेट

किनारे की पहाड़ी खोदी जा सकती है

एस. ओ. टी. एन. द्वारा पर्यावरणीय प्रवाह को मजबूत किया गया

सी. डब्ल्यू. सी. और सोक के साथ परामर्श।

समझौता ज्ञापन को एस. ओ. टी. एन. 1032 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. द्वारा निष्पादित करना होगा।

और सोक, सरकार के एक प्रतिनिधि की उपस्थिति में।

भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, के बारे में

एक निश्चित समय के भीतर नई सुरंग का निर्माण।

215. ई. सी. ने स्वयं नोट किया है कि दूसरा विकल्प है

दोनों राज्यों के बीच समझौते पर निर्भर लेकिन हमारे लिए

इस पर आपसी सहमति की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है।

पहलू भी। निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाए गए विकल्प सार्थक हैं।

दोनों राज्यों द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है लेकिन अपरिवर्तनीय को ध्यान में रखते हुए

उनके द्वारा अपनाया गया रुख, यह संभव नहीं लगता है।

तथापि, हम पक्षकारों को न्यायालय में आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं यदि -

वे दोनों में से किसी एक पर कुछ सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने में सक्षम हैं।

निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाए गए दो विकल्प।

मुद्दा संख्या। 2 (ख) और 11

216. इन मुद्दों के संदर्भ में, यह पुरजोर आग्रह किया जाता है

केरल द्वारा कि तमिलनाडु को कोई चोट नहीं लगी है क्योंकि

मुल्लापेरियार बांध में भंडारण को घटाकर 136 फीट करना। 1979 से। केरल के अनुसार, 1979 के बाद अधिक पानी खींचा गया और अधिक क्षेत्र की सिंचाई की गई। केरल ने इस संबंध में

विभाग और उसका विश्लेषण। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1979 से पहले की अवधि के दौरान औसत पानी की निकासी 19,277 थी।

एम. एफ. टी. जबकि 1979 के बाद की अवधि में खींचा गया पानी 21,434 था।
एम. सी. जहां तक सिंचाई की सीमा का संबंध है, केरल प्रस्तुत करता है कि

मुल्लापेरियार से तमिलनाडु में सिंचाई का विस्तार, पानी है

1979 से पहले लगभग 1,71,307 एकड़ से बढ़ा

2,31,412 एकड़ तक। केरल ने प्रश्न संख्या के लिए पीडब्लू-1 के उत्तरों पर भी भरोसा किया है। 585 601 और 58 से 59 तक। केरल ने

आंध्र राज्य में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया।

प्रदेश 3 जिसमें इस न्यायालय ने कहा, "... कि एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के खिलाफ दायर निषेधाज्ञा के मुकदमे में, बोझ

शिकायत करने वाला राज्य आम तौर पर उससे बहुत अधिक है।

मुकदमे में निषेधाज्ञा की मांग करने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जाना आवश्यक है

निजी दिलों के बीच। शिकायत करने वाले राज्य को स्थापित करना होगा

यह कि अधिकारों का खतरापूर्ण आक्रमण पर्याप्त है और तमिल नाडु बनाम के एक गंभीर राज्य का है।

केरल राज्य 1033

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

परिमाण। राज्यों के बीच के मामले में, निषेधाज्ञा का पालन नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके कुछ अधिकारों का उल्लंघन होता है।

शिकायत करने वाला राज्य लेकिन उच्च इक्विटी का मामला बनाया जाना चाहिए

जो देने में न्यायालय की अंतरात्मा को प्रेरित करता है

निषेधाज्ञा "।

217. दूसरी ओर तमिलनाडु का कहना है कि बांध में जल स्तर को मूल एफआरएल तक बढ़ाना बिल्कुल आवश्यक है

पांच सूखा संभावित क्षेत्रों में लगभग 2 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करना।

थेनी, डिंडीगुल, मदुरै, शिवगंगई और

रामनाथनपुरम। लगभग 68 लाख किसान और कृषि

उपरोक्त पाँच जिलों के 80 लाख लोगों के अलावा मजदूर

सिंचाई और पीने के उद्देश्यों के लिए पानी की अपर्याप्त समय पर आपूर्ति के कारण पीड़ित होना जारी है।

218. उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने इस पहलू पर भी विचार किया है और निम्नलिखित रूप में देखा गया:

" निर्वाचन आयोग ने अनुमान लगाया है कि वैगई में सिंचाई में वृद्धि हुई है

बेसिन मुख्य रूप से i) 1954 में वैगई बांध के निर्माण और 1974 के बाद संबंधित नहर वितरण प्रणाली के कारण है।

जिनसे निकलने के लिए एक संतुलनकारी जलाशय के रूप में काम किया

1954 के बाद से गैर-सिंचाई महीनों में बिजली स्टेशन, और ii) विश्व बैंक ने पेरियार के आधुनिकीकरण में सहायता की।

वैगई सिंचाई परियोजना, चरण-I और II, में कार्यान्वित

1980'एस, जिसने जल उपयोग दक्षता में सुधार किया।

यद्यपि एस. ओ. टी. एन. द्वारा सिंचाई को मजबूत किया जाता है, वैगई बेसिन में अभी भी बड़ा सूखा-प्रवण क्षेत्र है और

क्षेत्र की घरेलू/नगरपालिका/औद्योगिक आवश्यकताएँ हैं - महत्वपूर्ण है। ये वर्तमान आवश्यकताएँ अधूरी रहती हैं, यदि

ई. सी. सोक के इस कथन को स्वीकार करने में असमर्थ है कि नहीं इन परिस्थितियों में एस. ओ. टी. एन. को नुकसान पहुंचाया जाएगा।

यदि एफ. आर. एल. को बहाल नहीं किया गया है। "1034 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर.

219. जहाँ तक 1979 से पहले की अवधि में पानी की निकासी का संबंध है और

1979 के बाद की अवधि का संबंध है, तमिलनाडु का एकमात्र गवाह यह स्वीकार किया है कि 1979 के बाद की अवधि में खींचा गया पानी था

21,434 एम. एफ. टी. और 1979 से पहले का औसत पानी

यह 19,277 एम. सी. एफ. टी. था। इसी तरह, उन्होंने वृद्धि को स्वीकार किया है

1979 से पहले 1,71,307 एकड़ से 2,31,412 एकड़ तक सिंचाई

1992-93 में, लेकिन, जैसा कि इसी द्वारा देखा गया है, यह इसके कारण हुआ है

1954 में वैगई बांध और संबंधित नहर का निर्माण

1974 के बाद वितरण प्रणाली। पाँच जिले थेनी, डिंडीगुल,

मदुरै, शिवगंगाई और रामनाथनपुरम जो परोसे जाते हैं पेरियार परियोजना सूखा प्रवण है। लगभग 2 लाख एकड़ भूमि

ये इन पाँच जिलों में आते हैं जिन्हें सिंचित करने की आवश्यकता है। ► द.

सिंचाई के लिए समय पर पानी की अपर्याप्त आपूर्ति और इन जिलों की आबादी के लिए पीने के उद्देश्य प्रभावित हो सकते हैं

उनके जीवन के साथ-साथ आजीविका भी। सिंचाई में वृद्धि और

1979 के बाद पानी की अधिक निकासी अभी भी कम प्रतीत होती है

इन जिलों में 80 लाख से अधिक लोगों की आबादी के लिए।

220. इन तथ्यों में, इसलिए यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि तमिल

नाडु यह स्थापित करने में सक्षम रहा है कि उसके अधिकारों पर आक्रमण है

सारगर्भित। तमिलनाडु इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर निषेधाज्ञा देने के लिए एक मामला बनाने में सक्षम रहा है।

आंध्र प्रदेश राज्य 3. इसके अलावा, वर्तमान सूट एक सूट नहीं है

निषेधाज्ञा के लिए मुख्य प्रार्थना यह है कि केरल

सिंचाई और जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 अपने आवेदन में असंवैधानिक और अधिकार से बाहर घोषित किया गया और

मुल्लापेरियार बांध पर प्रभाव ।

अंक संख्या पर निष्कर्ष । 2 ((ख) और 11 ।

221. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि तमिलनाडु पैरा 40 (i) और (ii) में प्रार्थना के अनुसार राहत का हकदार है ।

सूट से । नतीजतन, यह घोषित किया जाता है कि केरल सिंचाई

और जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा पारित

केरल विधानमंडल अपने अनुप्रयोग में असंवैधानिक है और

मुल्लापेरियार बांध पर प्रभाव । प्रथम प्रतिवादी-राज्य

केरल-से स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश द्वारा प्रतिबंधित है आक्षेपित विधान या
तमिल नाडु के किसी भी राज्य में लागू करना और लागू करना ।

केरल राज्य 1035

[आर. एम. लोधा, सीजेआई ।]

तमिलनाडु राज्य में हस्तक्षेप करने या बाधा डालने का तरीका

जल स्तर को बढ़ाकर 142 फीट करना । और इस न्यायालय के दिनांकित निर्णय के अनुसार मरम्मत कार्यों को पूरा करने से

27.2.2006 डब्ल्यू. पी. में (ग) न. 386/2001 संबंधित मामलों के साथ ।

222. हालांकि, केरल की आशंकाओं को दूर करने के लिए

कोई मौजूद नहीं है-मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा के बारे में एफ. आर. एल. का
पुनर्निर्माण करके इसे 142 फुट तक पहुँचाया जाना । , ए 3-सदस्य पर्यवेक्षी

समिति का गठन किया जाता है । समिति के पास एक होगा

केंद्रीय जल आयोग के प्रतिनिधि और एक

दोनों राज्यों से प्रत्येक प्रतिनिधि-तमिलनाडु और

केरल। केंद्रीय जल आयोग का प्रतिनिधि
समिति के अध्यक्ष होंगे। यह समिति करेगी
अपने कार्यालय के लिए उस स्थान का चयन करें, जो केरल द्वारा प्रदान किया जाएगा।
तमिलनाडु समिति का पूरा खर्च वहन करेगा।

223. पर्यवेक्षी की शक्तियाँ और कार्य

समिति इस प्रकार होगी:

(1) समिति पुनर्स्थापना की निगरानी करेगी

मुल्लापेरियार बांध में एफ. आर. एल. की ऊंचाई 142 तक
फीट।

((ii) समिति समय-समय पर बांध का निरीक्षण करेगी। विशेष रूप से मानसून से ठीक पहले और मानसून के दौरान और कड़ी नजर रखें इसकी सुरक्षा और आवश्यक उपायों की सिफारिश करना। इस तरह के कदम उठाए जाएंगे तमिलनाडु।

((ग) समिति उचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी। कदम उठाएँ और दोनों को आवश्यक निर्देश जारी करें आपात स्थिति में मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा के लिए यदि आवश्यक हो तो राज्य-तमिलनाडु और केरल-या उनमें से कोई भी। इस तरह के निर्देश होंगे सभी संबंधित लोगों द्वारा पालन किया गया।

((iv) समिति तमिलनाडु को 1036 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 12 एस. सी. आर. करने की अनुमति देगी। एहतियाती उपाय जो बांध के आवधिक निरीक्षण पर आवश्यक हो सकते हैं केंद्रीय जल आयोग और बांध सुरक्षा संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार।

224. मुकदमा ऊपर के रूप में घोषित किया गया है, जिसके बारे में कोई आदेश नहीं है लागतें।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था आदेश 2006 के मूल वाद संख्या 3 (तमिलनाडु राज्य बनाम. की स्थिति केरल और एक अन्य), आगे कुछ भी तय नहीं किया जाना है।

यह विशेष अनुमति याचिका और इसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

मुकदमा तय किया गया।

बिभूति भूषण बोस

